



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

No. 108]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2007/चैत्र 29, 1929

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2007/CHAITRA 29, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2007

सं. 1 (आर.ई. 2007)/2004-2009

फा. सं. 01/94/180/प्रक्रिया पुस्तक/एएम-08/पीसी-I.-विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथा निहित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के वार्षिक परिशिष्ट जिसमें 19 अप्रैल, 2007 तक अद्यतन वार्षिक परिशिष्ट शामिल करते हुए तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट: <http://dgft.gov.in> पर यथा उपलब्ध प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्टों को, एतद्वारा, अधिसूचित करते हैं। यह 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

भवानी सिंह मीना, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## शब्दावली

## संक्षिप्त अक्षर

## पूर्णाक्षर

एसीसी	सीमाशुल्क उपायुक्त
एसीयू	एशियायी निकासी संघ
एईजैड	कृषीय निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एएसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुर्नस्थापना बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार निगम
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव तकनीकी पार्क
सीबीईसी	उत्पाद सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीआईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीआईएफ	लागत बीमा और भाड़ा
सीआईएस	स्वतन्त्र राज्य का कॉमनवैल्थ
सीओडी	नकद भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीवीडी	काउंटरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीओबीटी	जैव तकनीकी विभाग
डीसी	विकास आयुक्त
डीईपीबी	शुल्क पात्रता पासबुक योजना
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार
डीएफआरसी	शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीआई	विद्युत विभाग
डीओआईटी	सूचना तकनीकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा

ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईएच	निर्यात सदन
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क
ईआईसी	निर्यात निरीक्षण समिति
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफआईईआई	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफएमएस	फोक्स बाजार योजना
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफपीएस	फोक्स उत्पाद योजना
एफटी (डी एंड आर)	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 20)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य संविदा
जीआरसी	शिकायत निवारण समिति
एचएसीसीपी	खतरा विश्लेषण और नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी वी1	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)
एचबीपी वी2	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2)
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड संख्या (कूट)
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (तालमेल प्रणाली) निर्यात और आयात मर्चों का वर्गीकरण 2004-2009
आईटीपीओ	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
एलओसी	साख पत्र
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक शपथ-पत्र
एमएआई	बाजार पहुँच अभिप्रेरण
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश व्यापार मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय

एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
पीआरसी	नीति छूट समिति
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
पीटीएच	प्रीमियर व्यापार सदन
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएससीक्यू सी	गुणवत्ता शिकायतों हेतु क्षेत्रीय उप समिति
एसबी	पोत लदान बिल
एसईएच	स्टार निर्यात सदन
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टिट्यूट कैपाबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफआईएस	भारत से सेवित योजना
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईओएन	मानक निवेश उत्पादन मानदंड
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपी	सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क
टीईई	टाऊनस ऑफ एक्पोर्ट एक्सेलेंस
टीएच	व्यापार सदन
टीआरक्यू	टैरिफ रेट कोटा
वीए	मूल्य संवर्धन
वीआरजीयूवाई	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना
डब्ल्यू एचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन निर्माण



## अध्याय - एक

## प्रस्तावना

अधिसूचना

1.1

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अनुसार महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा समेकित प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), और प्रक्रिया पुस्तक (भाग-2) और डी ई पी भी दरों की अनुसूची नामक पुस्तकों के संकलन को अधिसूचित करते हैं।

समय-समय पर यथासंशोधित ये संकलन 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेंगे।

उद्देश्य

1.2

उद्देश्य आसान पारदर्शी और ई डी आई संगत प्रक्रियाओं के द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति (2004-2009) को लागू करना जिससे अनुपालन और विदेश व्यापार के प्रबंधन का संचालन करना आसान हो।

परिभाषा

1.3

इस प्रक्रिया पुस्तक के उद्देश्य हेतु, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, उसके तहत बने नियमों और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति (2004-09) में उल्लिखित परिभाषाएँ और शब्दावली लागू होंगी।

## अध्याय - दो

## निर्यात और आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

नीति	2.1	नीति के अध्याय-2 में निर्यात और आयात के बारे में सामान्य प्रावधान से संबंधित नीति दी गई हैं।
आयात/निर्यात के देश	2.2	जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो, किसी भी देश से/को आयात/निर्यात करना वैध होगा। तथापि, ईराक से/को हथियारों और संबंधित सामग्री के आयात/निर्यात निषिद्ध होगा।  तथापि, उपर्युक्त प्रावधान आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के तहत यथा आवश्यक सभी शर्तों, अथवा लाइसेंस की जरूरत, अथवा अनुमति के मद्दे होंगे।
आवेदन-शुल्क	2.3	शुल्क की मात्रा, भुगतान का तरीका, शुल्क-वापसी की प्रक्रिया और शुल्क से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणियाँ परिशिष्ट-21ख में दी गई हैं।
क्षेत्रीय प्राधिकारियों की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता	2.4	जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्रत्येक आवेदन पत्र, प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
आवेदन पत्र प्रस्तुत करना	2.5	अधूरे अप्राधिकृत आवेदन पत्र को विशिष्ट कारण बताते हुए रद्द कर दिया जाएगा। तथापि, मैनुअल आवेदनों के मामले में आवेदक को एम एस वर्ड फॉर्मेट में आवेदन की एक साफ्ट कापी प्रस्तुत करनी होगी।
आयातक/निर्यातक का प्रोफाइल	2.6	प्रत्येक आयातक/निर्यातक को 'आयात निर्यात प्रपत्र' के भाग-1 में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को एक बार आयातक/निर्यातक प्रोफाइल प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 'आयात निर्यात प्रपत्र' के भाग-1 में दी गई सूचना को अपने डाटा-बेस में डालना होगा ताकि बार-बार सूचना मांगने की जरूरत ना पड़े। 'आयात निर्यात प्रपत्र' के भाग-1 में दी गई सूचना में किसी परिवर्तन की स्थिति में आयातक/निर्यातक लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करेगा।
डाक टिकट लगा स्व-पता लिफाफा	2.7	आवेदक मांगे गए कागजातों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने हेतु 40x15 सेमी. का स्वपता लिखा हुआ लिफाफा प्रस्तुत करेगा जिस पर अपेक्षित डाक टिकट लगी हो।

आयातक-निर्यातक कोड 2.8  
संख्या: छूट प्राप्त श्रेणियाँ

आयातकों-निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों को आयातक-निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करने से छूट है:-

- (1) विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियमों से छूट) आदेश, 1993 की धारा 3(1) (उप धारा (ड.) और (ठ) को छोड़कर) में शामिल आयातक तथा धारा 3(2) (उप धारा (झ) और (ट) को छोड़कर) में शामिल निर्यातक।
- (2) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग।
- (3) जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार अथवा विनिर्माण या कृषि से असम्बद्ध माल का आयात या निर्यात करते हैं।
- (4) जो व्यक्ति नेपाल, भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्रों के माध्यम से म्यांमार तथा चीन (गुजी, नामग्या, शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से) से/को माल का आयात/निर्यात करता है बशर्ते कि एकल परेषण का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय 25,000/- रुपये से अधिक न हो।

“तथापि, उपर्युक्त श्रेणी 2 द्वारा निर्यात के मामलों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2, परिशिष्ट-3 में सूचीबद्ध विशेष रसायनों, जीवों, सामग्रियों उपकरणों और प्रौद्योगिकियाँ (एस सी को एम ई टी) के निर्यात के लिए आयातक-निर्यातक कोड (आई ई सी) संख्या प्राप्त करने की छूट लागू नहीं होगी।

- (5) आयात-निर्यात प्रयोजन हेतु निर्यातक/आयातक की श्रेणियों द्वारा उनके प्रति उल्लिखित निम्नलिखित स्थाई आई ई सी संख्या का उपयोग किया जायेगा।

क्र.सं.	कोड सं.	आयातक/निर्यातक की श्रेणियाँ
1.	0100000011	केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।
2.	0100000029	राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।
3.	0100000037	डिप्लोमेटिक कार्मिक, भारत में काउंसिलर अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारी।
4.	0100000045	विदेश जाने/लौटने वाला भारतीय बैगेज नियमों के अधीन लाभों का दावा करता हो।

5. 0100000053 व्यक्ति/संस्थान/अस्पताल को व्यापार या विनिर्माण अथवा कृषि से जुड़ा न हो और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात या निर्यात करता हो।
6. 0100000061 वह व्यक्ति जो नेपाल को/से माल का निर्यात/आयात करता हो।
7. 0100000070 वह व्यक्ति जो म्यांमार को/से भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से माल का निर्यात/आयात करता हो।
8. 0100000088 फोर्ड फाउंडेशन।
9. 0100000096 आयातक जिसने ए टी ए कार्नेट के प्रावधानों के अधीन मेले/प्रदर्शनियाँ या इसी प्रकार के आयोजनों में प्रदर्शन का उपयोग करने के लिए माल का आयात करता हो।
10. 0100000100 निदेशक, राष्ट्रीय ब्लड ग्रुप संदर्भ प्रयोगशाला, मुम्बई या उनके द्वारा प्राधिकृत कार्यालय।
11. 0100000126 व्यक्ति/खैराती संस्था/पंजीकृत गैर सरकारी संगठन जो माल का आयात करती है और जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पीड़ित द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
12. 0100000134 गुंजी, नामग्या, शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से चीन से/को समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुमत माल का आयात/निर्यात करनेवाले व्यक्ति।

**टिप्पणी :-** वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने "पैन" प्राप्त किया है को भी, आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करनी होगी। गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपर्युक्त अनुसार स्थायी आई ई सी संख्या प्रयोग करनी होगी।

**आयातक-निर्यातक कोड संख्या की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र** 2.9

आयातक निर्यातक कोड संख्या की मंजूरी के लिए आवेदक का पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार के तहत, कम्पनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय और अन्य के मामलों में मुख्यालय आता हो 'आयात निर्यात प्रपत्र' में आयातक-निर्यातक कोड संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करेगा और समर्थन में उसके साथ निर्धारित दस्तावेज लगाना होगा।

एक "पैन" नम्बर पर एक ही आई ई सी जारी की जाएगी।

**आयातक-निर्यातक कोड फार्मेट और विवरण** 2.9.1

संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी परिशिष्ट-18ख क में दिए गए फार्मेट पर आई ई सी संख्या जारी करेगा। ऐसे आयातक निर्यातक कोड संख्या की एक प्रति संबंधित बैंक (आयात-निर्यात प्रपत्र 2क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) को भेजी जाएगी।

क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी आयातक निर्यातक कोड संख्या का समेकित विवरण (परिशिष्ट-18ग) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, परिशिष्ट-18घ में

दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनियमन नियंत्रण विभाग के कार्यालयों को भेजा जाएगा।

- |  |       |  |
|--|-------|--|
| आयातक-निर्यातक कोड संख्या की वैधता           | 2.9.2 | किसी आवेदक को आबंटित आयातक निर्यातक कोड संख्या, इसकी सभी शाखाओं/प्रभागों/यूनिटों फैक्ट्रियों के लिए वैध होगा।  |
| आयातक-निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट प्रति | 2.9.3 | जहाँ आयातक-निर्यातक कोड संख्या गुम हो जाता है, तो वह जारी करने वाला प्राधिकारी, आयातक निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट की मंजूरी हेतु शपथ पत्र पर अनुरोध पर विचार करेगा जिसने उसे मूल प्रमाणपत्र जारी किया था।   |
| आयातक-निर्यातक कोड संख्या को लौटाना          | 2.9.4 | यदि कोई आयातक-निर्यातक कोड संख्या धारक आबंटित कोड संख्या का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करके उक्त कोड संख्या को लौटा सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, जारी करने वाला लाइसेंसिंग प्राधिकारी तत्काल उसे रद्द कर देगा और सीमाशुल्क और विदेश व्यापार महानिदेशालय को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करेगा।  |
| अनिवार्य विवरण                               | 2.9.5 | हटा दिया गया है।   |
| प्रतिबंधित मदों के आयात-निर्यात हेतु आवेदन   | 2.10  | आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित मदों के आयात या निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु ओवदन पत्र, इस प्रक्रिया पुस्तक के सम्बद्ध अध्यायों में विनिर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को फॉर्म पर प्रस्तुत करना होगा।  |
| भारत-अमेरिका समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आयात  | 2.11  | <p>संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्दिष्ट पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों आदि का आयात संयुक्त राज्य निर्यात विनियमों के अधीन किया जाएगा।</p> <p>ऐसी मदों के संयुक्त राज्य अमेरिका आपूर्तिकर्ताओं को, भारत में जारी आयात प्रमाणपत्र के आधार पर निर्यात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा। आयात प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (आई.सी.आई.ए.) निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पर आधारित सिस्टम के आयात हेतु इलैक्ट्रॉनिकी विभाग।</li> <li>(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, तकनीकी सहायता खण्ड (टी एस डब्ल्यू), इसके अधीन पंजीकृत संगठित क्षेत्र की यूनिटों के लिए कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित सिस्टम को छोड़कर।</li> <li>(3) रक्षा से संबंधित मदों के लिए रक्षा मंत्रालय।</li> </ol> |

- (4) लघु उद्योगों तथा इकाइयाँ जो उपर्युक्त में से किसी के लिए तथा उपर्युक्त से भिन्न के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार,
- (5) उपर्युक्त किसी की भी ओर से भारतीय दूतावास, वाशिंगटन (डी सी)

आयात प्रमाणपत्रों के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में अनुरोध करना होगा। परिशिष्ट-31 के में दिए गए आयात प्रमाण-पत्र आई.सी.आई.ए. द्वारा सीधे ही आयातक को दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि (1) विदेश मंत्रालय (ए एम एस अनुभाग), नई दिल्ली (2) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, नई दिल्ली, और (3) विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली को दी जाएगी।

तथापि, आई टी सी(एच एस) में यथा प्रतिबंधित मर्चें के बारे में प्राधिकार पत्र इस आयात को आयात लाइसेंस के स्थान पर नहीं माना जाएगा और ऐसे मर्चों के लिए जब अपेक्षित हो आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

आयात लाइसेंस/  
प्रमाणपत्र/ प्राधिकार  
पत्र/सीसीपी/निर्यात  
लाइसेंस की वैधता

2.12

आयात-निर्यात प्राधिकार पत्र की वैधता, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से निम्नवत् होगी जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो:-

- (1) नीति के अध्याय 4 के अनुसार 24 माह  
रत्न और जेवरों के लिए  
अग्रिम लाइसेंस (वार्षिक  
आवश्यकता के लिए अग्रिम  
लाइसेंस सहित) और प्रतिपूर्ति लाइसेंस
- (2) ई पी सी जी लाइसेंस 36 माह  
(स्पेयर्स के अलावा)
- (3) स्पेयर्स, रिफ्रेक्टरींग कैटालिस्ट ईपीसीजी लाइसेंस  
आ उपभाज्यों के लिए के निर्यात दायित्व  
ई पी सी जी लाइसेंस अवधि के साथ समाप्त
- (4) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो 24 माह  
सी पी पी और शुल्क हकदारी  
पार. तक योजना सहित अन्य
- (5) मान्य निर्यात हेतु अग्रिम 24 माह अथवा  
लाइसेंस (वार्षिक परियोजना की कार्य  
आवश्यकता हेतु अवधि के साथ समाप्त  
अग्रिम लाइसेंस सहित) होना, जो भी बाद में हो।

- 2.12.1 जहाँ प्राधिकार पत्र माह के दौरान समाप्त होता है, ऐसा प्राधिकार पत्र माह के अंतिम दिन तक वैध माना जाएगा।

यह प्रावधान पुनः वैध प्राधिकार-पत्र हेतु भी लागू होगा।

- 2.12.2 “वैधता की अवधि का अर्थ है, शिपमेन्ट की अवधि अथवा लाइसेंस प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र के अधीन शामिल माल का प्रेषण। आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की वैधता शिपमेन्ट की तारीख/इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 9.11क में यथाउल्लिखित आपूर्तिकर्ताओं देश से माल के प्रेषण की तारीख होगी न कि भारतीय पत्तन पर माल की पहुंचने की तारीख।

- 2.12.3 ऊपर पैरा 2.12.2 के प्रावधान स्तरधारकों और सेवा प्रदायकों, लक्ष्योपरि योजना और विशेष कृषि उपज योजना के लिए उल्लिखित डी ई पी बी, शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाण-पत्र, पर लागू नहीं होंगे। स्तरधारकों और सेवा प्रदायकों, लक्ष्योपरि योजना, विशेष कृषि उपज योजना के लिए डी ई पी बी, शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाण-पत्र जो शुल्क साख हकदारी के अंतर्गत आते हैं की वास्तविक वैधता शुल्क जमा करने की तारीख तक मान्य मानी जाएगी।

- 2.12.4 इसी प्रकार, निर्यात दायित्व अवधि महीने के अन्त तक मानी जाएगी।

आयात/निर्यात लाइसेंस/  
प्रमाण पत्र/ प्राधिकार पत्र/  
अनुमति का पुनः वैधीकरण

- 2.13 संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसने लाइसेंस/प्रमाण पत्र/ प्राधिकार पत्र/ अनुमति जारी किया था। के द्वारा गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति का एक बार में बारह माह की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है।

- 2.13.1 तथापि, हस्तांतरणीय लाइसेंस/प्राधिकार पत्र और स्टॉक तथा बिक्री प्राधिकार पत्र पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि प्राधिकार पत्र, सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास ही समाप्त न हो गया है।

- 2.13.2 ऐसा पुनः वैधीकरण (ऊपर 2.13 और 2.13.1 के तहत) संबंधित कार्यालय प्रमुख के विशेष आदेशों के तहत कब्जे की अवधि तक अधिकतम होगा।

- 2.13.3 पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को दिया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी पुनःवैधीकरण के लिए आवेदन की तारीख को लाइसेंस में उल्लिखित मदों के आयात को नियन्त्रित करने वाले सरकारी नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार प्रतिबन्धित सूची लाइसेंस पुनःवैधीकरण के लिए आवेदन पर विचार करेगा। जहां संबंधित प्राधिकारी है, मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक स्वसत्यापित प्रति महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत करनी होगी।

- निर्यात-आयात लाइसेंसों/ प्रमाण पत्र/ प्राधिकार पत्र/ अनुमति पत्र/सीमाशुल्क निकासी परमिटों की डुप्लीकेट प्रतियाँ
- 2.14 जब कोई प्राधिकार पत्र खो जाता है तो परिशिष्ट-24 में दिए गए फार्म में शपथ पत्र की प्रति के साथ उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसकी डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, गुणावगुण के आधार पर, मूल प्राधिकार पत्र का रद्द करने तथा उन संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों, जिनके यहाँ इस प्राधिकार की मूल प्रति पंजीकृत थी, को सूचित करने के बाद उस प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करेगा।
- 2.15 मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन के प्रति जारी की जाएगी:-
- (क) बचाए गए शुल्क अथवा शुल्क साख (अप्रयुक्त बकाया) के 10 प्रतिशत के समतुल्य फीस के साथ एक आवेदन पत्र।
  - (ख) गुम होने की दर्ज की गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की एक प्रति।
  - (ग) नोटरी स्टैम्प पेपर पर मूल शपथपत्र की एक प्रति।
  - (घ) डुप्लीकेट लाइसेंसों को जारी करने के कारण राजस्व की होने वाली क्षति की पूर्ति करने की वचनबद्धता दर्शाने वाले स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड।
- 2.15.1 जब प्राधिकार पत्र सरकारी एजेन्सी द्वारा गुम हो जाता है और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो (क) से (घ) तक के दस्तावेज नहीं माँगे जाएंगे।
- ऐसे मामलों में, पुनः वैधीकरण पृष्ठांकन की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए होगा।
- 2.15.2 संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, डुप्लीकेट जारी करने से पूर्व पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्राधिकार पत्र के उपयोग से संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करेगा।
- 2.15.3 डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता मूल अवधि के साथ समाप्त होगी। यदि वैधता समाप्त हो गई हो तो किसी अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 2.15.4 हटा दिया गया है।
- 2.15.5 2.15.2 तथा 2.15.3 पैरा के प्रावधान, पैरा 2.14 तथा 2.15 दोनों के नामले लागू होगी।



- पहचान पत्र 2.16 प्राधिकार पत्र तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय प्राधिकारियों (परिशिष्ट 20 ख, 3 वर्षों हेतु वैध) से अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए आयातक और निर्यातक को प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक और प्राधिकृत कर्मचारियों (तीन से अधिक नहीं) को पहचान पत्र जारी किए जा सकते हैं।
- तथापि लिमिटेड कंपनियों के मामले में, क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रति कम्पनी तीन से अधिक पहचान पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकता है।
- तथापि, एक ही डायरेक्टर/पार्टनर, ग्रुप कंपनी अथवा समकक्ष मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी का प्रमुख लिखित में कारण दर्ज करने के बाद बहुप्रयोजन पहचान पत्र जारी कर सकता है।
- प्राधिकृत अधिकारियों के साथ साक्षात्कार 2.17 ऐसे अधिकारी अपने विवेकानुसार आयातक/निर्यातक के किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि को भी साक्षात्कार/स्पष्टीकरण की अनुमति दे सकते हैं। साक्षात्कार/स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारी के ई.मेल के माध्यम से भी किए जा सकते हैं।
- लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मर्दों का निर्यात 2.18 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मर्दों के संबंध में लघु उद्योग एककों से भिन्न अन्य एककों को नई क्षमताओं का सृजन करने या इनमें विस्तार करने की अनुमति है बशर्ते कि उन्होंने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो।
- लाइसेंसधारी को इस आशय की विधिक वचनबद्धता क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी। निर्यात दायित्व को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मानीटर किया जाएगा।
- गोदामों की सुविधा 2.19 विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.28 के अनुसार सार्वजनिक/निजी सीमाशुल्क वाण्डेड गोदाम, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय-9 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए घरेलू ट्रेफिक क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं।
- माल की प्राप्ति पर, गोदाम इस माल को यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना एक वर्ष की अवधि के लिए रख सकेगा। यथालागू सीमाशुल्क के भुगतान करने पर घरेलू उपभोग के लिए आगम-पत्र और प्राधिकार पत्र की प्रस्तुति, जहाँ कहीं आवश्यक हो, के प्रति माल की निकासी की जा सकती है।
- शुल्क मुक्त श्रेणियों/शुल्क रियायत श्रेणियों के मदे निपटान के मामलों में, शुल्क में छूट रियायत, जैसा भी मामला हो की अनुमति दी जा सकती है।
- डी.ई.पी.बी. के प्रति निकासी के मामले में, आयात पर सीमाशुल्क को शुल्क क्रेडिट के मदे समायोजित किया जा सकता है।

माल का सीमाशुल्क के भुगतान किए बिना पुनः निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि (1) ऐसे माल के मामले में शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो, और (2) ऐसे माल का निर्यात करने के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया हो।

अग्रिम लाईसेंस तथा ई पी 2.20  
सी जी के लिए बैंक  
गारंटी/विधिक वचनबद्धता  
का निष्पादन

माल की निकासी से पूर्व, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करना होगा।

प्रत्यक्ष आयात के मामले में, क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र पर निम्नलिखित शर्त को पृष्ठांकित कर देंगे:

“बैंक गारंटी/विधिक वचन वद्धता जो लागू हो संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचना/परिपत्र के अनुसार निष्पादित होगा।”

स्वदेशी माल की प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा:-

(क) विधिक वचनबद्धता हेतु निम्नलिखित हस्तियाँ हकदार होंगी:-

1. सभी स्तरधारक/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
2. विनिर्माता निर्यातक (प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्मों को छोड़कर) जो केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत हों जिन्होंने पिछले वर्ष में कम से कम रु. 1 करोड़ और उस से अधिक का कारोबार किया हो और पिछले दो वित्त वर्ष में निर्यात किया हो।
3. विनिर्माता निर्यातक, जो केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत हों और जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 1 करोड़ से अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया हो।
4. सभी निर्यातक जिन्होंने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में रु. 5 करोड़ से अधिक निर्यात कारोबार किया हो और जिनका ट्रेक रिकार्ड अच्छा तथा 3 वर्ष का निर्यात निष्पादन किया हो।

(ख) निम्नलिखित शुल्क पर बचाए शुल्क एवं शिक्षा उपकर के 15 प्रतिशत तक बैंक गारंटी सहित बांड, यदि लागू हो, देनी होगी:-

1. अन्य विनिर्माता निर्यातक जो क में शामिल न हो (प्रोपराइटरशिप व पार्टनरशिप फर्मों के अतिरिक्त) पिछले 3 वर्ष से निर्यात कर रहे

हो या 3 वर्षों में किसी भी वर्ष निर्यात करते हों। तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया हों उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत हों।

बशर्ते कि विगत किन्हीं तीन वर्षों हेतु यूनिट सीमा शुल्क प्राधिकारियों अथवा राज्य बिक्री कर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हों।

2. विनिर्माता कम्पनियाँ (कम्पनी अधिनियम के अनुसार) जिन्होंने पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात न किया हो परन्तु निम्नलिखित मापदण्डों में खरी उतरती है:-

(i) कम्पनी, केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया हो (जब तक मुक्त न किया जा); और

(ii) कम्पनी, राज्य बिक्री कर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो तथा बिक्री कर का भुगतान किया हो (जब तक मुक्त न किया जा); और

(iii) कम्पनी ने अपना आडिट किया हुआ बैलेन्स सीट प्रस्तुत किया तथा प्लान्ट व मशीनरी में न्यूनतम निवेश 50 लाख हो।

ग. निम्नलिखित को 100 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क में छूट तथा शिक्षा चुंगी यदि लागू हो, की बौण्ड व बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी:

1. मरचैन्ट निर्यातक, सभी प्रकार के प्रोपाइटरशिप व पार्टनरशिप फर्म (स्तरधारक/ पी.एस.यू. तथा ऊपर श्रेणी 4 के अतिरिक्त)

2. सेवा प्रदायक ऊपर श्रेणी (क) 1 और (क) 4 के अतिरिक्त।

घ. निम्न दो श्रेणियों के विनिर्माताओं/मरचैन्ट निर्यातकों को जोखिम प्रोफाइल के आधार पर 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा शिक्षा चुंगी यदि लागू हो, बाण्ड व बैंक गारण्टी देने की आवश्यकता है यह कार्यालय प्रमुख जो कि उप महानिदेशक, विदेश व्यापार के पद से नीचे का न हो, को कारणों को लिखित रूप से रिकार्ड करके निर्धारित किया जा सकता है:-

(क) गंभीर अनियमितताओं के लिए महानिदेशक विदेश व्यापार/सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद के प्रतिकूल नोटिस में आया हो।

(ख) बचे हुए निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिकूल ट्रैक रिकार्ड में हो

स्वदेशी खरीददारी के मदों के मामले में जहाँ उत्पाद शुल्क शून्य हो, प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी उसी उत्पाद के मूल सीमाशुल्क का 25 प्रतिशत होगी। बैंक गारंटी व विधिक वचन बद्धता परिशिष्ट-25क व 25ख में दिये गये शर्तों के अनुसार वैध होगी। बैंक गारंटी/विधिक वचन बद्धता की वैधता निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस सम्बंध में लाइसेंस/प्राधिकार पत्र में विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा।

ऊपर श्रेणी (क) 3, (क) 4 व (ख) 5 के संबंध में अगर निर्यातक ने पिछले 3 वर्षों में निर्यात न किया हो तो बचाए हुए शुल्क की राशि पर 15 प्रतिशत बैंक गारंटी लगायी जाएगी बशर्ते की सी.आई.एफ मूल्य स्वदेशी कारोबार का 200 प्रतिशत या आपूर्ति का 200 प्रतिशत एफओबी/ एफओआर मूल्य जो भी ज्यादा हो से अधिक न हो। 200 प्रतिशत पात्रता से अधिक के लाइसेंसों/प्राधिकार पत्र में 200 प्रतिशत सीआईएफ मूल्य की पात्रता के अधिक के लिए बचायी हुए शुल्क राशि का 100 प्रतिशत बैंक गारंटी लगायी जाएगी। तथापि निर्यात निष्पादन तथा निर्यात प्राप्ति/आपूर्ति प्राप्ति के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर पात्रता को फिर से जमा कर दिया जाएगा।

ऊपर श्रेणी (क) 2 और (क) 4 के संबंध में, प्राधिकार पत्र धारक को सनदी लेखाकार द्वारा जारी निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र परिशिष्ट 26 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

ई.पी.सी.जी. स्कीम के अधीन कार के आयात/स्वदेशी खरीद पर 100 प्रतिशत बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। स्तर धारक/पी.एस.यू. जो दी गयी शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे, के मामलों को छोड़कर।

ऊपर निर्दिष्ट बैंक गारंटी की छूट/रियायत उन पिछले प्राधिकारों के मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ प्राधिकार धारक बैंक गारंटी प्रस्तुत कर चुके हैं परन्तु उस तारीख में प्राधिकार धारक बैंक गारंटी छूट के लिए हकदार है।

यदि फर्म ने सीमाशुल्क में स्वदेशी मदों की खरीददारी का पूरे कीमत के प्राधिकार पत्र के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का पहले ही निष्पादन का किया हो तथा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया हो तो क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष कोई बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता नहीं देनी होगी।

## कारपोरेट गारंटी

### 2.20.1

स्तर धारक अथवा पी.एस.यू. इस संबंध में बैंक गारंटी/ एल.यू.टी. के बदले में कारपोरेट गारंटी प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर-स्तरधारक समूह कम्पनी के मामलों में स्तरधारक द्वारा गारंटी दी जा सकती है।

उद्गम का प्रमाणपत्र 2.21 उद्गम का प्रमाण पत्र देश से निर्यातित माल के उद्गम का प्रमाण है ।  
उद्गम के प्रमाण पत्र की दो श्रेणियाँ हैं यानी

(1) तरजीही और (2) गैर तरजीही

तरजीही 2.21.1 तरजीही प्रबंध/स्कीमें जिसके तहत भारत अपने निर्यातों हेतु टैरिफ तरजीहें प्राप्त कर रहा है वह हैं - तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जी एस पी), व्यापार तरजीहों की विश्व प्रणाली (जी एसटीपी), सार्क तरजीही व्यापार समझौता (साप्टा) और बैंकाक समझौता और भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएलएफटीए) भारत थाइलैंड मुक्त व्यापार समझौता। ये प्रबंध/ समझौते उद्गम के नियमों को निर्धारित करते हैं जिन्हें टैरिफ तरजीहों हेतु पात्र होने के लिए निर्यातों हेतु पूरा करना होता है ।

प्राधिकृत एजेंसियों उद्गम के प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में सेवाएँ उपलब्ध कराएँगी जिनमें उद्गम के नियमों से संबंधित ब्यौरे, समझौते के तहत आने वाली मदों की सूची, टैरिफ तरजीहों की सीमा, पात्रता आदि का प्रमाणन एवं जाँच । खाली प्रमाणपत्रों को प्रिंट करने के लिए ई आई सी अकेली एजेंसी है। प्राधिकृत एजेंसियाँ प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित शुल्क ले सकती हैं ।

तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली  
(जीएसपी)

(क) जी एस पी एक गैर अनुबंधीय व्यवस्था है जिसके द्वारा औद्योगिक (विकसित) देश एकतरफा तौर पर और गैर-आदान प्रदान के आधार पर विकसित देशों को टैरिफ छूट दे सकती हैं। निम्नलिखित देश अपनी जी एस पी स्कीम के तहत टैरिफ तरजीहें उपलब्ध कराते हैं ।

- |                   |                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| (i) अमेरिका       | (ii) न्यूजीलैंड | (iii) बेलारूस      |
| (iv) यूरोपीयन संघ | (v) जापान       | (vi) रूस           |
| (vii) कनाडा       | (viii) नार्वे   | (ix) आस्ट्रेलिया   |
| (x) स्विटजरलैंड   | (xi) बुल्गेरिया | (केवल एल डी सी को) |

इन देशों की जी एस पी स्कीमों में सैक्टरों/उत्पादों और टैरिफ लाइनों के ब्यौरे हैं जिसके तहत ये लाभ उपलब्ध हैं, ये लाभों को दिलाने की शर्तों और प्रक्रियाओं के अलावा है । ये स्कीमें समय-समय पर नवीकरण और संशोधित की जाती हैं । जी एस पी प्रदान करने वाले देशों के सीमाशुल्क कार्यालय सामान्यतः लाभान्वित देशों के निर्यातकों द्वारा बाकायदा भरे फार्म 'ए' (उद्गम के जी एस पी नियमों हेतु निर्धारित) में अपेक्षित सूचना मांगते हैं जो प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो । उद्गम का

जी एस पी प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-4क में दी गयी है।

व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली  
(जीएसटीपी)

(ख) व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली स्थापित करने वाले समझौते के अन्तर्गत विकासशील देशों के बीच व्यापारिक छूटों का आदान-प्रदान होता है जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हों। इस समय, जी एस टी पी के सदस्य देशों की संख्या 46 है और भारत ने उत्पादों की सीमित संख्या के बारे में 12 देशों के साथ व्यापारिक छूटों को आदान-प्रदान किया है। जी एस टी पी के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्यात जाँच परिषद् (ई आई सी) एकमात्र एजेंसी है।

सार्क तरजीही व्यापार समझौता  
(साफ्टा)

(ग) साफ्टा स्थापित करने वाले समझौते पर सात सार्क देशों यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने 1993 में हस्ताक्षर किए थे तथा यह 1995 में संज्ञान में लाया गया था। व्यापार समझौते के 4 चरण पूरे हो चुके हैं तथा सार्क देशों के बीच टैरिफ रियायत के अधीन 3000 से अधिक टैरिफ लाईसेंस पूरे हो चुके हैं। साफ्टा के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-4ख में दी गयी है।

एशिया-प्रशांत समझौता

(घ) एशिया-प्रशांत समझौता एक तरजीही व्यापार समझौता है जो एशिया और प्रशांत हेतु आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्कैप) क्षेत्र में टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोधकों में छूट के तौर पर इन उपायों और अन्य समझौता तकनीकों के इस्तेमाल के माध्यम से वस्तुओं के व्यापार को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने और उदार बनाने के लिए बनाया गया है। इस समय बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, भारत व चीन टैरिफ रियायत का आदान प्रदान कर रहे हैं। एशिया-प्रशांत समझौते के अंतर्गत उद्गम का प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत एजेंसियों की सूची परिशिष्ट 4-ख पर दी गई है।

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार  
समझौता (इसलाफ्टा)

(ड.) भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर 20 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीलंका और भारत सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ छूटों की अधिसूचना जारी करने के बाद मार्च, 2000 में समझौते पर कार्यान्वयन शुरू हुआ। इसलाफ्टा के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निर्यात जाँच परिषद् एकमात्र एजेंसी है।

भारत-अफगान तरजीह व्यापार समझौता (च)

ट्रान्जिसनल इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान और भारतीय गणराज्य के बीच एक तरजीह व्यापार समझौता 6 मार्च 2003 को हस्ताक्षर

किये गये तथा दिनांक 13 मई 2003 के सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 76/2003 को लागू हुआ था। भारत अफगानिस्तान के बीच तरजीह व्यापार समझौता जारी करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् एकमात्र एजेंसी होगी।

मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए भारत

- (छ) 01 सितम्बर, 2004 को भारत-थाइलैण्ड मुक्त व्यापार समझौता के तहत अर्ली हार्बेस्ट स्कीम को कार्यान्वयन करने के लिए भारत और थाइलैण्ड ने एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया। अर्ली हार्बेस्ट स्कीम के मर्दों पर आयात हेतु प्रशुल्क तरजीह केवल उन उत्पादों को होगी जो मूल मानदण्ड जो वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उनके अधिसूचना सं० 101/2004-सीमाशुल्क दिनांक 31 अगस्त 2004 द्वारा अधिसूचित किया गया है, के नियमों को संतुष्ट करते हैं। भारत-थाइलैण्ड मुक्त व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क समझौते में अर्ली हार्बेस्ट स्कीम के तहत उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् एक मात्र एजेंसी होगी।

भारत-थाइलैण्ड मुक्त व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क समझौते में अर्ली हार्बेस्ट स्कीम के तहत उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् एक मात्र एजेंसी होगी।

गैर तरजीही

2.21.2

सरकार ने भी सीमाशुल्क औपचारिकताएँ 1923 के सरलीकरण से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के अनुसार मूल के गैर-तरजीह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुछेक प्राधिकृत एजेंसियों को नामित किया है। मूल के ये प्रमाणपत्र सामान के मूल के साक्ष्य है और इनपर तरजीह शुल्क का कोई अधिकार नहीं होता है। इन एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-4ग में दी गई है। इसके अलावा, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.21.1 के अनुसार तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियाँ भी गैर-तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत हैं।

सभी निर्यातकों को जिन्हें उद्गम का प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) प्रस्तुत करना है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट-4ग में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी को आवेदन करना होगा:-

- (क) निर्यात उत्पादों में निवेश/उपभोज्य उपयोग की मात्रा/उद्गम के ब्यौरे।
- (ख) बीजक की दो प्रतियाँ।
- (ग) संबंधित बीजक के लिए पैकिंग सूची (दो प्रतियाँ)।

(घ) संबंधित अभिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रति प्रमाण पत्र 100/- रु० या इससे कम शुल्क।

उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने से पूर्व अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उद्गम के नियमों को शामिल करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुसार वस्तुएँ भारतीय मूल की हैं। प्रमाणपत्र परिशिष्ट-4ग के अनुलग्नक 2 में दिये गये मूल प्रमाणपत्र के प्रारूप के अनुसार प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र में कोई शुद्धि/पुनः टंकित नहीं किया गया है।

कोई एजेन्सी परिशिष्ट -1 से परिशिष्ट -4ग के अनुसार अपने आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को कर सकता है।

चाय के मामले में, सभी निर्यातक जिन्हें उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) अपेक्षित है वे चाय बोर्ड अथवा चाय बोर्ड अथवा जांच एजेंसी को आवेदन करेगा जो प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के परिशिष्ट-4ग में सूचीबद्ध जाँच एजेंसी हो।

स्तर धारकों हेतु स्वचालित  
लाइसेंस/प्रमाण पत्र/  
प्राधिकार पत्र/ अनुमति पत्र

2.22

स्तर धारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतः ही प्राधिकार पत्र जारी किए जायेंगे। यदि कोई कमी होती है तो इसे कवरिंग पत्र में सूचित किया जायेगा, कमी को सूचित करने की तारीख से 10 दिन के भीतर स्तर धारकों द्वारा इन कमियों को दूर किया जाएगा।

दस्तावेजों की प्रमाणित  
प्रतियाँ प्रस्तुत करना

2.23

जहाँ कहीं विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरण/नामजद अभिकरण या इसी क्षेत्रीय प्राधिकरण के अलग प्रभाग को मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं तो आवेदक मूल दस्तावेजों के स्थान पर स्वयं विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

अग्रिम भुगतान

2.24

यदि भुगतान पहले प्राप्त हो जाता है और निर्यात/मान्य निर्यात बाद में किया जाता है तो प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन आगामी माह के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस माह के दौरान निर्यात/मान्य निर्यात किया गया हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

ई सी जी सी कवर के  
माध्यम से भुगतान

2.25.1

ई सी जी सी कवर के माध्यम से भुगतान विदेश व्यापार नीति के तहत लाभों हेतु गिना जाएगा।

सामान्य बीमे के जरिए  
भुगतान

2.25.2

अन्तरण हानि हेतु सामान्य बीमा कवर की राशि विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यातों के लिए वसूल किया गया भुगतान माना जाएगा।



अपरिवर्तनीय साख पत्र	2.25.3	उन मामलों में जहाँ आवेदक अपरिवर्तनीय साखपत्र ( या विनिमय बिल जो बिना शर्त बैंक द्वारा भुनाया/सह-स्वीकृत गारंटी दी गयी हो) के प्रति शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन करता है तथा निर्यात और प्राप्ति के संबंधित बैंक प्रमाणपत्र में निर्यातक बैंक द्वारा पुष्ट और प्रमाणित किया जाता है तो निर्यात आय का भुगतान प्राप्त कर लिया गया माना जाएगा।
डाक द्वारा निर्यात	2.26	डाक द्वारा निर्यात के मामले में समुद्र/वायु मार्ग द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. परिशिष्ट 22क में दिया गया आयात वसूली का बैंक प्रमाणपत्र</li> <li>2. संबद्ध डाक रसीद।</li> <li>3. सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा बाकायदा सत्यापित बीजक।</li> </ol>
कूरियर सेवा के माध्यम से आयात/ निर्यात	2.26.1	राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से आयात/निर्यात अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों की आयातीयता/निर्यातीयता विदेश व्यापार नीति के अनुसार विनियमित होगी।
निर्यात दस्तावेजों का सीधे लेन-देन	2.26.2	उन मामलों में जहाँ निर्यातक भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से दस्तावेज का सीधे (प्राधिकृत डीलर के माध्यम से नहीं) लेन-देन करता है, उसे निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :- <p>क) दस्तावेजों के सीधे लेन-देन की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति (तथापि, यह स्तर धारकों हेतु आवश्यक नहीं है जिन्हें आय अनुमति प्रदान की गई है)</p> <p>ख) बी आर सी के बदले में आयकर विभाग के फार्म-10 ज के अनुसार विदेश से स्वदेश में धन प्राप्ति प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) की प्रति तथा</p> <p>ग) शिपिंग बिलों/बीजक के ब्यौरे देने का विवरण जिसके प्रति एफ आई आर सी जारी की गई थी ।</p>
नमूनों का आयात/ निर्यात	2.27	किसी आयातक को सब्जियों के बीज, मधुमक्खी और नई औषधियों को छोड़कर, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण किसी आयातक को सब्जियों के बीज, मधुमक्खी और नई औषधियों को छोड़कर, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में प्रतिबंधित मदों के रूप में उल्लिखित मदों के प्रमाणिक तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के लिए किसी लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि चाय उद्योग से सम्बद्ध

किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति पत्र के बिना एक परेक्षण में 2000 रूपए (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) तक चाय के नमूनों के आयात की अनुमति होगी।

सभी निर्यातकों के लिए 75000 रु० तक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति (रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों के लिए 30,000 रु०) सीमा-शुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

मुक्त रूप से निर्यात योग्य मद के वास्तविक व्यापार और तकनीकी नमूनों का निर्यात सीमा बिना अनुमत होगा।

पट्टा वितीयन के तहत  
आयात

2.28

ई पी सी जी स्कीम/ ई ओ यू/ई पी जैड, स्कीम के अन्तर्गत पट्टा वितीयन के तहत आयात उपलब्ध होगा। मान्य निर्यात के पात्र श्रेणियों के पूंजीगत माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता, ऐसे मामलों में भी जहां आपूर्ति पट्टा, वितीयन के तहत की गई है, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.3 में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे।

राष्ट्रीय और अन्तर-  
राष्ट्रीय प्रदर्शनी या  
मेलों और प्रदर्शनों के  
लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएँ

2.29

विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों को अवर सचिव, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य विभाग, महानिदेशक, विदेश व्यापार से कम का न हो अथवा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के किसी अधिकारी जिसका इसके चेयरमैन में अपनी ओर से ऐसी प्रदर्शनी, मेले या इसी प्रकार के शो या डिस्पले, जैसा भी मामला हो, के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया हो, का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति पत्र के बिना पुनः निर्यात/आयात के आधार पर छः माह की अवधि के लिए प्रदर्शनियों, मेले या इसी प्रकार के शो या डिस्पले पर अस्थाई स्टेण्ड हेतु अपेक्षित विनिर्माण और सज्जा सामग्री सहित प्रदर्शों के आयात/निर्यात की अनुमति होगी:-

(1) वाणिज्य विभाग भारत सरकार या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अनुमोदित या प्रयोजित; और

(2) लोकहित में आयोजित हो रहा हो।

पुनः निर्यात/आयात के लिए छः माह से आगे अवधि बढ़ाने पर विचार सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शित वस्तुओं से संबंधित पेन्ट, प्रिंट सामग्री, पैम्पलैट, साहित्य आदि जैसे उपभोग्यों का पुनः निर्यात/आयात की आवश्यकता नहीं है।

आयात नीति

2.30

पूँजीगत माल, कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोग्यों अतिरिक्त पुर्जों, उपांगों, उपकरणों तथा अन्य माल के आयात के संबंध में सामान्य शर्तों से संबंधी विदेश व्यापार नीति अध्याय 2 में दी गई है।

प्रतिबंधित सामान के  
लाइसेंस के लिए सामान्य  
प्रक्रिया

2.31 जहाँ इस अध्याय में दी गई नीति, प्रक्रिया के तहत आयात प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार सीमाशुल्क निकासी परमिट (सी सी पी) विदेश व्यापार नीति के तहत अपेक्षित है, इस अध्याय में निहित प्रक्रिया लागू होगी।

2.32 धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात

2.32.1 किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रेप को आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव कांटेनेटेड वेस्ट/स्क्रेप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारूद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या चला हुआ बारूद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, नहीं होगा।

2.32.2 निम्नलिखित प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात कुछ शर्तों के अधीन होगा जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	एडिजम कोड	मद ब्यौरा
1	72041000	कास्ट आयरन का छीजन और स्क्रेप
2.	72042190	अन्य
3.	72042920	हाई स्पीड स्टील का
4.	72042990	अन्य
5.	72043000	टिन वाले लोहे या स्टील का छीजन और स्क्रेप
6.	72044100	टर्निंग, शेविंग, चिप्स, मिलिंग वेस्ट, सॉ डस्ट, फिलिंग, ट्रिमिंग और स्टैपिंग, चाहे गठ्ठर में हो या नहीं
7.	72044900	अन्य
8.	72045000	दोबारा पिघलने वाले स्क्रेप इनगोट्स
9.	74040010	कॉपर स्क्रेप
10.	74040022	ब्रास स्क्रेप
11.	75030010	निकल स्क्रेप
12.	76020010	एल्युमिनियम स्क्रेप
13.	79020010	जिंक स्क्रेप
14.	80020010	टिन स्क्रेप
15.	81042010	मैगनीशियम स्क्रेप

खंडित रूप: उपर्युक्त पैरा 2.32.2 में सूची बद्ध धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात भारत के सभी पतनों से अनुमत किया जाएगा। होदाईडेह, यमन ओर बंदार अधास, ईरान से आयात केवल खंडित रूप में होगा।

अखंडित, संपीडित और खुला रूप: उपर्युक्त 2.32.2 में सूचीबद्ध धात्विक छीजन, स्क्रेप जोकि अखंडित, संपीडित और खुले रूप में हो, का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

क पोतलदान पूर्व जांच निर्धारित की जा सकती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस उद्देश्य हेतु ऐजेंसियों/निकायों का पंजीकरण किया जा सकता है।

ख स्क्रेप का आयात केवल निम्नलिखित पत्तनों द्वारा किया जा सकेगा और ईओयू तथा आई जैड के मामले में अनुमत हेतु अपवाद नहीं होगा:

“1. चैन्ने 2. कोचीन 3. इन्नोर 4. जे.एन.पी.टी 5. काण्डला 6. मोर्मूगुआ 7. मुम्बई 8. न्यू मेंगलोर 9. पारादीप 10. तूतीकोरिन 11. विशाखापटनम 12. आईसीडी तुगलकाबाद 13. पिपावा 14. मुन्द्रा 15. कोलकाता 16. आईसीडी लुधियाना 17. आईसीडी दादरी, ग्रेटर नोएडा 18. आईसीडी नागपुर 19. आईसीडी जोधपुर 20. आईसीडी जयपुर और 21. आईसीडी उदयपुर 22. सी एफ एस मुलुंड 23. आई सी डी कानपुर 24. आई सी डी अहमदाबाद 25. आई सी डी पीतमपुर और 26. आई सी डी मलानपुर।”

ग पंजीकृत स्रोतों से आयात की प्रणाली 1-10-2007 से प्रभावी होगी। तथापि उन मामलों में जहाँ लदान बिल दिनांक 30-09-2007 अथवा उससे पूर्व है आयात प्रक्रिया पुस्तक ( भाग-1) के पैरा 2.32 के प्रावधानों के अनुसार पोत लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रणाली जोकि सार्वजनिक सूचना सं.1 दिनांक 8 अप्रैल 2005 तथा समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा अधिसूचित है, के आधार पर आयात अनुमत किए जाएंगे। जब तक पंजीकृत स्रोतों से आयात की नयी प्रणाली प्रभावी नहीं होती। पूर्व व्यवस्था के तहत अधिसूचित पोतलदान पूर्व ऐजेंसियों की सूची विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2.32.3 तथापि, अन्य प्रकार की धात्विक छीजन ओर स्क्रेप आईटीसी (एच एस) निर्यात और आयात मर्दों का वर्गीकरण, 2004-2009 की शर्तों तथा प्रावधानों के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

- 2.32.4 पुराने और दोषपूर्ण, पुराने कपड़े (चीथड़े) प्लास्टिक बोतले/छीजन और समुद्री जहाजों के विषय में आयात नीति आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित है।
- पुराने पूंजीगत माल का आयात 2.33 रिफर्बिश्ड/रिकन्डीशन्ड स्पेयर्स सहित पुराने पूंजीगत माल का आयात निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शर्तों के अनुसार अनुमत होगा।
- वैयक्तिक कम्प्यूटर और लैपटॉप सहित पुराने कम्प्यूटरों का आयात आयातों के लिए प्रतिबंधित है।
- रिफर्बिश्ड/रिकन्डीशन्ड पुर्जों का आयात सनदी अभियन्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत होगा जिसमें दर्शाया गया हो कि इन पुर्जों का बचा हुआ जीवन वास्तविक पुर्जों के जीवन के 80 प्रतिशत से कम नहीं है।
- यदि वास्तविक तार्किक कारणों के परिणामस्वरूप पूंजीगत माल दो सीमाशुल्क स्थलों पर दो भागों में आयात किया जाता है तो उक्त आयात यह संतोष करने के बाद अनुमत किया जा सकता है कि दोनों खेपें मिलाकर एक अकेली पूंजीगत वस्तु बनती है।
- 2.33.1 उपर्युक्त पैरा 2.33 की शर्तों के बावजूद, पुराने कम्प्यूटर, लैपटॉप और प्रिन्टर, प्लॉटर, स्कैनर, मॉनीटर, की बोर्ड और स्टोरेज यूनिटों सहित कम्प्यूटर पैरीफेरियल्स निम्नलिखित दानकर्त्ताओं की श्रेणियों द्वारा दान के रूप से मुक्त रूप से आयात किए जा सकते हैं
- (1) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित स्कूल।
  - (2) किसी संस्था द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाई गई शैक्षिक संस्था
  - (3) पंजीकृत चैरिटेबल अस्पताल
  - (4) पब्लिक लाइब्रेरी
  - (5) सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थान
  - (6) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित समुदाय सूचना केन्द्र
  - (7) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
  - (8) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र का संगठन

इस उप - पैरा के अन्तर्गत आयातों की अनुमति होगी बशर्ते कि माल किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग न किए जाए, अहस्तांतरणीय

हो, और संगत सीमाशुल्क विनियमों और अधिनियमों की शर्तों के अनुरूप हो।

- 2.33.क सीमाशुल्क अथवा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार प्राधिकारी पूंजीगत माल की शेष कालावधि/मूल्य निर्धारण/ खरीद मूल्य दोनों प्रमाणित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 5 में दी गई निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसियों की सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

लाइसेंसधारी हथियार  
व्यापारियों द्वारा हथियारों  
का आयात

2.34

लाइसेंसधारी हथियार व्यापारी द्वारा प्राधिकार पत्र के प्रति निम्नलिखित किस्म के हथियारों का आयात अनुमत है बशर्ते कि यह यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो :

- (1) शाटगन कार्टरिज 28, बोर
- (2) रिवाल्वर कार्टरिज .450, .455 और .45 बोर के।
- (3) पिस्टल कार्टरिज .25, .30 माउजर, .450 और .45 बोर
- (4) राइफल कार्टरिज 6.5 एम एम, .22 सेवेज, .22 हार्नेट, 300 शेरवुड, 32/40, .256, 275, 280, 7 एम/ एम मएउजर, 7 एम/एम मैनस्कूइनर, 9 एम/एम माउजर, 9 एम/एम मैनस्कूइनर, 8x57, 8x57 एस, 9.3 एम/एम, 9.5 एम/एम, .375 मैनगन, .405, .30 .06 .270, .30/30 विंच, .318, .33 विंच .275 मेग, .350 मेग, 400/350, .369 पुरडे, .450/400, .470, .32 विन 458 विन, .380 रूक, .220 स्वीफ्ट और .44 विन बोर्स के।

आयात/प्राधिकार पत्र विगत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान गोला बारूद की वार्षिक बिक्री-कारोबार (देशी अथवा आयातित) के मूल्य के 5 प्रतिशत आयात तक दिया जा सकता है बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य 2000/-रूपये से कम न हो।

उपर्युक्त पैरा में दी गई मदों के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात-निर्यात फार्म में क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।

होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल  
एजेंटों, टूर-आपरेटरों  
और अन्य विनिर्दिष्ट  
श्रेणियों द्वारा अपेक्षित  
प्रतिबंधित मदें

2.35

महानिदेशक, पर्यटन भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेंटों और टूर आपरेटरों द्वारा अपेक्षित निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण में आयात के लिए प्रतिबंधित के रूप उल्लिखित मद प्राधिकार पत्र के प्रति अनुमत होंगी।

2.35.1

महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटन होटलों सहित, होटल, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत मूल्य तक के प्राधिकार पत्र पात्र होंगे।

2.35.2 भारत सरकार के पर्यटक महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, दूर संचालकों रेस्तराओं तथा पर्यटन परिवहन संचालकों और साहसिक/वन्य जीव जैसे पर्यटन के लिए अन्य यूनिट और कन्वेन्शन यूनिट को गत लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत मूल्य का प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसे प्राधिकार पत्र ट्रेवल तथा पर्यटन उद्योग को उनकी व्यावसायिक प्रयोग के लिए अपेक्षित कार्यालय एवं अन्य उपकरणों सहित अनिवार्य वस्तुओं का आयात करने के लिए दिए जाएंगे।

2.35.3 पैरा 2.35.1 तथा 2.35.2 के अन्तर्गत किसी भी वर्ष की आयात हकदारी के लिए पूरी अथवा उसके एक भाग को आगे ले जाया जा सकता है तथा दो आगामी लाइसेंसिंग वर्षों की आयात हकदारी में जोड़ा जा सकता है। और यह समूह कम्पनी या प्रबंधित होटलों के भीतर के अलावा हस्तांतरणीय नहीं होगा।

2.35.4 हटा दिया गया है।

2.35.5 ऐसी आयातित वस्तुएं विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति से 2 वर्ष के बाद हस्तांतरित की जा सकती हैं।

आयातित माल के पुर्ननिर्यात के मामले में हस्तांतरण के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि पुर्ननिर्यात पर आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची II में आवश्यक सभी शर्तों अथवा लाइसेंस की आवश्यकताओं अथवा आज्ञा लागू होगी।

2.35.6 पैराग्राफ 2.35.1 और 2.35.2 के अधीन प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 2ख पर महानिदेशक विदेश व्यापार को निदेशक पर्यटन, भारत सरकार के जरिए देना होगा। वे इस आवेदनपत्र को आयात किए जाने वाले माल और आयात की पात्रता की सिफारिश करके संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

अन्य प्रतिबंधित मर्चों  
का आयात

2.36 निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण नामक पुस्तक में प्रतिबंधित मर्चों की सूची दी गई है। ऐसे मर्चों के आयात के लिए लिए आवेदन पत्र आयात निर्यात प्रपत्र 2ख में निर्धारित दस्तावेजों के साथ विदेश व्यापार महानिदेशालय को दिया जाएगा। ट्रेजरी रसीद/डिमांड ड्राफ्ट सहित मूल आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के प्रस्तुत किए जायेंगे और इसकी स्व-सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रमाण सहित दो प्रतियों में विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्यात आयात सुविधा समिति	2.37	<p>प्रतिबंधित मद प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक या उनके ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय/लाइसेंसिंग प्राधिकारी, सुविधा समिति की सहायता और सलाह ले सकते हैं।</p> <p>सुविधा समिति में संबंधित तकनीकी प्राधिकारियों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।</p>
उपभोज्य अथवा अन्य माल का उपहार	2.38	<p>विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.19 में दिए प्रावधानों के अनुसार, निर्यात और मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में आयात के लिए प्रतिबंधित रूप में उल्लिखित मदों का उपहार के रूप में आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक, नई दिल्ली को निर्धारित प्रलेखों के साथ 'आयात निर्यात प्रपत्र-2ख' में दिए प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा:</p> <p>जहां उपहार का प्राप्त कर्ता समितियों अथवा ट्रस्टों के पंजीकरण से संबंधित कानून के तहत पंजीकृत हैं और आयात किया जाने वाला उपहार वित्त मंत्रालय द्वारा सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, ऐसा आयात सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञापन के बिना अनुमत होगा।</p>
एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत आयात	2.39	<p>एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उनकी संतुष्टि के अनुसार आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्राधिकार पत्र या सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना अनुमत किया जा सकता है।</p>
चैक बुक/टिकट फार्म आदि का आयात	2.40	<p>विदेशी बैंकों, बी 7 कम्पनियों तथा ट्रेवल एजेंसियों की भारतीय शाखाओं द्वारा चैक बुक, बंक ड्राफ्ट फार्म तथा ट्रेवलर चैक फार्मों का सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना आयात किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत में कार्यरत एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियाँ जिनमें ऐसे एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल हैं, सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना पैसेजर्स टिकट फार्मों का आयात कर सकती है।</p>
पुनरनुकूलन/ वायुयान के अतिरिक्त पुराने पुर्जों का आयात	2.41	<p>नगर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार की सिफारिशों पर रिकंडिशनड/सेकिन्ड हैंड एयर क्राफ्ट के कलपुर्जों प्राधिकार पत्र के बिना आयात करने के पात्र होंगे।</p>
प्रतिस्थापन माल का आयात	2.42	<p>सामान और उसके पुर्जे आयात करने पर खराब या अन्यथा उपयोग के लिए उपयुक्त न हो अथवा जो आयात करने के बाद नष्ट हो गये हों उनका प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है तथा सामान का विदेशी सप्लायरों द्वारा बिना प्रभार की आपूर्ति या समुद्री बीमा के प्रति आयात अथवा बीमा कम्पनी द्वारा निपटाये गए समुद्री व निर्माण बीमा दावों</p>



का निपटान कर लिया है उसकी मुफ्त आपूर्ति की जा सकती है। ऐसे सामान का सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस के बिना निकासी करने की अनुमति होगी बशर्त कि:

- (क) सीमाशुल्क द्वारा पिछले आयातित सामान की निकासी की तारीख से 24 माह के भीतर प्रतिस्थापन माल की निकासी की गई है अथवा मशीन या उसके कलपुजों के मामलों में, 24 माह से अधिक समय लग गया है परन्तु गारंटी अवधि के भीतर हो, और
- (ख) जब आयातक द्वारा किए गए बीमा और/अथवा भाड़े के भुगतान के अधीन है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की प्रतिपूर्ति पर बीमा और भाड़े के भुगतान को छोड़कर कोई प्रेषण भार नहीं लिया जाएगा और प्रेषण शुल्क देते समय इस प्रयोजन का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

2.42.1 ऐसे मामलों में जहाँ माल पोत में कम चढ़ाया, कम उतारा पाया जाए या आवाजाही में गुम पाया जाए, प्रतिस्थापन माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की क्षमता पर अनुमत होगा। ऐसे मामलों में, कोई आयात प्राधिकार पत्र की जरूरत नहीं होगी। वह प्रक्रिया उस मामले में भी लागू होगी जहाँ विदेशी सप्लायर द्वारा पोत में सामान का कम लदान को प्रमाणित किया जाता है और वह सामान मुफ्त बदलने के लिए तैयार है।

2.42.2 जो मामले उपर्युक्त प्रावधानों द्वारा कवर नहीं होते हैं उनके संबंध में मंजूरी विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा गुणावगुण के आधार पर दी जाएगी वस्तुओं के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन पत्र आयात निर्यात फार्म में प्रस्तुत करने होंगे।

आयातित माल  
का हस्तांतरण

2.43 मुक्त रूप से आयात योग्य वस्तुओं का आयातक बिक्री द्वारा या अन्यथा मुक्त रूप से इनका हस्तांतरण कर सकता है। ऐसे आयातित माल का जो नीति के अधीन वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन हैं और वास्तविक उपयोक्ता की आवश्यकता से अधिक है, का हस्तांतरण केवल संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित सूचना, हस्तांतरण के लिए मंजूरी के अनुरोध सहित, सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

- (1) आयातित सामग्री के हस्तांतरण के कारण,
- (2) जिसको हस्तांतरित किया जाता है उस व्यक्ति का नाम, पता, आयातक-निर्यातक कोड संख्या तथा औद्योगिक प्राधिकार पत्र पंजीकरण, यदि कोई हो।

- (3) आयातित माल का विवरण, मात्रा और मूल्य तथा जिसका हस्तांतरण करने की अनुमति मांगी गई है।
- (4) किए गए आयात से संबंधित आयात प्राधिकार पत्र और आगमपत्र की प्रतियां, और
- (5) क्रेता और विक्रेता के बीच हस्तांतरण की शर्तें।

2.43.1 तथापि, ऐसे माल के हस्तांतरण या निपटान में किए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी जिसको वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्तों पर आयात किया गया हो बशर्ते कि उसके हस्तांतरण की तारीख को वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्तों के बिना मुक्त आयात किया जाता हो।

2.43.2 ऐसे आयातित माल के आयात की तारीख से दो वर्षों की अवधि के बाद हस्तांतरण या निपटान के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि सभी आयातित आग्नेयास्त्रों के हस्तांतरण की अनुमति आयातकों/प्राधिकार धारकों को महानिदेशक, विदेश व्यापार के अनुमोदन से आयात की तारीख के केवल 10 वर्ष बाद होगी।

नुमाइशी मदों की बिक्री

2.44

(1) भारतीय व्यापार उन्नयन संगठन (आई टी पी ओ) द्वारा अनुमोदित/प्रायोजित अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/आयोजित मेलों के लिए आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित मदों के प्रदर्शनों की बिक्री प्रभावी सीमाशुल्क के भुगतान करने पर प्राधिकार पत्र बिना बाण्ड अवधि के भीतर पुनः निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि प्रत्येक प्रदर्शक के लिए ऐसे प्रदर्शनों की लागत बीमा भाड़ा मूल्य की निर्धारित सीमा 5 लाख रु. हो। तथापि, जिन प्रदर्शित मदों का मुक्त आयात किया गया था उनकी भावी लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर पुनः निर्यात की अनुमत बाण्ड अवधि के भीतर प्राधिकार पत्र के बिना बिक्री की जाएगी।

(2) यदि आयातक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण नुमाइश के लिए लाई गई वस्तुओं का बाण्ड अवधि के अंदर पुनः निर्यात या बिक्री नहीं की जाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी गुण-दोष आधार पर बाण्ड अवधि में वृद्धि कर सकते हैं।

विदेशी कार्यालय  
उपकरणों का आयात

2.45

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्थापित समुद्रपारीय कार्यालयों को बंद करने पर, कार्यालय उपकरणों और अन्य मदों का आयात प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है।

2.46

हटा दिया गया है।

- प्रोटो टाइप्स 2.47 वास्तविक उपयोक्ता, नई/पुराने प्रोटोटाइप्स/पुराने नमूनों का आयात बिना प्राधिकार पत्र कर सकते हैं। जो उत्पादन कार्य में लगें हैं या उनके पास औद्योगिक लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र/आशय पत्र है अथवा अनुसंधान में लगी है और उन्हें उत्पाद विकास या अनुसंधान, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रोटो टाइप/सेम्पल की जरूरत है, वे सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुरूप स्व घोषणा करके आयात कर सकते हैं। राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा सभी प्रतिबंधित मर्दों और आयात की जाने वाली अनुमत मर्दों।
- अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रतिबंधित मर्दों 2.48 अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए जीवित जानवरों को छोड़कर सभी प्रतिबंधित मर्दों का आयात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है।
- निर्यात नीति 2.49 निर्यात से संबंधित नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में दी गई है। इसके अलावा, आई टी सी (एच एस) के परिशिष्ट 1 अनुसूची-2 में उन मर्दों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनका किसी प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है, जो कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।
- निर्यात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र 2.50 आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 में उल्लिखित मर्दों के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, आयात-निर्यात फार्म 2घ (स्कोमेट मर्दों के लिए 2ड.) में विदेश व्यापार महानिदेशक को दिया जाए और इसके साथ उसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। विदेश व्यापार सुविधा समिति, निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए गुण-दोष के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगी।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय में स्थित अन्तर मंत्रालयीय कार्य समूह नीचे दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2, परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिष्ट विशेष रसायनों, अर्गेनिजन, सामग्री, उपकरणों और प्रौद्योगिकी स्कोमेट के निर्यात के आवेदनों पर विचार करेगा।
- स्कोमेट सूची पर निर्यात मर्दों या प्रौद्योगिकी के लाइसेंसों के आवेदनों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है जो अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित सामान्य मानदण्डों पर आधारित है:
- I. स्कोमेट सूची पर निर्यात मर्दों के आवेदनों का मूल्यांकन करते समय अन्य कारकों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जायेगा।
  - क अन्तिम प्रयोक्ता के व्यक्तिगत ब्योरे, मद, या प्रौद्योगिकी के अन्तिम प्रयोक्ता की घोषणाओं की विश्वसनीयता, अन्तिम प्रयोक्ता

को आपूर्तिकर्ता से मद की सुपुर्दगी और मद या प्रौद्योगिकी क्षमता की निष्ठा जिसमें इसके निर्यात का समय शामिल है जो अन्तिम प्रयोग के लिए योगदान देता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों वैश्विक गैर निरस्तीकरण के उद्देश्यों या उन उद्देश्यों जिन, संधियों के लिए यह अनुरूप नहीं है।

ख इसमें यह भी देखा गया है कि निर्यातित मदें आतंकवादियों के हाथ न लग जाए। मूल्यांकित खतरे कि निर्यातित मदें आतंकवादी, आतंकवादी समूहों और देशद्रोहियों के हाथों में जा सकती है।

ग प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा स्थापित निर्यात नियंत्रण उपाय,

घ हथियारों और उनकी सुपुर्दगी से संबंधित प्राप्त कर्ता राज्य के कार्यक्रमों की क्षमताएँ और उद्देश्य,

ङ मदों के अन्तिम प्रयोग का मूल्यांकन,

च संगत द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौतों जिसमें भारत एक पक्ष हो, के निर्यात लाइसेंस आवेदनों की उपयुक्तता।

II. निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन पर विचार किए जाने की एक शर्त अन्य बातों के साथ साथ यह है कि उससे संबंधित निर्धारित प्रमाणन प्रस्तुत किया जाए, कि:

क मद का प्रयोग सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रयोग को भारत सरकार की मंजूरी के बिना बदला नहीं जाएगा, न ही मदों को संशोधित अथवा दुहराया जाएगा,

ख भारत सरकार की मंजूरी के बिना न ही मदों को न ही उनकी प्रतिकृति अथवा व्युत्पन्न को पुनर्हस्तांतरित किया जाएगा।

ग अन्तिम प्रयोक्ता, भारत सरकार द्वारा जैसा भी आवश्यक होगा वैसे प्रमाणन उपलब्ध कराएगा।

प्राप्तकर्ता के राज्य से, अन्तिम प्रयोग और गैर-पुनर्हस्तांतरण सहित, जैसा भी ठीक हो, भारत सरकार को अतिरिक्त औपचारिक आश्वासन की भी आवश्यकता हो सकती है।

III. नीचे श्रेणी 0 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी परमाणु उर्जा विभाग है। लागू दिशानिर्देश उस विभाग द्वारा परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचित हैं। श्रेणी 0

की कुछ मदों के लिए प्राप्तकर्ता राज्य से औपचारिक आश्वासनों में किसी नाभकीय विस्फोट उपकरण में न प्रयोग किया जाना भी शामिल है। श्रेणी 0 की कुछ मदों के निर्यात के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा, जबतक की हस्तांतरण अतिरिक्त रूप से उचित संरक्षण के तहत और उचित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (आई ए ई ए) रक्षोपाय अथवा हस्तांतरणीय मदों के किसी भी अन्य पारस्परिक सहमति नियंत्रणों के तहत नहीं होगी।

IV. मदों अथवा तकनीक के निर्यात के लिए लाइसेंसों में अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग शर्तें निर्धारित की जाएँ, जो दिशा परिवर्तन की संभावना रखती हों। अथवा उसके विकास अथवा विनिर्माण में प्रयोग हों अथवा व्यापक विध्वंश के हथियारों की सुपुर्दगी में सक्षम प्रक्रिया के रूप में प्रयोग हो।

V. सूची में दी गई किसी मद के लिए "तकनीक" के हस्तांतरण के लिए आवेदनों पर स्वयं मद के निर्यात के लिए आवेदन के रूप में विचार किया जाएगा।

VI. सिर्फ प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के उद्देश्य के लिए इस सूची (श्रेणी 0.1 और 2 को छोड़कर) में दिए मदों के निर्यात के लिए लाइसेंसों हेतु किसी अन्तिम प्रयोग अथवा अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। (किसी भी श्रेणी में 'तकनीक' के लिए, प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हेतु निर्यात लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा। श्रेणी 0.1 और 2 के अंतर्गत आने वाले मदों के लिए प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा)।

VII. स्कोमेट सूची में जो मदें नहीं हैं उनका निर्यात भी व्यापक विध्वंश के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों की निषिद्धता) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नियंत्रित होगा।

टिप्पणी:1- निर्यात अथवा निर्यात के प्रयास में लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन, दीवानी और/अथवा फौजदारी अभियोजन को आमंत्रित करेगा।

टिप्पणी:2- विदेश में प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के लिए इस सूची की मदों के निर्यात के लिए लाइसेंस छः माह के भीतर की अवधि में पुनः आयात शर्त के अधीन है। विदेश में प्रदर्शनी के दौरान यदि प्रदर्शनीकर्ता ने मद को बिक्री के लिए रखा हो, तो विदेश में प्रदर्शित ऐसी मदों के लिए निर्यातक, निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन करने का हकदार है। ऐसी बिक्री बिना वैध लाइसेंस के नहीं होगी।

टिप्पणी:3- इस सूची की श्रेणी-2 में निर्यात की मदें, समय-समय पर जारी अन्य लागू दिशा निर्देशों द्वारा भी नियंत्रित होंगी। इस श्रेणी में मदों के निर्यातकों को विदेश व्यापार महानिदेशालय से दिशा निर्देश प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

टिप्पणी:4- देशों और/अथवा देशों के समूहों को निर्यात के लिए “ गंतव्य लाइसेंस” हेतु निर्यातक, आवेदन के हकदार हैं जहाँ सिर्फ पुनर्हस्तांतरण शर्तें लागू किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी:5- निर्यातक यह अनुरोध कर सकते हैं कि केवल ऐसी शर्तें ही लगाई जाएँ जो स्कोमेट सूची की मदों के निर्यात पर सरकार से सरकार समझौते के अधीन हैं।

टिप्पणी:6- ‘ तकनीक’ (आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट -3 की शब्दावली में प्रविष्टि “ तकनीक” को भी देखें)। स्कोमेट सूची की मद के निर्यात का अनुमोदन, मद की स्थापना, संचालन, रख-रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक न्यूनतम ‘तकनीक’ के लिए उसी अन्तिम प्रयोक्ता को निर्यात के लिए प्राधिकृत करता है।

डीजीएफटी कार्यालय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों व व्यापार ऐसोसिएशनों के सहयोग से व्यापार से संबंधित आयातक/निर्यातक के मध्य विशेष रूप से एससीओ एमईटी मदों के संबंध में प्रभावी जागरूकता के लिए इन्डस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम का नियमित आधार पर आयोजन करेंगे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय, आवेदन करने पर, अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक आदि में प्रयोग होने वाले चिकित्सीय और शल्य उपकरणों के लिए, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत न आने वाली निर्यात की मदों के लिए और जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र भी जारी कर सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

राज्य व्यापार व्यवस्था के तहत मदों का निर्यात	2.51	राज्य व्यापार व्यवस्था के अधीन आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित मदों के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाएँ ।
नमूनों/नुमाइशी वस्तुओं का निर्यात	2.52	ऐसे नमूनों या नुमाइशी वस्तुएँ, जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित हों, के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाए।
निःशुल्क निर्यात	2.52.1	स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे जोकि पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 10 लाख रु० या 2 प्रतिशत की वार्षिक सीमा, जो भी ज्यादा हो, के अधीन होगा।

- उपहार/पूर्व/  
प्रतिस्थापन माल 2.53 नीति के पैराग्राफ 2.32, 2.33 और 2.37 में निर्धारित सीमा/अवधि से अधिक में देशी/आयातित वारण्टी स्पेयर्स और प्रतिस्थापन माल, उपहार के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाए।
- गैर वास्तविक रूप में  
निर्यात संबंधी रिटर्न भेजना 2.54 हाई स्पीड डाटा कम्यूनिकेशन लिंक्स, इन्टरनेट, टेलीफोन लाईन और कोई अन्य चैनल जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकरण शामिल नहीं होता, सहित कम्यूनिकेशन लिंक का उपयोग करके, गैर वास्तविक रूप में किए जाने वाले सभी निर्यातों के बारे में अनिवार्य रूप से परिशिष्ट 19ग में उल्लिखित फार्म में संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद को तिमाही आधार पर सूचना भेजनी होगी।
- यह प्रावधान सभी निर्यात करने वाले यूनिटों पर लागू होंगे चाहे देश में कहीं भी स्थित हों इनमें एस टी पी, एस ई जैड, ई एच टी पी और 100% ई ओ यू स्कीम के अधीन स्थित यूनिटें भी शामिल हैं।
- भेषज और जैव-  
प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए  
अनुसंधान और विकास  
उपकरण का शुल्क  
मुक्त आयात 2.55 उन विनिर्माता निर्यातकों को (समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं० 21/2002 दिनांक 1.3.2002 की सूची 28 में यथा निर्दिष्ट) पिछले लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।
- पात्र यूनिट परिशिष्ट-15क में दिए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रति - हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 2.55.1 कृषि रसायन क्षेत्र यूनिट को सीमा-शुल्क अधिसूचना सं० 21/2002 दिनांक 1.3.2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) की सूची 28(क) में यथा निर्दिष्ट पिछले लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।
- पात्र यूनिट परिशिष्ट-15ख में दिए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- एक योजना से दूसरी  
योजना में शिपिंग बिल  
की ईपी प्रति में परिवर्तन 2.56 यदि सीमाशुल्क प्राधिकारी, लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद, किसी स्कीम पोत बिल की ई.पी. प्रति के परिवर्तन की अनुमति देते हैं जिस पर उस योजना का लाभ नहीं लिया गया है, निर्यातक उस योजना के तहत लाभ पाने का पात्र हो जिसमें शिपमेंट को बाद में परिवर्तित किया गया है।

उद्योगों की पुनर्स्थापना	2.57	हटा दिया गया है।
निर्यात आय की ऑफ सेटिंग	2.58	किसी भी निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक किसी देय या इक्विटी निवेश के मद्दे निर्यात आय को ऑफसेट प्राप्तियों के रूप में प्रयोग कर सकता है बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष अनुमोदन लिया गया हो। ऐसे मामलों में, यदि निर्यातक निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऑफ सेटिंग निर्यात आय की प्राप्ति के बराबर होगी :-

(क) बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र की एवज में परिशिष्ट-22 घ

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति ।

गुणवत्ता प्रमाणन	2.59	यह निरन्तर कोशिश रहनी चाहिए कि निर्यात उत्पाद का विनिर्माण करने वाले एककों/निर्यात उत्पाद के गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा दिया जाएगा।
------------------	------	---

2.59.1 गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्राफ 3.5.2 टिप्पणी-1 के अनुसार विदेश व्यापार नीति में शामिल की गई मुख्य-मुख्य बातों में से एक यह है कि आई एस ओ-9000(श्रृंखला), आई एस ओ-14000 (श्रृंखला) या एच ए सी सी पी प्रमाणन या डब्ल्यू एच ओ जी एम पी या एस ई आई सी एम एम स्तर-2 और उपर्युक्त स्तर/प्रमाणन वाले एककों के लिए न्यूनतम प्रारम्भिक सीमा प्राप्त करने पर स्टार निर्यात सदन स्तर की मंजूरी दी जाए ।

2.59.2 गुणवत्ता प्रमाणन देने के लिए जिन्हें प्राधिकृत किया गया है, ऐसे अभिकरणों की सूची परिशिष्ट-6 में दी गई है। परिशिष्ट-6 में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण परिशिष्ट-6 के अनुलग्नक-I के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय लाईसेंसिंग प्राधिकारी को अपना आवेदन कर सकता है ।

2.59.3 हटा दिया गया है।

2.60 हटा दिया गया है।

2.61 प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के तहत आयात की प्रक्रिया

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में, नीचे दी गई मात्रा के साथ-साथ दर्शाई गई सीमाशुल्क की रियायती दरों पर, चार मदों अर्थात्, (1) स्किम्ड और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, बच्चों के लिए दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ आदि (0402.10 अथवा 0402.21) (2) मक्का (कान);



आदि (1005.99) (3) कच्चा सूरजमुखी बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (1512.11) और (4) रेप, कोल्जा अथवा सरसों का रिफाइनड तेल, आदि (1514.19 अथवा 1514.99) के आयात की अनुमति है:-

15) आप के फ्रैंक ऑफ आर्किव

क्र० आईटीसी कोड संख्या	कोटा की मात्रा	रियायती शुल्क
प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21	10,000 मी.टन	15%
दुध और संपूर्ण दुध		
पूर्ण दूध के लिए		
खाद्य पदार्थ आदि		
प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90	5,00,000 अन्य	15% मी.टन
मक्का (कान)		
प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11	1,50,000 मी.टन	15%
कच्चे सूरजमुखी के बीज अथवा तेल अथवा उनके भाग		
प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 और 1514.99	1,50,000 मी.टन	45%
रेप, कोल्जा अथवा सरसों का तेल अन्य (रिफाइनड)		
दुध-घृण (प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21):		
राष्ट्रीय दुध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), राष्ट्रीय सहकारी दुध संघ (एनसीडीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी) और मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल)।		
मक्का (कान) (प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90):		
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और राज्य सहकारी विपणन संघ।		
कच्चे सूरजमुखी के बीज अथवा कुसुम्भ अथवा उनके भाग (प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11):		
रिफाइनड रेप, कोल्जा या सरसों का तेल, अन्य (प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 या 1514.99)		
राष्ट्रीय दुध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और		

केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्लूसी), राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम। सभी पात्र कंपनियाँ प्राप्त आवेदकों के आवेदनों के अनुसार कोटा पात्र कंपनियाँ कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।

उत्तर उल्लिखित के अनुसार कोटा प्राप्त करने की इच्छुक सभी पात्र कंपनियाँ, विदेश व्यापार महानिदेशालय, के कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में, प्रक्रिया पुस्तक के आयात-निर्यात फार्म में निर्यात आयात सुविधा समिति को आवेदन कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक/निर्धारित दस्तावेजों सहित कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 1 मार्च, 2007 तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। उदाहरणतः टी आर क्यू के लिए वर्ष 2007-2008 के लिए आवेदन 1 मार्च, 2007 तक विदेश व्यापार महानिदेशालय पहुँच जाने चाहिए।

आयात वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए अर्थात् इस तारीख से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खेप की निकासी कर दी जानी चाहिए।

चूँकि, मक्के (कान) का आयात राज्य व्यापार व्यवस्था (एसटीआर) के तहत है, कोटे के आवंटन अर्थात् इस मद के लिए पैरा 1 (ख) में नामित एजेंसियाँ को भी, विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैरा 2.11 के अनुसार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 दिनांक 1/3/2002 की क्रम संख्या 21 (ख) में दर्शाई आवंटित मात्रा के लिए आयात लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, यदि वे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से आयात नहीं करना चाहते।

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I के परिशिष्ट 21 ख में शामिल प्रक्रिया के अनुसार इन आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात आयात सुविधा समिति (ईएफसी) मूल्यांकन करेगी और कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से आवेदकों के मध्य कोटा आवंटित करेगी अर्थात् 2007-08 के लिए ईएफसी 31 मार्च, 2007 से कोटा आवंटित करेगी।

जहाजरानी बिलों  
कीई पी प्रति और/या  
मूलबैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र  
खो जाने पर पावती-पत्र  
जारी करना

2.62

यदि जहाजरानी बिल की ई पी प्रति/मूल बी आर सी खो गया है तो वी के जी यू वाई/एफ एम एस/एफ पी एस के तहत दावे के बारे में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा :-

क) जारी किए गए संबंधित दस्तावेज की डुप्लीकेट/ प्रमाणित प्रति;

- ख) सम्बद्ध हकदारी के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी अभिकरणों द्वारा ये दस्तावेज़ गुम करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस आशय का दस्तावेज़ी सबूत प्रस्तुत किया गया है;
- ग) निर्यातक द्वारा दस्तावेज़ खो जाने के बारे में शपथ-पत्र और यह बचनबद्धता कि यदि बाद में यह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को वापिस कर दिया जाएगा।
- घ) निर्यातक द्वारा इस आशय का क्षतिपूर्ति बॉण्ड कि गुम हो गए जहाजरानी बिलों/बी आर सी के मद्दे जारी ड्यूटी क्रेडिट के कारण यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा। निकासी की अनुमति देने से पहले सीमा-शुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे जहाजरानी बिल के मद्दे लाभ/ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया है।

2.62.1 जहाजरानी बिल/बी आर सी गुम होने के मद्दे दावा जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट प्रति जारी होने की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर निर्यात आय की प्राप्त की तारीख को प्रस्तुत करना होगा। इस अवधि के बाद प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

2.63 हटा दिया गया है।

वस्तु बोर्डों सहित निर्यात संवर्धन परिषद्

2.64 वस्तु बोर्ड सहित निर्यात संवर्धन परिषदों की एक सूची और उत्पाद श्रेणी परिशिष्ट-2 में दी गई है। वस्तु बोर्ड इन्हें आबंटित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् के रूप में कार्य करते हैं। निर्यात संवर्धन परिषद् आर सी एम सी जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

गैर-लाभकारी, स्वायत्त और व्यावसायिक निकाय

2.65 निर्यात संवर्धन परिषदें कम्पनी अधिनियम या सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन हैं।

2.65.1 निर्यात संवर्धन परिषदें स्वायत्त हैं और अपने कार्यों को स्वयं देखेंगी। तथापि, यदि केन्द्र सरकार निर्यात संवर्धन परिषदों के संविधान और/या कार्य प्रणाली के लिए कोई एक समान उप-नियम बनाती है तो वे ऐसी निर्यात संवर्धन परिषद् के विशेष स्वरूप या कार्य-पद्धति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संशोधनों के अनुसार अपनायेंगी। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ वर्ष में कम से कम दो बार वार्तालाप करेगा।

2.65.2 हटा दिया गया है।

2.66 हटा दिया गया है।

- आर सी एम सी  
जारी करने के लिए  
पंजीकरण प्राधिकरण
- 2.67 स्तर धारक फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्टर्स आर्गनाइजेशन (फियो) से आर सी एम सी प्राप्त कर सकता है। गौण वान्य उत्पाद और इनके मूल्य संबंधित उत्पादों के निर्यातक शीफेक्सिल, ई पी सी से आर सी एम सी प्राप्त कर सकते हैं। साफ्टवेयर के निर्यातक इलेक्ट्रानिक एण्ड साफ्टवेयर ई पी सी के पास खुद को पंजीकृत करवायेगा। प्रक्रिया - पुस्तक, खण्ड - 1 के परिशिष्ट-2 की क्र.सं 34 में सूचीबद्ध 13 विशिष्ट सेवाओं के निर्यातक स्वयं को सेवा ई पी से की पास पंजीकृत करवायेंगे। अन्य सेवा निर्यातक स्वयं को फियो के पास पंजीकृत करवायेंगे। जिन निर्यातकों के मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में हैं, वे आर सी एम सी भुवनेश्वर में फियो कार्यालय से प्राप्त करेंगे, चाहे उत्पादों को उनके द्वारा निर्यात किया गया हो या न किया गया हो।
- 2.67.1 इसके अलावा, निर्यातक आर सी एम सी फियो या अन्य किसी सम्बद्ध ई पी सी से प्राप्त कर सकता है यदि उसके द्वारा निर्यातित उत्पाद इन ई पी सी से संबंधित है।
- 2.67.2 यदि निर्यात उत्पाद ऐसा है कि वह किसी ई पी सी में शामिल नहीं है तो इसके संबंध में आर सी एम सी फियो द्वारा जारी की जाएगी।
- पंजीकरण - सह -  
सदस्यता प्रमाणपत्र  
(आरसीएमसी)
- 2.68 निर्यातक परिशिष्ट-19क में दिए गए प्रपत्र में आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकता है और ई पी सी का सदस्य बन सकता है। सदस्यता मिल जाने पर आवेदक को परिशिष्ट-19ख में दिए गए प्रपत्र में संबंधित ई पी सी का पंजीकरण - सह - सदस्यता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यदि कोई निर्यातक विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसे इस आशय का सबूत देना होगा। भावी/सम्भावित निर्यातक भी आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं और ई पी सी के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं।
- आर सी एम सी  
की वैधता अवधि
- 2.68.1 आर सी एम सी लाइसेंसिंग वर्ष, जिसमें यह जारी किया गया है, 1 अप्रैल से वैध होगा और लाइसेंसिंग वर्ष, 31 मार्च के अन्त तक पाँच वर्ष के लिए वैध-होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया है।
- संविधान में परिवर्तन  
के संबंध सूचना देना
- 2.69 निर्यातक का स्वामित्व, संविधान, नाम या पते में परिवर्तन होने पर आर सी एम सी धारक को ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को इस परिवर्तन के बारे में बताना जरूरी होगा। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारी गुण - दोष के आधार पर विलम्ब को नज़रअंदाज़ कर सकता है।
- विवरणी प्रस्तुत करना
- 2.70 निर्यातक विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की तिमाही विवरणी/ ब्यौरे संबंधित पंजीकरण - प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। तथापि, स्तर धारक फियो द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में फियो को तिमाही विवरणी भी भेजेंगे।

वि - पंजीकरण	2.71	पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर निर्दिष्ट अवधि के लिए आर सी एम सी धारक का वि-पंजीकरण कर सकता है। ऐसे वि-पंजीकरण से पहले, आर सी एम सी धारक को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा कारण भताओ नोटिस जारी किया जाएगा और प्रस्तावित वि-पंजीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। वि - पंजीकरण किए जाने पर संबंधित ई पी सी इसके बारे में सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित करेगा।
वि - पंजीकरण के विरुद्ध अपील	2.72	यदि किसी व्यक्ति को आरसीएमसी जारी किए जाने के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय से कोई दिक्कत है तो वह विदेश व्यापार महानिदेशालय या इनकी ओर से पदनामित किसी अधिकारी को उक्त निर्णय लिए जाने के विरुद्ध 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी निर्णय अंतिम होगा।
विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देश	2.73	विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातक को पंजीकृत करने या वि-पंजीकृत करने के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को निदेश दे सकता है अथवा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों, इसके तहत बनाये गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई निदेश जारी कर सकता है।
	2.74	इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज
	2.74.1	ईडीआई की भूमिका और कार्यों को विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.45 में परिभाषित किया गया है। ईडीआई की पहल का मूल प्रयोजन विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ता समुदाय के सेवाओं में सुधार करना है ताकि परिचालन में बेहतर पारदर्शिता लाई जा सके और विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करके ट्रांजेक्शन लागत को कम किया जा सके। ईडीआई की इस पहल से हमारा निर्यात अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बना है।
पात्रता	2.74.2	इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा सभी निर्यातकों को उपलब्ध होगी।
प्रक्रिया	2.74.3	निर्यातक डीजीएफटी की वेबसाइट <a href="http://dgft.gov.in/">http://dgft.gov.in/</a> पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन पर मौजूदा नियमों और वि-नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आवेदक को आवेदन शुल्क सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड प्रतिलिपि देने के लिए संबंधित कार्यालय में आना होगा। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा के करने के बाद दस्तावेजों की हार्ड प्रतिलिपि प्राप्त होने पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

ईडीआई के लिए  
वित्तीय प्रोत्साहन

2.74.4 डीजीटल रूप से हस्ताक्षरित आवेदनों और/या आवेदन शुल्क ईएफटी (इलेक्ट्रानिक फंड ट्रान्सफर) के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप से दिया गया है तो आवेदन शुल्क में निम्नलिखित कटौती अनुमत होगी:

क्रम सं.	आवेदन का तरीका	शुल्क कटौती (सामान्य आवेदन शुल्क का %)
1	डीजीटल रूप से हस्ताक्षरित	25%
2	ईएफटी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान	25%
3	डीजीटल रूप से हस्ताक्षरित और आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए ईएफटी दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाना	50%

लाभ

2.74.5 इस सुविधा से विदेश व्यापार महानिदेशालय में अनावश्यक शारीरिक श्रम में कमी आएगी। इससे शीघ्र कार्यवाही करने, कमियों को तेजी से बताने यदि कोई हो और ऑन लाइन पर आवेदन की कार्यवाही के बारे में पता चल सकेगा।

2.74.6 विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रानिक आवेदन पद्धति का प्रयोग करके जारी किए जाने वाले प्राधिकार पत्र के बारे में ग्राहकों को सूचना ईडीआई पद्धति के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी। इससे निकासी की अनुमति देने से पहले प्राधिकार पत्रों की जाँच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

नई ईडीआई पहल

2.74.7 सेवाओं में और सुधार करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कुछ नई ईडीआई पहलें की गई हैं। 'आयात निर्यात प्रपत्र' (एएनएफ) को सरल बनाने के लिए इस वर्ष योजना विशिष्ट एएनएफ शुरू किया गया है। इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

## अध्याय - 3

## संवर्धनात्मक उपाय

- स्तर प्रमाण पत्र 3.1 नीति के अध्याय-3 में स्तर धारकों से संबंधित नीति दी गई है।
- स्तर प्रमाण पत्र की मंजूरी 3.2 किसी स्तर की मंजूरी के लिए आवेदन आयात निर्यात फार्म 3-क में 31 मार्च से पहले प्रस्तुत करना होगा।

के लिए आवेदन पत्र

मौजूदा स्तरधारक को स्वतः ही नीचे दी गयी तालिका के अनुसार स्तरधारक के बराबर माना जाएगा :-

विदेश व्यापार नीति 2004-09 (संशोधित संस्करण - 2006) के अनुसार स्तर	विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अनुसार परिवर्तित स्तर (संशोधित संस्करण - 2006)
एक स्टार निर्यात सदन	निर्यात सदन
दो स्टार व्यापार सदन	स्टार निर्यात सदन
तीन स्टार निर्यात सदन	व्यापार सदन
चार स्टार व्यापार सदन	स्टार व्यापार सदन
पांच स्टार व्यापार सदन	डिलक्स व्यापार सदन

- 3.2.1 आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी/विकास आयुक्त (डी सी) को प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, उन मामलों जोकि ई ओ यू/एस ई जैड इकाईयों के कंपनी या फर्म/डी टी ए में समूह कंपनियों के साथ जोड़ा जाना है तो वह केवल क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।
- 3.2.2 सभी नए जारी किए गए स्तरधारक प्रमाण पत्र 1 अप्रैल से उस वर्ष के लिए वैध होंगे जिसमें मान्यता के लिए आवेदन जमा किया गया है। नवीकरण के लिए आवेदन वैधता समाप्त होने से पहले आवेदन जमा किया जाना चाहिए। नवीकरण अगले लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से वैध होगा। अन्यथा वैध अवधि उस वर्ष के 1 अप्रैल से होगी जिसमें आवेदन जमा किया जाएगा। तथापि सभी स्तरधारक प्रमाण पत्र 31.3.2009 को समाप्त हो जाएंगे।
- 3.2.3 हटा दिया गया है।
- 3.2.5 हटा दिया गया है।

- खातों का रख-रखाव 3.3 स्तर धारक ने जो निर्यात और आयात किया है और जिससे उसे यह मान्यता दी गई है तथा मान्य प्रमाणपत्र की वैध अवधि के भीतर उसने जो निर्यात और आयात किया है के खाते का सही और उचित लेखा रखेगा। यह रिकार्ड ऐसे प्रमाण पत्र की वैध तारीख की समाप्ति से कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा। ये लेखे लाइसेंसिंग प्राधिकारी या विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रमाण पत्र की अस्वीकृति/ 3.4 यदि प्रमाण पत्र धारक/आवेदक या कोई एजेंट अथवा कर्मचारी जो निलम्बन/रद्द करना उनकी ओर से कार्य करता हो, निम्नलिखित कार्य करने में असफल रहता है तो उस प्राधिकारी द्वारा स्तर प्रमाण पत्र की मान्यता अस्वीकृत अथवा निलम्बित या रद्द की जा सकती है जो ऐसे प्रमाणपत्र जारी/नवीकृत करने के लिए सक्षम है: (क) लगाए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है; (ख) प्राधिकार पत्र में रद्दोबदल करता है; (ग) किसी प्राधिकार पत्र को प्राप्त करने में अन्यथा विवरण देने, या भ्रष्ट या छल कपट करने में एक पक्ष बनता है; (घ) विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम 1992 अथवा उसके अधीन बने नियमों या आदेशों का उल्लंघन करता है; या (ङ) विदेश व्यापार महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है;
- 3.4.1 उपरोक्त पैराग्राफ के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व आवेदक या स्तर धारक को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
- अपील 3.5 जो आवेदक प्रमाण पत्र के निलम्बन या रद्द के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वह उक्त निर्णय की तारीख से 45 दिनों के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार को अपील कर सकता है। महानिदेशक, विदेश व्यापार का निर्णय अन्तिम होगा।
- 3.6से3.12 हटा दिया गया है।
- 3.12.1 हटा दिया गया है।
- 3.12.1.1 हटा दिया गया है।
- 3.12.1.2 हटा दिया गया है।  
से 3.12.1.4
- 3.13से3.17 हटा दिया गया है।
- 3.17.1  
से 3.17.7 हटा दिया गया है।



## 3.18 भारत से सेवित स्कीम

3.18

(क) भारत से सेवित स्कीम हेतु नीति का विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

(ख) शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र हेतु अकेला समेकित आवेदन 'आयात निर्यात फार्म' 3ख में निर्धारित प्रपत्रों सहित संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(ग) से (च) हटा दिया गया है।

(छ) सेवा प्रदायक किए गए आयातों को पूरा करने के एक महीने के भीतर अथवा शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, 'आयात निर्यात फार्म' के अनुसार प्रमाणपत्र के तहत किए गए आयातों की विवरणिका क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति क्षेत्राधिकारी उत्पाद शुल्क प्राधिकारी (सेवा कर प्रकोष्ठ को देगा) जहाँ भी लागू होगा।

(ज) हटा दिया गया है।

(झ) हटा दिया गया है।

अपात्र प्रेषित धन एवं सेवाएं 3.18.1

सेवा क्षेत्र से भिन्न सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा की गणना हकदारी के लिए नहीं की जाएगी।

इसी प्रकार अन्य साधनों से अर्जित विदेशी मुद्रा जैसे इक्विटी या ऋण भुगतान, दान, ऋण की अदायगी इत्यादि और अन्य साधनों से प्राप्त विदेशी मुद्रा अपात्र होगी।

(क) निम्नलिखित प्राप्त विदेशी मुद्रा इस स्कीम के अन्तर्गत हकदारी के लिए योग्य नहीं होगी:

- I. वित्तीय सेवा क्षेत्र से सम्बंधित प्राप्त की गई रकम
1. सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना
2. ग्राहकों को निर्यात आय की प्राप्ति
3. ए डी आर/जी डी आर अथवा वैसे अन्य जरिए से विदेशी मुद्रा को जारी करना
4. विदेशी मुद्रा बांड को जारी करना
5. प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उपायों की बिक्री
6. अन्य प्राप्तियाँ जो वित्तीय संस्थानों द्वारा चलाई जा रही सेवाओं से जुड़ी नहीं है

- II. करार/विदेशों में नियमित रोजगार के जरिए प्राप्त धन (जैसे मजदूरी से प्राप्त धन)
- (ख) ई ई एफ सी खाते से प्राप्त भुगतान का आकलन स्कीम के तहत लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
- (ग) स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों जैसे इक्विटी भागीदारी, अनुदान आदि के लिए विदेशी मुद्रा कारोबार (तथापि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया चिकित्सा उपचार शल्य चिकित्सा, जाँच सलाह और स्वास्थ्य परिचर्या के लिए प्राप्त प्रेषण अपात्र नहीं होगा)
- (घ) शैक्षिक संस्थानों जैसे इक्विटी भागीदारी, अनुदान आदि द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार (तथापि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया पाठ्यक्रम शुल्क और सलाह के लिए प्राप्त प्रेषण पात्र होगा)
- (ङ.) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी स्कीम के अधीन कार्य कर रही यूनिटों की सेवाओं से संबंधित निर्यात कारोबार या ऐसी यूनिटों को की गई सेवाओं की आपूर्ति;
- (च) डी टी ए सेवा प्रदाताओं के कारोबार के साथ एसईजेड/ ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी यूनिटों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारोबार को जोड़कर; और
- (छ) माल का निर्यात

3.18.2 हटा दिया गया है।

3.19 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना

3.19.1 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना से संबंधित नीति का विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 37क में विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना मदों की सूची शामिल है।

विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के अधीन 1-4-2007 के बाद किए गए निर्यात के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रदान करने के लिए आवेदन आयात-निर्यात प्रपत्र 3 (ग) में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किए जाएंगे।

आवेदक एक या अधिक आवेदन इस शर्त पर दाखिल कर सकता है कि प्रत्येक आवेदन में 50 से अधिक शिपिंग बिल नहीं होंगे। एक आवेदन में सभी शिपिंग बिल केवल एक सीमाशुल्क सदन से किए गए निर्यात से सम्बंधित होने चाहिए। जोकि शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट हेतु पंजीकरण का पत्तन होगा।

शिपमेन्ट्स के सम्बंध में, जिसके लिए दावा किया गया है, क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्यात की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर या वसूली की तारीख से 6 महीने के भीतर या मुद्रण की तारीख/पोतलदान बिल जारी होने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत किए जाएंगे।

3.19.2 हटा दिया गया है।

3.19.3 सीधे साथ-साथ तीसरे पक्ष के द्वारा निर्यातों हेतु, निर्यात दस्तावेज यानी निर्यात आदेश, बीजक, जी आर फार्म, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र केवल आवेदक के नाम में होना चाहिए।

3.19.4 हटा दिया गया है।

से 3.19.9

फोकस मार्केट स्कीम

3.20 फोकस मार्केट स्कीम से संबंधित स्कीम विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में दी गयी है। अधिसूचित मार्केट परिशिष्ट 37ग में सूचीबद्ध है।

3.20.1 ईडीआई समर्थित पत्तनों के जरिये सभी निर्यातों हेतु एक समेकित आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 3घ में उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन छह महीनों के आधार पर यानी अप्रैल-सितम्बर और अक्टूबर-मार्च को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जहाँ वसूली आवेदन अवधि के दौरान की गई है। अग्रिम भुगतान (और उन मामलों में जहाँ प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 का पैरा 3.23.3 लागू होता है) के मामले में निर्यातों की तारीख को आवेदन की अवधि में शामिल करने हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

शुल्क क्रेडिट का दावा करने हेतु आवेदक को आवेदन की अवधि के अंत से छह महीनों की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा। (अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2007 अवधि के लिए, अन्तिम तारीख मार्च, 2008 अवधि के लिए अन्तिम तारीख सितम्बर, 2008 होगी)।

चूंकि एफएमएस निर्यात हेतु 1-4-2006 से शुरू की गई है, 1-4-2006 से निर्यात हेतु लाभ प्रदान करने के लिए आवेदनों पर निम्नानुसार विचार किया जाएगा:-

(क) अप्रैल-सितम्बर, 2006 अवधि हेतु आवेदन के संबंध में आवेदन दायर करने की अन्तिम तारीख 31 मार्च, 2008 होगी। यह केवल उन पोत लदानों पर लागू होगा जिनका निर्यात 1-4-2006 को या उसके बाद किया गया है किन्तु जिनके लिए वसूली 30-09-2006 तक प्राप्त हुई है।

(ख) अक्टूबर-मार्च, 2007 अवधि हेतु आवेदन के संबंध में आवेदन दायर करने की अन्तिम तारीख 31 मार्च, 2008 होगी। यह उन सभी पोत लदानों पर लागू होगा जिनका निर्यात 1-4-2006 को या उसके बाद किया गया है किन्तु जिनके लिए वसूली 31-03-2007 तक प्राप्त हुई है।

निर्यातक केवल एक अनुपूरक दावा दायर कर सकता है यदि अप्रैल-सितम्बर और अक्टूबर-मार्च अवधि हेतु मूल दावे में कुछ पोतलदान शामिल नहीं किए गए हैं। इससे दावा की गई धनराशि पर अनुपूरक कटौती लगेगी यह सुनिश्चित करने के बाद पोतलदान पूर्व दावे में शामिल नहीं किया गया है। यदि अनुपूरक दावा देर से किया जाता है तो विलम्ब कटौती नहीं लगाई जाएगी। यह उन निर्यातों पर भी लागू होगा जो 1-4-2006 को किए गए हैं।

3.20.2 सीधे के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा निर्यातों हेतु, निर्यात दस्तावेज यानी निर्यात आदेश, बीजक, जी आर फार्म, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र केवल आवेदक के नाम में होने चाहिए।

3.20.3 आवेदक को निर्धारित बाजार में निर्यात खेप पहुँचाने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

3.20.4

से 3.20.8 हटा दिया गया है।

#### फोकस उत्पाद स्कीम

3.21 फोकस उत्पाद स्कीम से संबंधित स्कीम विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में दी गयी है। अधिसूचित उत्पाद परिशिष्ट 37घ में सूचीबद्ध है।

3.21.1 ईडीआई समर्थित पत्तनों के जरिये सभी निर्यातों हेतु एक समेकित आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 3ड. में उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन छह महीनों के आधार पर यानी अप्रैल-सितम्बर और अक्टूबर-मार्च को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जहाँ वसूली आवेदन अवधि के दौरान की गई है। अग्रिम भुगतान (और उन मामलों में जहाँ प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 का पैरा 3.23.3 लागू होता है) के मामले में निर्यातों की तारीख को आवेदन की अवधि में शामिल करने हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

शुल्क क्रेडिट का दावा करने हेतु आवेदक को आवेदन की अवधि के अंत से छह महीनों की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा। (अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2007 अवधि के लिए, अन्तिम तारीख मार्च, 2008 अवधि के लिए अन्तिम तारीख सितम्बर, 2008 होगी)।

चूंकि एफपीएस निर्यात हेतु 1-4-2006 से शुरू की गई है, 1-4-2006 से निर्यात हेतु लाभ प्रदान करने के लिए आवेदनों पर निम्नानुसार विचार किया जाएगा:-

- (क) अप्रैल-सितम्बर, 2006 अवधि हेतु आवेदन के संबंध में आवेदन दायर करने की अन्तिम तारीख 31 मार्च, 2008 होगी। यह केवल उन पोत लदानों पर लागू होगा जिनका निर्यात 1-4-2006 को या उसके बाद किया गया है किन्तु जिनके लिए वसूली 30-09-2006 तक प्राप्त हुई है।
- (ख) अक्टूबर-मार्च, 2007 अवधि हेतु आवेदन के संबंध में आवेदन दायर करने की अन्तिम तारीख 31 मार्च, 2008 होगी। यह उन सभी पोत लदानों पर लागू होगा जिनका निर्यात 1-4-2006 को या उसके बाद किया गया है किन्तु जिनके लिए वसूली 31-03-2007 तक प्राप्त हुई है।

निर्यातक केवल एक अनुपूरक दावा दायर कर सकता है यदि अप्रैल-सितम्बर और अक्टूबर-मार्च अवधि हेतु मूल दावे में कुछ पोतलदान शामिल नहीं किए गए हैं। इससे दावा की गई धनराशि पर अनुपूरक कटौती लगेगी यह सुनिश्चित करने के बाद पोतलदान पूर्व दावे में शामिल नहीं किया गया है। यदि अनुपूरक दावा देर से किया जाता है तो विलम्ब कटौती नहीं लगाई जाएगी। यह उन निर्यातों पर भी लागू होगा जो 1-4-2006 को किए गए हैं।

3.21.2 सीधे के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा निर्यातों हेतु, निर्यात दस्तावेज यानी निर्यात आदेश, बीजक, जी आर फार्म, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र केवल आवेदक के नाम में होने चाहिए।

3.21.3 आवेदक को निर्धारित बाजार में निर्यात खेप पहुँचाने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

3.21.4 हटा दिया गया है।  
से 3.21.8

3.22 उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम

3.22.1 विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम संबंधी नीति दी गई है। अधिसूचित उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद परिशिष्ट 37ड. में सूचीबद्ध है।

3.22.2 उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम के अधीन शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रदान करने के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 3 च में निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। चालू

- लाइसेंसिंग वर्ष 2007-08 के दौरान निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने के लिए आवेदन चालू लाइसेंसिंग वर्ष की समाप्ति पर 12 महीनों की अवधि के भीतर दायर किए जाएंगे।
- 3.23 संवर्धन स्कीमों के लिए सामान्य प्रक्रियात्मक विशेषताएँ इस अध्याय में सभी स्कीमों पर लागू है अन्यथा विशेष रूप से उपलब्ध कराया गया है।
- आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी 3.23.1 आवेदक को आई ई सी पर पृष्ठांकित नेगमिक कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, शाखा कार्यालय के पते के आधार पर आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारी को चुनने का विकल्प होगा। तथापि, एक बार विकल्प चुनने के बाद दोबारा परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- 3.23.2 इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 2, 9 में शामिल प्रावधान सभी संवर्धन स्कीमों पर लागू होंगे।
- अपरिवर्तनीय साख पत्र 3.23.3 उस मामले में जहाँ आवेदक अपरिवर्तनीय साख पत्र (या विनिमय बिल जिसको बैंक द्वारा बिना शर्त उपयोग/सह-स्वीकृति/प्रतिभूति दी गई हो) के मद्दे शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन करता है और इसकी पुष्टि और सत्यापन निर्यातक बैंक द्वारा संगत निर्यात और वसूली बैंक प्रमाण पत्र में की जाती है कि निर्यात आय का भुगतान वसूल किया गया मान लिया जाएगा।
- पंजीकरण का पत्तन 3.23.4 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (अलग-अलग समेत) आवेदक की पसन्द के अनुसार पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा। पंजीकरण से पूर्व प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की सत्यता का सत्यापन करेगा जब तक कि मैसेज एक्सचेंज का ई डी आई सिस्टम लग नहीं जाता।
- तथापि, आवेदक पंजीकरण के पत्तन पर प्राधिकारियों से टी आर ए प्राप्त करने के बाद किसी अन्य पत्तन से (जिसमें आई सी डी/एल सी एस) आयात हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग कर सकता है।
- विभाजित स्क्रिपों हेतु सुविधा 3.23.5 आवेदन के समय अनुरोध पर विभिन्न पंजीकरण पत्तनों सहित न्यूनतम 5 लाख रुपये और उसके गुणकों की शर्त के अधीन विभाजित शुल्क क्रेडिट स्क्रिप भी जारी की जा सकती है। प्रत्येक विभाजित प्रमाण पत्र के लिए 1000/- रुपये का शुल्क अदा करना होगा। जारी होने के बाद विभाजन का अनुरोध उसी पंजीकरण के पत्तन पर अनुमित होगा जैसाकि मूल स्क्रिप में दिया गया है।
- प्राइवेट/पब्लिक बाण्डिड गोदाम से आयात 3.23.6 विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.28 और राजस्व विभाग अधिसूचना की शर्तों एवं निबंधनों की पूर्ति के अधीन प्राइवेट/पब्लिक बाण्डिड गोदाम से आयात के लिए हकदारी का उपयोग किया जा सकता है।

खराब/अनुपयुक्त  
माल का पुनः निर्यात

3.23.6

आयात किया गया माल जो खराब या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है उसका राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। जहाँ आयात के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग किया गया है उन मामलों में सीमा शुल्क उपयोग की गई स्क्रिप, पुनः निर्यातित माल के आयात की तारीख और ऐसे माल का आयात करते हुए नामे डाली गई धनराशि का ब्यौरा देने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर, आवेदन पर, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नामे डाली गई धनराशि की 98 प्रतिशत की सीमा तक पंजीकरण के समान पत्तन और खराब/अनुपयुक्त माल के आयात की तारीख को शेष उपलब्ध अवधि के समतुल्य अवधि हेतु वैध एक स्वच्छ स्क्रिप जारी की जाएगी।

वैधता अवधि एवं  
पुनर्वैधीकरण

3.23.7

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 24 महीनों की अवधि के लिए वैध होगी। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

## अध्याय-चार

### शुल्क मुक्त/छूट स्कीम

- |                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| नीति             | 4.1   | नीति के अध्याय-4 में विनिर्दिष्ट शुल्क मुक्त/शुल्क छूट स्कीम संबंधी नीति दी गई है।   |
| सामान्य प्रावधान | 4.2   | अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र डी एफ आर सी/डी ई पी बी/ डी एफ आई ए हेतु आवेदन, पात्र निर्यातक के पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को किया जा सकता है।  |
|                  | 4.3   | जहाँ निर्यातक, शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट (यूनिटें) का आवेदक है, वह वैध आर सी एम सी की स्वतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा जहाँ शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट का नाम दिया गया है।   |
| अग्रिम           | 4.4   | जहाँ मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड प्रकाशित कर दिए गए हैं, 'आयात प्राधिकार पत्र निर्यात प्रपत्र' 4क में आवेदन निर्धारित दस्तावेज, सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएँगे।  |
|                  | 4.4.1 | स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा इनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के मामले में, मात्रा, अपशिष्ट तथा मूल्य संवर्धन मानदण्ड, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) और विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 क के अनुसार होंगे।   |
|                  | 4.4.2 | उन मामलों में, जहाँ मानदण्ड प्रकाशित नहीं किए गए हैं, मानदंडों के निर्धारण के लिए आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) में सम्बंधित मानदंड समिति को प्रस्तुत करना होगा।<br><br>ऐसे मामलों में, आवेदन की मूल प्रति के साथ निर्धारित शुल्क संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को देना होगा जिसकी एक स्व सत्यापित प्रति मानदंड समिति को देनी होगी। ऐसे मामलों में मानदंड समिति की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएँगे।<br><br>मानदण्ड समिति मानक निवेश-उत्पादन मानदंडों हेतु सिफारिशी प्राधिकारी के तौर पर भी कार्य करेगी। महानिदेशक, विदेश व्यापार ऐसे मानदंडों को अधिसूचित करेंगे। |
|                  | 4.4.3 | जहाँ आयात के लिए निविष्टि के रूप में ऐसेटिक एनहाइड्राइड, इफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन की अपेक्षा है, ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाएँगी।  |



ऐसे आवेदनों की प्रतियाँ भारत के औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली, स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित जोनल निदेशक को भी पृष्ठांकित करनी होगी जिसके साथ यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक रिकार्डों का रखरखाव करेगा और निर्धारित रिकार्ड/विवरणियाँ भी प्रस्तुत करेगा।

- 4.4.4 क्षेत्रीय प्राधिकारी जब एसेटिक एनहाईड्राइड, इफेड्राइन और स्यूडो इफेड्रिन के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करेगा तो वह यह शर्त पृष्ठांकित करेंगे कि आयात करने से पूर्व, भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली और संबंधित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक को भी पृष्ठांकित करेगा।
- 4.4.5 हटा दिया गया है।
- अधिक यूनितों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र 4.5 विनिर्माण प्रयोजन हेतु एक कंपनी की यूनित से दूसरी कंपनी को अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे प्राप्त या आयातित किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना के तहत, स्पष्ट करते हुए कि ऐसे हस्तांतरित निविष्टियों पर कोई सेनवेट लाभ का दावा नहीं किया जाएगा, हस्तांतरण किया जाएगा। उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त कम्पनी/उत्पाद के मामले में, यूनित को इसका सही रिकार्ड रखना होगा। तथापि, सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसी सभी यूनितें आई ई सी प्रमाण-पत्र में उपलब्ध होनी चाहिए और जाब वर्क के लिए केन्द्रीय उत्पाद के नियमों और विनियमों का पालन करेगी। बड़ी करदाता यूनितें जिनकी बहुत यूनितें हैं उन्हें निर्यात दायित्व पूर्ति के बाद उपर्युक्त जाब वर्क प्रक्रिया नहीं अपना सकती हैं।
- निःशुल्क और भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र 4.6 पैरा 4.1.8 में नीति हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र के विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति पर विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा जिसमें निःशुल्क सप्लाई किए गए माल के प्रति शुल्क वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी आयातित निवेशों को वेस्टेज के अलावा उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा।
- जहाँ मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड विद्यमान नहीं है वहाँ स्वघोषित प्राधिकार पत्र 4.7 जहाँ मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, वहाँ मानदंड समिति द्वारा निर्धारित तदर्थ/मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के अनुसार अंतिम समायोजन के लिए आवेदक के स्वघोषणा और वचनबद्धता के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र भी जारी कर सकता है।

तथापि, निम्नलिखित उत्पादों के आयात के लिए इस पैराग्राफ के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा :-

- (I) अध्याय-15 के तहत वर्गीकृत सभी सब्जियाँ/खाद्य तेल और

आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-12 के तहत वर्गीकृत बीजों के तेल की सभी किस्में;

(II) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-10 के तहत वर्गीकृत अनाजों की सभी किस्में

(III) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-9 और 12 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क वाले सभी मसाले, हल्की काली मिर्च (लाइट बेरिज) को छोड़कर;

(IV) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-7 और अध्याय-8 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क वाले फलों/सब्जियों की सभी किस्में।

(V) सींग, खुर और जानवर का कोई अन्य अंग।

निर्यात के लिए इत्र, इत्र संयोजकों और विभिन्न भोज्य अवयवों जिनमें विटामिन निहित हों, क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आवेदक उपर्युक्त पैरा 4.4.2 के तहत आवेदन कर सकता है। जहाँ जैव तकनीकी मदों का निर्यात और/या आयात शामिल है, इस पैराग्राफ के तहत केवल जैव तकनीकी विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

हकदारी

4.7.1

एक या अधिक ऐसे लाइसेंसों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य स्तर धारकों के मामले में पिछले वर्ष के निर्यात/या आपूर्ति का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य और/अथवा रेल पर्यन्त शुल्क मूल्य का अधिकतम 500 प्रतिशत होना चाहिए और अन्यो के लिए पिछले वर्ष निर्यात और/या आपूर्ति के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य और/या रेल पर्यन्त निशुल्क का 5 करोड़ रूपए अथवा 500 प्रतिशत होना चाहिए, जो भी ज्यादा है।

तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ मानदंड समिति ने पैरा 4.7 के तहत प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में उसी निर्यात और आयात उत्पाद हेतु मानदंडों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है, ऐसे मानदंड अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु वैध होंगे।

"तदर्थ मानदंड निर्धारित" श्रेणी के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाएँगे तथा ऐसे मामलों में आवेदन की प्रतियाँ मानदंडों के निर्धारण/ अनुमोदन हेतु मानदंड समिति को भेजने की जरूरत नहीं होगी।

ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र धारक मानदंड समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार और अधिक प्राधिकार पत्रों हेतु पात्र होगा और मानदंड समिति द्वारा बाद में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में आवेदक तदर्थ मानदंड निर्धारित श्रेणी के तहत आवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, मानदंड समिति को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे तदर्थ मानदण्ड, यदि पहले से अधिसूचित नहीं है तो, ऐसे तदर्थ मानदण्डों के अनुमोदन के छः माह के बाद एक माह की अवधि के भीतर अधिसूचित हो।

4.7.2 मानदंड समिति द्वारा मानदण्ड निर्धारित करने के बाद उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित मूल्य सीमाएँ, इस पैरा के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर लागू नहीं होगा। ऐसे प्राधिकार पत्र, मानदंड समिति द्वारा मानदण्डों के निर्धारण के बाद तक बढ़ाए जा सकते हैं। मानदण्ड निर्धारित करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय/ईपीसी द्वारा जैसा आवश्यक हो, उद्योग के लिए उत्पादन डाटा आदि प्रदान करना अनिवार्य है। अन्यथा, आवेदक को स्वघोषणा आधार पर पुनः अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

हकदारी से अधिक  
प्राधिकार पत्र

4.7.3 आवेदक सीमाशुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी प्रस्तुत करके पैरा 4.7.1 में उल्लिखित हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र हेतु हकदार होगा। प्राधिकार पत्र पर इस आशय का विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा।

आवेदन

4.7.4 निर्धारित दस्तावेजों सहित मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर, मानदण्डों के निर्धारण के लिए मानदंड समिति को आवेदन पत्र की एक प्रति ऐसे प्राधिकार पत्र के जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर भेजेगा।

वचनबद्धता

4.7.5 आवेदक यह वचनबद्धता देगा कि वह मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेगा तथा तदनुसार मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपयोग में न लाए गए निविष्टियों पर ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करेगा। तथापि, प्राधिकार पत्र धारी के पास अतिरिक्त अनुपुक्त निविष्टि के अनुपात में अतिरिक्त निर्यात दायित्व का विकल्प होगा। यदि मानदंड समिति द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो प्राधिकार पत्र धारक यथा अधिसूचित आयातित निविष्टियों पर बचाए गए सीमा शुल्क का, ब्याज सहित भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए पैरा 4.28 (i) (ख) के अनुसार धनराशि जमा करानी होगी।

4.7.6 ऐसे मामलों में, जहाँ मानदंड समिति द्वारा प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 4 माह के भीतर मानदण्डों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, वहाँ यथा आवेदित मानदण्डों को अंतिम माना जाएगा और कोई समायोजन

नहीं किया जाएगा। तथापि, जिन मामलों में अपेक्षित दस्तावेज/ सूचना न देने के कारण तदर्थ/मानक मानदण्डों के निर्धारण के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, वहाँ प्राधिकार पत्र धारी को उपर्युक्त पैरा के दर्शाए गए अनुसार अर्थदण्ड देना होगा। यदि कथित उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अधिसूचित है, तो मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अपशिष्ट मानदण्ड और निर्यात दायित्व निश्चित करने के प्रयोजन हेतु लागू कर दिए जाएंगे।

मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के निर्धारण से पूर्व पूरे किए गए निर्यात दायित्व के मामलों में, पैराग्राफ 4.7.1 में यथा उल्लिखित प्राधिकार पत्र की हकदारी विगत लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण (शिपिंग बिल/निर्यात बिल की प्रतियाँ/बीजकों की केन्द्रीय उत्पाद प्रमाणित प्रतियाँ) प्रस्तुत करने पर पुनः उनके खाते में डाली जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में मानदंडों के निर्धारित होने तक बांड मुक्त करने/बांड निष्क्रीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### वित्तीय शक्तियाँ

4.8

क्षेत्रीय प्राधिकारी और मानदंड समिति की वित्तीय शक्तियाँ नीचे सारणी में दी गयी हैं :-

प्रकाशित मानदण्डों और प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.7 के तहत

#### क्षेत्रीय प्राधिकारी

विदेश व्यापार महानिदेशालय, मुख्यालय (सिओन मामले) /मानदंड समिति (तदर्थ मानदंड मामले) की सिफारिश पर क्षेत्रीय प्राधिकारी

#### आवेदन की श्रेणी

पेट्रोलियम/पेट्रो रसायन  
उत्पाद और वार्षिक  
आवश्यकताओं हेतु  
अग्रिम प्राधिकार पत्र

अन्य

पेट्रोलियम/पेट्रो रसायन  
उत्पाद और वार्षिक  
आवश्यकताओं हेतु  
अग्रिम प्राधिकार पत्र

अन्य

#### प्राधिकार पत्र का लागत बीमा भाड़ा मूल्य

500 करोड़ रुपये तक

100  
करोड़  
रुपये तक

500 करोड़ रुपये या अधिक

100  
करोड़  
रुपये  
या अधिक

#### तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण

4.9

मानदण्डों के मानकीकरण के लिए, सहायक विनिर्माता से जुड़े व्यापार-निर्यातक अथवा विनिर्माता निर्यातक द्वारा बाकायदा सम्पूर्ण आंकड़ों सहित आवेदन किया जा सकता है। ऐसे आवेदन 'आयात निर्यात प्रपत्र' 4ग में मानदंड समिति को किए जा सकते हैं।

मानदंड समिति द्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत भी ईंधन के आयात की अनुमति भी दी जा सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :-

- (क) ईंधन के आयात की सुविधा केवल कैप्टिव पावर प्लांट वाले विनिर्माताओं को दी जायेगी।
- (ख) उन मामलों में जहाँ ईंधन को विशिष्ट तौर पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत अनुमति है, उसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी। तथापि, मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड के तहत यदि ईंधन की अनुमति नहीं है, मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए सामान्य ईंधन नीति के अनुसार ईंधन की अनुमति दी जाएगी या उपर्युक्त पैरा 4.7 के तहत अनुमति दी जाएगी।
- (ग) ईंधन की केवल वास्तविक प्रयोक्ता प्राधिकार पत्र के प्रति अनुमति होनी चाहिए। तथापि डी एफ आर सी के मामले में, ईंधन केवल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मार्केटिंग अधिकार प्राप्त एजेंसियों को हस्तांतरित किया जा सकता है।
- (घ) हटा दिया गया है।
- (ड.) नये क्षेत्रों के लिए ईंधन हकदारी के निर्धारण के लिए तथा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) में ईंधन हेतु सामान्य टिप्पणी के अनुसार मौजूदा हकदारी के संशोधन के लिए आवेदन, “ईंधन दर के लिए डाटा शीट” से सम्बन्धित आयात निर्यात प्रपत्र 4घ में अपेक्षित डाटा सहित मानदंड समिति को किया जाएगा।

मानक निविष्टि उत्पादन 4.10 सहायक विनिर्माता से जुड़े विनिर्माता निर्यातक और व्यापार-निर्यातक द्वारा मानदंड समिति के समक्ष ‘आयात निर्यात प्रपत्र’ 4इ. में मौजूदा मानक निविष्टि-उत्पाद मानकों में संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

निर्यात मद और निविष्टि का संशोधन 4.10.1 सिओन अथवा तदर्थ मानदण्ड के अन्तर्गत निर्यात मद अथवा निवेशों के संशोधन हेतु कोई भी विनिर्माता अथवा व्यापारी निर्यातक ‘आयात निर्यात प्रपत्र’ 4च के अनुसार आवेदन कर सकता है।

आवेदक को संशोधन हेतु औचित्य भी बताना होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पास विचार हेतु कार्यालय प्रमुख के विशेष अनुमोदन के साथ भेजेगा। निविष्टि में किसी मुख्य परिवर्तन अथवा तदर्थ मानदण्ड अथवा सियोन के तहत अनुमत अधिक वेस्टेज के लिए आवेदन के मामले में इसे पुष्टि के लिए मानदंड समिति को भेजा जाएगा।

एन.सी. द्वारा शिपान का संशोधन 4.10.2 मानदंड समिति ऐसे शिपानों की पहचान करेगी, जिनमें उसके विचार से पुनरीक्षण की आवश्यकता है। निर्यातकों को ऐसे पुनरीक्षण के लिए दिए गए आयात निर्यात फार्म 4छ में संशोधित डाटा देना होगा। उद्योग/निर्यातक के लिए यह अनिवार्य है कि शिपान के पुनरीक्षण के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय/ईपीसी को आवश्यक उत्पादन और खपत के

आँकड़े आदि उपलब्ध करवाएँ। अन्यथा, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

अग्रिम प्राधिकार  
पत्र का विवरण

4.11

अग्रिम प्राधिकार पत्र में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया जायेगा :-

- (क) आयात और निर्यात/आपूर्ति की जानेवाली मदों का नाम और विवरण;
- (ख) आयात की जानेवाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा जहां कहीं मात्रा नहीं बताई जा सकती, मद का मूल्य बताया जाएगा। तथापि, यदि मानक निवेश उत्पादन मानदंड में प्रत्येक निवेशों की मात्रा और मूल्य सीमित कारक है तो वह स्वीकार्य होगा;
- (ग) आयातों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य और
- (घ) निर्यात/आपूर्तियों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा।

प्राधिकार पत्र की  
प्रत्याशा में निर्यात

4.12

अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए ई डी आई द्वारा तैयार फाइल संख्या करने की तारीख से किए गए निर्यात/ आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार की जाएंगी। जारी प्राधिकार पत्र के साथ निर्यातों/आपूर्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए फाइल संख्या अथवा प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पोत/आपूर्ति दस्तावेज पृष्ठांकित करना चाहिए। यदि आवेदन अनुमादित हो, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रभावी निवेश/उत्पादन मानदंडों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा, जो कि मानदंडों में किसी भी संशोधन के अधिसूचित होने तक किए गए अन्तरिम निर्यात/आपूर्तियों के अनुपात में होगा। निर्यात के शेष हिस्से के लिए, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति/ प्रक्रिया लागू होगी।

4.12.1

अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलने की प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्तियाँ पूर्णतः निर्यातक की जिम्मेवारी और जोखिम होगी।

4.12.2

क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन का मामला संशोधित अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा शुल्क मुक्त शिपिंग बिलों से शुल्क वापसी बिलों में परिवर्तन की भी अनुमति दी जा सकती है।

अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु  
अग्रिम प्राधिकार पत्र  
अथवा डीएफआर सी  
अथवा डीएफआईए

4.13

अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस अथवा डीएफआईए की मंजूरी के लिए आवेदन, अग्रिम लाइसेंसधारी अथवा डीएफआईए निर्यातक (वास्तविक/मान्य) के साथ पारस्परिक करार के आधार पर दिया जा सकता है। ऐसे अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस, अथवा डीएफआईए अन्तरवर्ती निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई मदों के सीधे आयात के लिए प्राधिकार पत्र को अवैध घोषित करने के बाद जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में, प्राधिकार पत्र-धारक को अवैधीकरण पत्र की एक प्रति दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति मध्यवर्ती संभरक के साथ-साथ मध्यवर्ती संभरक के क्षेत्रीय प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी। ऐसे मामले में, लाइसेंसधारक के पास अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक को अन्तरवर्ती उत्पाद की आपूर्ति करने अथवा सीधे निर्यात करने का विकल्प होगा। तथापि, क्षेत्रीय प्राधिकारियों में इलेक्ट्रॉनिक सन्देश हस्तांतरण की सुविधा पूर्णतया संचालित होने के बाद क्षेत्राधिकार प्राप्त प्राधिकारी अवैधीकरण पत्र/एआरओ की प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार की सुविधा उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए वाले निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करने पर सामग्री की आपूर्ति कर दी है या करना चाहता है जहाँ से अवैधीकरण पत्र जारी किया गया था।

अग्रिम रिलीज आदेश

4.14

स्वदेशी स्रोतों/राज्य व्यापार उद्यमों से निविष्टियों की प्राप्ति के लिए अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ) की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.14.1

आवेदन पत्र में (1) मद का नाम, विवरण और मात्रा, और (2) खरीद की जाने वाली मदों के अलग-अलग मूल्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के साथ अथवा बाद में एक एआरओ जारी किया जा सकता है और इसकी वैधता अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए की वैधता के साथ होगी। अलग-अलग मद की खरीद के लिए जारी अग्रिम रिलीज आदेश स्वतः एक या अधिक स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए भी वैध होगा।

बैंक टू बैंक अन्तरदेशीय  
साखपत्र (एल सी)

4.15

निर्यातक, बैंक से प्राप्त बैंक टू बैंक अन्तरदेशीय साख पत्र की सुविधा का बारी-बारी से लाभ उठा सकता है। अग्रिम लाइसेंस धारक/ डीएफआरसी/ डीएफआईए धारक, स्वदेशी संभरक के पक्ष में अन्तरदेशीय (एल सी) साखपत्र खोलने हेतु बैंक के पास जा सकता है।

4.15.1

एल.सी. खोलने से पूर्व, बैंक सुनिश्चित करेगा कि अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/डीएफआईए के वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा आवश्यक बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन कर दिया गया है तथा प्राधिकार पत्र पर उसका पृष्ठांकन कर दिया गया है।

तथापि, डी एफ आर सी या हस्तांतरणीय या डी एफ आई ए के प्रति बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता आवश्यक नहीं होगा। अन्तरदेशीय साखपत्र

खोलने के बाद, बैंक, प्राधिकार पत्र/ डीएफआरसी/डीएफआईए के इक्सचेन्ज कन्ट्रोल और सीमाशुल्क की प्रति पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा:-

अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डी एफ आर सी /डी एफ आई ए मूल्य.....रुपये कम हो गया है, क्योंकि लाइसेंसधारक ने मैसर्स..... (स्वदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) के पक्ष में आज इतने ही मूल्य पर अन्तरदेशी साखपत्र संख्या .....खोल दिया है।”

- 4.15.2 स्वदेशी रूप में प्राप्त की जा रही मद की मात्रा और मूल्य के संबंध में केवल सीधे आयात हेतु बैंक द्वारा प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र को अवैध किया जायेगा।
- 4.15.3 बैंक द्वारा परक्रामण के लिए मूल साख पत्र रख लिया जाएगा तथा साखपत्र की केवल गैर-परक्रामण प्रति स्वदेशी संभ्रक को दी जायेगी।
- 4.15.4 पृष्ठांकन करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। जब लाइसेंसधारी बैंक से पृष्ठांकन के लिए अनुरोध करता है तो उसके द्वारा दिया गया कोई गलत विवरण या मिथ्या कथन के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में बैंक द्वारा खोला गया अन्तरदेशीय साख पत्र चाहे कुछ भी कारण हो, रद्द नहीं किया जाएगा।
- 4.15.5 बैंक द्वारा विधिवत पृष्ठांकित अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/डीएफआईए की फोटो प्रति सहित अन्तरदेशीय साख पत्र की गैर परक्रामण प्रति स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के लिए मान्य निर्यात लाभों के दावे के लिए पर्याप्त होंगी। तथापि, डी एफ आर सी के मद्दे जारी साख पत्र नीति के पैरा 8.3 (ख) में निर्दिष्ट लाभ पाने का पात्र होंगे, जबकि अन्य श्रेणियों के साख पत्र विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 (ख) और (ग) में निर्दिष्ट लाभ पाने के पात्र होंगे।
- 4.15.6 जहाँ इस स्कीम के अधीन, निविष्टि के रूप में स्वर्ण/चाँदी का आयात अनुमेय है, वहाँ ऐसी स्वर्ण/चाँदी को इस कार्य के लिए जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आर सी/ डी एफ आई ए के मद्दे आपूर्ति के लिए नीति के अध्याय-4 में पैराग्राफ 4क के बाद उल्लिखित नामित एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सामग्री की आपूर्ति से पूर्व, नामित एजेंसियाँ उपर्युक्त पैरा 4.15.1 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगी।

सह-विनिर्माताओं/  
जाबकर्त्ता/सह प्राधिकार  
पत्र की सुविधा

- 4.16 आयातित माल अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक या डी एफ आई ई प्रमाण पत्र धारक या जाबकर्ता सहविनिर्माता के किसी भी एकक में प्रयुक्त हो सकता है बशर्ते कि उसका पृष्ठांकन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र में किया गया है। यदि आवेदक किसी विनिर्माता अथवा जाबकर्ता का नाम प्राधिकार



पत्र में जोड़ना चाहता है, वह ऐसे पृष्ठांकन के लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ अग्रिम लिए निर्यात से पहले पूर्व निर्यात एक शर्त है प्राधिकार/डीएफआईए स्कीम और प्राधिकार पत्र धारक किसी अन्य विनिर्माता अथवा जाबकर्ता के जरिए सामग्री संसाधित करवाना चाहता है, वहाँ ऐसा पृष्ठांकन अनिवार्य होगा।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किए गए पृष्ठांकन पर, प्राधिकार पत्र धारक और प्राधिकार पत्र धारक संयुक्त रूप से और भिन्न रूप से निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सह-प्राधिकार पत्र धारक में से कोई एक माल का आयात अपने नाम अथवा संयुक्त नाम से कर सकता है। उनके संयुक्त नाम में बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता भी प्रस्तुत की जाएगी।

तथापि, यदि प्राधिकार पत्र धारक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत है, तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र के पृष्ठांकन के बदले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा जाबकर्ता के नामों को प्राप्त करने का विकल्प होगा। ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार पत्र धारक विनिर्माता निर्यातक केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं है/पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, सहायक विनिर्माता के नाम के पृष्ठांकन के बिना जाब वर्क की अनुमति होगी। तथापि प्राधिकार पत्र धारक आयातित मर्चों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

यदि बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता विमुक्त कर दी गयी है, तो अग्रिम प्राधिकार प्रमाणपत्र धारक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के तहत निर्धारित जाब कार्य विनियमन के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन किसी विनिर्माता से शुल्क मुक्त निविष्टियों का संसाधन करा सकता है। तथापि, हस्तान्तरणीय डी एफ आई ई प्रमाणपत्र के मामले में ऐसे प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

सह - लाइसेंसधारक  
की सुविधा 4.17

हटा दिया गया है।

बैंक गारंटी/विधिक  
वचनबद्धता की स्वीकार्यता 4.18

प्राधिकार पत्र जारी करते समय, आवेदक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को 'आयात निर्यात प्रपत्र' में दी गई वचनबद्धता की स्वीकार्यता को अग्रिम प्राधिकार पत्र के पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा। प्राधिकार पत्र धारक प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.20 की शर्तों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन करेगा।

पंजीकरण का पत्तन 4.19

अग्रिम प्राधिकार पत्र नीचे विनिर्दिष्ट किसी एक बंदरगाह या वायुपत्तन अथवा आई सी डी अथवा एल सी एस के माध्यम से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा। प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार में विनिर्दिष्ट पत्तन के साथ प्राधिकार पत्र को पंजीकृत करेगा और उसके बाद

उस प्राधिकार पत्र के प्रति सभी आयातों को तब तक केवल उसी पत्तन से करेगा जब तक कि वह उस पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी से किसी दूसरे विशिष्ट पत्तन के माध्यम से आयात करने की अनुमति नहीं ले लेता। तथापि, निर्यात किसी भी एक विनिर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है।

समुद्र पत्तन: मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, काकीनाड़ा, कांदला, मंगलौर, मरमागाँव, चैन्नई, न्हावशेवा, पाराद्वीप, पिपवाव, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, दहेज, नागपत्तनम, ओखा, मुद्रा और सूरत (मगडाला) जामनगर, न्हावशेवा।

वायु पत्तन : अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर, एयर कार्गो परिसर, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, नागपुर और चेन्नई।

आई सी डी: आगरा, बंगलौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहाटी (अमीनगाँव), गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पित्तमपुर (इंदौर), सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रुद्रपुर (नैनीताल), दिधी (पुणे), बदोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वलूज (औरंगाबाद), अनापार्थी, सलेम मल्लनपुर, सिंगनालूर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी, मदुरै, बीलवाड़ा, पाण्डिचेरी, गढ़ी हरसरु, भटिण्डा, दम्पर, छेहराता (अमृतसर), करूर, मिराज, रेवाड़ी, भूसावल, जमशेदपुर, सूरजपुर, दादरी और तूतीकोरिन।

एल सी एस: रानाघाट, सिंहबाद और रक्सोल, जोगबनी, नवतनवा (सोनौली), पेटरापोल, महादीपुर, हिली, चेंगराबन्दा दाबकी और अटारी।

एस ई जैड: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई बी एस ई जैड आयात एवं निर्यात के लिए निर्दिष्ट पत्तन हो सकता है।

4.19.1 सीमाशुल्क आयुक्त, किसी अन्य समुद्री पत्तन/वायु पत्तन/आई सी डी या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन से भी आयात-निर्यात की अनुमति दे सकता है।

4.19.2 उन मामलों में, जहां प्राधिकार पत्र में (प्राधिकार पत्र में) निर्दिष्ट पत्तन पर पंजीकरण नहीं हुआ है और आयात नहीं हुआ है, तो पंजीकरण के पत्तन में परिवर्तन हेतु आवेदन पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा बशर्ते प्राधिकार पत्र को विमुक्त न किया गया हो।

- 4.19.3 पंजीकरण पत्तन के अलावा किसी वायु पत्तन/समुद्री पत्तन/आई सी डी/एलसीएस से आयात के लिए पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी को टेलीग्राफिक रिलीज सलाह (टी आर ए) भी जारी किया जाएगा।
- मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा 4.20 मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा सिर्फ मामलों की विमुक्ति/विनियमन के लिए उपलब्ध होगी और आगे कोई आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं होगी। इस सुविधा के लिए विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए भी सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता है। तथापि, 2004-2009 अवधि में जारी प्राधिकार पत्रों के मामले में, विभिन्न सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलाए जा सकते हैं।
- 4.20.1 क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिनके कार्यक्षेत्र के अधीन प्राधिकार पत्र जारी किया गया है अथवा अन्य मामलों में ए एल सी, एक से अधिक शुल्क मुक्त, अग्रिम प्राधिकार पत्र के आयात और निर्यात को मिलाने के अनुरोध पर भी विचार कर सकती है बशर्ते कि आयातित निवेश का उचित आकलन मानदण्डों के अनुसार किया गया है। इस प्रकार मिलाए गए प्राधिकार पत्रों का मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया में निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन अलग-अलग प्राधिकार पत्र पर लगाए गए मूल्य संवर्धन का औसत होगा। मिलाने के बाद सभी प्रयोजनों के लिए इन प्राधिकारों को एक प्राधिकार माना जाएगा। और इसके बाद कमी, यदि कोई है प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4.28 की शर्तों के अनुसार नियमित होगी।
- 4.20.2 वार्षिक आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्राधिकार सहित अग्रिम प्राधिकार की अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित आयातों और निर्यातों के उत्तरदायित्व को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- 4.20.3 सिर्फ अग्रिम प्राधिकार के लिए सुविधा उपलब्ध होगी जहाँ निर्यात दायित्व के पूरा करने में कमी है और जो आयात के लिए वैध अग्रिम प्राधिकार के साथ जोड़ा जाना अपेक्षित है। निर्यात दायित्व की कमी के साथ समाप्त प्राधिकार के लिए और आयात के लिए वैध अग्रिम प्राधिकार के साथ जोड़े जाने के लिए आवेदक पैराग्राफ 4.22 के अनुसार निर्यात दायित्व की अवधि विस्तार के लिए संयोजन शुल्क अदा करेगा।
- 4.20.4 जहाँ कहीं पहले के प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व विस्तार अवधि के (नीचे 4.22 के अनुसार अनुमत) बाद निर्यात किए गए हैं वहाँ उन्हें मिलाने (क्लबिंग) की अनुमति नहीं होगी।
- 4.20.5 उपर्युक्त पैरा 4.20.3 और 4.20.4 के प्रावधानों के बावजूद, सभी समाप्त प्राधिकारों को मिलाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सम्पन्न प्राधिकार

एग्जिम नीति अवधि 1 अप्रैल, 1992 से 31 अगस्त, 2004 के मध्य जारी किए गए हों। तथापि, पूर्व मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्राधिकार पत्र के  
मूल्य में वृद्धि/कमी

4.21

अग्रिम प्राधिकार के संबंध में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (उनकी वित्तीय शक्तियों के अनुसार), (क) प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी (ख) लागत बीमा भाड़ा मूल्य में निविष्टियों की मात्रा, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और अग्रिम प्राधिकार पत्र के निर्यात की मात्रा वृद्धि/कमी के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से कम नहीं आता तथा निविष्टि उत्पाद मानदण्डों और विदेश व्यापार नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया हो। जिसके अनुसार प्राधिकार जारी किया गया था।

4.21.1

हटा दिया गया है।

4.21.2

मूल्य और मात्रा में यथानुपातिक वृद्धि हेतु आवेदन निर्यात से पूर्व या बाद में किया जा सकता है। उन मामलों में जहाँ उक्त उत्पाद के निर्यात से पूर्व मानक निवेश उत्पादन मानदंडों में परिवर्तन किया गया हो, संशोधित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों पर हकदारी की गणना करने के बाद यथानुपातिक वृद्धि प्रदान की जाएगी।

4.21.3

प्राधिकार पत्र के मूल्य में वृद्धि /कमी के लिए, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के 'आयात निर्यात प्रपत्र' 4ज में आवेदन किया जाएगा।

वृद्धि के लिए  
आवेदन शुल्क

4.21.4

वृद्धि के लिए लगने वाले आवेदन शुल्क पर मूल और अन्तिम प्राधिकार के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अन्तर पर लगेगी। तथापि, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि प्राधिकार पत्र के मूल्य को कम किया जाए अथवा आवेदक ने अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए मूल आवेदन के साथ अधिकतम शुल्क क्रमशः 150,000 रुपये (व्यक्तिगत तौर पर आवेदन के लिए) और 75,000 रुपये (डिजिटली हस्ताक्षरित आवेदनों के लिए) जमा किए हैं।

निर्यात दायित्व अवधि  
और इसका विस्तार

4.22

अग्रिम प्राधिकार के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार जारी करने की तारीख से आरम्भ होगी। मान्य निर्यात श्रेणी के अन्तर्गत भारत/विदेश में परियोजना/टर्नकी परियोजनाओं को आपूर्तियों के मामले को छोड़कर 24 महीनों की अवधि के भीतर निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा, जहाँ संविदा अवधि के दौरान निर्यात दायित्व पूरा किया जाए। मसालों के मामले में निर्यात के लिए {निर्यात और आयात मर्दों के वर्गीकरण आई टी सी (एच एस) अध्याय 9 में शामिल} निर्यात दायित्व उस तारीख के 90 दिनों के भीतर करना होगा जिस तारीख को

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रथम आयात खेप स्वीकृत की है।

तथापि, V क प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ग्राउन्डिंग/स्टेरलाइजेशन या तेल और ओलियो रेजिन के वे विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में न कि सामान्य साफ सफाई, ग्रेडिंग, री-पैकिंग आदि, निर्यात दायित्व 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

दवाइयों के आयात (विशिष्ट निर्यात आदेश और आयात पूर्व शर्त सहित) और चाय के लिए आयात हेतु निर्यात दायित्व की अवधि 6 महीने होगी।

#### 4.22.1

निर्यात दायित्व में बढ़ोतरी हेतु आवेदन, 'आयात निर्यात प्रपत्र' 41 में दिए जा सकता है। प्राधिकार पत्र के अनुसार सभी अपूर्ण आयातित मर्दों पर बचाए गए संयोजन शुल्क का 2 प्रतिशत भुगतान के साथ निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए एक वृद्धि प्रदान करेगा।

क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा छः महीने के और विस्तार के आवेदन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र के अनुसार सभी अप्रयुक्त आयातित मर्दों पर आधारित शुल्क के 5 प्रतिशत संयोजन शुल्क का भुगतान किया गया हो।

निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की सुविधा अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में अनमत नहीं होगी जहाँ पेसिलीन और उसके लवणों आईटीसी (एचएस) कोड सं0 29411010 और 6-ए.पी.ए (आईटीसी (एचएस) कोड सं0 29411050) की निविष्टि के रूप में आयात की अनुमति दी गई है और साथ ही मसालों और चाय के आयात की अनुमति। क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र में इस आशय का पृष्ठांकन करेगा।

पूर्व मूल्य आधारित अग्रिम प्राधिकार (वी ए बी ए एल एस) और वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार के मामले में ऐसे विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन प्राधिकारों के संबंध में जहाँ क्षेत्रीय प्राधिकारियों की जानकारी में गलत बयानी/धोखाधड़ी देखने में आई है, निर्यात दायित्व की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उन प्राधिकारों के संबंध में जहाँ न्याय निर्णय आदेश पहले से ही जारी कर दिया गया है निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी।

#### 4.22.2

सीमाशुल्क निर्यात प्रेषण की अस्थायी निकासी की अनुमति दे सकता है जब प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व बढ़ाने के लिए आवेदन किये जाने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।

प्राधिकार पत्र का पुनर्वैधीकरण	4.23	क्षेत्रीय प्राधिकारी मूल प्राधिकार पत्र धारक के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं और मूल प्राधिकार की समाप्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण कर सकते हैं। प्राधिकार के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन, आयात-निर्यात फार्म 41 में देना होगा।
दायित्व की मानीटरिंग	4.24	क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है, निर्यात दायित्व की मॉनीटरिंग करने के लिए वह एक मास्टर रजिस्टर में दायित्व प्रारंभ होने और समाप्त होने की तारीख और अन्य विवरणों का उचित रिकार्ड रखेगा। दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकार पत्र धारक, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.25 के अनुसार निर्यात दायित्व को पूरा करने के संबंध में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। तथापि जहाँ शिपमेंट की विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए छः महीने (स्तर प्रमाण-पत्र धारक के मामले में एक वर्ष) देय नहीं है, क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यातों के बैंक प्रमाण-पत्र को जमा न करने और वसूली के लिए कार्यवाही नहीं करेगा बशर्ते कि निर्यात दायित्व को पूरा करने के अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए।
	4.24.1	यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने अथवा संबंधित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्राधिकार पत्र धारक असफल रहता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी आगे प्राधिकार देने की मनाही, प्राधिकार की शर्त तथा वचनबद्धता को लागू करने संबंधी कार्यवाही कर सकता है तथा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकता है।
वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र	4.24 क	<p>(क) ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए पात्र निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को 'आयात निर्यात फार्म' में आवेदन करेंगे। ऊपर दिए गए अग्रिम प्राधिकार पत्रों के सभी प्रावधान निम्नलिखित को छोड़कर लागू होंगे:</p> <p>(i) क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र जारी करते समय ऐसे निविष्टियों के संबंध में तकनीकी विशेषताएँ, गुणवत्ता और विशिष्टिकरणों का उल्लेख करेगा। स्टेनलेस स्टील, कापर एलाय सिंथेटिक रबड़ बीयरिंग्स सॉल्वेंट्स परफ्यूम्स/ आवश्यक तेल/एरोमैटिक्स रसायन, सरफेक्टेंट्स, सम्बद्ध फैब्रिक्स और संगमरमर सहित एलाय स्टील।</p> <p>(ii) छूट प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करने वाले निर्यात उत्पाद समूह के अन्तर्गत आने वाले किसी उत्पाद का निर्यात करने का प्राधिकार पत्र धारक को छूट प्राप्त होगी।</p> <p>(iii) पात्रता हकदारी के भीतर, निर्यातक किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक या अधिक प्राधिकारों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते</p>

पंजीकरण के एक पत्तन के मद्दे उसी उत्पाद समूह के लिए केवल एक प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र की एक बारगी वृद्धि/कटौती उपायुक्त पैराग्राफ 4.21 की शर्तों के अनुसार उपलब्ध होगी।

- (iv) लाइसेंस वर्ष में एक अथवा अधिक प्राधिकारों के प्रति निर्यात दायित्व पूरा होने पर निर्यातक की हकदारी, उस लाइसेंसिंग वर्ष के लिए प्राधिकारों के मद्दे निर्यात दायित्व पूरा होने के बराबर राशि जितना पुनः जीवित मान लिया जाएगा।

(ख) से हटा दिया गया है।

(छ)

4.24(ख) हटा दिया गया है।

निर्यात दायित्व की पूर्ति

4.25 प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व की पूर्ति के समर्थन में ए एन एफ 4जे में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

क (i) से

(iv) हटा दिया गया है।

ख (i) से

(iv) हटा दिया गया है।

निष्क्रियता/बाण्ड  
प्रमाण पत्र रहित

4.26

यदि निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया हो तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी मामले को विमुक्त कर देगा। निष्क्रियता के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी निष्क्रियता पत्र की एक प्रति जिसमें शिपिंग बिल संख्या, तिथि, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जो कि भारतीय रुपये में शिपिंग बिल(बिलों) के अनुसार हो और निर्यात उत्पाद का विवरण पंजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा। डीजीएफटी वेबसाइट पर प्राप्त करने के लिए निर्यात दायित्व पूर्तिप्रमाण पत्र या नो बांड प्रमाणपत्र को जारी होने के तुरन्त बाद क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी महीने के आधार पर इन ब्योरों को डीजीएफटी वेबसाइट पर डालेगा।

निर्यात दायित्व निमुक्ति प्रमाण पत्र (ईओडीसी)/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा बाण्ड वेवर जारी करने के 30 दिन के भीतर बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की विमुक्ति/निरस्तीकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। सामान्यतः बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्क्रियकरण प्राधिकार पत्र धारक के किसी अनुपस्थिति, गलत घोषणा और गलत तथ्यों को बार-बार प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क द्वारा की गई कार्रवाई से प्रभावित नहीं होगी।

इसके अलावा नीचे पैराग्राफ 4.30 में यथा निर्धारित विधिवत भरे गये परिशिष्ट 23 के प्रस्तुत न करने पर या परिशिष्ट 23 में प्रस्तुत और घोषित ब्यौरों के मिथ्या निरूपण, मिथ्या बयानी और गलत तथ्यों को बार-बार प्रस्तुत करने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस धारक के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। विमुक्ति प्रमाणपत्र में इससे सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी एक पृष्ठांकन करेगा।

31.8.2004 तक जारी किए गए लाइसेंसों के लिए संक्रमण व्यवस्था

4.27

31.8.2004 तक जारी वार्षिक जरूरतों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र सहित अग्रिम प्राधिकार पत्र 31-3-2002 को यथा अधिसूचित समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) 2002-2007 (आर ई 2001) के अध्याय-4 एवं प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर ई 2001) के अध्याय-7 क्रमशः में निहित शर्तों के अनुसार अधिशासित किए जाएंगे। निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार और क्लबिंग से सम्बंधित केवल उस प्रावधान को छोड़कर, जो डीजीएफटी द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रावधान और प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.20 और 4.22.1 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित किया जायेगा। तथापि जिन मामलों में अप्रयुक्त माल पर सीमाशुल्क देय है, वह उस पर यथा अधिसूचित ब्याज सहित देय होगा।

वास्तविक चूक का विनियमन

4.28

निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है :-

1) यदि निर्यात दायित्व मूल्य के अनुसार पूरा किया गया है लेकिन मात्रा के अनुसार उसमें कमी है तो प्राधिकार पत्र धारक विनियमन के लिए निम्नलिखित को भुगतान करेगा:-

(क) सीमा शुल्क प्राधिकारी को यथा अधिसूचित ब्याज के साथ आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क देगा और

(ख) “शीर्ष लेखा : 1453, विदेश व्यापार और निर्यात संभर्धन तथा लघुशीर्ष 102” बताते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में एक खजान रसीद के माध्यम से उपर्युक्त आयातित माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के समतुल्य राशि के 3% रकम। प्राधिकार पत्र धारक को बढ़े हुए आयातित निविष्ट के विनियमन के लिए एक अलग आयात लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। तथापि इस उप पैरा के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि आयात की तारीख को उपर्युक्त आयातित माल मुक्त रूप से आयात योग्य हों।

(2) यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक



पर नीति और प्रक्रिया में निर्धारित सकारात्मक मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि मूल्य संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पत्र धारी खजाना रसीद के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 1% राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करेगा। मूल्यवार कमी गणना निर्यात की मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के संदर्भ में यथाअनुपात की जायेगी। उदाहरण के लिए यदि निर्यात निष्पादन मात्रावार केवल 50% है लेकिन आयात अनुमत पूर्ण लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए है तो मूल्यवर्धन की यथानुपात आधार पर गणना की जाएगी अर्थात् आयात लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50% होगी। तदनुसार उसका यह मतलब होगा कि जहाँ प्राधिकार पत्र धारक निर्यात निष्पादन करने में असमर्थ हो वहाँ मूल्यवार कमी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

- (3) यदि निर्यात दायित्व की प्रतिपूर्ति मात्रात्मक और मूल्यात्मक दोनों ही शर्तों के अनुसार पूरी नहीं होती है तो प्राधिकार पत्र धारक उम्पर उल्लिखित (1) और (2) के अनुसार विनियमन के लिए भुगतान करेगा।
- (4) यदि निर्यातक, निर्यात दायित्व को पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ है और उसने प्राधिकार पत्र के अधीन कोई आयात नहीं किया है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास शिपिंग बिलों को शुल्क वापसी शिपिंग बिलों में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने और लाइसेंस रद्द करवाने का विकल्प होगा।
- (5) लाइसेंसिंग प्राधिकारी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित और सत्यापित परिशिष्ट 23 के सम्बद्ध अंशों को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के शुरू में प्राधिकार (प्राधिकारों) के मद्दे आयातित वास्तविक मात्रा और प्राधिकार (प्राधिकारों) में अनुमत मानदण्डों से तुलना करेगा। इस सत्यापन प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकार पत्र धारक ने आयातित से कम मात्रा की खपत की है, तो प्राधिकार पत्र धारक आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज के दर से भुगतान करना होगा या निर्यात दायित्व की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करना होगा।

जुर्माना, सीमाशुल्क  
आदि जमा कराने हेतु  
समय अवधि

4.29

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को विनियमित या लागू करने के संबंध में प्राधिकार पत्र धारक से वसूल किया जाने वाला ब्याज सहित सीमाशुल्क, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा की गई माँग के 30 दिनों के भीतर निर्धारित

टी.आर.चालान में संबंधित सीमाशुल्क राजस्व के “मुख्य शीर्ष 0037-सीमाशुल्क उपशीर्ष 001 आयात शुल्क” में जमा करेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास तत्काल इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकार पत्र धारक से ऐसे दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की गई वसूली/जमा का ब्यौरा संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी पंजीकरण पत्तन को भेजेगा और उसकी सूचना संयुक्त सचिव (शुल्क वापसी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप भवन नई दिल्ली को देगा। विनियमन के लिए शुल्क, ब्याज और किसी अन्य राशि का भुगतान अथवा विशेष आयात लाइसेंस को वापिस करना बिना इस पूर्वाग्रह के होना चाहिए कि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत किसी समय सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी।

खातों का समुचित  
रख-रखाव

4.30

प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 23 में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोत से प्राप्त वस्तुओं के इस्तेमाल और खपत को सही और उचित हिसाब रखेगा। प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरू में उन सभी प्राधिकार पत्रों के लिए जो पिछले लाइसेंसिंग वर्षों में विमुक्त किए गये हैं, इन रिकार्ड्स को सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजना होगा। तथापि, 13-5-2005 को या इसके बाद जारी प्राधिकारों हेतु इन रिकार्ड्स को उक्त प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। इन रिकार्ड्स को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति  
प्रमाणपत्र  
(डीएफआरसी)

4.31

हटा दिया गया है।

4.31क

हटा दिया गया है।

4.32 से

हटा दिया गया है।

4.34

4.34.1 से

हटा दिया गया है।

4.34.3

4.35

हटा दिया गया है।

4.35.1

हटा दिया गया है।

4.36

हटा दिया गया है।

4.36 क

हटा दिया गया है।

### शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी)

शुल्क हकदारी  
पासबुक स्कीम

4.37

शुल्क पात्रता पासबुक योजना से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 में दी गई है। इस योजना के अधीन शुल्क क्रेडिट, एस आई ओ एन के उपर्युक्त निर्यात उत्पादों के मान्य निर्यातों और ऐसे सिओन के

डी ई पी बी दर का निर्धारण	4.38	<p>अनुसार मान्य निर्यातों पर लगाने वाले सीमा शुल्क के आधार पर परिकलित की जायेगी। इस योजना के अधीन, ऐसे उत्पादों के निर्यात के माध्यम से मूल्य संवर्धन शुल्क क्रेडिट की जो दर निर्धारित की गई है, के खाते में डाली जायेगी।</p> <p>‘आयात निर्यात फार्म’ में डी ई पी बी दरों के निर्धारण से संबंधित है। डी ई पी बी दरों के निर्धारण के सभी आवेदन संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से भेजे जाएँगे जो निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य की निविष्टियों के अंतराष्ट्रीय मूल्य सहित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों के अनुसार जाँच करेगी।</p>
अनंतिम डी ई पी बी दर	4.38क	<p>विविधता को उत्साहित करने और नये उत्पादों के निर्यात को तरक्की प्रदान करने के लिए, डी ई पी बी समिति को ऐसे उत्पादों को विशेष मामलों के तौर पर ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तथापि, ऐसी डी ई पी बी दरें कुछ निश्चित अवधि के लिए वैध रहेंगी जिसके दौरान दरों के नियमित निर्धारण के लिए निर्यातक, निर्यात और आयात डाटा प्रस्तुत करेगा।</p>
डी ई पी बी दर की प्रत्याशा में निर्यात	4.39	<p>डी ई पी बी योजना के अधीन किसी निर्यात की अनुमति नहीं है जब तक कि संबंधित निर्यात उत्पाद की डी ई पी बी दर अधिसूचित नहीं कर दी जाती हैं।</p>
पंजीकरण का पत्तन	4.40	<p>उत्तर पैराग्राफ 4.19 में दिए गये विनिर्दिष्ट समुद्री पत्तनों, वायु पत्तनों, आई सी डी और एल.सी.एस और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) को किए गये निर्यात/आयात डी.ई.पी.बी के लिए पात्र होंगे।</p>
	4.40.1	<p>डी ई पी बी केवल एकल पंजीकरण पोर्ट के लिए जारी की जायेगी। यह वह पत्तन होगा जहाँ से निर्यात किया गया है।</p>
रिकार्ड का रख-रखाव	4.40.2	<p>पत्तनों पर प्रत्येक सीमाशुल्क सदन डी ई पी बी के अधीन किए गए निर्यात के भ्रूरे का अलग रिकार्ड रखेगा।</p>
डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट और मौजूदा बाजार मूल्य	4.41	<p>जिन उत्पादों के संबंध में डी ई पी बी योजना के अधीन क्रेडिट हकदारी की दर 10 प्रतिशत या इससे ज्यादा है वहां ऐसे प्रत्येक निर्यात उत्पाद के प्रति क्रेडिट की राशि निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य (पीएमवी) के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निर्यात के समय निर्यातक को जहाजरानी बिल पर यह घोषणा करनी चाहिए कि निर्यात उत्पाद के प्रति डी ई पी बी योजना के तहत लाभ निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। तथापि मौजूदा बाजार मूल्य घोषणा उन उत्पादों पर लागू नहीं होगी जिनके उत्पाद की डी ई पी बी दर के संबंध में वैल्यू कैप न हो।</p>

- डी ई पी बी क्रेडिट का उपयोग 4.42 डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट का इस्तेमाल पूंजीगत माल सहित किसी भी मद पर सीमाशुल्क का भुगतान करने के लिए किया जाएगा जो मुक्त रूप से आयात योग्य है।
- डी ई पी बी के लिए आवेदन 4.43 डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट प्रदान करने के लिए आवेदन संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 'आयात निर्यात फार्म' में उल्लिखित फार्म में निर्धारित दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है। मुक्त विदेशी मुद्रा में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्यात के विनिमय दर जो सीमाशुल्क द्वारा "अनुमत निर्यात" के आदेश की तिथि पर यथा लागू होगी, के अनुसार भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है।
- 4.43 (क) परेषण निर्यात के संबंध में, जहाँ निर्यातक ने अनंतिम आधार पर उत्पाद के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की घोषणा कर दी है तो निर्यातक ऐसे माल की मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में बिक्री से प्राप्त वास्तविक पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर आधारित शिपिंग बिल का अन्तिम मूल्यांकन के लिए पात्र होगा।
- 4.43 (ख) डी टी ए से एस ई जैड यूनिटों को आपूर्तियों हेतु क्रेडिट को प्रदान करने के लिए डीटीए यूनिट या एसईजैड यूनिट द्वारा आवेदन किया जा सकता है। यदि दावा लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास किया गया है तो डीटीए यूनिट लाभ का दावा या तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी या संबंधित विकास आयुक्त से कर सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी डीटीए यूनिट को लाभ अनुमत करने के साथ-साथ पत्र की एक प्रति संबंधित विकास आयुक्त को पृष्ठांकित करेगा। इसके साथ निर्यात दस्तावेजों का ब्यौरा होगा जिसके मद्दे शामिल लेन देन की पुष्टि हेतु लाभ अनुमत किए गए हैं। यदि डीटीए सभरक विकास आयुक्त के पास दावा करना पसंद करता है तो विकास आयुक्त डीईपीबी लाभ अनुमत करने से पहले डीजीएफटी की वेबसाइट से सभरक के निषिद्ध फर्म सूची (डीईएल) का सत्यापन करेगा। एसईजैड यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को आयात निर्यात फार्म में निर्धारित दस्तोवजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- 4.44 भुगतान की पुष्टि के बाद डी ई पी बी हस्तान्तरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जायेगी। अन्य मामलों में शुरु में डी ई पी बी निर्यात कारोबार की प्राप्ति के बाद अहस्तान्तरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जायेगी और निर्यात आय प्राप्त होने पर ऐसे डी ई पी बी को हस्तान्तरित के तौर पर पृष्ठांकित किया जा सकता है।
- प्राप्ति की मोनिटरिंग 4.45 क्षेत्रीय प्राधिकारी उन मामलों को मानिटर करेगा जहां निर्यात कारोबार की आय से पूर्व डी ई पी बी मंजूर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वसूली निर्धारित समय के भीतर हो जाएगा। ऐसा करने में असफल रहने पर क्षेत्रीय प्राधिकारी यथा अधिसूचित ब्याज के साथ डी ई पी बी साख के बराबर राशि की वसूली के लिए कार्यवाई शुरु करेगा। मामलों में वसूली की गई राशि पैरा 4.29 में बताए गये सीमा शुल्क के मुख्य लेखा शीर्ष खाते में जमा की जायेगी।

- 4.45.1 यदि निर्यात आय निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता तो डी ई पी बी धारक को ऐसे निर्यात के प्रति आयात की तिथि से जमा करने के तिथि तक यथा अधिसूचित ब्याज सहित आयातों पर प्रयुक्त शुल्क मुक्त क्रेडिट के बराबर नगर राशि जमा करना होगा। जहां विदेशी मुद्रा में प्राप्त की गई राशि कम है तो अदा की जाने वाली राशि अनुपातिक तौर पर कम कर दी जायेगी।
- समय- अवधि 4.46 क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्यात की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर या वसूली की तारीख से छह माह के भीतर या शिपिंग बिल के प्रिन्टिंग/रिलीज होने के तीन महीने के भीतर जो भी बाद में हो, किए जाएंगे। शिपमेंट जिसके लिए दावा किया गया है उसका हिसाब वसूली/निर्यात की अंतिम तारीख से लगाया जाएगा।
- 4.47 जहां कहीं सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनन्तिम पोतलदान की अनुमति दी गयी है वहां ऐसे निर्यात के प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जहाजरानी बिल रिलीज करने के बाद ही डी ई पी बी जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में, डी ई पी बी के लिए आवेदन ऐसे जहाजरानी बिल के रिलीज की तारीख से छः महीनों के भीतर या वसूली की तारीख से छः महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, किए जाएंगे।
- आवेदनों की बारम्बारता 4.48 किसी एक आवेदन में सभी जहाजरानी बिल केवल एक सीमाशुल्क सदन से किए गए निर्यात से संबंधित होने चाहिए। जहाजरानी बिलों की संख्या पर कोई समय सीमा नहीं है जिन्हें एक आवेदन में ई डी आई के तरीके जारी किया जा सकता है।
- सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापन 4.49 1-10-2005 से पहले के ई डी आई शिपिंग बिलों और गैर ई डी आई शिपिंग बिलों के मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी डी ई पी बी जारी करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जहाजरानी बिल संख्या और तारीख, जहाजरानी बिल (बिलों) के अनुसार पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य भारतीय रुपयों में और निर्यात उत्पाद का ब्यौरा डी ई पी बी पर पृष्ठांकित है। डी ई पी बी के प्रति आयात अनुमत करने से पहले, सीमाशुल्क यह सत्यापित करेगा कि डी ई पी बी पर दिए गए निर्यात का ब्यौरा उनके लेख के अनुसार है। तथापि, ई डी आई पत्तनों से 1-10-2005 को या उसके बाद जारी ई डी आई शिपिंग बिलों के मामले में जिन्हें सीमाशुल्क द्वारा डी जी एफ टी को इलेक्ट्रानिक रूप से भेजा गया है तो जारी डी ई पी बी को इलेक्ट्रानिक मैसेज एक्सचेंज सिस्टम के माध्यम से पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क को भेजा जाएगा तथा डी ई पी बी का इलेक्ट्रानिक रूप से पंजीकरण के पत्तन पर पंजीकरण किया जाएगा। शिपिंग बिलों का कोई सत्यापन, जिसके मद्दे ऐसी डी ई पी बी जारी की गई है, इन डी ई पी बी के मद्दे आयात अनुमत करने से पहले, की आवश्यकता नहीं होगी।

पुनः वैधीकरण	4.50	कोई पुनः वैधीकरण डी ई पी बी की मूल वैधता अवधि के बाद प्रदान नहीं किया जाएगा। जब तक कि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.13 के तहत प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय/सीमाशुल्क की सुरक्षा में यह समाप्त नहीं हो जाता।
डी ई पी बी स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात	4.51	डीईपीबी स्कीम के तहत आयातित माल, जो खराब या इस्तेमाल हेतु ठीक नहीं पाये जाते हैं का प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.23.6 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है।
जहाजरानी बिलों की खो गई डी ई पी प्रतिलिपि के मद्दे डी ई पी बी और अन्य शुल्क क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना	4.52	<p>जिन मामलों में जहाजरानी बिलों की डी ई पी प्रतिलिपि खो गई है, वहाँ डी ई पी बी और अन्य ड्यूटी क्रेडिट प्रमाण पत्र के दावे पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाएं।</p> <p>(क) खो गए मूल जहाजरानी बिल के स्थान पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट/सत्यापित प्रतिलिपि।</p> <p>(ख) खो गए जहाजरानी बिल के संबंध में डी ई पी बी या अन्य शुल्क क्रेडिट हकदारी के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी एजेंसियों द्वारा शिपिंग बिल खोने पर दस्तावेजी प्रमाण देने से शुल्क नहीं लगेगा।</p> <p>(ग) खो गए जहाजरानी बिलों के संबंध में निर्यातक द्वारा एक शपथ-पत्र और यह आश्वासन कि यदि बाद में यह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>(घ) इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बांड निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि खो गए जहाजरानी बिल के बदले जारी किए गए डी ई पी बी के कारण सरकार को यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।</p> <p>निकासी करने से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसी शिपिंग बिल के प्रति डी ई पी बी का लाभ नहीं लिया गया है।</p>
4.52.1		<p>खोए हुए जहाजरानी बिल का दावा जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट प्रतिलिपि की वसूली की तिथि के छः महीने के भीतर होना चाहिए तथा इस प्रकार के किसी आवेदन पर इसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। तथापि यदि कोई अनंतिम मूल्यांकित डी ई पी बी जहाजरानी बिल खो जाता है तो इस प्रकार के मामले में डी ई पी बी के आवेदन की तारीख अंतिम मूल्यांकित जहाजरानी बिल की वसूली की तिथि से छः महीने के भीतर होगी।</p>

- मूल बैंक प्रमाणपत्र  
का खो जाना
- 4.53 जिन मामलों में मूल बैंक प्रमाणपत्र खो जाता है उन मामलों में डीईपीबी दावे पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ :-
- (क) खोए हुए मूल प्रमाणपत्र के बदले बैंक प्राधिकारी द्वारा जारी बैंक प्रमाण पत्र की अनुलिपि।
  - (ख) खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के संबंध में डी ई पी बी पात्रता के 2% के बराबर आवेदन शुल्क जैसा बी मामला हो।
  - (ग) बैंक प्रमाणपत्र के खो जाने के संबंध में निर्यातक द्वारा एक हलफनामा जिसमें यह वचन दिया गया हो कि यदि यह प्रमाण पत्र बाद में मिल जाता है तो उसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को लौटा दिया जाएगा।
  - (घ) निर्यातक द्वारा इस आशय का एक इडैमैनिटी बान्ड प्रस्तुत किया जाएगा कि वह खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के प्रति जारी डी ई पी बी के मद में यदि सरकार को कोई क्षति होती है तो वह उस क्षति की पूर्ति करेगा।
- खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के प्रति दावों को निर्यात की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाए कि उसके बाद प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
- ऐसे मामलों में जहाँ दोनों दस्तावेज खो जाते हैं तो निर्यातक पैराग्राफ 4.52 व 4.53 में दी गई प्रक्रिया को अपनाएगा। ऐसे आवेदन की समयावधि पैराग्राफ 4.52 और 4.53 जो भी बाद में हो, के अनुसार होगी।
- शुल्क मुक्त आयात  
प्राधिकार पत्र स्कीम  
(डी एफ आई ए)
- 4.54 शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम से सम्बन्धित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 में दी गई है
- आवेदन
- 4.55 'आयात निर्यात फार्म' में आवेदन निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 4.55.1 ऊपर पैराग्राफ 4.4.1 और 4.4.3 में दिए गये दिशा निर्देशों को लागू किया जायेगा।
- 4.55.2 हटा दिया गया है।
- 4.55.3 तथापि निम्नलिखित मदों के संबंध में निर्यातकों से शिपिंग बिल में तकनीकी स्थिति, मात्रा और विशिष्टकरण की घोषणा करनी होगी।

लाईसेंसिंग प्राधिकारी शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी करते समय निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों की मात्रा, तकनीकी विशेषताओं और विशिष्टियों के संबंध में एक उल्लेख करेगा। स्टेनलेस स्टील सहित एलॉय स्टील, कॉपर एलॉय, सिंथेटिक रबर, बेयरिंग, सोलवेंट, परफ्यूमस/एसेंसेयल आयल/एयरोमेटिक रसायन, सरफैक्टेंट्स, रिलेवेन्ट फैब्रिक्स, मारबल पोलीप्रोपीन से बनी वस्तुएं, पेपर और बोर्ड से बनी वस्तुएं, इन्सेक्टीसाइड्स, लेडइनगोट्स, जिक इन्गोट्स साइट्रिक एसिड, रेलिवेंट ग्लास फाइबर, चोपड/स्ट्रेन्डिड मैटोविंग वूवन सेर्फेसिंग मैट, रेलिवेंट सिंथेटिक रेजिन (अनसेचूरेटिड, विनाइल ईस्टर रेजिन, हाइड्रोक्सी इथिलसेल्यूलोज), स्लाइनिंग मैटिरियल

4.55.4 हटा दिया गया है।

बहु यूनिटों वाले आवेदकों हेतु डीएफआईए 4.56 वास्तविक प्रयोक्ता डीएफआईए के मद्दे आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तान्तरण ऊपर पैराग्राफ 4.5 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

निःशुल्क और प्रदत्त माल हेतु डीएफआईए 4.57 प्रक्रिया विदेश व्यापार नीति में ऊपर पैराग्राफ 4.6 और 4.2.7 के अनुसार होगी।

वित्तीय शक्तियाँ 4.58 वित्तीय शक्तियाँ प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.8 के अनुसार होगी।

डीएफआईए का विवरण 4.59 डीएफआईए ऊपर पैराग्राफ 4.11 के अनुसार ब्यौरों करेगा।

डीएफआईए की प्रत्याशा में निर्यात 4.60 डीएफआईए के लिए आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए ऊपर पैराग्राफ 4.12, 4.12.1 और 4.12.2 के अनुसार स्वीकार की जाएंगी।

4.60.1 हटा दिया गया है।

4.60.2 हटा दिया गया है।

पंजीकरण का पत्तन 4.61 ऊपर पैराग्राफ 4.19 के प्रावधान डीएफआईए के मामले में भी लागू होंगे।

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति 4.62 ऊपर पैराग्राफ 4.18 के प्रावधान लागू होंगे।

डीएफआईए के मूल्य में वृद्धि/कमी 4.63 ऊपर पैराग्राफ 4.63 के प्रावधान लागू होंगे।

निर्यात दायित्व अवधि और इसमें वृद्धि 4.64 निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि और इसमें वृद्धि इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.22 में दिये गये उपबंधों के अनुसार शासित होगी।



तथापि प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 36 महीनों से ज्यादा के विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी।

डीएफआईए की पुनर्वैधीकरण	4.65	डीएफआईए धारक को पुनर्वैधीकरण की सुविधा इस पुस्तक के पैराग्राफ 4.23 में दिये गये उपबन्ध के अनुसार उपलब्ध होगी।
डीएफआईए स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात	4.66	हस्तांतरणीय डीएफआईए के मद्दे आयातित माल, जिसे खराब या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ऐसे माल के निर्यात हेतु डीएफआईए के मद्दे डेबिट किया गया लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का 95 प्रतिशत सम्बन्धित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक प्रमाणपत्र के रूप में जिसमें सृजित धनराशि और मूल डीएफआईए का ब्यौरा शामिल हो, प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक स्वच्छ डीएफआईए जारी किया जाएगा। इस प्रकार जारी किया गया स्वच्छ डीएफआईए प्राधिकरण का सम्मान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त सामान के आयात की तारीख पर उपलब्ध शेष अवधि के समकक्ष अवधि के लिए वैध होगा।
निर्यात दायित्व की मानीटरिंग	4.67	ऊपर पैराग्राफ 4.24 के प्रावधान लागू होंगे।
निर्यात दायित्व की पूर्ति और आयात के उचित खातों का रख रखाव	4.68	ऊपर पैराग्राफ 4.24 के प्रावधान लागू होंगे। मूल डीएफआईए धारक परिशिष्ट 23 में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/घरेलु स्रोतों से प्राप्त माल के उपयोग और खपत का सही और उचित लेखा जोखा रखेगा। बाण्ड वेबर/विमुक्ति/निर्यात दायित्व के निष्पादन/हस्तान्तरणीयता के लिए इन रिकार्डों को अनुरोध सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजना होगा। इन रिकार्डों का विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखना होगा।
	4.69	हटा दिया गया है।
निष्क्रियता	4.70	ऊपर पैराग्राफ 4.26 के प्रावधान लागू होंगे।
वास्तविक चूक का विनियमन	4.71	निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पैरा 4.28 में निर्धारित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है।
डीएफआईए की हस्तांतरणीयता	4.72	पैरा में यथा निर्धारित निर्यात दायित्व की पूर्ति और दस्तावेजों की प्रस्तुति पैरा 4.68 में विनिर्दिष्ट के बाद क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र को हस्तांतरणीय बनाएगा बशर्ते कि इस स्कीम हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो। तथापि, प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकित प्रतिबंधित मद को विदेश व्यापार नीति और उसमें निर्धारित व्यापार नीति प्रक्रिया के अनुसार केवल अलग से जारी आयात लाइसेंस/अनुज्ञापत्र के मद्दे अनुमत होगी।

## रत्न और आभूषण

- 4क रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र और स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम जेवरों के लिए स्कीम विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4क में दी गई है।
- प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र 4क.1 प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन पत्र, निर्धारित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट-1क में उल्लिखित “आयात निर्यात फार्म” के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा किया जाए।
- 4क.1.1 आवेदन पत्र उस माह से छ माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जिस माह/तिमाही के दौरान निर्यात आय प्राप्त की गई है। माह के दौरान निर्यात से प्राप्त आय के लिए पूरे महीने के लिए समेकित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 4क.1.2 हटा दिया गया है।
- 4क.1.3 जिस मामले में भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त हो गया है और निर्यात बाद में किया जाता है तो प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान निर्यात किया गया है, उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4क.1.4 स्पष्टता के प्रयोजन के लिए, यह पुनः दोहराया गया है कि अग्रिम भुगतान मामले में, जिस माह निर्यात किया गया है और निर्यात करने के बाद जिस माह निर्यात आय आंशिक रूप से या पूरी तरह प्राप्त की जाती है उस माह को प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन पत्र दाखिल करने के प्रयोजन के लिए छः माह की अवधि को गिना नहीं जाएगा।
- छीजन मानदण्ड 4क.2 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा वस्तुओं के लिए छीजन या विनिर्माण हानि नीचे दी गई है :-

निर्यात की मद		निर्यात मद में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के अंश के संबंध में भार के रूप में छीजन का प्रतिशत	
		स्वर्ण/प्लेटिनम	चाँदी
क.	सादा आभूषण और वस्तुएँ और आभूषण जैसे मंगल सूत्र जिसमें स्वर्ण और ब्लैक मोती/कृत्रिम स्टोन्स, क्यूबिक जिराकोनिया हीरे, कीमती और अर्द्धकीमती पत्थर	3.5 प्रतिशत	4.5%
ख.	जड़ित आभूषण और उसकी वस्तुएँ	9.0 प्रतिशत	10%

ग.	स्वदेशी रूप से (गैर मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित) मार्जेंटिंग और फाईडिंग	3.5 प्रतिशत	4.5 %
घ.	पूर्णतः मशीनी प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित और अजड़ित कोई भी आभूषण/वस्तुएं	1.25 प्रतिशत	1.25 %
ड.	जड़ित जेबरात में प्रयुक्त मार्जेंटिंग्स या तो आयातित हो या स्वदेशी रूप से प्राप्त किए गए/विनिर्मित हों	2.5 प्रतिशत	2.5 %
च.	स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम मैडेलीयन्स और सिक्के (कानून प्रकृति के सिक्कों को छोड़कर)	0.25 प्रतिशत	0.25 %
छ.	मशीनी तकनीक तरीके द्वारा तैयार किए गए फाईडिंग व मार्जेंटिंग।	1.25 प्रतिशत	1.25 %

## मूल्य संवर्धन

4क.2.1

आभूषण निर्यात स्कीम के तहत मूल्य संवर्धन का परिकलन विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.6 के अनुसार किया जायेगा। न्यूनतम मूल्य संवर्धन निम्नानुसार होगा:

क्र. सं.	निर्यात मद	न्यूनतम मूल्य संवर्धन
क.	सादा स्वर्ण/प्लेटिनम/चाँदी के आभूषण और मंगल सूत्र जिसमें स्वर्ण और ब्लैक बीड्स/इमटेशन स्टोन्स, कीमती पत्थर और अर्धकीमती पत्थर क्यूबिक जिरिकोनिया हीरे, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर आदि लगे हों।	4 प्रतिशत
ख.	सभी स्वर्ण/प्लेटिनम/चाँदी के आभूषण और वस्तुएँ	6.5 प्रतिशत
ग.	पूर्णतः मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई भी आभूषण/वस्तुएँ	2 प्रतिशत
घ.	स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के मैडेलीयन और सिक्के (कानूनी निविदा के स्वरूप के सिक्कों को छोड़कर)	2 प्रतिशत
ड.	मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम फाईडिंग्स/मार्जेंटिंग्स	3 प्रतिशत

4क.2.2

निर्यात के प्रति स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा की हकदारी में अनुमत छीजन/विनिर्माण क्षति सहित निर्यात की मद में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा होगी।

रत्न और आभूषण खो जाना	4क.3	देश के बाहर निर्यातित रत्न और आभूषण मदों के खेप, जो निर्यात के बाद रास्ते में खो गए हैं तथा ऐसे निर्यातों के मद्दे जहाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो चुकी हो अथवा बीमा दावा कर लिया गया हो, वे भी प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे।
रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र	4क.4	रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र, अपरिष्कृत हीरों, बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध-बहुमूल्य तथा सिन्थेटिक स्टोन और मोतियों के आयात के लिए वैध होगा। इसके आलावा, यह प्राधिकार पत्र समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के मूल्य के भीतर 5% तक आभूषणों के खाली भक्कों के आयात के लिए भी वैध होगा। जड़ित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों/सामग्री के आयात के प्रति जारी रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र, समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक के पन्ना के अतिरिक्त कट और पालिश किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के आयात के लिए भी वैध होगा।
	4क.4.1	रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र परिशिष्ट-12ख में दिए गए मापदण्ड के अनुसार उपलब्ध होगा।
आवेदन प्रस्तुत करना	4क.4.2	<p>(1) रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को परिशिष्ट 1क में दिए गए प्रपत्र में निर्धारित दस्तावेजों सहित परिशिष्ट-22च के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>(2) यदि जहाजरानी बिल की ई पी प्रति और नामित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बीजक नामित अभिकरणों को प्रस्तुत किया जाता है तो निर्यातक इसकी स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा और इसके साथ नामित अभिकरण से यह प्रमाण पत्र बी बी होगा जिसमें जड़ित आभूषणों के मामले में स्टडिंग के कैरेट/मूल्य और सादे आभूषणों तथा वस्तुओं के मामले में प्राप्त किए गए अधिक मूल्य परिवर्धन को प्रमाणित किया गया हो।</p> <p>(3) रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकरण पत्र के लिए पैरा 4क.1.1 से 4क.1.4 के प्रावधान भी लागू होंगे।</p>
अभिकरण कमीशन	4क.5	स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण स्कीम का उपयोग करने वाले निर्यातक को अभिकरण कमीशन देने की अनुमति है। मूल्य परिवर्धन का परिकलन अभिकरण कमीशन को घटा कर किया जाएगा। जहाँ कहीं ऐसा अभिकरण कमीशन दिया जाता है तो मूल्य परिवर्धन अभिकरण कमीशन प्रतिशत द्वारा तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

- जहाजरानी बिल और बीजक पर पृष्ठांकन 4क.6 आभूषणों के निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल और बीजक में मद का विवरण, इसकी शुद्धता, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश का भार, इस पर दावा किए गए वेस्टेज, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश का कुल भार जमा दावा किए गए वेस्टेज तथा स्वर्ण/चाँदी के लिए 0.995/0.999 शुद्धता और प्लेटिनम के लिए 0.9999 शुद्धता में इसकी समकक्ष मात्रा तथा इसका मूल्य, निर्यात का एफ ओ बी मूल्य, प्राप्त मूल्य परिवर्धन के ब्यौरे होने चाहिए। निर्यात के लिए इन प्रत्येक धातुओं से निर्मित सभी या कुछ मदों के संबंध में इस्तेमाल किए गए स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की शुद्धता यदि वही है तो निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कुल भार और ऐसी ही मदों, जिनकी शुद्धता वही है, के अन्य ब्यौरे भी देने होंगे। जड़ित मदों के मामलों में, जहाजरानी बिल में विनिर्माण में इस्तेमाल किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/हीरों/मोतियों का भार और मूल्य तथा स्वर्ण/चाँदी के मिश्रण में इस्तेमाल की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का भार/मूल्य के ब्यौरे भी होने चाहिए।
- निर्यात की शर्तें 4क.7 सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि जहाजरानी बिल और बीजक में पृष्ठांकन ठीक किया गया हो तथा प्राप्त किया गया मूल्य परिवर्धन विदेश व्यापार नीति में निर्धारित मूल्य संवर्धन से कम न हो।
- निर्यात का प्रमाण 4क.8 निर्यातक को जहां कहीं अपेक्षित हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात का प्रमाण देना होगा :-
- (क) जहाजरानी बिल की ई पी प्रति,
  - (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बीजक, और
  - (ग) परिशिष्ट 22क में दिए गए प्रपत्र में निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र जिसमें यह दर्शाया गया हो कि दस्तावेज लेन देन/संचयन के लिए भेजे गए हैं।
  - (घ) निम्नानुसार एक घोषणा :-
- “मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि 180 दिनों के बाद की निर्यात आय विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों के औसत निर्यात के 10% से ज्यादा नहीं होगी। मैं/हम आगे घोषणा करता हूँ/करते हैं कि कोई भी निर्यात आय एक वर्ष या ऐसी बढ़ी हुई अवधि जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की गई हो, से ज्यादा बकाया नहीं है।” विदेशी क्रेता द्वारा आभूषणों की व्यक्तिगत सामान के मामले में निर्यात हकदारियों का दावा करने के लिए निर्यात के सबूत के तौर पर निर्यातक/विक्रेता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- (क) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए शिपिंग बिल की प्रति
- (ख) विदेशी क्रेता के आगमन के समय सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत किए गए मुद्रा घोषणा प्रपत्र की एक प्रति; और
- (ग) बैंक से विदेशी मुद्रा नकदी प्रमाणपत्र।

इसके अतिरिक्त, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डी ए)/सुपुर्दगी पर नकद आधार पर व्यक्तिगत सामान की भी अनुमति है। निर्यात हकदारी का दावा करने हेतु निर्यातक को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे:

- (i) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए जहाज रानी बिल की प्रति
- (ii) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र इस संबंध में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी निर्देशों का आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन किया जायेगा।

शुद्धता/परिशुद्धता  
का परिवर्तन

4क.9

परिशुद्धता के रूप में स्वर्ण / चाँदी / प्लेटिनम के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित फार्मूला अपनाया जाएगा :-

- (i) जहां स्वर्ण वस्तुओं का कैरेट में निर्यात किया गया है, वहाँ स्वर्ण अंश को 24 से भाग किया जाएगा और इसके बाद 0.995 / 0.999 / 0.900 से गुणा किया जाएगा ताकि क्रमशः 0.995 / 0.999 / 0.900 परिशुद्धता के रूप में स्वर्ण की समकक्ष मात्रा तक पहुँचा जा सके, और
- (ii) जहां कहीं निर्यात की वस्तु की शुद्धता, परिशुद्धता के रूप में व्यक्त की गई है, वहां स्वर्ण / चाँदी / प्लेटिनम मात्रा को 0.995/0.999/ 0.900 से भाग किया जाएगा ताकि स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम क्रमशः 0.995/0.999/0.900 परिशुद्धता की बराबर मात्रा तक पहुँचा जा सके।

नामित अभिकरण द्वारा 4क.10  
स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम  
की रिलीज

नामित अभिकरणों/भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत बैंकों द्वारा आभूषणों के निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम केवल 10 ग्राम या स्वर्ण के संबंध में दस तोला छद्मों के गुणकों में रिलीज किया जाएगा। तथापि, निर्यातकों को चाँदी केवल 1 किग्रा गुणकों में रिलीज की जाएगी स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कोई भी शेष निर्यातक को उसकी भावी हकदारी सहित उपलब्ध रहेगा। नामित प्राधिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/ 0.995 परिशुद्धता में और प्लेटिनम 0.900 या इससे अधिक परिशुद्धता में रिलीज की जाएगी।

- भुगतान की शर्तें 4क.11 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साख-पत्र, के मद्दे सुपुर्दगी पर नकद भुगतान के आधार पर स्वीकृति के प्रति दस्तावेज आधार पर या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान के आधार पर होगी।
- निर्यात बन्दरगाह 4क.12 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात की अनुमति मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, कोची, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, डेबोलिन एअरपोर्ट, गोवा और हैदराबाद स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए वायु भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी। प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बटूर दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद के स्थित सीमा-शुल्क सदनों के माध्यम से कूरियर द्वारा निर्यात भी अनुमत होगा।
- डाक द्वारा निर्यात 4क.13 विदेशी डाक घर के जरिए रत्न और आभूषण निर्यात की नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.17 में दी गयी है। निर्यात के समय, निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
- (i) विदेशी डाकघर में प्रस्तुत किया गया जहाजरानी बिल या बीजक,
  - (ii) नामित अभिकरणों से प्रमाण पत्र जिसमें वह मूल्य दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम बुक किया गया था या तुरन्त बिक्री आधार पर या ऋण के आधार पर दिया गया था।
  - (iii) बीजक की तीन प्रतियाँ।
- 4क.14 हटा दिया गया है।
- विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के मद्दे निर्यात 4क.15 विदेशी क्रेता द्वारा की गई आपूर्ति के प्रत्येक आयात परेषण की निकासी से पहले, नामित अभिकरण इस आशय के एक बॉण्ड का सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निष्पादन करेगा कि वह करार में निर्धारित अवधि के भीतर ग्राह्य वेस्टेज को छोड़कर स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम माउंटिंग और फाइंडिंग आदि के सम्पूर्ण आयात के बराबर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों या वस्तुओं का निर्यात करेगा। सोना/चाँदी/प्लेटिनम, अयस्क, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंगस और माउंटिंगस और सादा अर्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों की स्तर धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष पूर्ति के मामले में शुल्क प्राधिकरण को आयातित सोना/चाँदी/प्लेटिनम, एलॉयस, सोना/चाँदी/ प्लेटिनम की फाइंडिंगस और माउंटिंगस और सादा अर्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगने वाले सीमा शुल्क की बैंक गारंटी सीमा शुल्क के पास जमा करानी होगी। सीमा शुल्क विभाग के पास निष्पादित बैंक गारंटी विधिक बचनबद्धता एक वर्ष की

अवधि के लिए वैध होगा। स्तर-धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष आपूर्ति के संबंध में, निर्यात 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। निर्यात दायित्व को पूरा न करने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त न करने की स्थिति में सीमा शुल्क विभाग, सीमा शुल्क और ब्याज की वसूली कर सकता है जिसमें बैंक गारंटी को लागू भी सम्मिलित है। इसके अलावा आयातक सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी हो सकता है।

4क15.1 नामित अभिकरण स्तर धारक/निर्यातक को उस मात्रा पर लगने वाला सीमाशुल्क देना होगा जिसके बारे में यह साबित हो गया है कि निर्यात नहीं किया गया है।

4क15.2 सीमाशुल्क प्राधिकारी के जरिए नामित अभिकरण/स्तर धारक/निर्यातक द्वारा माल के निकासी करायी जाएगी। उन मामलों में भी जहाँ सहायक कम्पनियों द्वारा निर्यात आदेश प्राप्त किया गया है नामित अभिकरण द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा माल निकासी करायी जाएगी न कि सहायक द्वारा/ ऐसे मामलों में, सहायक कम्पनी नामित अभिकरण को आगम पत्र और जहाजरानी बिल प्रस्तुत करने के लिए इसके एजेंट के रूप में प्राधिकृत करेगी।

4क.15.3 निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल में निम्नलिखित ब्यौरे भी होने चाहिए :-

- (i) सहायक/स्तर धारक/ निर्यातक का नाम और पता
- (ii) नामित एजेन्सी द्वारा स्वीकृति कि सम्बद्ध साझेदार द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे निर्यात किया गया है, नामित एजेन्सी के पास इसके पंजीकरण की तिथि स्तर धारक/ निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में, इस संबंध में स्व घोषणापत्र दिया जाएगा।
- (iii) सीमाशुल्क सदन का नाम जिसके माध्यम से सोना/ चाँदी/ प्लेटिनम सादा अर्ध-निर्मित सोना/सिल्वर/प्लेटिनम आभूषण का आयात किया गया है और आगम पत्र संख्या एवं तारीख तथा आयात की तारीख।

4क15.4 प्रत्येक शिपिंग बिल निर्यात हेतु केवल उस सीमा शुल्क सदन के माध्यम से वैध होगा जहाँ संबंधित नामित अभिकरण/ स्तरधारक/निर्यातक का कार्यालय स्थित है। यह पोत लदान हेतु 7 दिन की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें वह तारीख भी शामिल है जिस दिन नामित अभिकरण द्वारा पृष्ठांकन किया गया था। यदि निर्यात इस समयावधि में नहीं किया जाता है, तो निर्यातक एक नया पोतलदान बिल दाखिल करेगा।



4क15.5 निर्यात के समय निर्यातक, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

- (1) सीमाशुल्क सदन जिसके माध्यम से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम सादा अर्ध-निर्मित/सोना/सिल्वर/प्लेटिनम आभूषण का तदनु रूप आयात हुआ है, के अतिरिक्त, सीमाशुल्क सदन जहां निर्यात किया गया है, के पोतलदान बिल की दो अतिरिक्त प्रतियाँ साहित। अन्य मामलों में पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति;
- (2) बीजक की तीन प्रतियाँ;
- (3) विदेशी खरीददारों द्वारा भेजी गई मदों की मात्रा और मूल्य को इंगित करने वाला नामित एजेन्सी का प्रमाण पत्र।

4क15.6 सीमाशुल्क प्राधिकरण पोतलदान बिल और सम्बद्ध बीजक की विधिवत सत्यापित दो प्रतियाँ वापिस लौटाएगा। एक प्रति उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नामित एजेन्सी/स्तर धारक/ निर्यातक के कार्यालय को भेजी जाएगी।

4क15.7 निर्यात की तिथि से 15 दिन के भीतर उस नामित एजेन्सी को जिसने निर्यात किया है, निर्यातक, निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो दस्तावेजों की जाँच करने के पश्चात् निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि की अनुमत मात्रा जारी करेगा।

4क15.8 बैंक गारंटी/विधिक वचन बद्धता प्रस्तुत करके निर्यातक अग्रिम रूप से विदेश क्रेता द्वारा आपूर्ति स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। उन मदों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत जोड़कर उन पर लगने वाले सीमाशुल्क के बराबर राशि का बैंक गारंटी की राशि तभी वापिस की जाएगी जब निर्यातक नामित एजेन्सी को निर्यात का सबूत और निर्यात उत्पाद में मदों की अग्रिम आपूर्ति के उपयोग के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

4क15.9 सीमाशुल्क कार्यालय से निष्पादित बाँड/बैंक गारंटी/विधिक वचन बद्धता को छुड़ाने के उद्देश्य हेतु नामित अभिकरण/स्तर धारक/निर्यातक, विदेशी खरीदार द्वारा आपूर्ति मदों की मात्रा और मूल्य, तदनु रूप आगम बिल संख्या और तिथि, तदनु रूप किए गए निर्यात संबंधी प्रत्येक शिपिंग बिल की संख्या के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

खार्तों का रखरखाव

4क16 नामित अभिकरण प्रत्येक निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित सोना, चाँदी, माउंटिंग्स, फाइडिंग्स सादा अर्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण इत्यादि किए गए निर्यात और ऐसे निर्यात के लिए जारी सोना/

चाँदी, माउटिंग्स, फाइंडिंग्स इत्यादि का प्रेषण वार पूर्ण लेखा जोखा रखेगा। सीधे निर्यातों के मामले में ऐसा लेखा-जोखा स्तरधारक द्वारा रखा जाएगा। इस लेखा जोखा का रख-रखाव निर्यात की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

प्रदर्शनियों/ निर्यात  
संवर्धन दौरों/ ब्रॉण्डेड  
आभूषण के निर्यात  
के जरिए निर्यात

4क.17

नामित अभिकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शनी लगाने/ब्रॉण्डेड आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट सरकारी अनुमोदन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा। अन्य कोई व्यक्ति सहायक सीमाशुल्क आयुक्त के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शनी लगाने/निर्यात संवर्धन दौरों/ब्रॉण्डेड आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट जी जे ई पी सी अनुमोदन सहित प्रस्तुत करेगा। पुनः आयात के मामले में, ऐसी मर्दों के पहुँचने पर निकासी से पहले निर्यात दस्तावेजों के साथ जाँच की जाएगी।

4क.18

(क) निर्यात के निम्नलिखित तरीकों के लिए इस योजना के अन्तर्गत निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) विदेशी प्रदर्शनी में आयोजित/भाग लेने के लिए रत्नों और आभूषणों का निर्यात। इस योजना के तहत निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होंगे: विदेशों में न बेची गई मर्दें प्रदर्शनी के बन्द होने के 60 दिनों के भीतर पुनः आयातित की जाएंगी। तथापि यदि निर्यातक पहली प्रदर्शनी के बन्द होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में भाग ले रहा है तो दूसरी प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 60 दिन गिने जाएंगे विदेश प्रदर्शनी में आयोजन/भाग लेने के लिए रत्न और आभूषण के व्यक्तिगत सामान के मामले में, ऐसे रत्न और आभूषण का मूल्य 2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगी। ऐसी प्रदर्शनियों में बेची गई मर्दों पर सोना/चाँदी/प्लेटिनम अंश प्रतिपूर्ति के रूप में आयातित किए जा सकते हैं। निर्यातक को प्रदर्शनी में विदेश में बेचे गए माल के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए सोना/चाँदी/प्लेटिनम के बन्द होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी से प्रतिपूर्ति ले सकता है।

(ii) विदेशों के निर्यात संवर्धन दौरों/फोटो प्रदर्शनियों/फैशन शो हेतु वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए रत्न और आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना या निर्यात। 100,000 अमरीकी डालर तक सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण, कटे और पॉलिशड डायमण्ड, कीमती अर्द्ध-कीमती पत्थर, मोती और नमूनों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना/वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए निर्यात के रूप में वस्तुएँ निर्यात प्रमोशन टूर/फोटो प्रदर्शनी/फैशन शो और अस्थायी डिस्पले/विदेश में बिक्री के लिए भी रत्न और आभूषण निर्यात

संवर्धन परिषद् के अनुमोदन के साथ अनुमति है बशर्ते कि प्रोमोटर सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर आभूषण/सामान या बिक्री से प्राप्त आय को वापिस लाएगा। निर्यात संवर्धन दौरों के लिए पर्सनल कैरिज के मामले में, निर्यातक, देश को छोड़ते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को ऐसे नमूनों की पर्सनल कैरिज घोषित करेगा और सीमाशुल्क के आभूषण मूल्यांकन कर्ता द्वारा जारी निर्यात प्रमाणपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में, निर्यातक निर्यात संवर्धन दौर के बाद 120 दिनों के भीतर या 45 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, जो बी पहले हो, सोना/चाँदी/प्लेटिनम विदेश में बेची गई मर्दों के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए नामित एजेंसी के साथ बुक करेगा।

(iii) ब्रान्डेड आभूषणों का निर्यात ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात भी विदेशों में स्थापित अनुमत दुकानों या उनके वितरकों/एजेंटों के शोरूम में डिस्प्ले/बिक्री के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन से अनुमत है। 180 दिनों के भीतर विदेश में न बेची गई मर्दें 45 दिनों के भीतर पुनः आयातित की जाएंगी। विदेशों में बेची गई मर्दों के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के उद्देश्य हेतु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को 180 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी को बुक करेगा।

(ख) ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे

(1) सीमाशुल्क सत्यापित बीजक।

(2) सरकार/जीजेईपीसी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की प्रति।

(3) परिशिष्ट-22च में दिए गए प्रपत्र में नामित अभिकरण/ जी जे ई पी ई से प्रमाणपत्र।

(ग) नामित अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति के रूप में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का आयात किया जाएगा।

4क.19

नामित अभिकरण किए गए निर्यात, विदेश में बेची गई वस्तुओं, वस्तुओं को पुनः आयात और विदेश में खरीदी गई और भारत में आयातित धातुओं का पूरा लेखा जोखा रखेगा। ऐसा लेखा जोखा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

नामित अभिकरणों द्वारा आपूर्ति के तहत निर्यात	4क.20	निर्यातक निम्नलिखित आधार पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है :-  (1) निर्यात पूरा करने के पश्चात प्रतिपूर्ति के आधार पर, (2) अग्रिम रूप से तत्काल खरीद आधार पर, (3) ऋण आधार पर
प्रतिपूर्ति आधार	4क.21	निर्यातक बहुमूल्य धातु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की बुकिंग के लिए नामित अभिकरण को आवेदन कर सकता है। नामित अभिकरण के पास बुक बहुमूल्य धातु की मात्रा निर्यात उत्पाद में बहुमूल्य धातु के अंश और स्वीकार्य वेस्टेज के बराबर होनी चाहिए।
	4क.21.1	आवेदक बुकिंग के समय बहुमूल्य धातु के अनुमानित मूल्य का कम से कम 20% बयाना राशि जमा करेगा जिसे वास्तविक बिक्री के समय समायोजित कर लिया जाएगा।
	4क.21.2	निर्यातक बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र आधार पर जेवरात नोशनल दर पर निर्यात करेगा। निर्यातक क्रेता के क्रेडिट शर्तों के अन्दर मूल्य निर्धारित करेगा तथा उसकी आय नियत समय अथवा 180 दिन जो बी पहले हो प्राप्त करे। निर्यातक जो प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुमान आधार पर निर्यात कर रहे हैं वो उसी दर पर तथा मात्रा के नामित एजेंसी से सोना बुक कर सकते हैं जो उन्होंने क्रेता के साथ बुक किया है। नामित अभिकरण निर्यातक के बदले निर्धारित दर पर बहुमूल्य धातु खरीदेंगे और इसके पश्चात निर्यातक क्रम संख्या वाला एक खरीद प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य डालर में निर्दिष्ट होगा, साथ ही रुपये में भी मूल्य दर्शाया जाएगा। मूल्य वह वास्तविक मूल्य होगा जिस पर नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम खरीदा गया है और इसमें नामित अभिकरणों द्वारा मूल्य परिवर्धन के प्रयोजन के लिए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम के मूल्य पर लगाया गया अनुमत सेवा प्रभार शामिल होगा नामित एजेंसियों द्वारा निर्यातक हेतु क्रय प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित निर्यातक के आवेदन की दूसरी और तीसरी प्रतियाँ संबंधित सीमाशुल्क सदन को तथा नेगोशियेटिंग बैंक को भेजी जाएंगी जो सोने के क्रय की पुष्टि करेगी। निर्यातक जो अनुमानित दर पर निर्यात कर रहे हैं वे प्रतिपूरक तभी लेंगे जब आय प्राप्त हो जाएगी।
	4क.21.3	बुकिंग की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा और बुकिंग की तारीख से 150 दिन की अवधि के भीतर या निर्यात की तारीख से 30 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, बहुमूल्य धातु को निकाला जाएगा।

अग्रिम रूप से तत्काल  
खरीद आधार पर

4क.22

निर्यातक तत्काल खरीद आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को बैंक गारंटी/विविध वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विविध वचनबद्धता जैसा भी मामला हो, को लागू करेंगे।

4क.22.1

बहुमूल्य धातु की तत्काल खरीद की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा।

ऋण आधार पर

4क.23

निर्यातक ऋण आधार पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को बैंक गारंटी/विविध वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विविध वचनबद्धता को लागू करेंगे।

4क.23.1

निर्यातक को ऋण के आधार पर लिए गए स्वर्ण पर यथानिर्दिष्ट दर ब्याज देना होगा।

4क.23.2

सोने को ऋण आधार पर प्राप्त होने के 90 दिन के अधिकतम अवधि के अन्दर निर्यात पूर्ण करना है। निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4क.23.3

निर्यातक को नामित अभिकरणों रत्न/आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा जारी किए गए अनुमानित दर प्रमाणपत्र के आधार पर किए गए रत्न निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी। यह दरें मौजूदा स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर तथा अमेरिकी/ भारतीय रुपया दर अनुमानित दर प्रमाण-पत्र के आधार पर होगी। नामित एजेसियों/जीजेईपीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोतलदान की तारीख से 7 कार्य दिवसों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मूल्य संवर्धन को खरीददार और नामित अभिकरणों के साथ निर्धारित की गई दर को प्राप्त करना होगा। निर्यात की तिथि से 180 दिनों के अन्दर निर्यातकों को मूल्य निर्धारण करने और स्वर्ण ऋण की वापसी की छूट होगी। इस मूल्य के बारे में नामजद अभिकरणों को सूचित किया जाएगा जो दस्तावेजों पर कार्रवाई करने वाले बैंकों को दरन की अन्तिम पुष्टि दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि इस दर पर निर्यात आय को सुनिश्चित किया जाएगा।

4क.24

नामित एजेन्सी निर्यातक के ई ई एफ सी खाते से बहुमूल्य धातु के आयात की लागत का डालर में भुगतान स्वीकार कर सकती है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात	4क.25	मूल्य संवर्धन निर्यात दायित्व अवधि और चूक के विनियमन को छोड़कर इस प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय 4 के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए लागू प्रक्रिया इस स्कीम हेतु भी लागू होगी।
	4क.25.1	निर्यात दायित्व को प्राधिकार पत्र के तहत प्रत्येक परेषण के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा करना होगा। तथापि, निर्यात दायित्व अवधि स्वर्ण प्लेटिनम और चांदी के बने हुए फाइन्डिंग माउन्टिंग के आयात और आभूषणों के निर्यात के आयात होने के 180 दिन के भीतर होगी। इसके पश्चात निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। अग्रिम प्राधिकार पत्र निर्यात पूरा होने के पश्चात प्रतिपूर्ति के रूप में स्वर्ण का आयात कर सकता है।
	4क.25.2	अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले नामित अभिकरणों से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में, नामित अभिकरण प्राधिकार पत्र की विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति दोनों सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा।
हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र	4क.26	हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र हेतु नीति को विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.14 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
आवेदन पत्र	4क.26.1	इस स्कीम के प्रयोजन हेतु एक आवेदन प्रपत्र 'आयात निर्यात फार्म' में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
निर्यात दायित्व	4क.26.2	प्रत्येक खेप के प्रति निर्यात दायित्व की, सीमाशुल्क के माध्यम से ऐसी खेप की निकासी की तारीख से 5 महीने की अवधि के भीतर पूर्ति करनी होगी। तथापि, आयातक को किसी भी समय, न तो प्रत्येक आयात खेप के रिकार्ड रखने की आवश्यकता होगी। और न ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रति तुलनात्मक आयात खेपों के साथ निर्यात खेपों का सह संबंध रखने की आवश्यकता होगी।
वास्तविक चूक का विनियमन	4क.27	निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों में, उन बहुमूल्य धातुओं को जिन्हें उसने नामित अभिकरणों से प्राप्त किया है, को नियमित करेगा बशर्ते निर्यातक ने सीमाशुल्क प्राधिकारी को यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान किया हो। तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, उपरोक्त पैराग्राफ 4.28 में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे। यह किसी भी ऐसी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा इसके अधीन जारी आदेश या नियमों के तहत निर्यातक के विरुद्ध की जा सकती है।
उपभोक्त्यों के आयात हेतु प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र	4क.28	सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र जिसमें निर्यात निष्पादन दर्शाया हो के प्रस्तुत करने पर पिछले वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य के 2% के

बराबर के उपभोज्यों शुल्क मुक्त आयात के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। तथापि, रेडियम फिनिश चाँदी के आभूषणों के मामले में हकदारी ऐसे आभूषणों की 3 प्रतिशत होगी। यह प्राधिकार पत्र अहस्तान्तरणीय तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के मद्दे होगा। वह प्रतिपूरक प्राधिकार पत्र उपभोज्यों के शुल्क मुक्त आयात के लिए वैध होगा जैसा कि सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। यथोपरोक्त उपभोज्यों के आयात के लिए आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

रत्नों और आभूषणों  
के निर्यात पार्सलों को  
व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

4क.29

सभी ई ओ यू / एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बटूर, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डी टी ए में स्थित फर्मों से भी विदेशी क्रेताओं द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है। निर्यात के पर्सनल कैरिज की प्रक्रिया सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित होगी तथापि निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये प्राप्त किया जाएगा। विदेश जाने वाले यात्री द्वारा निर्यात के पर्सनल कैरिज के मामले में प्रतिपूर्ति दावे के लिए दस्तावेज वही होंगे जो ऊपर पैरा 4क.21.2 में दिये गये हैं। प्राधिकृत कोरियर कम्पनियाँ भी उपरोक्तानुसार में काम कर सकते हैं।

रत्नों और आभूषणों  
के आयात पार्सलों को  
व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

4क.30

सभी ई ओ यू और एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई बंगलौर, हैदराबाद और जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डी टी ए में स्थित सभी फर्मों से भी भारतीय आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है। इसकी प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल के आयात के समान होगी लेकिन और करने के लिए पार्सलों को आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारी को रिलीज सौंपा जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत आयातों की निकासी सामान्य सीमाशुल्क निकासी पद्धति के अनुसार होगी।

नमूनों का शुल्क  
मुक्त आयात

4क.31

रत्न और आभूषण मर्दों के विगत तीन वर्ष के निर्यात कारोबार के औसत के 0.25 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये तक के रत्न और आभूषण के नमूनों का शुल्क मुक्त आयात, जो भी कम हो, सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अनुमत होगा।

अस्वीकृत आभूषणों  
का पुनः आयात

4क.32

सादे/बहुमूल्य पत्थर जड़ित आभूषणों के निर्यातक को, पिछले लाइसंसिंग वर्ष में सीमाशुल्क नियमों और विनियमनों के अनुसार प्रयोग किए गए निवेशों पर प्राप्त किसी शुल्क छूट/वापसी/प्रतिपूर्ति लाभ की वापसी के साथ, किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक, अस्वीकृत और खरीदार द्वारा लौटाए गए आभूषण के शुल्क मुक्त पुनः आयात की अनुमति होगी।

रत्न और आभूषण 4क.33 रत्न और आभूषण डालर लेखा हेतु नीति का विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.19 में उल्लेख किया गया है। इसके संचालन की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

पिघलाने के लिए बहुमूल्य धातु स्क्रेप/प्रयोग किए गए आभूषणों के आयात और आभूषणों के पुनर्निर्यात की नीति विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4 क.21 में दी गई है। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

आयातित बहुमूल्य धातु स्क्रेप/प्रयोग किए गए आभूषणों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीमाशुल्क से निकासी की अनुमति दी जाएगी:

(क) कि आयातक उक्त प्रयोग किए गए आभूषण/बहुमूल्य धातु स्क्रेप पर डेढ़ गुना लेवी योग्य शुल्क के बराबर की बैंक गारंटी का बाण्ड प्रस्तुत करे:

(ख) आयातक, केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित निर्यात दायित्व और मूल्य संवर्धन को पूरा करे:

(ग) ऐसे आयात की, हैण्ड बैगेज के माध्यम से अनुमति नहीं होगी।

इस पैराग्राफ के तहत सुविधा के संचालन के लिए मूल्य संवर्धन आवश्यकता और निर्यात दायित्व आदि सहित ब्यौरेवार प्रक्रिया को डीजीएफटी द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

खेप आधार पर हीरे और आभूषण के निर्यात 4 क.35

खेप आधार पर हीरे और आभूषण के निर्यात के लिए नीति विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4 क.23 में दी गई है।

इस संबंध में ब्यौरेवार प्रक्रिया संगत सीमा शुल्क नियमों और विनियमों के द्वारा नियंत्रित होगी। खेप आधार पर निर्यातित मर्दों या पूरे अथवाआंशिक तौर पर का पुनः आयात इस शर्त के अधीन होगा कि निर्यातक यह स्थापित करने के लिए कि निर्यात किया गया माल वही है संगत सीमाशुल्क अधिसूचना के निर्धारित प्रावधानों का पालन करेगा।



## अध्याय - 5

## निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ई. पी. सी. जी.) स्कीम

- नीति 5.1 विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 में निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम से संबंधित नीति दी गई है।
- आवेदन प्रपत्र 5.2 प्राधिकार पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन, 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजे जा सकते हैं जहाँ बचाया गया शुल्क 50 करोड़ रुपये हो।
- आवेदनों पर विचार 5.3 ऐसे मामलों के लिए जहाँ, बचाया गया शुल्क 50 करोड़ रुपए से अधिक है, आवेदक, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुख्यालय में सीधे आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में, डी.जी.एफ.टी. के निर्देशों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।
- 5.3.1 सम्बंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट 32 क में दिए गए स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर (सीईसी) के नेक्सस प्रमाणपत्र के आधार पर ई पी सी जी प्राधिकार पत्र जारी करेगा।
- 5.3.2 प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकारी अथवा स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर (सी.ई.सी.) द्वारा जारी प्रमाण पत्र आयात पूरा करने के 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि पूँजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं)/विक्रेता (विक्रेताओं) की फैक्टरी परिसर में स्थापित कर दिया गया है।
- 5.3.3 आयातों के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 के पैरा 4.19 में निर्दिष्ट एक मात्र पंजीकरण पत्तन के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। तथापि, पैराग्राफ 4.19 में विनिर्दिष्ट किसी पत्तन से निर्यात किया जा सकता है।
- 5.3.4 (1) आवेदक पूँजीगत माल के रख-रखाव और अधिष्ठापन के लिए आवश्यक स्पेयर्स, टूल्स, स्पेयर, रिफ्रैक्टरी और कैटालिस्ट के आयात के लिए भी आवेदन कर सकता है। आवेदन में, चार्टर्ड इंजीनियर अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित, आवेदक की फैक्ट्री/प्रांगण में अधिष्ठापित प्लांट/मशीनरी की सूची, संलग्न होनी चाहिए, जिसके लिए स्पेयर्स, टूल्स, स्पेयर रिफ्रैक्टरीज और कैटालिस्ट की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र स्पेयर्स की सूची को

विनिर्दिष्ट नहीं करेगा बल्कि निम्नलिखित को दर्शाएगा:

- (क) प्लांट/मशीनरी का नाम जिसके लिए स्पेयर्स की आवश्यकता है।
- (ख) प्राधिकार पत्र के तहत अनुमत बचाए गए शुल्क का मूल्य।
- (ग) विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात दायित्व के मूल्य सहित निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण।

(2) हटा दिया गया है।

(3) इसके अलावा, निर्यात दायित्व को अन्तिम रूप से पूरा करते समय प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्राधिकार पत्र धारक द्वारा रखे गए स्टॉक और खपत रजिस्टर के आधार पर अधिष्ठापित पूंजीगत वस्तुओं में इस प्रकार आयातित स्पेयर्स, टूल्स, स्पेयर रिफ्रैक्ट्रीज और कैटालिस्ट का प्रयोग किया गया।

ईओयू/पुनर्स्थापित  
एस ई जैड यूनिटों का  
ई.पी.सी.जी. स्कीम  
में परिवर्तन

5.4

एक ई.ओ.यू/पुनर्स्थापित एस.ई.जैड एकक, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में दिए गए प्रपत्र में, निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है। संबंधित विकास आयुक्त से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

पूंजीगत माल की  
स्वदेशी स्रोतों से प्राप्ति

5.5

स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत माल को प्राप्त करने के इच्छुक ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक, सीधे आयात के लिए आवेदन पत्र सहित अथवा ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद ई पी सी जी प्राधिकार पत्र को अमान्य कराने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी को अनुरोध भेजेंगे जिसमें उस व्यक्ति का नाम और पता भी होगा जिससे वह पूंजीगत माल प्राप्त करना चाहता है।

5.5.1

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी दो प्रतियों में अवैधीकरण पत्र जारी करेगा।

5.5.2

ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति करने के इच्छुक स्वदेशी विनिर्माता, 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में दिए गए प्रपत्र में, क्षेत्रीय प्राधिकारी को, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को आपूर्ति के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए यथा अपेक्षित ऐसी निविदियों के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस को जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- 5.5.3 हटा दिया गया है।
- पूँजीगत माल को 5.6 ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक, पूँजीगत माल को घरेलू लीजिंग पट्टे पर देना कम्पनी से प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में, आयातित पूँजीगत माल का प्रविष्टि बिल या स्वदेशी रूप से प्राप्त वाणिज्यिक बीजक, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक और लीजिंग कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। तथापि, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्त 5.7 विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 5.4 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी लागू होगी:-
- 5.7.1 ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक या तो सीधा निर्यात अथवा तीसरी पार्टी (पार्टियों) के माध्यम से निर्यात करेगा। यदि व्यापारी निर्यातक, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक है तो सहायक विनिर्माता का नाम जहाजरानी बिल में दर्शाया जाएगा। निर्यात के समय, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र सं. और तारीख जहाजरानी बिल पर पृष्ठांकित किया जाएगा जिसे निर्यात दायित्व के निष्पादन के लिए प्रस्तुत किया जाना है।
- 5.7.2 मान्य निर्यात के अलावा निर्यात आय, मुक्त रूप से मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएगी।
- 5.7.3 हटा दिया गया है।
- 5.7.3.1 तेल और गैस क्षेत्र को की गई आपूर्तियों को ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व को पूरा किया गया समझा जाएगा बशर्ते इसे 31.3.2000 को या उससे पहले जारी किया गया हो और ऐसी आपूर्तियों के लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 के तहत कोई लाभ न लिया गया हो।
- 5.7.4 निर्यात का औसत स्तर निर्धारित करने के लिए पूर्व यू.एस.एस.आर. या महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य देश को किये गये निर्यात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
- 5.7.5 ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत किए गए निर्यात, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 के तहत लाभों के भी हकदार होंगे।
- 5.7.6 हस्तशिल्प, कुटीर, हथकरघा, अत्यन्त छोटे उद्योग, कृषि, जल कृषि, पशु-पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगुरोत्पादन, मुर्गीपालन, और रेशमोत्पाद से संबंधित वस्तुओं के निर्यात के मामले में निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इन क्षेत्रों द्वारा

ईपीसीजी स्कीम के तहत औजारों को छोड़कर आयातित माल को, आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे मामलों में भी जहाँ निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया है, हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, पूंजीगत माल के हस्तांतरण की अनुमति समूह कम्पनियों या प्रबंधित होटलों के भीतर दी जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय प्राधिकारी और विनिर्माता/ व्यापारी निर्यातकों के मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी और सेवा प्रदायकों के मामले में केवल क्षेत्रीय प्राधिकारी को दी जाएगी।

5.7.7 हटा दिया गया है।

5.7.8 जहाँ साथ-साथ अथवा बारी-बारी से एक से अधिक ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं, वास्तविक प्राप्ति के बावजूद, सिर्फ पिछले औसत निर्यात दायित्व के आधार पर नए ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र तैयार किए जाएंगे।

5.8 हटा दिया गया है।

5.8.1 हटा दिया गया है।

5.8.2 हटा दिया गया है।

5.8.3 हटा दिया गया है।

5.8.4 31.3.2000 तक जारी किए गए ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर.ई-99) के पैराग्राफ 6.11 में दिए गए प्रावधानों द्वारा अधिशासित किए जाएंगे। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर.ई-99) के उन्हीं प्रावधानों के बावजूद, मूल्यवार कमी के मामले में प्राधिकार पत्र धारक को विशेष आयात लाइसेंस वापिस नहीं करना होगा। 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-01) के अध्याय-6 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित किए जाएंगे।

1 अप्रैल 2002 से 31 अगस्त, 2004 तक जारी प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-02) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित किए जाएंगे। तथापि, पुराने लाइसेंसों के मामले में भी क्लबिंग की शर्त इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.18 की मौजूदा शर्त के अनुसार होगी।

5.8.5 हटा दिया गया है।

5.8.6 ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत मौजूदा निर्यात दायित्व के मामले में, एक नया ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र तभी जारी किया जा सकता है जब कि पिछले दायित्व की औसत (पिछले ई.पी.सी.जी. में बचाए गए शुल्क की वजह से बड़ी रकम सहित) को बनाए रखा जाए।

- निर्यात दायित्व की निगरानी 5.9.1 प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व को पूरा करने में की गई प्रगति के बारे में, क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट डी.जी.एफ.टी. की वेबसाइट पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से भी प्रस्तुत की जायेगी। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी पूरे किए गए निर्यात दायित्व के लिए आंशिक निर्यात दायित्व पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा बशर्ते कि निर्यात निष्पादन आनुपातिक रूप से पर्याप्त हो।
- 10 प्रतिशत सी आई एफ मूल्य तक स्वचालित कमी/ वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/ वृद्धि 5.10 यदि जारी प्राधिकार पत्र प्राधिकार पत्र के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक/बचाए गए शुल्क से अधिक मूल्य के आयात के लिए उपयोग किया गया है तो प्राधिकार पत्र को यथा-अनुपात आधार पर बढ़ा दिया जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना ही प्राधिकार पत्र के 10 प्रतिशत/ बचाए गए शुल्क से अधिक में माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा।
- ऐसे मामलों में, प्राधिकार पत्र धारक लागत बीमा भाड़ा मूल्य/ बचाई गई राशि के आधार पर किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए अतिरिक्त आयातों के एक महीने के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अतिरिक्त फीस देगा। निर्यात दायित्व स्वयं यथानुपातिक रूप से बढ़ जाएगा।
- 5.10.1 इसी प्रकार, यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक ने प्राधिकार पत्र में दिए गए मूल्य से कम प्राधिकार पत्र का प्रयोग किया है, तो उसका निर्यात दायित्व प्राधिकार पत्र के वास्तविक प्रयोग के सन्दर्भ में यथानुपात आधार पर कम हो जाएगा।
- 5.11 संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र के तहत लागू कुल निर्यात दायित्व के 10 प्रतिशत तक लागू निर्यात दायित्व में वृद्धि अथवा प्राधिकार पत्र के तहत बचाये गये कुल शुल्क के 2 प्रतिशत के संयोजन शुल्क का भुगतान करके निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की मंजूरी हेतु एक अथवा अधिक आवेदनों पर विचार कर सकता है जैसा भी मामला हो, वह माँगे गये विस्तार के प्रत्येक वर्ष हेतु निर्यातक की इच्छा पर आधारित होगा। यह विस्तार 2 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए हो सकता है।
- तथापि ऊपर उपलब्ध 2 वर्षों से अधिक की अवधि हेतु निर्यात दायित्व विस्तार पर 50 प्रतिशत तक बढ़ाये निर्यात दायित्व पर 2 वर्षों तक के विस्तार हेतु इस शर्त पर विचार किया जाएगा कि प्राधिकार पत्र धारक द्वारा आपूर्ति निर्यात दायित्व का 50 प्रतिशत शुल्क सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भुगतान करना होगा, यह क्षेत्रीय प्राधिकार पत्र द्वारा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र में विस्तार करने के पृष्ठांकन करने से पहले करना होगा। ऐसे मामलों में, संयोजन प्रशुल्क का भुगतान नहीं करना होगा या अतिरिक्त निर्यात दायित्व लगाया जाएगा जैसा कि उपरोक्त पैरा में

विनिर्दिष्ट होगा। यदि फर्म अभी भी निर्यात दायित्व पूरा नहीं कर सकी है तो पहले से जमा किए शुल्क को कुल शुल्क और निर्यात दायित्व में चूक करने के लिए दिये जाने वाले ब्याज में से काट लिया जाएगा।

निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार उन शर्तों के तहत दिया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।

- 5.11.1 फर्म/कम्पनी जो कि भी आई एफ आर/राज्य सरकार के पुर्नवास विभाग के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन कर रही है, संबंधित एजेन्सी द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए छूट के संबंध में, यदि कोई हो, महानिदेशक, विदेश व्यापार को सूचित करेगी।

उसके बाद महानिदेशक, विदेश व्यापार ऐसी फर्म/कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर लगाए गए निर्यात दायित्व की पूर्ति में चूक के संबंध में संबंधित एजेन्सी से सरकार के हितों की रक्षा के मामले पर विचार करेंगे।

विदेश व्यापार महानिदेशक, 12 वर्ष तक के विस्तार की अवधि की मंजूरी के लिए अथवा संचालन एजेंसी द्वारा तैयार और भी एफ आई आर बोर्ड/राज्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार कर सकते हैं।

- 5.11.2 निर्यात दायित्व को हटाने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि निर्यातक अवश्यभावी स्थितियों अथवा अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों/कारणों से निर्यात दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहा। ऐसे अनुरोध पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के तहत वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इस समिति के निर्णय को कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

- निर्यात दायित्व में कमी 5.12 संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, बचाए गए शुल्क से हुई निर्यात दायित्व में 5 प्रतिशत तक की कमी को माफ भी कर सकता है।

- विमुक्ति 5.13 निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रूप में, प्राधिकार पत्र धारक आयात-निर्यात फार्म में दिए गए दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेगा।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी सन्तुष्ट होने पर, ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व के निष्पादन का प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, सीमाशुल्क प्राधिकारियों जिनके साथ बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित की है, को भेजेगा।

क्षेत्रीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आवेदन 30 दिनों के भीतर निपटाए जाएँ। यदि कोई कमी है तो उसे एक बार में देख लिया जाए। उसके बाद सभी पत्राचार सिर्फ उन कमियों के बारे में होंगे। यदि आवश्यक हुआ तो नया पत्राचार 15 दिनों के भीतर किया जाए। एक बार दस्तावेज पूरे हो जाने पर सभी दस्तावेजों/ सूचनाओं के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व निष्पादित कर दिया जाएगा। अन्तिम निष्पादन प्रमाणपत्र/अस्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया, प्रारम्भिक आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। जो आवेदन 90 दिनों की अवधि के बाद भी बकाया है उनकी सूचना कारणों सहित तत्काल डी.जी.एफ.टी. को दी जाएगी।

- |   |        |   |
|---|--------|---|
| वास्तविक घूक का विनियमन                                 | 5.14   | यदि ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारी निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह, सीमाशुल्क प्राधिकारी को सीमाशुल्क तथा ब्याज का भुगतान करेगा। ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक द्वारा अपनी मर्जी से बाहर होने की सुविधा रहेगी।   |
| लेखों का रख-रखाव  | 5.15   | प्रत्येक ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक विमुक्ति की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए निर्यात/की गई आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं का सही और उचित लेखा रखेगा।  |
| ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का पुनः निर्यात | 5.16   | ई.पी.सी.जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल जो खराब अथवा अप्रयुक्त पाया गया हो अपने आयात के शुल्क के भुगतान की तारीख से 3 वर्षों के भीतर विदेशी सप्लायर को पुनः निर्यात कर दिया जाए जिसकी अनुमति क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमाशुल्क प्राधिकारी से ली जाए। परिणामस्वरूप निर्यात दायित्व पुनः निर्धारित किया जाएगा।          |
| पूंजीगत माल की प्रतिस्थापना                             | 5.16.1 | आयातित और खराब पाया गया अथवा अन्यथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त पूंजीगत माल को निर्यात किया जाएगा तथा ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत उसके बदले में आयात किया जाएगा। ऐसे मामलों में, निर्यात की अनुमति देते समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी प्राप्त किए गए शुल्क लाभ को ऐसे प्रतिस्थापित पूंजीगत माल को आयात के समय पुनः घटा दिया जाएगा। |
| दण्डात्मक कार्यवाही                                     | 5.17   | निर्यात दायित्व या प्राधिकार पत्र की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, प्राधिकार पत्र धारक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और नियमों एवं नीति तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाई की जा सकती है।                        |
| ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग                     | 5.18   | उसी प्राधिकार पत्र धारक के दो अथवा इससे अधिक ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी।  |

- 5.18.1 हटा दिया गया है।
- 5.18.2 क्लबिंग के लिए आवेदन 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में केवल क्षेत्रीय प्राधिकारी को किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के मामले में क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी।
- (क) हटा दिया गया है।
- (ख) हटा दिया गया है।
- (ग) हटा दिया गया है।
- 5.18.3 कुल निर्यात दायित्व बचाए गए कुल शुल्क अथवा आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पुनः नियत किया जाएगा।
- 5.18.4 क्लबिंग पर, सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र एकल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र माना जाएगा। क्लब किए गए प्राधिकार पत्र के लिए निर्यात दायित्व अवधि पहले प्राधिकार पत्र को जारी करने की तारीख से मानी जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, जहाँ क्लब किए गए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/ बचाया गया शुल्क मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक हो, निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि में को संगत लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।
- 5.18.5 क्लब किए गए प्राधिकार पत्र के लिए औसत निर्यात दायित्व क्लबिंग के लिए व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र पर लगाए गए औसत निर्यात दायित्वों का अधिकतम होगा।
- 5.18.6 ई ओ पी के समाप्त होने के बाद क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी।
- सी आई एफ आधारित  
ई ओ से शुल्क आधारित  
निर्यात दायित्व में परिवर्तन  
होने पर निर्यात दायित्व  
का पुनः निर्धारण
- 5.19 (क) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक नोति के पैरा 5.4 (1) में दिए गए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में दिए गए निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है।
- (ख) हटा दिया गया है।
- (ग) सभी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए, प्राधिकार पत्र धारक आवेदन की तारीख से पिछले ब्लाक तक के अनिवार्य (वास्तविक अथवा संशोधित) ब्लाकवार निर्यात दायित्व को पूरा करे। ऐसे सभी मामलों में, पुनः निर्धारित निर्यात दायित्व का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा: (पूरा न किया गया प्रतिशत निर्यात दायित्व) x (8) x (प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से बचाया गया शुल्क)
- (घ) हटा दिया गया है।



(ड.) निर्धारित किए गए औसत निर्यात दायित्व अथवा वास्तविक प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि में परिवर्तन नहीं होगा।

(च) हटा दिया गया है।

पूँजीगत माल का  
तकनीकी उन्नयन

5.20

पूँजीगत माल के तकनीकी उन्नयन के लिए आवेदन 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में किया जाएगा।

रिफरबिशड/रिकंडीशंड  
पुर्जों और औजारों  
का आयात

5.21

रिफरबिशड पुर्जों का आयात ईपीसीजी योजना के तहत अनुमत किया जाएगा।

तथापि ऐसे रिफरबिशड/रिकंडीशंड पुर्जों की शेष अवधि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक द्वारा प्रमाणित मूल पुर्जों की कालावधि 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

ईपीसीजी योजना के तहत आयातित औजार आवेदक की समूह कंपनियों या किसी भी एकक को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

5.22

ई.पी.सी.जी. योजना के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्रों के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

## अध्याय - 6

**निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क  
(ई एच टी पी), साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी) स्कीम और बायो टेक्नोलॉजी पार्क  
(बी टी पी एस)**

स्कीम	6.1	निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी) और साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी) व जैव प्रौद्योगिकी पार्क बी टी पी एस स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 6 में दी गयी है।
	6.2	हटा दिया गया है।
अनुमोदन/आवेदन और आवेदन का नवीनीकरण	6.3.1	ई ओ यू स्थापित करने हेतु परिशिष्ट-14-1क में दिए गए अनुसार आवेदन की तीन प्रतियां विकास आयुक्त को प्रस्तुत करनी होगी।
	6.3.2	सेवा क्षेत्रों में (आर एंड डी, साफ्टवेयर और आई टी समर्पित सेवाएं, या बी ओ ए द्वारा नामित कोई अन्य सेवा कार्यक्रमों में यूनिट की स्थापना हेतु प्रस्तावों के अलावा) ई ओ यू स्कीम के तहत यूनिटों की स्थापना हेतु आवेदन परिशिष्ट-14-1ग में दिए अनुमोदन संबंधित क्षेत्र विशिष्ट शर्तों तथा परिशिष्ट 14-1 ख में उल्लिखित मापदण्डों के अनुसार 15 दिनों के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अथवा रद्द किया जाएगा। अन्य मामलों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निकासी के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
	6.3.3	औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ई ओ यू स्थापित करने वाले प्रस्तावों को अनुमोदन बोर्ड (परिशिष्ट-14-1घ) और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा गुण दोष के आधार पर 45 दिनों के भीतर प्रस्ताव की निकासी के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
	6.3.4.1	साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कॉम्प्लेक्सों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उद्यमों अथवा उनके किसी संयोजन के द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अन्तर मंत्रालय स्थायी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित होगा। ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट स्थापित करने हेतु आवेदन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.3.4.2 बीटीपी यूनिट केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र उद्यमों अथवा इनके किसी भी संयोजन द्वारा स्थापित किया जाएगा। बी टी पी स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग को देना होगा और ऐसे आवेदन जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों पर पूरे उतरते हैं उन्हें मंजूर कर डीजीएफटी को अधिसूचना हेतु संस्तुत किया जाएगा। बीटीपी यूनिट को स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.3.6 एल ओ पी/एल ओ आई में विनिर्माण मर्दे/सेवा गतिविधियों वार्षिक क्षमता, डालरों में प्रथम पांच वर्षों के लिए अपेक्षित वार्षिक निर्यात, शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन, सीमाएँ, तैयार माल उप-उत्पाद और डीटीए में बेकार माल की बिक्री, यदि कोई हो तथा ऐसे कोई अन्य मामले जो आवश्यक हो तथा ऐसी शर्तें भी लगा सकते हैं जो अपेक्षित है का उल्लेख होगा।

6.3.7 संबंधित प्राधिकारी द्वारा ई ओ यू / ई एच टी पी / एस टी पी / बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी / एल ओ आई सभी उद्देश्यों हेतु प्राधिकार पत्र माने जाएंगे। ई ओ यू यूनिटों हेतु एल ओ पी का मानक प्रपत्र परिशिष्ट 14-1 ड में दिया गया है।

6.3.8 ई ओ यू का अलग एल ओ पी हेतु अलग निर्धारित परिसर होंगे। ई ओ यू लीजड परिसरों पर अनुमोदित की जा सकती है बशर्त कि लीज सरकारी विभाग/उद्यम/एजेंसी से प्राप्त की गयी हो। तथापि, यदि लीज निजी पक्षों से प्राप्त की गयी हो तो इसकी वैधता एल यू टी की तारीख से 5 वर्षों की अवधि हेतु होगी तथा विकास आयुक्त लीज की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

6.3.9 नीति के पैरा 6.6 में उल्लिखित अनुमोदित अवधि के पूरा होने पर, स्कीम में बने रहने अथवा उससे बाहर चले जाने का विकल्प यूनिट को होगा। यदि अनुमोदित अवधि की समाप्ति के छह महीनों की अवधि के भीतर यूनिट से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती तो विकास आयुक्त ई ओ यू स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदन को स्वयं रद्द करने की कार्यवाही करेगा और इस संबंध में आगे की कार्यवाही करेगा। जहाँ यूनिट स्कीम के तहत बने रहना चाहती है, विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि को आगे बढ़ा देगा।

विधिक वचनबद्धता

6.4.1 अनुमोदित ई ओ यू/ईएचटीपी/एस टी पी/बीटीपी यूनिट परिशिष्ट-14-1 च में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार संबंधित विकास आयुक्त को विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी।

6.4.2 सभी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों का स्थायी ई.मेल पता होना चाहिए। स्थायी ई.मेल पता तथा उपरोक्त ई.मेल आई डी पर डिजिटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में नई यूनिटों हेतु कोई विधिक वचनबद्धता निष्पादित नहीं की जाएगी। ईओयू का स्थायी ई.मेल पता तथा

डिजीटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में आगे आयात और डीटीए बिक्री की विकास आयुक्त द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

माल और सेवाओं  
का निर्यात

- 6.5.1 सॉफ्टवेयर यूनिटें, पेशेवर सेवाओं के सहित निर्यात समेत डाटासंचार लिंकों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक निर्यात (जो कूरियर सेवा के माध्यम से भी) कर सकती हैं।
- 6.5.2 ईओयू नामित एजेंसी द्वारा जारी नोशनल रेट सर्टीफिकेट के आधार पर आभूषणों का निर्यात करने हेतु अनुमति होगी। यह रेट नोशनल रेट सर्टीफिकेट में प्रचलित स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर और अमेरिकी डालर/भारतीय रूपया दर पर आधारित होगा। नामित एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोत लदान की तारीख के 3 कार्य दिवसों से पहले का नहीं होना चाहिए।
- 6.5.3 निर्यातक को निर्यात करने की तारीख से 180 दिन के भीतर स्वर्ण का मूल्य निर्धारित करने और स्वर्ण ऋण चुकाने की छूट होगी। नामित एजेंसियों को मूल्य की सूचनाएं दी जाएगी जो प्रमाणपत्र जारी करेंगी जिसमें निर्यात आय इस दर पर प्राप्त करने को सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज तैयार करने वाले बैंक की दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाता हो।
- 6.5.4 रत्न और आभूषण तथा आभूषण ईओयू आयातित माल का पुनः निर्यात और घरेलू तौर पर खरीदे माल का निर्यात कर सकती हैं इनमें आंशिक संसाधन/विनिर्माण से पैदा हुई वस्तुएँ शामिल हैं। इसके अलावा, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करके यथा लागू वैध रत्न एवं आभूषण प्रतिपूर्ति के प्रति डीटीए में आयातित अथवा स्वदेशी तौर पर खरीदे माल के मूल्य के 5% तक अनुपयुक्त/ टूटे कटे और पालिशड हीरों, कीमती और अर्ध-कीमती रत्नों की आपूर्ति भी अनुमत होगी।

माल का आयात/  
घरेलू प्रापण

- 6.6.1 घरेलू टेरिफ क्षेत्र से निम्नलिखित पूँजीगत माल के आयात/खरीद की अनुमति होगी:-
- (क) कच्चा माल, संघटक, उपभोग्य, अन्तरवर्ती, कल-पुर्जे और पैकिंग सामग्री;
  - (ख) पूँजीगत माल, चाहे नया हो या पुराना हो, जिसमें अब तक के परिवर्तनों सहित निम्नलिखित और उनके कल-पुर्जे:
    - (i) डी जी सैट्स, कैपटिव पावर प्लांट्स, ट्रांसफार्मर्स तथा सभी के लिए सहायक उपकरण।
    - (ii) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।
    - (iii) गुणवत्ता आश्वासन उपकरण।

- (iv) सामग्री प्रबंधन उपकरण जैसे फोर्क लिफ्ट्स तथा ओवरहैड क्रेन्स, मोबाइल क्रेन्स, कालर क्रेन्स, हाईस्टस और स्टेकर
- (v) अबाधित बिजली आपूर्ति प्रणाली (यू पी एस) संचयन के लिए विशेषरैक्स, संचयन प्रणाली, मोड्यूलर फर्नीचर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, एंटी स्टैटिक कारपेट, टेलीकन्फ्रेंसिंग उपकरण, सर्वो कन्ट्रोल प्रणाली, एयर-कंडीशनर्स/एयरकंडीशनिंग सिस्टम विद्युत उपकरण के लिए पैनल स्पेशल डाटा ट्रान्समीशन केबल।
- (vi) सुरक्षा प्रणालियाँ।
- (vii) टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स, गोजिस, मोल्ड्स, डाइस, उपकरण तथा अनुषांगिक मदें।
- (ग) यूनिट के भीतर उपयोग हेतु पूँजीगत माल बनाने के लिए कच्चा माल।
- (घ) अन्य जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
  - (i) मौजूदा उत्पाद (उत्पादों) हेतु प्रोटोटाइप तथा तकनीकी नमूने तथा उत्पाद दिशान्तरण, विकास अथवा मूल्यांकन
  - (ii) ड्राइंग्स, ब्लू प्रिन्ट्स, चार्ट्स, माइक्रो फिल्म और तकनीकी डाटा।
  - (iii) पी ए बी एक्स, फैक्स मशीनें, वीडियो प्रोजेक्शन प्रणाली कम्प्यूटर्स, लेपटाप, सर्वर सहित कार्यालय उपकरण।
- (ङ) उक्त मदों के लिए कल-युर्जे तथा उपभोज्य।
- (च) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अन्य कोई मद जो ऊपर उल्लिखित न हो।

6.6.2 ईओयू मरम्मत/पुनर्निर्माण के बाद निर्यात हेतु सादा/जड़ित स्वर्ण/प्लेटिनम अथवा चाँदी आभूषणों का आयात कर सकती है।

आयात की शर्तें

6.7 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी द्वारा आयात निम्नलिखित शर्तों के प्रति होगा:-

- (क) माल का ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी परिसरों में आयात किया जाएगा। तथापि, ईओयू में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के एकक क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पहले ही सूचित करके फार्मों/खदानों में पूँजीगत वस्तुओं और निविष्टियों की आपूर्ति/हस्तांतरण कर सकते हैं बशर्ते माल का स्वामित्व ईओयू एकक का हो। ग्रेनाइट सैक्टर को खदान स्थल को पूँजीगत माल के मूल्य के 5 प्रतिशत तक हिस्से पूजों को ले जाने की भी अनुमति होगी।

- (ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी की एककों के लिए सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों के अधीन यथा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया अपनाई जायेगी और सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के पास उचित बॉण्ड प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ग) पूँजीगत माल और कल-पूजों को छोड़कर वस्तुओं का ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी द्वारा उपयोग तीन वर्ष या सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर किया जायेगा। तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मर्दों के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व (जी.आई.टी.सी) (एच एस) के अध्याय-9 के अन्तर्गत) की प्रतिपूर्ति आयात की प्रथम खेप की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा तथा आयात की प्रथम खेप की तिथि को सीमा शुल्क प्राधिकारी स्पष्ट करेगा।
- (घ) अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व आयातित/जहाज से भेजी गई/पहुँच चुकी वस्तुएँ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी के तहत शुल्क मुक्त निकासी हेतु पात्र होंगी बशर्ते सीमा-शुल्क का भुगतान न किया गया हो और वस्तुओं की सीमाशुल्क प्राधिकारी से निकासी न कराई गई हो।

अनुमोदित परिसरों के बाहर फैक्स मशीनों/लैपटॉप कम्प्यूटर	6.8.1	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट पर एक फैक्स मशीन लगा सकते हैं बशर्ते कि इसके कार्य स्थल के बारे में सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित सहायक आयुक्त को सूचित किया जाएगा।
	6.8.2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट आयातित लैपटॉप कम्प्यूटर और वीडियो प्रोजेक्शन सिस्टम को बांडेड कार्य स्थल से अस्थायी रूप से बाहर ले जा सकते हैं ताकि इन पर प्राधिकृत कर्मचारी कार्य कर सकें।
	6.8.3	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय में राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के प्रति शुल्क मुक्त आयातित/प्राप्त निजी कम्प्यूटर, जो दो से ज्यादा न हो लगा सकते हैं।
	6.8.4	सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर यूनिटों द्वारा प्राधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी संचालित सेवाएँ और व्यक्ति संचार लिंकों के माध्यम से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में स्थापित सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
पूँजीगत माल की लीजिंग	6.9	लीजिंग कम्पनियों के माध्यम से वित्तपोषित मुफ्त प्राप्त और/अथवा ऋण आधार पर आयातित पूँजीगत माल के मूल्य को भी विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित नेट विदेशी मुद्रा के परिकलन के उद्देश्य हेतु गिना जाएगा।
निबल विदेशी मुद्रा अर्जन	6.10.1	ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी यूनिटें निबल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। शुद्ध विदेशी मुद्रा की संगणना पांच वर्षों के ब्लाक हेतु निम्नलिखित

फार्मूला के अनुसार किया जाएगा। केवल अनुज्ञापत्र/आगमपत्र में विनिर्दिष्ट निर्यात हेतु विनिर्माण की मंटे निबल विदेशी मुद्रा की संगणना हेतु ध्यान में रखी जाएंगी। सकारात्मक एन एफ ई = 'ए' - बी > शून्य जबकि एन एफ ई निबल विदेशी मुद्रा है ए ई ओ यू/ई एच टी पी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है और 'बी' सभी आयातित व निविष्टि का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, सभी आयातित माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाह्य उधार पर ब्याज के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतान का मूल्य या कोई अन्य प्रभार का समग्र योग है। निविष्टि का तात्पर्य कच्चे माल, अन्तरवर्ती, संघटक, उपभोज्य, कलपुर्ज और पैकिंग से है।

6.10.2 यदि कोई निविष्टि अन्य ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/एसईजैड/बी टी पी यूनिट या भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों अथवा बॉडेड गोदाम अथवा नामित एजेन्सियों से प्राप्त कीमती धातु से प्राप्त होती हैं तो ऐसी निविष्टि का मूल्य बी के अधीन शामिल किया जाएगा।

6.10.3 यदि किसी लीजिंग कम्पनी से मुफ्त आयातित किसी पूँजीगत माल को लीज किया जाता है, मुफ्त और/अथवा ऋण आधार पर या हस्तांतरण आधार पर प्राप्त किया जाता है तो पूँजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य को प्रत्येक यूनिट के पास जिस शेष अवधि के लिए बी के अधीन यथानुपात जैसा भी मामला हो, शामिल किया अथवा नहीं किया जाएगा।

6.10.4 निबल विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना के लिए आयातित पूँजीगत माल के मूल्य का भुगतान इस प्रकार किया जाएगा। प्रथम - दस वर्ष = 10 प्रतिशत।

खातों का रखरखाव

6.11.1 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने खातों को नियमित रखें और परिशिष्ट-14 1-च में दर्शाये गए नियमों के अनुसार विकास आयुक्त/सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय/जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6.11.2 यूनिट डीटीए में निर्यात और बिक्री/आपूर्ति या अन्य एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को हस्तांतरित और अपने स्टॉक के शेष माल के माध्यम से प्रमुख मालों के प्रत्येक श्रेणी के आयात/प्राप्त माल का हिसाब लगा सकेगी। तथापि किसी भी समय यूनिटों को अपने निर्यातों के साथ प्रत्येक आयात खेप को सम्बद्ध करना, अन्य एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को हस्तान्तरण करने, डीटीए में बिक्री करने और शेष वस्तुओं को स्टॉक में रखना अपेक्षित है। ऐसे मामले में स्पष्टीकरण कि माल समान हैं अथवा नहीं, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा।

निवल विदेशी मुद्रान लैपटॉप कम्प्यूटर	6.12.1	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14.1छ में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ईओयू/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के निष्पादन की निगरानी की सचूना व तकनालाजी मंत्रालय/ जैव प्रौद्योगिकी विभाग संबंधित केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से करेगा।
	6.12.2	सकारात्मक एन एफ टी सुनिश्चित न कर पाने और ओपी/एलओआई/आईएल/एलयूटी की शर्तों का अनुसरण न कर पाने पर इस एकक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन किसी अन्य कानून/ नियमों और एलओपी/एलओआई/आई एल को रद्द करके या मंजूर करके बिना किसी पूर्वाग्रह के दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रेप/डस्ट/ स्वीपिंग का मानक छड़ों में परिवर्तन	6.13	सोना/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रेप/डस्ट/स्वीपिंग ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी से गर्वन्मैट ऑफ इण्डिया मिण्ट/प्राइवेट मिण्ट को भेजी जा सकती है और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मानक रोध में उन्हें लौटाई जा सकती है अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित सोना/ चाँदी/प्लेटिनम काण्टेन्ट के आधार पर लागू सीमाशुल्क के भुगतान पर डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है।
डीटीए आपूर्ति	6.14	नीति के पैरा 6.8 में डी टी ए बिक्री के प्रावधान को ध्यान में न लाकर, ऐसी डी टी ए बिक्री उस समय में आयात के समय लागू नियमों एवं अन्य प्रतिबंधों को भी ध्यान में लाना होगा ऐसा करने से आयातक किसी अन्य लागू नियम/विनियम की छूट के लिए अधिकृत नहीं होगा। आयातक को कानूनों अथवा नियमों के सतह किन्ही आवश्यकताओं के प्रति प्रतिबद्धता अथवा अनुपालन से किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत भी प्राप्त नहीं होगी।
अन्य ईओयू/ईएच टीपी/एसटीपी/एसईजैड/ बीटीपी यूनिटों को आपूर्ति	6.15	अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड/बीटीपी यूनिटों को आपूर्ति निवल विदेशी मुद्रा से गिनी जाएगी बशर्ते कि ऐसा माल इन यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हो।
एक एकक से दूसरे एकक को ऊर्जा का हस्तांतरण	6.16	एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट से दूसरे ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/एसईजैड यूनिट को कैपटिव पावर प्लान्टो (डी जी सैटो) से ऊर्जा का स्थानान्तरण परिशिष्ट 14-1ग में क्षेत्र विशिष्ट शर्त में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुमति होगी।
डीटीए से बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/ सिंथेटिक पत्थरों की आपूर्ति	6.17	डीटीए से ईओयू एकको को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मदों और दरों पर प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र पाने के पात्र होंगे। प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के संगत अध्याय में है। तथापि, आवेदन



संबंधित एस ई जेड के विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए। ईओयू को ऐसी आपूर्तियों को मान्य निर्यात लाभों के किसी भी प्रयोजन के लिए मान्य निर्यातों के रूप में नहीं माना जाता है।

हकदारियों की मंजूरी  
के लिए आवेदन पत्र

6.18

सभी हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किए जाए।

अन्य निर्यातकों के  
जरिए निर्यात

6.19

कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बीटीपी की यूनिट अपने विनिर्मित माल/इसके द्वारा विकसित साफ्टवेयर का निर्यात किसी निर्यातक या किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बीटीपी यूनिट के जरिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है :-

क) माल संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड/बीटीपी में तैयार किया जाएगा।

ख) निवल विदेशी मुद्रा का स्तर अथवा यथानिर्धारित आयातों और निर्यातों से संबंधित अनय शर्तें संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी द्वारा विनियमित की जाएगी।

ग) इस प्रकार से प्राप्त निर्यात आदेश ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी स्कीम के अन्तर्गत ही निष्पादित किए जाएंगे और माल यूनिट से सीधे ही पोत लदान के पत्तन पर भेज दिया जाएगा।

घ) इस प्रकार के निर्यात ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों द्वारा एन एफ ई को पूरा करने के लिए अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी /एस ई जेड यूनिट से या अन्य निर्यातक से ई ओ यू द्वारा आपूर्ति किए गए मूल्य के आधार पर गणना की जाएगी।

ड.) सभी निर्यात पात्रताएँ जिसमें स्तरधारक की मान्यता भी शामिल हैं भी निर्यातक के खाते में जोड़े जाएंगे जिसके नाम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है तथापि ऐसा निर्यात ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार को पूरा करने के लिए गिना जाएगा।

अन्य हकदारियाँ

6.20.1

स्टार व्यापार सदन स्तर प्रदान करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट डी टी ए में की मुख्य कंपनी अथवा विलोमतः के निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के साथ निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को मिला दिया जाएगा।

6.20.2 भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेवा गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्षेत्रीय मानदण्ड लागू होंगे।

6.20.3 प्रशिक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक प्रशिक्षण शामिल है) के लिए सॉफ्टवेयर यूनितों को कम्प्यूटर पद्धति के उपयोग की भी अनुमति है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए बाण्डेड परिसर से बाहर कोई कम्प्यूटर टर्मिनल न हो।

6.20.4 लौह अयस्क का निर्यात भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णय के अधीन होगा। आई टी सी(एचएस) के अनुसार निर्यात की अन्य शर्तें जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य/ उपभोक्ता पैक आदि में निर्यात की अपेक्षा डीटीएस खरीदे गए कच्चे माल और प्रसंस्करण/विनिर्माण के बिना निर्यात के मामले में लागू होगी। वस्त्र मदों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत आएगा। काष्ठ आधारित एककों को इमारती लकड़ी/अन्य काष्ठ के उपयोग के संबंध में 1996 के रिट याचिका संख्या 171 टीएन गोडावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत सरकार और अन्य - 1995 के रिट (सिविल) संख्या 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।

उप ठेके

6.21.1 अन्य ईओयू या एसईजैड यूनिट अथवा डीटीए की यूनिट के माध्यम से ईओयू रत्न और आभूषण यूनिटों द्वारा उप-ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा :-

- (क) उप ठेके पर दिया गया तौर या अर्ध तैयार माल जिसमें जड़ित आभूषण भी शामिल हैं, की 90 दिनों के भीतर यूनिट में वापस लाना होगा।
- (ख) किसी कटे और पालिस किए हीरों, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों जिनपर शून्य शुल्क हो, को छोड़कर) उप-ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी।
- (ग) डीटीए/ईओयू/एसईजैड यूनिटों से सादे स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम के बराबर मात्रा के बदले प्राप्त सोना/चाँदी/ प्लेटिनम के आभूषण, जैसा भी मामला हो, उक्त आभूषण शामिल हैं।
- (घ) ईओयू प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-4क.2 के अनुसार उप ठेके हेतु अदला-बदली के मद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा।
- (ङ.) डीटीयू यूनिट जो सोना/चाँदी/प्लेटिनम के बदले में फुटकर ठेका या आभूषण आपूर्ति का कार्य करती हैं वे मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगे।

6.21.2 डीटीए यूनिट से जाब वर्क करवाने की सुविधा तब भी उपलब्ध होगी चाहे

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण में जाबवर्कर को पंजीकृत न भी कराया गया हो। यह इस शर्त के अधीन होगा कि जाबवर्क पूरा होने पर वस्तुओं को यूनिट के प्रांगण में वापस लाया जाएगा।

6.21.3 फुटकर ठेकेदार के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे परिसर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हों। जहाँ जाब वर्कर एसईजैड/ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट है, ऐसे मामलों में उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है और निर्यात या तो जाँब वर्कर के परिसर अथवा यूनिट के परिसरों से किया जा सकता है। जाँब वर्कर के परिसर से ऐसे उत्पादों के तृतीय पार्टी के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जैसा कि विदेश व्यापार नीति में उल्लेख किया गया है।

6.21.4 ईओयू को उप ठेकेदारों के परिसर से माउल्ड जिम्स, टूल्स, फिक्चर्स, टेकल्स, उपकरण, हैंगर्स और पैटर्न और डाइंग को हटाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर फुटकर ठेका कार्य पूरा होने पर यूनिट के परिसर में वापस लाने की अनुमति होगी। इस माल के साथ कच्चा माल भेजा अथवा नहीं भेजा जाएगा।

6.21.5 विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के उपठेके के मामले में माल का उपठेकेदार के परिसर से निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि जाँबवर्क परिसरों का, निर्यात घोषणा फार्मों, बीजकों आदि में घोषणा की जाए और पूरी विदेशी मुद्रा देश में वापस लाई जाए।

ठेका कृषि

6.22 कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के उत्पादन/संसाधन में संलग्न ई ओ यू सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के मद्दे डीटीए फार्म से उपकरण और साजो सामान निकाल सकती है (परिशिष्ट-14 आई जे )

(क) ठेके फार्मों से ईओयू द्वारा निवेशों की आपूर्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिसूचित निवेश-उत्पादन मानदंडों के मद्दे होगी।

(ख) ईओयू और डी टी ए किसानों के बीच खेती संबंधी ठेका होगा।

(ग) ईकाई कृषि/ बागवानी जलकृषि उत्पादों के निर्यात में दो वर्षों के लिए संलग्न रहनी चाहिए अन्यथा उस यूनिट को उप/सहायक सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद के पास बाहर ले जाने वाले पूंजीगत माल/निविष्टियों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। जब तक यूनिट दो वर्ष पूरे न कर लें।

प्रदर्शनी के माध्यम से निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे

6.23 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने/ प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल का निर्यात कर सकती है :-

- (क) यूनिट, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को मूल का पत्र या इसकी प्रमाणित प्रति जिसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा। रत्न और आभूषण मर्दों के लिए, उत्पाद की एक स्व प्रमाणित फोटोप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
- (ख) पुनः आयात के मामले में, आने पर ऐसे मर्दों को, निकासी से पूर्व निर्यात दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाएगा।
- (ग) जो मर्दे विदेश में बिक्री न हों, प्रदर्शनी समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उसका आयात किया जाएगा। तथापि, यदि निर्यातक प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में, भाग लेना चाहता है तो 60 दिनों की गणना प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने की तारीख से की जाएगी।
- (घ) वस्तुओं को व्यक्तिगत असवाब के रूप में ले जाने और विदेशों में प्रदर्शिनियों में भाग लेने के लिए ऐसे रत्नों और आभूषणों का मूल्य 2 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए।

निर्यात संवर्धन दोरों  
के लिए रत्न एवं  
आभूषणों को व्यक्तिगत  
असवाब के रूप  
में ले जाना

6.24

ईओयू द्वारा निर्यात संवर्धन दोरों और विदेशों में अस्थायी प्रदर्शन/बिक्री के लिए 100,000 अमरीकी डालर तक के सोना/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कटे और पालिस किए हुए हीरों, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य रत्नों, मानकों और नमूनों के रूप में सामग्री के व्यक्तिगत असवाब की निम्नलिखित शर्तों पर विकास आयुक्त की अनुमति है :-

- (क) ईओयू, प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर माल को वापस लाएगा अथवा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से बिक्री आय को वापस लाएगा।
- (ख) यूनिट ऐसे नमूनों के व्यक्तिगत असवाब की सीमाशुल्क को देश छोड़ने से पहले घोषणा करेगा/ आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा।

विदेशों में शोरूम/  
शुल्क मुक्त दुकानों  
के माध्यम से निर्यात

6.25

विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों या वितरकों/एजेंटों के शोरूम में प्रदर्श/बिक्री के लिए भी माल के निर्यात की अनुमति है, जो मद 180 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती उसका 45 दिनों में पुनः आयात किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों  
में शोरूम/फुटकर  
दुकानों से बिक्री

6.26

ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की बिक्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वायु-पत्तनों में शो रूम/फुटकर दुकान स्थापित कर सकते हैं, जो मद 60 दिन के भीतर विदेशों में नहीं बिकती है उसे निर्यात किया जायेगा या संबंधित ईओयू को लौटा दिया जाएगा।

आयात/ निर्यात पार्सलों  
के व्यक्तिगत असवाब

6.27.1

रत्न और आभूषण मर्दों के व्यक्तिगत असवाब के माध्यम से आयात/निर्यात, सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

जिनमें विदेश जाने वाले यात्रियों का असभाव भी शामिल है

निर्यात आय सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। रत्न और आभूषण यूनिटों से अन्य पर्सनल कैरेज के माध्यम से आयात/निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते की माल वाणिज्यिक मात्रा में न हो।

6.27.2

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत असवाब के लिए ईओयू यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे :-

(क) ईओयू द्वारा फाईल की गई पोत लदान बिल की प्रति।

(ख) विदेशी खरीददार द्वारा आगमन के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत मुद्रा घोषणा फार्म की प्रति।

(ग) बैंक से विदेशी मुद्रा वसूली प्राप्ति/नकदीकरण प्रमाणपत्र

6.27.3

इसके अलावा, विदेश जाने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत असवाब की स्वीकृति के प्रति दस्तावेज/सुर्मुदगी पर भुगतान आधार पर अनुमति होगी। ईओयू को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) जहाज रानी बिल की प्रति

(ख) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र

6.27.4

आयात पार्सलों का व्यक्तिगत कैरेज के लिए वहीं प्रक्रिया जो वायुभाड़ा द्वारा माल को आयात के लिए होती है इसमें वह पार्सल शामिल नहीं है जिसे ईओयू / विदेशी नागरिक द्वारा जाँच और निकासी के लिए सीमाशुल्क के पास लाया जाता है। इस संबंध में कस्टम प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा।

6.27.5

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा पाटर्स को व्यक्तिगत समान के तौर पर ले जाने की अनुमति होगी यदि ग्राहक के स्थान पर निर्यातित माल की मरम्मत हेतु उनकी आवश्यकता हो। निर्यातों के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(क) निर्यातों हेतु सीमाशुल्क कार्यालय से अनुज्ञा पत्र

(ख) मूल्य सहित बीजक (भुगतान करने पर अथवा निःशुल्क)

आयातित/माल का प्रतिस्थापन/ मरम्मत

6.28.1

यूनिट पूँजीगत माल की मरम्मत के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचना दिए जाने पर विदेश भेजा जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए किसी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति भी होगी।

6.28.2

इ ओ यू / इ एच टी पी/ एस टी पी/बीटीपी यूनिट अपने रिकार्ड के अनुसार और सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कार्य करेगा:

- क माल की डी टी ए में/विदेश हेतु मरम्मत/ प्रतिस्थापन जाँच या केलिब्रेशन तथा वापसी ।
- ख माल के वापसी के लिए सीमाशुल्क के उपयुक्त वचनबद्धता देते हुए शुल्क का भुगतान किये बिना प्रतिवर्ष रु. 5 लाख तक के माल का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ संस्थान को गुणवत्ता जाँच/ आर एण्ड डी प्रयोजन के लिए स्थानान्तरण किया जा सकता है। तथापि, यदि माल नष्ट हो जाता है तो इस आशय का प्रमाण प्रयोगशाला/संस्थान से सीमा शुल्क को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नमूने

- 6.29.1 इ ओ यू/ इ एच टी पी/ एस टी पी/बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के आधार पर तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर डी टी ए में नमूनों की आपूर्ति या विक्रय कर सकता है। वे यथा लागू शुल्क का भुगतान करके प्रदर्श/ बाजार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- 6.29.2 निर्धारित सीमा के भीतर नमूनों की वापसी सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उपयुक्त वचनबद्धता प्रस्तुत करके शुल्क का भुगतान किये बिना हटाया जा सकता है।
- 6.29.3 इ ओ यू कुरियर एजेंसियों/डाकघर के माध्यम निर्यात के सभी अनुमत तरीकों से किसी सीमा के बिना मुक्त निर्यात कर सकता है जिनमें वैक्स मोल्ड, सिल्वर मोल्ड और रबर मोल्ड के नमूने शामिल हैं।
- 6.29.4 अपने पास रखे रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर कोई ई.ओ.यू अन्य ई.ओ.यू को 30 दिनों के भीतर वापसी आधार पर प्रदर्शन हेतु नमूने भेज सकता है।

कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पैरिफेरिअल्स का दान

- 6.30 संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इ ओ यू/ इ एच टी पी / एस टी पी/बीटीपी यूनिट को यह अनुमति दी गयी है कि वह आयातित/ स्वदेश से खरीदे गये/ उधार दिए गये कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पैरिफेरिअल्स जिनमें प्रिन्टर्स, प्लॉटर, स्कैनर, मॉनिटर, की-बोर्ड और स्टोरेज यूनिट शामिल हैं उनको आयात/खरीद और यूनिट द्वारा उपयोग की गई दो वर्ष के बाद शुल्क का भुगतान किसी मान्यताप्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थाओं, पंजीकृत खैराती अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के संगठनों को इस संबंध में जारी सीमा/उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार दान स्वरूप दे सकता है।

माल को नष्ट करना

6.31

सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सूचना देकर या यूनिट के बाहर पूँजीगत माल कच्चा माल, उपभोग्य, कलपूर्ज, विनिर्मित माल/ प्रसंस्कृत या पैकड और स्क्रैप/ अवशिष्ट/अवशेष/रद्दीमाल को नष्ट करने के मामले में कोई शुल्क

देय नहीं होगा। नष्ट करना जैसे उमर उल्लेख किया गया है, सोना, चाँदी, प्लेटिनियम, हीरा बहुमूल्य अर्द्धमूल्य रत्नों पर लागू नहीं होगा।

### पृथक पहचान

6.32

यदि औद्योगिक उद्यम धरेलू यूनिट पहचान के साथ साथ इ ओ यू/ इ एचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट दोनो रूप में कार्य कर रहा है तो उसकी दो पृथक पहचान होगी और पृथक-पृथक बैंक खाते होंगे। तथापि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है की उसकी कोई पृथक कानूनी पहचान हो लेकिन इओयू/इएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी द्वारा प्रभावी आयात और निर्यात अथवा आपूर्तियों को प्रतिष्ठान के अन्य पूंजियों द्वारा किये गये कार्य से पृथक करना संभव हो।

### इओयू के लिए यूनिट अनुमोदन समिति

6.33.1

इओयू की एकक अनुमोदन समिति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार होंगे:-

- (क) सेवा क्षेत्र (साफ्टवेयर और आई.टी. संबंधी सेवाएँ या बी ओ ए द्वारा सौंपी गई कोई अन्य सेवा) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस वाली मद के लिए यूनिट स्थापित करने हेतु कोई अन्य प्रस्ताव के अलावा इ ओ यू स्थापित करने के लिए आवेदन पर बी ओ ए द्वारा विचार किया जाएगा।
- (ख) एस इ, जैड से इ ओ यू में यूनिट के परिवर्तन पर विचार और अनुमति
- (ग) यूनिट के कार्य निष्पादन की मानिट्रिंग
- (घ) यूनिट को दी गयी अनुमति निकासी, लाइसेंस का पर्यवेक्षण और मानिट्रिंग तथा विधि के अनुसार समुचित कारवाई करना
- (ङ) यूनिट को दी गयी अनुमति निकासी लाइसेंस के अधीन उसके कार्य निष्पादन का मानिट्रिंग करने के लिए उपस्थिति सूचना मांगना।
- (च) केन्द्रीय सरकार या उसकी ऐजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निष्पादन।
- (छ) राज्य सरकार या उसकी ऐजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निष्पादन।
- (ज) इ ओ यू की स्थापना और प्रचालन के लिए सभी अनुमोदन और निकासी देना

### इएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों का अनुमोदन

6.33.2

इएचटीपी/एसटीपी योजना के तहत यूनिटों के मामले में, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग/निदेशक (एसटीपीआई) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति

प्रदान की जाएगी। एस टी पी/ई एच टी पी के मामले में राजपत्र में दिनांक 30-1-2006 को जारी अधिसूचना सं. एस.ओ. 106 (ई) में उल्लिखित के अनुसार नामित अधिकारी को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 खण्ड-13 जो खण्ड-11 के साथ पठनीय है के अधीन निर्णय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार बीटीपी के तहत यूनिटों के मामले में, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। तथापि, परिशिष्ट 14-1-ख में दिए अनुसार, नए यूनिटों के स्वतः अनुमोदन देने के लिए मनोनीत अधिकारी इसके निर्धारित मानदण्डों को अपनाएँगे।

इ ओ यू का प्रशासन/ 6.34  
विकास आयुक्त की शक्ति

यूनिटों के संबंध में विकास आयुक्त नामित अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी। विकास आयुक्त का अधिकार क्षेत्र परिशिष्ट 14-1(ट) में दिया गया है।

1. रूग्ण/बन्द डीटीए यूनिट को इ ओ यू में बदलना
2. इ ओ यू को एस टी पी / इ एच टी पी तथा विलोमतः में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन करना।
3. विदेश विनिमय दर के घटने बढ़ने के कारण भारतीय रुपये में पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति
4. केवल बिना लाइसेंस वाले उद्योगों के मामले में सीमा से परे क्षमता वृद्धि अनुमत करना।
5. एलओपी में उल्लिखित समान वस्तुओं के लिए ब्रोड वैन्डिंग की अनुमित देना अथवा विनिर्माण की मौजूदा पद्धति को बैकवर्ड या फारवर्ड लिंकेज प्रदान करना।
6. कार्यान्वयन समिति या कम्पनी के नाम परिवर्तन को अधिकृत करना तथा एक कम्पनी से दूसरे में परिवर्तन करना बशर्ते कि नयी कार्यान्वयन समिति कम्पनी, मौजूदा यूनिट की सम्पत्ति और जिम्मेवारी लेने का वचन देती है।
7. एल ओ पी में उल्लिखित स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन अनुमत करना और या अतिरिक्त स्थान सम्मिलित करना बशर्ते कि अनुमोदन के अन्य शर्तों तथा समझौतों में किसी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और नया स्थान विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर हैं।
8. एल ओ पी की वैधता अवधि को एल ओ पी की शुरुआती वैधता अवधि से 3 वर्ष से बढ़ाना (अनुमोदन के शुरुआती अवधि पर जहाँ कहीं भी प्रतिबंधित हैं वैसे मामलों के अलावा, जैसे तेल परिशोधन परियोजना की स्थापना करना)



9. जहाँ कहीं भी न्याय संगत हो, एल ओ पी को निरस्त करना।
10. दो या अधिक यूनिटों को एक यूनिट में विलय करना बशर्ते की यूनिटें उसी विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती हैं, इस शर्त पर किया जायेगा कि यूनिटों का कार्यकलाप ब्रॉड बैंडिंग के प्रावधानों के तहत शामिल हैं।
11. राजपत्र अधिसूचना संख्या सां० आ० 194 (अ.) दिनांक 6.3.2000 में यथा उल्लिखित निर्यात अभिमुख यूनिटों के संबंध में विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत अधिनिर्णय शक्तियों का प्रयोग करना।
12. भारतीय रिजर्व बैंक ए.डी. (एम ए श्रृंखला) परिपत्र ए वी (डी आइ आर श्रृंखला परिपत्र संख्या 9 दिनांक 25.10.2001) के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा साफ्टेक्स फार्म पर घोषित निर्यातों का मूल्यांकन करना।
13. गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 25022/7/99-एफ 1 दिनांक 20.9.1999 के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा निम्न स्तर के विदेशी तकनीशियनों को काम में लगाने के लिए रोजगार वीसा प्रदान करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना।
- पंजीकरण -सह -सदस्यता माण पत्र 14. निर्यातोन्मुख इकाई/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में काम करना। मसालों के मामलों को छोड़कर, नीति के पैरा 2.44 में किए प्रावधान के अनुसार मसालों को छोड़कर यह आवश्यक है कि यूनिट को मसाला बोर्ड में स्वतः ही पंजीकरण करवाना होगा। मसालों के मामले में, इकाइयों को मसाला बोर्ड के पास स्वयं को पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य होगा।
- आयातक निर्यातक कोड सं. 1 15. फर्म को यदि पहले आयातक निर्यातक कोड संख्या आवंटित नहीं की गयी है तो निर्यात अभिमुख यूनिटों को उसे आवंटित करना।
- ग्रीन कार्ड 16. विधिक वचन बद्धता निष्पादन के बाद अपने आप ग्रीन कार्ड जारी करना ।
17. निर्यातोन्मुखी यूनिटों के संबंध में स्तर प्रमाण पत्र की स्वीकृति/नवीनीकरण बशर्ते कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में इसके उद्गम कम्पनी के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का मिलाना शामिल नहीं है।

18. निर्यातोन्मुखी यूनिट ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम का उसके क्षेत्राधिकार में प्रचार।

- |  |          |  |
|--|----------|--|
| डीटीए में पूँजीगत माल की निकासी                                | 6.35     | पुराने पूँजीगत माल के आयात की निकासी की अनुमति इ पी सी जी स्कीम के तहत नीति के अनुसार, दी जायेगी। अन्य मामलों में, ऐसी निकासी की तारीख को लागू आयात नीति और लागू शुल्क के भुगतान पर डीटीए में निकासी की अनुमति होगी।   |
| मूल्य ह्रास मानदंड   | 6.36.129 | कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर संबंधी मदों के मामले में 5 वर्षों में पूँजीगत माल के लिए मूल्य ह्रास 100 प्रतिशत है तथा अन्य मदों के मामले में यह 10 वर्ष होगा।  |
| कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पेरिफेरि-यल्स के लिए मूल्यह्रास मानदण्ड | 6.36.2   | सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक यूनितों के लिए कम्प्यूटर पेरिफेरलस तथा कम्प्यूटर के लिए ह्रास निम्नवत होगा:-प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 10 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 8 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 5 प्रतिशत, चौथे और पाँचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु 1 प्रतिशत।  |
| पूँजीगत माल के लिए मूल्यह्रास मानदण्ड                          | 6.36.3   | उपरोक्त के अलावा पूँजीगत माल के लिए तय की गई दर निम्नवत होगी:-प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत, द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत, चतुर्थ और पाँचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत, उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए 2 प्रतिशत।  |
| परिवर्तन   | 6.37.1   | मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनितों ई ओ यू/ ई एच टी पी/ एस टी पी/बीटीपी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं लेकिन पूर्वस्थापित प्लान्ट, मशीनरी और उपकरण के लिए स्कीम के तहत शुल्क और करो में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। परिवर्तन के बाद विनिर्माण के प्रारम्भ होने की मूल तारीख से आयकर से अधिकतम 10 वर्ष के लिए छूट होगी अथवा आयकर अधिनियम की धारा-10 के तहत निर्धारित छूट प्राप्त होगी, जो भी पहले हो। इस प्रयोजन के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र एकक संबंधित विकास आयुक्त नामित अधिकारी को उसी तरह आवेदन कर सकता है जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू होगा। यदि ई पी सी जी स्कीम/अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत बकाया निर्यात वचनबद्धता है तो यह यूनिट प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट - 14 - झ - 0 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। |
|  | 6.37.2   | मौजूदा ई एच टी पी/ एस टी पी/बीटीपी यूनितें ई ओ यू में परिवर्तन/ विलय होने के लिए आवेदन कर सकती हैं। तथा इ ओ यू भी इ एच टी पी/ एस टी पी यूनितों में परिवर्तन/ विलय होने के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिते सम्बद्ध स्कीम के तहत लागू शुल्कों और करों की छूट की अनुमति प्राप्त करना जारी रखेगी। ई ओ यू के रूप में   |

परिवर्तन इच्छुक ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिटें संबंधित विकास आयुक्त को सूचना तकनीकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू है, उसी तरह आवेदन कर सकती हैं। वैसे ही ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी में परिवर्तन को इच्छुक ई ओ यू संबंधित विकास आयुक्त के माध्यम से सूचना तकनीकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

6.37.3 विकास आयुक्त के अनुमोदन से एक निर्यातोन्मुख यूनिट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्ते कि निर्यातोन्मुखी यूनिट, निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के तहत यथानुपात दायित्व प्राप्त कर चुकी है।

रूग्ण यूनिट का पुनरुत्थान 6.38

उचित प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रूग्ण घोषित किये, जाने की शर्त पर यूनिट के पुनरुत्थान के प्रस्ताव या अधिकार में लेने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है। रूग्ण यूनिट के पुनरुत्थान पर दिशा निर्देश परिशिष्ट 14.1 ड में दिये गये हैं।

6.39 शीघ्र निपटान संबंधी प्रक्रिया

पात्रता

6.39.1 विदेश व्यापार नीति के तहत स्तरधारक प्रमाणपत्र रखने वाले ईओयू शीघ्र निपटान हेतु पात्र होंगे।

आयात कार्गो की जांच

6.39.2 स्तरधारक यूनिटों को आयात के पत्तन और यूनिट के प्रागण पर आयात कार्गो के परीक्षण से छूट दी जाएगी। तथापि, उस क्षेत्र का सीमाशुल्क आयुक्त/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ईकाई के स्थान पर जाकर भी खेप की परीक्षा कर सकता है।

माल की घरेलू खरीद व आयात

6.39.3 विगत वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये और उससे अधिक का वास्तविक निर्यात कारोबार करने वाली यूनिटों को सीमा-शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त द्वारा जारी किये पूर्व साक्षांकित खरीद प्रमाणपत्र के आधार पर शुल्क के भुगतान के बिना माल के आयात की अनुमति होगी। ऐसे यूनिटों को घोषणा के आधार पर वस्तुएं प्राप्त करने और गोदाम की सुविधा भी होगी।

फैक्स मशीन/कम्प्यूटरों की स्थापना

6.39.4 क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को पूर्व सूचना के तहत बान्डेड परिसरों के बाहर अपने प्रशासनिक/पंजीकृत कार्यालय में एक फैक्स मशीन और 2 कम्प्यूटरों को स्थापित करने हेतु निर्यातोन्मुख यूनिट पात्र होगी।

डी जी सैटों को

6.39.5 यूनिट की वास्तविक आवश्यकता से साथ क्षमता के अनुकूल डी जी सैट

प्राप्त करना		प्राप्त करने की अनुमति विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचित करते हुए दी जायेगी।
पूँजीगत माल को अस्थायी रूप से हटाना	6.39.6	पात्र निर्यातोन्मुख यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को पूर्ण सूचना के तहत मरम्मत हेतु अपने पूँजीगत माल अथवा उनके हिस्सों को हटा सकती है।
डीटीए में रिजैक्ट्स की निकासी	6.39.7	डीटीए में रिजैक्ट्स की निकासी की अनुमति हेतु आवेदन पर क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारी अग्रता आधार पर विचार करेगा।
नमूनों को वैयक्तिक रूप से लाना ले जाना	6.39.8	स्तर धारक निर्यातोन्मुख यूनिटों द्वारा रत्न और आभूषणों के नमूनों को वैयक्तिक तौर पर लाने ले जाने की अनुमति पैरा 6.24 में निर्धारित के सीमा के मद्दे होगी शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
कार्याकलाप जिनके लिए अनुमति आवश्यक नहीं	6.39.9	ईओयू के स्तरधारक के निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में विकास आयुक्त/क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। इसके स्थान पर यूनिट को निम्नलिखित पूर्व सूचना देनी होगी:-तैयार उत्पादों की विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(क) के अनुसार डीटीए में बिक्री। प्रदर्शिनियों में भाग लेना निर्यात संवर्धक दौरो के लिए रत्नों और आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 6.24 की शर्तों की पूर्ति के मद्दे। तथापि, उसकी पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
आवेदनों का समयबद्ध निपटान	6.40	विकास आयुक्त आवेदनों को शीघ्रता से निपटारेंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सीमा को अपनाया जाता है बशर्ते आवेदन हर तरह से पूरे हो और उनका साथ निर्धारित दस्तावेजों संलग्न हों।

क्र०सं०

आवेदन की श्रेणी

निपटान के लिए समय सीमा

- |    |                                     |        |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1. | अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी करना      | 15 दिन |
| 2. | अनुमति पत्र/आशय पत्र का परिवर्तन    | 15 दिन |
| 3. | विधिक वचन बद्धता की स्वीकृति        | 3 दिन  |
| 4. | विधिक वचन बद्धता नवीकरण             | 3 दिन  |
| 5. | ब्राड बैंडिंग/डिषान्तरण की अनुमति   | 3 दिन  |
| 6. | स्थापना स्थल में परिवर्तन की अनुमति | 7 दिन  |

7.	अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति	2 दिन
8.	यूनिटों के विलयन की अनुमति	7 दिन
9.	उत्पादन क्षमता की वृद्धि की अनुमति	3 दिन
10.	अनुमति पत्र को रद्द करना	3 दिन
11.	डिबान्डिंग/एक्जिट की अनुमति	7 दिन
12.	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति	2 दिन
13.	निम्नस्तरीय टेक्नीशियन के लिए रोजगार बीजा हेतु पात्रता प्रमाण पत्र	2 दिन
14.	ग्रीन कार्ड जारी करना	2 दिन
15.	ग्रीन कार्ड का नवीकरण	उसी दिन
16.	पूँजीगत वस्तुओं को लीज पर देने की	1 दिन
17.	स्क्रेप/वेस्ट के निपटान की अनुमति	2 दिन
18.	नाम में परिवर्तन की अनुमति	2 दिन
19.	अन्तर यूनिट स्थानान्तरण	2 दिन
20.	वेस्टेज संबंधी माप दण्ड, तदर्थ	2 दिन
21.	पुनः आयात करने की अनुमति	उसी दिन
22.	पुनः निर्यात करने की अनुमति	उसी दिन
23.	वस्तुओं के प्रतिस्थापन/मरम्मत की अनुमति	उसी दिन
24.	आई.ई.कोड का आवंटन	1 दिन
25.	साफ्टवेक्स फार्म का प्राधिकार	1 दिन
26.	सी.एस.टी दावों की प्रति पूर्ति	7 दिन
27.	जी.एस.पी प्रमाण पत्र जारी करना	उसी दिन
28.	एस.टी.पी.आई, ई.पी.सी.जी को ई.ओ.यू के परिवर्तन की अनुमति	5 दिन
29.	ई.ओ.यू की अन्तिम निकासी की अनुमति	5 दिन
30.	ई.ओ.यू में विस्तार की अनुमति	2 दिन
31.	पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य में	2 दिन
32.	प्रदर्शनी/दौरो के जरिये निर्यात की अनुमति	2 दिन
33.	शुल्क वापसी/टी.ई.डी की प्रतिपूर्ति	7 दिन

## अध्याय - 7

## विशेष आर्थिक जोन

विशेष आर्थिक जोन से सम्बंधित नीति और प्रक्रिया, विशेष आर्थिक अधिनियम, 2006 भारत के राजपत्र असाधारण सं. जीएसआर 54 (अ) दिनांक 10.2.2006 में शामिल हैं।

## अध्याय - आठ

## मान्य निर्यात

नीति	8.1	मान्य निर्यात सम्बंधी नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय- 8 में दी गई है।
मान्य निर्यातों के लाभों का दावा करने के लिए मानदण्ड	8.2.1	विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(क) के तहत आपूर्तियों के सम्बंध में ए आर ओ तथा बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख-पत्र को जारी करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 के पैरा 4.14 और 4.15 में दी गई है।
	8.2.2	विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ख) और डी एफ आई ए के अन्तर्गत आपूर्तियों के संबंध में, विकास आयुक्त अथवा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से मान्य निर्यात लाभों का दावा किया जा सकता है। अग्रिम प्राधिकार पत्र और डीएफआईए के लिए सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से दावा किया जा सकता है। ऐसी आपूर्तियों को प्राप्त करने वाली एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
	8.2.3	विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ग) के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक से उस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि विनिर्मित पूंजीगत माल की आपूर्ति हो गई है।
	8.2.4	विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (घ), (ड.), (च), (छ), (झ) और (ज) में दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत आपूर्ति के संबंध में, अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन के साथ परिशिष्ट-27 में दिए परियोजना प्राधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न होगा। ऐसी आपूर्तियों के मद्दे भुगतान परिशिष्ट 22-ग में दिए गए फार्म के अनुसार संबंधित परियोजना प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
मान्य निर्यात शुल्क वापसी और अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी/ अंतिम उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट पर दावे की प्रक्रिया	8.3.1	विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 (ख) और (ग) के तहत लाभों का दावा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है :-  1. आयात निर्यात प्रपत्र में, उसमें बताए गए दस्तावेजों सहित आपूर्तिकर्ता द्वारा आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्राप्तिकर्ता निर्धारित दस्तावेजों के अलावा सेनवेट क्रेडिट न लेने सम्बंधी प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 के परिशिष्ट 22ग

में स्व-घोषणा के साथ आपूर्तिकर्ता के उपयुक्त दावेदारी छोड़ने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके भी लाभ की दावेदारी कर सकता है।

2. पैरा 8.2 (क), (ख), और (ग) के अन्तर्गत आपूर्तियों के मामले में दावा परिशिष्ट-22ख में दिए प्रपत्र में सामान्य बैंकिंग चैनल के द्वारा भुगतान की प्राप्ति के मद्दे किया जायेगा। ऐसे दावे आवेदक के विकल्प के अनुसार भुगतान की तिथि से आकलन करके मासिक/तिमाही/छमाही अवधि के अन्त से 6 महीने के अन्दर दर्ज किये जायेंगे। उन मामलों में जहाँ अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है, आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि भुगतान प्राप्त करने की तिथि के बदले, आपूर्ति करने की तिथि से सह सम्बद्ध होगी।
3. विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ख) के अन्तर्गत आपूर्तियों के सम्बंध में, जहाँ आपूर्तिकर्ता क्षेत्रीय प्राधिकारी से लाभ का दावा करना चाहता है, क्षेत्रीय प्राधिकारी डी टी ए आपूर्तिकर्ता को मान्य निर्यात के लाभ की अनुमति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रमाणित प्रतियाँ, की गई आपूर्ति के प्रमाण के रूप में शुल्क की प्रमाणित बीजक की सत्यापित प्रतियाँ और/या उत्पाद शुल्क सत्यापित सीटी-3 फार्म और अनुमति-पत्र की वैधता के प्रमाण के रूप सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त होने पर देगा।
4. विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित श्रेणियों के तहत आपूर्तियों के संबंध में प्राप्त भुगतान/हुई आपूर्ति हेतु दावा, हुई आपूर्ति अथवा प्राप्त भुगतान के साक्ष्य के आधार पर आवेदक के विकल्पानुसार किसी विशेष माह/तिमाही/छमाही आधार पर किया जा सकता है। दावा किसी विशेष परियोजना अथवा सभी परियोजनाओं के मद्दे किया जा सकता है। ऐसे दावे आवेदक के विकल्प के अनुसार मासिक/तिमाही/ छमाही अवधि की समाप्ति से परियोजना अधिकारी द्वारा आपूर्ति की प्राप्ति की तारीख से गिने गए अथवा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे दावे जहाँ खण्डों में भुगतान प्राप्त हो वहाँ भी किए जा सकते हैं।

8.3.2 अंतिम उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

8.3.3 जहाँ ड्रा बैंक की कोई समग्र उद्योग दर उपलब्ध नहीं है या यह उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री या उपकरणों पर शुल्क के 4/5 से कम है तो निर्यातक/ आपूर्तिकर्ता क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा विकास आयुक्त को आयात निर्यात प्रपत्र में दिए गए आवेदन पत्र में ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है।

- 8.3.4 अगर ब्रांड दर के निर्धारण की आवश्यकता है तो शुल्क वापसी के ब्रांड रेट के निर्धारण के लिए आवेदन के साथ दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पैरा 9.3 के अन्तर्गत विलम्ब कटौती के प्रावधान और पैरा 9.4 के अन्तर्गत पूरक दावे भी इस उप पैरा के अन्तर्गत लागू होंगे।
- 8.3.5 क्षेत्रीय प्राधिकारी निजी कम्पनियों के मामले में शुल्क वापसी के दावे के 75 प्रतिशत तक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में 90 प्रतिशत तक अनन्तिम भुगतान पर विचार करेगा जोकि ब्रांड दर के निर्धारण के लिए लम्बित हैं।
- 8.3.6 इस प्रक्रिया पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अधीन, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 मान्य निर्यात के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- 8.4 पैरा 8.2(घ) (ड.) (च) (झ) और (ज) के तहत उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को की गई आपूर्तियों के संबंध में, मुख्य ठेकेदार उप ठेकेदार को भुगतान कर सकता है और परिशिष्ट 22ग में दिए गए फार्म 1-ग के रूप में भुगतान प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। तथापि, पैरा 8.2 (घ)(ड.)(च)(छ) और (ज) के तहत की गई आपूर्तियों के लिए, अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए मुख्य ठेकेदार से भुगतान प्रमाण पत्र लेने पर जोर नहीं दिया जायेगा। उप-ठेकेदार को मान्य निर्यात के लाभ वस्तुओं की उस सीमा तक उपलब्ध होंगे जिस सीमा तक उप- ठेकेदार द्वारा वस्तुओं का विनिर्माण किया गया है और इनकी आपूर्ति की गई है या अन्य विनिर्माताओं से इन्हें प्राप्त किया गया है, वस्तुओं का मूल्य प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड - 1 के परिशिष्ट-22ग में यथा निर्दिष्टानुसार होगा।

उप ठेकेदारों द्वारा मान्य निर्यात लाभों का दावा करने की प्रक्रिया



## अध्याय-9

## विविध मामले

नाम और संरचना में परिवर्तन	9.1	आईईसी धारक को नाम/पता/संरचना में ऐसे परिवर्तन के 90 दिनों के भीतर करवाना होगा बशर्ते कि तथापि आईई कोड नम्बर जारी करने वाला लाइसेंसिंग प्राधिकारी 1000/-रु० के जुर्माने पर देश को माफ कर सकता है। उक्त ढाँचे में परिवर्तन से सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के निदेशकों में परिवर्तन शामिल नहीं है।
आयात प्राधिकार/ लाइसेंस/प्रमाणपत्र/ अनुज्ञा को भुनाना	9.2	प्राधिकार/निर्यात दायित्व की पोत पर्यंत निशुल्क मूल्य के लागत बीमा भाड़ा मूल्य को रूपयों तथा मुक्त हस्तांतरणीय मुद्रा के विनिमय मूल्य (मूल्यों) जोकि प्राधिकार जारी करने की तिथि को विद्यमान हो, में दर्शाया जाएगा।
	9.2.1	विदेश विनिमय को जमा करना प्राधिकार के विरुद्ध निर्यात दायित्व की निकासी का मुक्त हस्तांतरणीय मुद्रा में नियमन किया जाएगा।
	9.2.1.1	रूपये के मूल्य में कोई वृद्धि जरूरी नहीं है अगर विदेशी विनिमय की जमा के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के प्राधिकार को मुक्त हस्तांतरणीय मुद्रा में दर्शाये जाने के तहत आ जाता है।
	9.2.2	तथापि, अग्रिम प्राधिकार (प्राधिकारों), जोकि एसीयू देशों को निर्यातों के लिए जारी किया जाता है, निर्यात दायित्व को एसीयू डालरों में भुनाया जाएगा।
	9.2.3	मान्य निर्यात और संक्रमण कालीन आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार में निर्यात दायित्व जहाँ आपूर्तियाँ देश के भीतर हैं, को भारतीय रूपये में भुनाया जाएगा।
प्राप्ति की निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदन	9.3	जब कभी प्राप्ति की तारीख समाप्त होने के पश्चात कोई आवेदन प्राप्त होता है, किन्तु अंतिम तारीख से छह माह के भीतर यह प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 10% विलम्ब कटौती लगा कर इन पर विचार किया जा सकता है।
अनुपूरक दावे	9.4	यदि निर्धारित समयावधि के भीतर, अनुपूरक दावे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 10% कटौती करके ऐसे आवेदन पर विचार किया जाएगा।
सूचना प्रस्तुत करना	9.5	प्रत्येक आयातक/निर्यातक महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना देगा।

नीति/प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण	9.6	नीति के किसी भी प्रावधान या प्रक्रिया पुस्तक, आई टी सी (एच एस) के तहत मर्दों की आयातीयता या निर्यातीयता के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण महानिदेशक, विदेश व्यापार से परिशिष्ट-28 में दिए गए प्रपत्र में माँगा जा सकता है। ई मेल के माध्यम से भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है।
उपभोग का रजिस्टर	9.7	आयातक, प्राधिकार पत्र के अधीन आयातित मर्दों के बारे में एक रजिस्टर जोकि परिशिष्ट 23 के अनुसार होगा, (3 वर्ष के लिए) रखेगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ आयातित मर्दों और उनकी खपत के लिए अलग से रजिस्टर रखेगा। विशेष स्कीमों के सम्बंध में ऐसे रजिस्टर विशिष्ट अवधि के लिए तैयार किए जाएंगे।
निर्यात सुविधा	9.8	निर्यातकों की समस्याओं को समन्वित रूप से समाधान के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यात सुविधा केन्द्रों और नोडल अभिकरणों का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी नामांकित किए गए हैं और निर्यातकों को सहयोग देने के लिए नामित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 17 में दी गई है।
स्थायी शिकायत समितियाँ	9.9	शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.49 में दिया गया है। नीति और प्रक्रिया सम्बंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अध्यक्षता (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) अलग-अलग लाइसेंसिंग कार्यालयों में संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ आई ई ओ), निर्यात संवर्धन परिषद/वस्तु बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग/तकनीकी प्राधिकारी, सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
	9.9.1	अलग-अलग शिकायत समिति का अध्यक्ष किसी सदस्य को शामिल कर सकता है। ऐसी समितियों की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाएँगी।
	9.9.2	प्रत्येक निर्यातक/आयातक को शिकायत समिति में अभ्यावेदन देने तथा यदि वह चाहे तो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अधिकार होगा। इस प्रयोजन के लिए, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।
	9.9.3	शिकायत समिति को अभ्यावेदन परिशिष्ट-26 में दिए गए प्रपत्र में भेजा जाएगा।

## काउंटर सहायता

9.10

आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में “काउंटर सहायता” प्रकोष्ठ कार्य करेगा। प्रत्येक कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी काउंटर का प्रभारी होगा। काउंटर पर आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक को एक टोकन दिया जाएगा और टोकन को उसी दिन लौटाने की सलाह दी जाएगी जब उसे यह बताया जाएगा कि उसका आवेदन पूर्ण है और इसे कार्यालय द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए रख लिया गया है या इसमें कोई कमी है जिसे आवेदक को पूरा करना है।

9.10.1

काउंटर सहायता प्रकोष्ठ आवेदन को आवश्यक संवीक्षा के लिए उसी दिन संबंधित अनुभाग को भेजेगा। यदि इसमें कोई कमी होगी तो इसे संबंधित अनुभाग द्वारा नोट किया जाएगा और इसे उसी दिन काउंटर सहायता प्रकोष्ठ को लौटा दिया जाएगा। पूर्ण आवेदन के मामले में, आवेदन को औपचारिक रसीद दी जाएगी जिसमें आगे संदर्भ के लिए फाइल नम्बर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों के मामले में, संबंधित अनुभाग द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए इसे आवेदक को लौटा दिया जाएगा। पूर्ण आवेदनों पर पैरा 9.11 के अधीन दी गई समय-सीमा के भीतर संबंधित अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यदि और कोई कमी नोट की जाती है तो कार्यालय के अध्यक्ष के अनुमोदन से इसे बताया जाएगा जो काउंटर सहायता के प्रभावी संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।

9.10.2

छोटी प्रकृति के संशोधन/पूछताछ के लिए भी काउंटर सहायता का उपयोग किया जाएगा। ऐसे मामलों में, आवेदन, उपयुक्त रसीद के प्रति काउंटर पर लाइसेंसिंग कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगे और प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/सूची/पूछताछ जैसा भी मामला हो, को काउंटर पर ही उसी दिन संशोधित करके/आवश्यक जवाब दे कर वापिस कर दिया जाएगा।

आवेदनों का समय  
बद्धनिपटान

9.11

लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सारणी को अपनाया जाएगा बशर्ते आवेदन हर तरह से पूर्ण हो और उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न हों :

**क्रमांक****आवेदन की श्रेणी****निपटान हेतु समय सीमा**

क.

आयातक निर्यातक कोड संख्या

2 कार्य दिवस

ख.

अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि-उत्पादन मानदण्ड को अधिसूचित किया गया है या पैराग्राफ 4.7 के तहत डी एफ आई ए, जहाँ निविष्टि उत्पादन मानदण्ड अधिसूचित है और वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

3 कार्य दिवस

	अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि उत्पादन मानदण्डों को अधिसूचित किया गया है किन्तु आवेदनों को मानदण्ड समिति (एनसी) के समक्ष रखना है।	15 कार्य दिवस
	अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि उत्पादन मानदंड अधिसूचित नहीं हैं।	15 कार्य दिवस
	निविष्टि-उत्पादन मानदंडों का निर्धारण	90 कार्य दिवस
ग.	डी एफ आर सी/डी ई पी बी	3 कार्य दिवस
घ.	(i) स्वघोषणा आधार पर ई पी सी जी प्राधिकार पत्र	3 कार्य दिवस
	(ii) अन्तर्संबंध के निर्धारण हेतु ई पी सी जी प्राधिकार पत्र (ऊपर 11 को छोड़कर)	45 कार्य दिवस
ङ.	रत्न और आभूषण स्कीम के तहत सभी प्राधिकार पत्र	3 कार्य दिवस
च.	प्राधिकार पत्र की पुनर्वैधता तथा क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि	3 कार्य दिवस
छ.	बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति	3 कार्य दिवस
	अग्रिम प्राधिकार पत्रों हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को	15 कार्य दिवस
	निष्क्रय बनाना ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्क्रय करना	30 कार्य दिवस
ज.	स्तर प्रमाण पत्र जारी करना/नवीकरण करना	3 कार्य दिवस
झ.	किसी भी श्रेणी के प्राधिकार पत्र का संशोधन	3 कार्य दिवस
ञ.	मान्य निर्यात शुल्क वापसी दर का निर्धारण	45 कार्य दिवस
ट.	विविध	10 कार्य दिवस
ठ.	ई डी आई माध्यम से प्रस्तुत सभी आवेदन	1 कार्य दिवस

आवेदनों के निपटान में अनुचित देशी के मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष की जानकारी में लिखित रूप से लाया जायेगा और शीघ्रता से इसकी जांच की जायेगी और उत्तर दिया जायेगा।

आयात के संबंध में शिपमेंट/प्रेषण की तारीख 9.11क आयात के उद्देश्य के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा:-

**परिवहन का तरीका****शिपमेंट/प्रेषण की तारीख**

समुद्र मार्ग द्वारा

लदान-पत्र पर लिखी तारीख

वायु मार्ग द्वारा

सम्बद्ध एयरवे बिल की तारीख बशर्ते इससे उस तारीख का पता चलता हो जब माल अपने देश के अंतिम हवाई अड्डे को छोड़ा हो, जहाँ से आयात किया गया।

स्थल-रुद्ध देशों से

प्रेषण आधार के माध्यम से भारत में खेप भेजने वाले को रेल, सड़क या अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन के साधन द्वारा प्रेषण की तारीख।

डाक पार्सल द्वारा

पैकेटों या प्रेषण नोट पर प्रेषण कार्यालय की स्टैम्प की तारीख

पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा

कुरियर रसीद/वे बिल पर अंकित तारीख

बहु आयामी परिवहन

लदान के संयुक्त परिवहन में पहले वाहन से सामान सौंपने की तारीख

निर्यात के संबंध  
में शिपमेंट/प्रेषण  
की तारीख

9.12

निर्यात के उद्देश्य के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा:-

**परिवहन का तरीका****शिपमेंट/प्रेषण की तारीख**

1. समुद्र मार्ग द्वारा

बल्क कार्गो के लिए, लदान-पत्र की तारीख या नेट रसीद की तारीख, जो भी बाद की हो।

क. कंटेनर-युक्त कार्गो के लिए, 'जहाज पर लदान बिल' या "लदानके जहाज-लदान-बिल के लिए प्राप्त" की तारीख जहाँ एल/सी में ऐसे लदान-पत्र की व्यवस्था है। अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो। आई सी डी। से कंटेनरों द्वारा निर्यात के लिए, सीमाशुल्क निकासी के पश्चात आई सी डी में निर्यात माल के लदान के समय शिपिंग एजेंटों द्वारा जारी किए गए लदान-पत्र की तारीख।

ख. लैश बार्जेज के लिए, लदान-पत्र की तारीख जिसमें जहाज पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लदान का प्रमाण हो।

2. वायु मार्ग द्वारा

उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा शिपिंग बिल पर उल्लिखित तारीख, जिसमें लदान या वायु कार्गो काम्पलैक्स, जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, को माल सौंपने का या उड़ान संख्या और तारीख का प्रमाण हो।

3. डाक पार्सल द्वारा

डाक रसीद पर अंकित तारीख।

4. रेल द्वारा रेलवे रसीद की तारीख।
5. पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा कुरियर रसीद/माल-सूची पर अंकित तारीख।
6. सड़क मार्ग द्वारा जैसा कि भूमि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, भारतीय सीमा से माल बाहर जाने की तारीख।

तथापि, जहाँ कहीं नीति सम्बंधी उपबंधों को निर्यातकों के हित में संशोधित किया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना की तारीख तक जाँच के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को पहले से ही सौंपे गए खेपों और बाद में निर्यातों पर लागू नहीं होंगे।

इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व अवधि के समाप्ति से पहले माल सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता, किन्तु वास्तविक निर्यात, निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के बाद किए जाते हैं, ऐसे निर्यातों पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाएगी।

पुनरीक्षा का सामान्य 9.13

महानिदेशक, विदेश व्यापार स्वयं या अन्यथा, ई पी सी/एफ आई ई ओ के किसी अधिकारी, जिसमें उसके द्वारा नामित व्यक्ति, नियुक्त या प्राधिकारियों का समूह/समिति शामिल है, के पास लम्बित पड़े किसी मामले या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तय किए गए मामले के रिकार्ड मंगा सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

## परिशिष्ट

परिशिष्ट प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (2004-2009) का अभिन्न अंग हैं जो सार्वजनिक सूचना सं० 1 (आरई-2007)/2004-09 दिनांक 19 अप्रैल, 2007 द्वारा यथा अधिसूचित वार्षिक परिशिष्ट में शामिल है।

परिशिष्ट विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट: <http://dgft.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 19th April, 2007

**No. 1 (RE-2007)/2004—2009**

**F. No. 01/94/180/Handbook/AM 08/PC-I.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby notifies annual supplement of the Handbook of Procedures (Volume I) incorporating Annual Supplement as updated on 19th April, 2007 as contained in annexure to this Public Notice and the Appendices to the Handbook of Procedures (Vol. I) as available on the website of Directorate General of Foreign Trade at <http://dgft.gov.in>. This shall come into force from 1st April, 2007.

This issues in Public interest.

**B. S. MEENA**, Director General of Foreign Trade and Ex Officio Addl. Secy.

**GLOSSARY (ACRONYMS)**

ACC	Assistant Commissioner of Customs
ACU	Asian Clearing Union
AEZ	Agri Export Zone
ANF	Aayaat Niryaat Form
ARO	Advance Release Order
ASIDE	Assistance to States for Infrastructure Development of Exports
BG	Bank Guarantee
BIFR	Board of Industrial and Financial Reconstruction
BoA	Board of Approval
BoT	Board of Trade
BRC	Bank Realisation Certificate
BTP	Bio Technology Park
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CCP	Customs Clearance Permit
CEA	Central Excise Authority
CEC	Chartered Engineer Certificate
CIF	Cost, Insurance & Freight
CIS	Commonwealth of Independent States

CoD	Cash on Delivery
CoO	Certificate of Origin
CVD	Countervailing Duty
DA	Document against Acceptance
DoBT	Department of Bio Technology
DC	Development Commissioner
DEPB	Duty Entitlement Pass Book Scheme
DFIA	Duty Free Import Authorisation
DFRC	Duty Free Replenishment Certificate
DGCI&S	Director General, Commercial Intelligence & Statistics
DGFI	Director General of Foreign Trade
DIPP	Department of Industrial Policy & Promotion
DoC	Department of Commerce
DoE	Department of Electronics
DoIT	Department of Information Technology
DoR	Department of Revenue
DoT	Department of Tourism
DTA	Domestic Tariff Area
EDI	Electronic Data Interchange
EEFC	Exchange Earners' Foreign Currency
EFC	Exim Facilitation Committee
EFT	Electronic Fund Transfer
EH	Export House
EHTP	Electronic Hardware Technology Park
EIC	Export Inspection Council
EO	Export Obligation
EOP	Export Obligation Period
EOU	Export Oriented Unit
EPC	Export Promotion Council
EPCG	Export Promotion Capital Goods
EPO	Engineering Process Outsourcing
FDI	Foreign Direct Investment
FIEO	Federation of Indian Export Organisation
FIRC	Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FMS	Focus Market Scheme
FOB	Free On Board
FPS	Focus Product Scheme
FT (D&R) Act	Foreign Trade ( Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992)



FTDO	Foreign Trade Development Officer
FTP	Foreign Trade Policy
GATS	General Agreement on Trade in Services
GRC	Grievance Redressal Committee
HACCP	Hazard Analysis And Critical Control Process
HBP v1	Hand Book of Procedures (Vol. 1)
HBP v2	Hand Book of Procedures (Vol. 2)
ICD	Inland Container Depot
ICM	Indian Commercial Mission
IEC	Importer Exporter Code
ISO	International Standards Organisation
ITC (HS)	Indian Trade Classification (Harmonised System) Classification for Export & Import Items, 2004-2009
ITPO	India Trade Promotion Organisation
LoC	Line of Credit
LoI	Letter of Intent
LoP	Letter of Permit
LUT	Legal Under Taking
MAI	Market Access Initiative
MDA	Market Development Assistance
MEA	Ministry of External Affairs
MoD	Ministry of Defence
MoF	Ministry of Finance
NC	Norms Committee
NFE	Net Foreign Exchange
NOC	No Objection Certificate
PRC	Policy Relaxation Committee
PTH	Premier Trading House
PSU	Public Sector Undertaking
R&D	Research and Development
RA	Regional Authority
RBI	Reserve Bank of India
REP	Replenishment
RCMC	Registration-cum-Membership Certificate
RSCQC	Regional Sub-Committee on Quality Complaints
S/B	Shipping Bill
SEH	Star Export House

SEI CMM	Software Engineers Institute's Capability Maturity Model
SEZ	Special Economic Zone
SFIS	Served from India Scheme
SIA	Secretariat for Industrial Assistance
SION	Standard Input Output Norms
SSI	Small Scale Industry
STE	State Trading Enterprise
STH	Star Trading House
STP	Software Technology Park
TEE	Towns of Export Excellence
TH	Trading House
TRQ	Tariff Rate Quota
VA	Value Addition
VKGUY	Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana
WHOGMP	World Health Organisation Good Manufacturing Practices

## CHAPTER-1

### INTRODUCTION

<b>Notification</b>	1.1	In pursuance of the provisions of paragraph 2.4 FTP, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby notifies the compilation known as HBP v1, HBP v2 and Schedule of DEPB rates. These compilations, as amended from time to time, shall remain in force until 31st March, 2009.
<b>Objective</b>	1.2	Objective is to implement provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made thereunder and FTP (2004-09) by laying down simple, transparent and EDI compatible procedures which are easy to comply with and administer for efficacious management of foreign trade.
<b>Definition</b>	1.3	For purpose of this Handbook, definitions and glossary contained in FT (D&R) Act, Rules and Orders made thereunder and the FTP (2004-09) shall apply.

## CHAPTER-2

### GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS AND IMPORTS

<b>Policy</b>	2.1	Policy relating to general provisions regarding exports and imports is given in Chapter-2 of FTP.
<b>Countries of Imports / Exports</b>	2.2	<p>Unless otherwise specifically provided, import / export will be valid from / to any country.</p> <p>Above provisions shall, however, be subject to all conditionality, or requirement of Authorisation as required under Schedule I and / or Schedule II of ITC (HS).</p>
<b>Application Fee</b>	2.3	The scale of fee, mode of payment, procedure for refund of fee and categories of persons exempted from payment of fee are contained in Appendix 21B.
<b>Territorial Jurisdiction of Regional Authorities (RA)</b>	2.4	Every application, unless otherwise specified, shall be submitted to RA concerned, as indicated in Appendix 1 of HBP v1.
<b>Filing of Application</b>	2.5	An incomplete or unauthorised application is liable to be rejected giving specific reason for rejection. In case of manual applications, applicant would furnish a soft copy of the application in MS word format.
<b>Profile of Importer/ Exporter</b>	2.6	Each importer / exporter shall be required to file importer / exporter profile once with RA in ANF 1. RA shall enter such information in database so as to dispense with need for asking information again. In case of any change in information given in ANF 1, importer / exporter shall intimate same to RA.
<b>Self Addressed Stamped Envelope</b>	2.7	Applicant shall furnish a self-addressed envelope of 40 x 15 cm with required postal stamp affixed for all documents required to be sent by Speed Post.
<b>IEC No: Exempted Categories</b>	2.8	<p>Following categories of importers or exporters are exempted from obtaining IEC number:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Importers covered by clause 3(1) [except sub-clauses (e) and (l)] and exporters covered by clause 3(2) [except sub-clauses (i) and (k)] of Foreign Trade (Exemption from application of Rules in certain cases) Order, 1993.</li> <li>(ii) Ministries / Departments of Central or State Government.</li> <li>(iii) Persons importing or exporting goods for personal use not connected with trade or manufacture or agriculture.</li> </ul>

- (iv) Persons importing / exporting goods from / to Nepal, Myanmar through Indo-Myanmar border areas and China (through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports) provided CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rs.25, 000.

However, exemption from obtaining IEC number shall not be applicable for export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipments and Technologies (SCOMET) as listed in Appendix 3, Schedule 2 of ITC (HS) except in case of exports by category (ii) above.

- (v) Following permanent IEC numbers shall be used by non-commercial PSUs and categories of importers / exporters mentioned against them for import / export purposes.

S.No	Code Number	Categories of Importers / Exporters
1.	0100000011	All Ministries / Departments of Central Government and agencies wholly or partially owned by them.
2.	0100000029	All Ministries / Departments of any State Government and agencies wholly or partially owned by them.
3.	0100000037	Diplomatic personnel, Counselor officers in India and officials of UNO and its specialised agencies.
4.	0100000045	Indians returning from / going abroad and claiming benefit under Baggage Rules.
5.	0100000053	Persons / Institutions / Hospitals importing or exporting goods for personnel use, not connected with trade or manufacture or agriculture.
6.	0100000061	Persons importing / exporting goods from / to Nepal
7.	0100000070	Persons importing / exporting goods from / to Myanmar through Indo-Myanmar border areas
8.	0100000088	Ford Foundation
9.	0100000096	Importers importing goods for display or use in fairs / exhibitions or similar events under provisions of ATA carnet.

	10.	0100000100	Director, National Blood Group Reference Laboratory, Bombay or their authorized offices.
	11.	0100000126	Individuals / Charitable Institution / Registered NGOs importing goods, which have been exempted from Customs duty under Notification issued by Ministry of Finance for bonafide use by victims affected by natural calamity.
	12.	0100000134	Persons importing / exporting permissible goods as notified from time to time, from / to China through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports.
<b><i>Application for Grant of IEC Number</i></b>	2.9		An application for grant of IEC number shall be made by Registered / Head Office of applicant, except EOUs and SEZ units to concerned RA in ANF 2A with documents prescribed therein.
			Only one IEC would be issued / allowed against a single PAN number.
<b><i>IEC Format and Statements</i></b>	2.9.1		RA concerned shall issue an IEC number in prescribed format (Appendix 18B). A copy of such IEC number shall be endorsed to concerned banker (as per details given in ANF 2A).
			A consolidated statement (in Appendix 18 C) of IEC numbers issued by RA shall be sent to Exchange Control Department of RBI as given in Appendix 18D.
<b><i>Validity of IEC No.</i></b>	2.9.2		An IEC number allotted to an applicant shall be valid for all its branches / divisions / units / factories.
<b><i>Duplicate Copy of IEC Number</i></b>	2.9.3		Where an IEC Number is lost or misplaced, issuing authority may consider requests for grant of a duplicate copy of IEC number, on an affidavit.
<b><i>Surrender of IEC Number</i></b>	2.9.4		If an IEC holder does not wish to operate allotted IEC number, he may surrender same by informing issuing authority. On receipt of such intimation, issuing authority shall immediately cancel it and electronically transmit it to DGFT and Customs authorities.
	2.9.5		Deleted
<b><i>Application for Import and Export of Restricted Items</i></b>	2.10		An application for grant of an Authorisation for import or export of items mentioned as restricted in ITC (HS) may be made to RA as specified under relevant Chapters of this Handbook.

**Imports under Indo-US Memorandum of Understanding**

2.11 Import of specified capital goods, raw materials and components, from United States of America (USA) is subject to US Export Control Regulations.

US suppliers of such items are required to obtain an export authorisation based on import certificate issued in India. The following are designated Import Certificate Issuing Authorities (ICIA):

- (i) Department of Electronics (DoE), for computer and computer based systems;
- (ii) Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Technical Support Wing (TSW), for organised sector units registered under it, except for computers and computer based systems;
- (iii) Ministry of Defence (MoD), for defence related items;
- (iv) DGFT for small scale industries and entities not covered above as well as on behalf of any of the above;
- (v) Embassy of India, Washington, DC, on behalf of any of the above.

A request for an import certificate shall be made in ANF 2C. Import certificate in Appendix 31 may be issued by ICIA directly to importer with a copy to (i) Ministry of External Affairs (MEA) (AMS Section), New Delhi, (ii) DoE, New Delhi; and (iii) DGFT.

However, this import certificate will not be regarded as a substitute for an import authorisation in respect of items mentioned as restricted in ITC (HS) and an import authorisation will have to be obtained for such items.

**Validity Of Import Licence / Certificate / Authorisation / Permissions / CCPs / Export licence**

2.12 Validity of import / export Authorisation from date of issue shall be as follows, unless specified otherwise:

- |  |  |
|--|--|
| (i) Advance Authorisation / DFIA<br>(including Advance Authorisation for annual requirement, and Replenishment Authorisation for Gem & Jewellery as per Chapter- 4 of FTP) | 24 months                                    |
| (ii) EPCG Authorisation<br>(other than spares)   | 36 months                                    |
| (iii) EPCG Authorisation for Spares, refractories, catalyst and consumables  | Co- terminus with EOP of EPCG Authorisation. |

- |   |  |
|---|--|
| (iv) Others including CCP and DEPB, unless otherwise specified  | 24 months  |
| (v) Advance Authorisation / DFIA for deemed export (including Advance Authorisation for annual requirement) | 24 months or Co-terminus with contracted duration of project execution whichever is later. |
| (vi) Export Licence / Authorisation   | 12 months  |

2.12.1 Where an Authorisation expires during the month, such Authorisation shall be deemed to be valid until last day of concerned month.

This proviso would be applicable even for a revalidated Authorisation.

2.12.2 Validity of an import Authorisation is decided with reference to date of shipment / dispatch of goods from supplying country as given in Paragraph 9.11 A of HBP v1 and not the date of arrival of goods at an Indian port.

2.12.3 Provisions of paragraph 2.12.2 above shall not be applicable to DEPB, Service Providers under SFIS, VKGUY and duty credit scrips issued under FMS and FPS, which are duty credit entitlements and must be valid on date on which actual debit of duty is made.

2.12.4 Similarly, EOP shall be deemed to be valid until month end.

**Revalidation of Import /  
Export Licence /  
Certificate /  
Authorisation /  
Permissions**

2.13 RA concerned may revalidate import Authorisation on merits, for six months from date of expiry of validity. However, Export Licence may only be revalidated by RA concerned on recommendation of DGFT for six months at a time and maximum upto 12 months from date of expiry of validity.

2.13.1 However, revalidation of freely transferable Authorisation and stock and sale Authorisation shall not be permitted unless validity has expired while in custody of Customs authority / RA.

2.13.2 Such revalidation (under 2.13 and 2.13.1 above) would be permitted under specific orders of Head of concerned Office and would be maximum up to extent of custody period.

2.13.3 An application for revalidation (including for restricted items), may be made to RA concerned. RA would consider such application as per government rules / notifications. Where DGFT is concerned authority, original application shall be submitted to

- RA concerned and self-attested copy of same shall be submitted to DGFT.
- Duplicate Copies of  
Export-Import Licence /  
Certificate / Authorisation /  
Permissions / CCPs**
- 2.14 Where an Authorisation is lost or misplaced, an application for issue of a duplicate may be made along with an affidavit, as given in Appendix 24, to issuing RA.
- RA concerned may, on merits to be recorded, issue a duplicate after issuing an order for cancellation of original and informing customs authority where original was registered.
- 2.15 Duplicate copy of freely transferable Authorisation, may be issued against an application accompanied with following documents:
- An application with fee equivalent to 10% of duty saved or duty credit (of unutilized balance).
  - A copy of FIR reporting loss.
  - Original affidavit on notorised stamp paper.
  - Indemnity bond on a stamp paper undertaking to indemnify revenue loss, which may be caused on account of issue of such duplicate.
- 2.15.1 When an Authorisation has been lost by a Government agency and a proof to this effect is submitted, documents at serial nos. (a) to (d) above shall not be required.
- In such cases, revalidation shall be for six months from date of endorsement.
- 2.15.2 RA concerned shall obtain a report regarding utilization of such Authorisation from Custom authority at port of registration before issuing duplicate, for balance unutilized.
- 2.15.3 Validity of duplicate Authorisation shall be co-terminus with original period. No request shall be entertained if validity has expired.
- 2.15.4 Deleted
- 2.15.5 Provision of paragraph 2.15.2 and 2.15.3 shall be applicable both for cases covered under paragraph 2.14 and 2.15.
- Identity Cards**
- 2.16 To facilitate collection of Authorisation and other documents from DGFT Head Quarters and RA, identity cards (as in Appendix 20B, valid for 3 years) may be issued to proprietor / partners / directors and authorised employees (not more than three), of importers and exporters, upon application as in Appendix 20A.



However, in case of limited companies, RA may approve allotment of more than three identity cards per company.

In case of loss of an identity card, a duplicate card may be issued on the basis of an affidavit.

Common directors / partners, of a group company or in any other similar cases, RA may issue multiple identity cards after recording reasons in writing.

***Interviews with  
authorised Officers.***

2.17

Officers may grant interview at their discretion to authorised representative of importer / exporter. Interviews / clarifications may also be sought through E-mails.

***Export of Items  
Reserved for SSI Sector***

2.18

Units other than small scale units are permitted to expand or create new capacities in respect of items reserved for small scale sector, subject to condition that they obtain an Industrial licence under the Industries (Development and Regulation), Act, 1951, with export obligation as may be specified.

Such licensee is required to furnish a LUT to RA and DGFT in this regard. DGFT / RA concerned shall monitor export obligation.

***Warehousing Facility***

2.19

Public / Private Customs Bonded Warehouses may be set up in DTA as per Chapter-IX of Customs Act, 1962, to import items in terms of paragraph 2.28 of FTP.

On receipt of goods, such warehouses shall keep these goods for one year without payment of applicable customs duties. Goods can be cleared against Bill of Entry for home consumption, on payment of applicable custom duty and on submission of Authorisation wherever required, after an order for clearance of such goods for home consumption is issued by competent customs authorities.

In case of clearance against duty free categories / concessional duty categories, exemption / concession from duty shall be, allowed.

In case of clearance against DEPB and other duty credit scrips customs duty on imports may be adjusted.

Goods can be re-exported without payment of customs duty provided (i) a shipping bill or a bill of export is presented in respect of such goods; and (ii) order for export of such goods has been made by competent customs authorities.

**Execution of Bank  
Guarantee / Legal  
Undertaking for Advance  
Authorisation / DFIA and  
EPCG Authorisation**

2.20

Before clearance of goods through Customs, Authorisation holder shall execute a LUT / BG with customs authorities.

"Bank Guarantee / LUT as applicable to be executed as per relevant Customs Notification / Circular"

In case of indigenous sourcing, Authorisation holder shall furnish BG / LUT to RA as prescribed below before sourcing the material:

(A). Following entities shall be entitled for LUT facility:

1. All Status holders / PSUs;
2. Manufacturer exporter (except Proprietorship and Partnership firms), Registered with Central Excise authority with a minimum export turnover of Rs.1 Crore in preceding year and having exported during previous two financial years.
3. Manufacturer Exporter, registered with Central Excise Authority and having paid Central Excise Duty of Rs.1 Crore or more during preceding financial year.
4. All exporters with an export turnover of at least Rupees 5 crores in preceding licencing year and having a good track record and three years of export performance.

(B) Following shall be required to furnish a Bond supported by BG to extent of 15% of duty saved on excise and education cess, if applicable:

1. Other Manufacturer Exporter not covered under (A) above (except Proprietorships and Partnership firms); exporting for last 3 years, or exporting in any of the last 3 years, based on Certification of their previous years' exports from Central Excise Authorities

Provided that for any of last 3 years, the unit should be registered with Excise Authorities or State Sales Tax Authorities.

2. Manufacturing companies (as per Companies Act) having not exported in each of preceding three licencing years but fulfilling following criterion:

- (i) Registration with Central Excise Authorities and payment of Central Excise duty (unless exempted); and

- (ii) Registration with State Sales Tax / VAT Authorities and payment of sales tax / VAT (unless exempted); and
  - (iii) Minimum investment of Rs 50 lakh in plant and machinery (as in audited Balance Sheet).
- (C) Following shall be required to furnish a Bond supported by BG to the extent of 100% of duty saved on excise and education cess, if applicable:
- 1. Merchant Exporter, all types of Proprietorship and Partnership firms (Other than Status Holders / PSUs and category (A) 4 above);
  - 2. Service providers other than those in category (A) 1 and (A) 4 above
- (D) Manufacturer / Merchant Exporters (under (A) & (B) above) falling under any of following two categories based on their risk profile are required to execute bond supported by BG to extent of 100% of duty saved amount on excise and education cess if applicable. This can be prescribed by Head of office not being below rank of Deputy DGFT by recording reasons in writing:
- 1. Have come under adverse notice of Customs / DGFT / Central Excise for serious irregularities;
  - 2. Having adverse track record in terms of fulfillment of pending export obligation.

In cases where Excise Duty is nil on items of indigenous procurement, BG furnished would be for 25% of basic Customs Duty on same product. BG and LUT should be valid as per terms and conditions incorporated in Appendix 25A & 25B respectively. Validity of BG / LUT is required to be extended in case of extension in EOP. Specific endorsement to this effect shall be made in the Authorisation by RA.

In respect of categories (A) 3, (A) 4 & (B) 1 above, if exporter has not exported for any of the 3 preceding years, 15% BG condition shall be imposed on duty saved amount provided the CIF value does not exceed 200% of domestic turnover or 200% of FOB / FOR value of supplies of preceding licensing year, whichever is higher. Authorisation beyond 200% entitlement shall be subject to 100% BG on duty saved amount for CIF value exceeding 200% entitlement. However, entitlement may be re-credited on production of documentary evidence showing fulfillment of export obligation and realization of export / supply proceeds.

In respect of categories at (A) 2 and (A) 4 above, Authorisation Holder would be required to submit Export Performance Certificate issued by a Chartered Accountant as per Appendix 26.

For import / domestic procurement of car under EPCG scheme, 100% BG will be required to be furnished except in case of status holders / PSUs who will furnish BG / LUT as aforesaid.

BG exemption / relaxation as mentioned above shall also be available in respect of past Authorisation where Authorisation holder had earlier filed BG but as on date he is entitled for BG exemption.

In case, firm has already executed BG / LUT for full value of Authorisation covering items indigenously procured, to Customs and furnishes proof of the same, no BG / LUT shall be required to be executed with RA.

**Corporate Guarantee**

- 2.20.1 A Status holder or a PSU may also submit Corporate Guarantee in lieu of BG / LUT, for import and domestic sourcing as prescribed. For a non-status holder group Company, a status holder can give such guarantee.

**Certificate of Origin (CoO)**

- 2.21 Certificate of Origin (CoO) is an instrument to establish evidence on origin of goods imported into any country. There are two categories of CoO viz. (1) Preferential and (2) Non preferential.

**Preferential**

- 2.21.1 Preferential arrangement / schemes under which India is receiving tariff preferences for its exports are Generalised System of Preferences (GSP), Global System Of Trade Preferences (GSTP), SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA), Asia-Pacific Trade Agreement (APTA), India-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISLFTA) and Indo- Thailand Free Trade Agreement. These arrangements / agreements prescribe Rules of Origin which have to be met for exports to be eligible for tariff preference.

Authorised agencies shall provide services relating to issue of CoO, including details regarding rules of origin, list of items covered by an agreement, extent of tariff preference, verification and certification of eligibility. Export Inspection Council (EIC) is agency authorised to print blank certificates. Authorised agencies may charge a fee, as approved by DoC, for services rendered.

**Generalised System of Preferences (GSP)**

- (a) GSP is a non-contractual instrument by which industrialized (developed) countries unilaterally and based on non-reciprocity extend tariff concessions to developing countries. Following countries extend tariff preferences under their GSP Scheme:

- |                               |                      |               |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (i) United States of America, | (ii) New Zealand     | (iii) Belarus |
| (vi) Russia                   | (iv) European Union, | (v) Japan     |
| (ix) Australia                | (vii) Canada,        | (viii) Norway |
| (only to LDCs)                | (x) Switzerland      | (xi) Bulgaria |

GSP schemes of these countries detail sectors / products and tariff lines under which benefits are available, including conditions and procedures governing benefits. These schemes are renewed and modified from time to time. Normally Customs of GSP offering countries require information in Form 'A' (prescribed for GSP Rules Of Origin) duly filled by exporters of beneficiary countries and certified by authorised agencies. List of agencies authorised to issue GSP CoO is given in Appendix 4A.

**Global System of Trade Preference (GSTP)**

- (b) Under agreement establishing GSTP, tariff concessions are exchanged among developing countries, who have signed agreement. Presently, 46 countries are members of GSTP and India has exchanged tariff concessions with 12 countries on a limited number of products. EIC is sole agency authorised to issue CoO under GSTP.

**SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA)**

- (c) SAPTA was signed by seven SAARC members namely India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives in 1993 and came into operation in 1995. Four rounds of trade negotiations have been completed and more than 3000 tariff lines are under tariff concessions among SAARC countries. List of agencies, authorised to issue CoO under SAPTA are notified under Appendix 4B.

**Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)**

- (d) APTA is a preferential trading arrangement designed to liberalise and expand trade in goods progressively in Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) region through liberalization of tariff and non-tariff barriers. At present, Bangladesh, Sri Lanka, South Korea, India and China are exchanging tariff concessions under APTA. Agencies authorised to issue CoO under APTA are listed in Appendix 4B.

**India-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISLFTA)**

- (e) Free Trade Agreement (FTA) between India and Sri Lanka was signed on 20.12.1998 and was operationalised in March, 2000 following notification of required Customs tariff concessions by Government of Sri Lanka and India. EIC is sole agency to issue CoO under ISLFTA.

***India Afghanistan Preferential Trade Agreement***

- (f) A Preferential Trade Agreement between Transitional Islamic State of Afghanistan and Republic of India was signed on 6.3.2003 and was operationalised with issuance of Customs Notification No 76/2003 dated 13.5.2003. EIC is sole agency to issue CoO under India Afghanistan Preferential Trade Agreement.

***Indo – Thailand Framework Agreement for Free Trade Area***

- (g) India and Thailand have signed protocol to implement Early Harvest Scheme under India- Thailand Free Trade Agreement on 01.09.2004. Tariff preferences for imports on items of Early Harvest Scheme would be available only to those products, which satisfy Rules of Origin Criteria, notified by Department of Revenue, Ministry of Finance, vide notification No.101/2004-Customs dated 31.08.2004. EIC would be sole agency to issue CoO under Early Harvest Scheme of Framework Agreement on India-Thailand Free Trade Agreement.

***Non Preferential***

- 2.21.2 Government has also nominated certain agencies to issue Non Preferential CoO in accordance with Article II of International Convention Relating to Simplification of Customs formalities, 1923. These CoOs evidence origin of goods and do not bestow any right to preferential tariffs. List of notified agencies is provided in Appendix 4C. In addition, agencies authorized to issue Preferential CoO as per Para 2.21.1 of HBP v1 are also authorized to issue Non-Preferential CoO.

All exporters who are required to submit CoO (Non Preferential) would have to apply to any of agencies enlisted in Appendix-4C with following documents:

- (a) Details of quantum / origin of inputs / consumables used in export product.
- (b) Two copies of invoices.
- (c) Packing list in duplicate for concerned invoice.
- (d) Fee not exceeding Rs.100 per certificate as may be prescribed by concerned agency.

The agency would ensure that goods are of Indian origin as per general principles governing rules of origin before granting CoO (non preferential). Certificate would be issued as per Format given in Annexure-II to Appendix 4C. It should be ensured that no correction/re-type is made on certificate.

Any agency desirous of enlistment in Appendix 4C may submit their application as per Annexure I to Appendix 4C to the concerned RA.

		In case of tea, all exporters who are required to submit CoO (Non-Preferential) shall apply to Tea Board or any Inspection Agency authorized by Tea Board and enlisted in Appendix 4C of HBP v1 with documents listed above.
<b>Automatic Licence / Certificate / Authorisation / Permission</b>	2.22	Status holders shall be issued Authorisation automatically within stipulated time period. Deficiency, if any, informed through covering letter, shall be required to be rectified by status holders within 10 days from date of communication of deficiency.
<b>Submission of Certified Copies of Documents</b>	2.23	Wherever original documents have been submitted to a different RA / nominated agencies or to a different division of same RA, applicant can furnish photocopy of documents duly certified by him in lieu of original.
<b>Advance Payment</b>	2.24	In case, payment is received in advance and export / deemed exports takes place subsequently, application for an Authorisation shall be filed within specific period following the month during which exports / deemed exports are made, unless otherwise specified
<b>Payment through ECGC cover</b>	2.25.1	Payment through ECGC cover would count for benefits under FTP.
<b>Payment through General Insurance</b>	2.25.2	Amount of General Insurance Cover for transit loss would be treated as payment realized for exports under various export promotion schemes.
<b>Irrevocable Letter of Credit</b>	2.25.3	In case where applicant applies for duty credit scrip / DEPB / DFIA / discharge of EO against confirmed irrevocable letter of credit (or bill of exchange which is unconditionally Avalised / Co-Accepted / Guaranteed by a bank) and this is confirmed and certified by exporter's bank in relevant Bank Certificate of Export and Realization, payment of export proceeds shall be deemed to be realized. For status holders, irrevocable letter of credit would suffice.
<b>Export by post</b>	2.26	In case of export by post, exporter shall submit following documents in lieu of documents prescribed for export by sea / air: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank Certificate of Export and Realisation as in Appendix 22A.</li> <li>2) Relevant postal receipt</li> <li>3) Invoice duly attested by Customs authorities.</li> </ol>
<b>Import/ Export through Courier Service</b>	2.26.1	Imports / Exports through a registered courier service is permitted as per Notification issued by DoR. However, importability / exportability of such items shall be regulated in accordance with FTP.

- |  |        |   |
|--|--------|---|
| <b>Direct negotiation of export documents</b>  | 2.26.2 | <p>In cases where exporter directly negotiates document (not through authorised dealer) with permission of RBI, he is required to submit following documents for availing of benefits under export promotion schemes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permission from RBI allowing direct negotiation of documents (not required for status holders),</li> <li>b. Copy of Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) as per Form 10-H of Income Tax department in lieu of BRC and</li> <li>c. Statement giving details of shipping bills / invoice against which FIRC was issued.</li> </ol>  |
| <b>Import / Export of Samples</b>  | 2.27   | <p>No Authorisation shall be required for Import of bonafide technical and trade samples of items restricted in ITC(HS) except vegetable seeds, bees and new drugs. Samples of tea not exceeding Rs.2000 (CIF) in one consignment shall be allowed without an Authorisation by any person connected with Tea industry.</p> <p>Duty free import of samples upto Rs 75,000 for all exporters (Rs.300,000 for gems and jewellery sector) shall be allowed as per terms and conditions of Customs notification.</p> <p>Exports of bonafide trade and technical samples of freely exportable item shall be allowed without any limit.</p>  |
| <b>Import under Lease Financing</b>  | 2.28   | <p>Import under lease financing shall be available under EPCG Scheme, EOU / SEZ scheme. Domestic supplier of capital goods to eligible categories of deemed exports shall be eligible for benefits of deemed exports as in paragraph 8.3 of FTP, even in cases where supplies are under lease financing.</p>  |
| <b>Exhibits Required for National and International Exhibitions or Fairs and Demonstration</b> | 2.29   | <p>Import / export of exhibits, including construction and decorative materials required for the temporary stands of foreign / Indian exhibitors at exhibitions, fair or similar show or display for a period of six months on re-export / re-import basis, shall be allowed without an Authorisation on submission of a certificate from an officer of a rank not below that of an Under Secretary/ Deputy DGFT in DoC / DGFT or an officer of Indian Trade Promotion Organization (ITPO) duly authorised by its Chairman in this behalf, to effect that such exhibition, fair or similar show or display</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) has been approved or sponsored by DoC or ITPO; and</li> <li>(ii) is being held in public interest.</li> </ol> |



Extension beyond six months for re-export / re-import will be considered by Customs authorities on merits. Consumables such as paints, printed material, pamphlets, literature etc. pertaining to exhibits need not be re-exported / re-imported.

**Import Policy**

2.30

Policy relating to general provisions regarding import of capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods is given in Chapter 2 of FTP.

**General Procedure for Licensing of Restricted Goods**

2.31

Wherever an import Authorisation, including CCP, is required under FTP, procedure contained in this chapter shall be applicable.

2.32

**Import of Metallic Waste and Scrap**

2.32.1

Import of any form of metallic waste, scrap will be subject to the condition that it will not contain hazardous, toxic waste, radioactive contaminated waste / scrap containing radioactive material, any type of arms, ammunition, mines, shells, live or used cartridge or any other explosive material in any form either used or otherwise.

2.32.2

Import of following types of metallic waste and scrap will be free subject to conditions detailed below :

Sl.No.	Exim code	Item description
1	720410 00	waste and scrap of cast iron
2.	72042190	Other
3.	72042920	Of High speed steel
4.	72042990	Other
5.	72043000	Waste and scrap of tinned iron or steel
6.	72044100	Turnings, shavings, chips, milling waste, saw dust, fillings, trimmings and stampings, whether or not in bundles
7.	72044900	Other
8.	72045000	Remelting scrap ingots
9.	74040010	Copper scrap
10.	74040022	Brass scrap
11.	75030010	Nickel scrap
12.	76020010	Aluminium scrap
13.	79020010	Zinc scrap
14.	80020010	Tin scrap
15.	81042010	Magnesium scrap

Shredded form: Import of metallic waste and scrap listed in para 2.32.2 above in shredded form shall be permitted through all ports of India. Import from Hodaideh, Yemen and Bandar Abbas, Iran will be in shredded form only.

Unshredded compressed and loose form: Import of metallic waste, scrap listed in para 2.32.2 above in unshredded compressed and loose form shall be subject to terms and conditions as notified by DGFT.

a. Preshipment inspection can be prescribed. Agencies / bodies can be registered for this purpose as per procedure prescribed by DGFT.

b. Import of scrap would take place only through following designated ports and no exceptions would be allowed even in case of EOUs, SEZs:-

“1.Chennai, 2.Cochin, 3.Ennore, 4.JNPT, 5.Kandla, 6.Mormugao, 7.Mumbai, 8.New Mangalore, 9.Paradip, 10.Tuticorin, 11.Vishakhapatnam, 12.ICD Tughlakabad (New Delhi), 13.Pipava, 14.Mundra, 15.Kolkata, 16.ICD Ludhiana, 17.ICD Dadri (Greater Noida), 18.ICD Nagpur, 19.ICD Jodhpur, 20.ICD Jaipur, 21.ICD Udaipur, 22.CFS Mulund, 23.ICD Kanpur, 24.ICD Ahmedabad, 25.ICD Pitampur and 26.ICD Malanpur”.

c. New system of import from registered sources will come into effect from 01.10.2007. However, in cases where Bill of Lading is dated 30.09.2007 or before, imports will be allowed on the basis of Pre-Shipment Inspection regime in terms of Para 2.32 of the HBP v1, notified vide Public Notice No. 1 dated 08.04.2005 and as amended from time to time, till new system of import from registered sources comes into effect. List of Pre-Shipment Agencies notified under earlier regime is available on DGFT web site.

2.32.3 However, import of other kinds of metallic waste and scrap will be allowed in terms of conditions of ITC (HS).

2.32.4 Import policy for seconds and defective, rags, PET bottles / waste, and ships is given in ITC (HS).

### **Import of Second Hand Capital Goods**

2.33 Import of second hand capital goods including refurbished / reconditioned spares, shall be allowed freely, subject to conditions for following categories:

Import of second hand computers including personal computers and laptops is restricted. Import of refurbished / reconditioned

spares will be allowed on production of a Chartered Engineer certificate that such spares have atleast 80% residual life of original spare.

In case a capital good is imported in parts at two customs stations, on account of bonafide logistical reasons, said imports may be allowed after satisfying that both consignments put together constitute a single capital good.

2.33.1 Notwithstanding provisions of Para 2.33 above, second hand computers, laptops and computer peripherals including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage units can be imported freely as donations by following category of donees:

- (i) Schools run by Central or State Government or a local body,
- (ii) Educational Institution run on non- commercial basis by any organization,
- (iii) Registered Charitable Hospital,
- (iv) Public Library,
- (v) Public funded Research and Development Establishment,
- (vi) Community Information Centre run by Central or State Government or local bodies,
- (vii) Adult Education Centre run by Central or State Government or a local body,
- (viii) Organization of Central or State Government or a Union Territory.

Imports under this sub Para would be subject to the condition that goods shall not be used for any commercial purpose, is non transferable and complies with all terms and conditions of relevant Customs Rules and Regulations.

2.33A Customs or any other Central or State Government authority may avail of services of Inspection and Certification Agencies in Appendix 5 of the HBP v1, for certifying residual life as well as valuation / purchase price of capital good.

**Import of Ammunition  
by Licensed Arms  
Dealers**

2.34 Import of following types of ammunition are allowed against an Authorisation by licensed arms dealers subject to conditions as may be specified:

- (i) Shotgun Cartridges 28 bore;

- (ii) Revolver Cartridges of .450, .455 and .45 bores;
- (iii) Pistol Cartridges of .25, .30 Mauser, .450 and .45 bores;
- (iv) Rifle Cartridges of 6.5 mm, .22 savage, .22 Hornet, 300 Sherwood, 32/40, .256, .275, .280, 7m/m Mauser, 7 m/m Man Schoener, 9m/m Mauser, 9 m/m Man Schoener, 8x57, 8x57S, 9.3 m/m, 9.5 m/m, .375 Magnum, .405, .30.06, .270, .30/30 Winch, .318, .33 Winch, .275 Mag., .350 Mag., 400/350, .369 Purdey, .450/400, .470, .32 Win, .458 Win, .380 Rook, .220 Swift and .44 Win. bores.

An import Authorisation shall be issued at 5% of value of annual average sales turnover of ammunition (whether indigenous or imported) during preceding three licensing years subject to a minimum of Rs. 2000.

An application for grant of an Authorisation for items listed above may be made to RA in ANF 2B along with documents prescribed therein.

***Restricted Items  
Required By Hotels,  
Restaurants, Travel  
Agents, Tour Operators  
And Other Specified  
Categories***

- 2.35 Items mentioned as restricted for imports in ITC (HS) required by hotels, restaurants, travel agents and tour operators may be allowed against an Authorisation, based on recommendation of Director General, Tourism, Government of India.
- 2.35.1 Hotels, including tourist hotels, recognised by Director General of Tourism, Government of India or a State Government shall be entitled to import Authorisation upto a value of 25% of foreign exchange earned by them from foreign tourists during preceding licensing year, for import of essential goods related to hotel and tourism industry.
- 2.35.2 Travel agents, tour operators, restaurants, and tourist transport operators and other units for tourism, like adventure / wildlife and convention units, recognized by Director General of Tourism, Government of India, shall be entitled to import authorisation up to a value of 10% of foreign exchange earned by them during preceding licensing year, for import of essential goods which are restricted for imports related to travel and tourism industry, including office and other equipment required for their own professional use.
- 2.35.3 Import entitlement under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 of any one licensing year can be carried forward, either in full or in part, and added to import entitlement of two succeeding licensing years and shall not be transferable except within the group company or to managed hotels.

	2.35.4	Deleted
	2.35.5	Such imported goods may be transferred after 2 years with permission of DGFT.  No permission for transfer will be required in case the imported goods are re-exported. However, re-export shall be subject to all conditionality, or requirement of licence, or permission, as may be required under Schedule II of ITC (HS).
	2.35.6	An application for grant of an Authorisation under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 may be made in ANF 2B to DGFT through Director of Tourism, Government of India who will forward application to RA concerned along with their recommendations.
<b>Import of Other Restricted Items</b>	2.36	ITC (HS) contains list of restricted items. An application for import of such items may be made, in ANF 2B along with documents prescribed therein. Original application along with Treasury Receipt (TR) / Demand Draft shall be submitted to RA concerned and self-attested copy of same shall be submitted to DGFT in duplicate along with proof of submission of application to concerned RA.
<b>EXIM Facilitation Committee</b>	2.37	Restricted item Authorisation may be granted by DGFT or any other RA authorised by him in this behalf. DGFT / RA may take assistance and advice of a Facilitation Committee. The Assistance of technical authorities may also be taken by seeking their comments in writing.  Facilitation Committee will consist of representatives of Technical Authorities and Departments / Ministries concerned.
<b>Gifts of Consumer or Other Goods</b>	2.38	In terms of provisions contained in paragraph 2.19 of FTP, an application for grant of CCP for import as gifts of items appearing as restricted for imports in ITC (HS) shall be made to the DGFT as in ANF 2B along with documents prescribed therein.  Where recipient of a gift is a charitable, religious or an educational institution registered under any law in force, and gift sought to be imported has been exempted from payment of customs duty by such import shall be allowed by customs authorities without a CCP.
<b>Import under Govt. to Govt. Agreements</b>	2.39	Import of goods under Government to Government agreements may be allowed without an Authorisation or CCP on production of necessary evidence to satisfaction of Customs authorities
<b>Import of Cheque Books/ Ticket Forms etc.</b>	2.40	Indian branches of foreign banks, insurance companies and travel agencies may import chequebooks, bank draft forms and

travellers cheque forms without a CCP. Similarly, airlines / shipping companies operating in India, including persons authorised by such airlines / shipping companies, may import passenger ticket forms without a CCP.

**Import of Reconditioned /  
Second Hand Aircraft  
Spares** 2.41

Import Authorisation for reconditioned / second hand aircraft spares is not needed on recommendation of Director General of Civil Aviation, Government of India (DGCA).

**Import of Replacement  
Goods** 2.42

Goods or parts thereof on being imported and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged after import may be exported without an Authorisation, and goods in replacement thereof may be supplied free of charge by foreign suppliers or imported against a marine insurance or marine-cum-erection insurance claim settled by an insurance company. Such goods shall be allowed clearance by the customs authorities without an import Authorisation provided that:

- (a) Shipment of replacement goods is made within 24 months from date of clearance of previously imported goods through Customs or within guarantee period in case of machines or parts thereof where such period is more than 24 months; and
- (b) No remittance shall be allowed except for payment of insurance and freight charges where replacement of goods by foreign suppliers is subject to payment of insurance and / or freight by importer and documentary evidence to this effect is produced while making remittance.

2.42.1 In case of short-shipment, short-landing or loss in transit, import of replacement goods will be permitted based on certificate issued by customs authorities without an import Authorisation.

This procedure shall also apply to cases in which short-shipment of goods is certified by foreign supplier, who has agreed to replace free of cost.

2.42.2 Cases not covered by above provisions will be considered on merits by DGFT for grant of Authorisation for replacement of goods for which an application may be made in ANF.

**Transfer of Imported  
Goods** 2.43

Freely importable goods can be transferred by sale or otherwise by importer freely. Transfer of imported goods, which are subject to Actual User condition and have become surplus to needs of Actual User, shall be made only with prior permission of RA concerned. Following information alongwith supporting documents shall be furnished with request for grant of permission for transfer, to RA concerned:

- (i) Reasons for transfer of imported material;

- (ii) Name, address, IEC number and industrial Authorisation registration, if any, of transferee;
- (iii) Description, quantity and value of goods imported and those sought to be transferred;
- (iv) Copies of import Authorisation and bills of entry relating to imports made;
- (v) Terms and conditions of transfer as agreed upon between buyer and seller.

2.43.1 Prior permission of RA shall not, however, be necessary for transfer or disposal of goods, which were imported with Actual User condition, provided such goods are freely importable without Actual User condition on date of transfer.

2.43.2 Prior permission of RA shall also not be required for transfer or disposal of imported goods after a period of two years from the date of import. However, transfer of imported firearms by the importer / Authorisation holder shall be permitted only after 10 years of import with approval of DGFT.

#### ***Sale of Exhibits***

- 2.44 (i) Sale of exhibits of restricted items, mentioned in ITC (HS), imported for an international exhibition / fair organized / approved / sponsored by ITPO may also be made, without an Authorisation within bond period allowed for re-export, on payment of applicable customs duties, subject to a ceiling limit of Rs.5 lakhs (CIF) for such exhibits for each exhibitor.

However, sale of exhibits of items, which were freely imported shall be made, without an Authorisation, within bond period allowed for re-export on payment of applicable customs duties.

- (ii) If goods brought for exhibition are not re-exported or sold within bond period due to circumstances beyond control of importer, customs authorities may allow extension of bond period on merits.

#### ***Import of Overseas Office Equipment***

- 2.45 On winding up of overseas offices, set up with approval of RBI, used office equipment and other items may be imported without Authorisation.

2.46 Deleted

#### ***Prototypes***

- 2.47 Import of new / second hand prototypes / second hand samples may be allowed on payment of duty without an Authorisation to an Actual User (industrial) engaged in production of or having

industrial licence / letter of intent for research in item for which prototype is sought for product development or research, as the case may be, upon a self-declaration to that effect, to satisfaction of customs authorities.

***Restricted items for R&D*** 2.48

All restricted items and items permitted to be imported by STEs, except live animals, required for R&D purpose may be imported without an Authorisation by Government recognized Research and Development units.

***Export Policy*** 2.49

Policy relating to Exports is given in Chapter-2 of FTP. Further, Schedule 2, Appendix 1 of ITC (HS) specifies list of items, which may be exported without an Authorisation but subject to terms and conditions specified.

***Application for Grant of Export Licence / Certificate / Permission*** 2.50

An application for grant of Export Authorisation in respect of items mentioned in Schedule 2 of ITC (HS) may be made in ANF 2D (2E for SCOMET items) to DGFT along with documents prescribed therein. EFC shall consider applications on merits for issue of export Authorisation.

An Inter-Ministerial Working Group in DGFT shall consider applications for export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) as specified in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) based on guidelines given below.

Applications for licences to export items or technology on SCOMET List are considered case-by-case, based inter alia on the following general criteria: -

- I. Following factors, among others, are taken into account in the evaluation of applications for export of items on SCOMET List :
  - a. Credentials of end-user, credibility of declarations of end-use of the item or technology, integrity of chain of transmission of item from supplier to end-user, and on potential of item or technology, including timing of its export, to contribute to end-uses that are not in conformity with India's national security or foreign policy goals and objectives, objectives of global non-proliferation, or its obligations under treaties to which it is a State party.
  - b. Assessed risk that exported items will fall into hands of terrorists, terrorist groups, and non-State actors;



- c. Export control measures instituted by recipient State;
- d. The capabilities and objectives of programmes of recipient State relating to weapons and their delivery;
- e. Assessment of end-uses of item(s);
- f. Applicability to an export licence application of relevant bilateral or multilateral agreements to which India is a party.

II. A condition for consideration of an application for an export licence is submission of stipulated certifications to effect, inter alia, that:

- a. The item will be used only for stated purpose and that such use will not be changed, nor items modified or replicated without consent of Government of India;
- b. Neither the items nor replicas nor derivatives thereof will be re-transferred without consent of Government of India;
- c. End-user shall facilitate such verifications as are required by Government of India.

Government of India may also require additional formal assurances, as appropriate, including on end-use and non-retransfer, from State of recipient.

III. Licensing authority for items in Category 0 in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC(HS) is Department of Atomic Energy. Applicable guidelines are notified by that Department under Atomic Energy Act, 1962. For certain items in Category 0, formal assurances from recipient State will include non-use in any nuclear explosive device. Licences for export of certain items in Category 0 will not be granted unless transfer is additionally under adequate physical protection and is covered by appropriate International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, or any other mutually agreed controls on transferred items.

IV. Additional end-use conditions may be stipulated in licences for export of items or technology that bear possibility of diversion to or use in development or manufacture of, or use as, systems capable of delivery of weapons of mass destruction.

- V. Applications for transfer of "Technology" for any item on the List will be considered as an application for export of item itself.
- VI. Licences for export of items in this List (other than those under Category 0, 1 and 2) solely for purposes of display or exhibition shall not require any end-use or end-user certifications. No export licence for display or exhibition shall be issued for 'Technology' in any category or for items under Categories 0, 1, and 2.
- VII. Export of items not on SCOMET List may also be regulated under provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005.

Note 1: Export or attempt to export in violation of any of conditions of licence shall invite civil and/or criminal prosecution.

Note 2: Licences for export of items in this List for display or exhibition abroad are subject to a condition of re-import within a period not exceeding six months. Exporters are entitled to apply for an export licence for such items exhibited abroad if exhibitor intends to offer that item for sale during exhibition abroad. Such sale shall not take place without a valid licence.

Note 3: Export of items in Category 2 of this list may also be controlled by other applicable guidelines issued from time-to-time. Exporters of items in this category are advised to seek guidance from DGFT.

Note 4: Exporters are entitled to apply for a 'destination licence' for countries and / or groupings of countries for export to which only re-transfer conditions need be imposed.

Note 5: Exporters are entitled to request that only such conditions need be imposed as are subject of government-to-government instruments of accord over export of items on SCOMET List.

Note 6: 'Technology' (see also entry 'Technology' in glossary in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS)): Approval of export of an item on the SCOMET List also authorizes the export to same end-user of minimum 'technology' required for installation, operation, maintenance and repair of the item.

DGFT in association with Administrative Ministries / Departments and Trade Associations will organize Industry Outreach Programme on regular basis for an effective awareness among the exporters /importers dealing with trade, in particular, in SCOMET items.

DGFT may also issue, on application, Free Sale and Commerce Certificate for export of items not covered under Drugs & Cosmetics Act, 1940, which have usage in hospitals, nursing homes and clinics, for medical and surgical purposes and are not prohibited for export. Validity of such certificate shall be two years from date of issue unless otherwise specified.

<b>Export Of Items under State Trading Regime (STR)</b>	2.51	An application for export of items mentioned in ITC (HS) under STR regime may be made to DGFT.
<b>Exports Of Samples/ Exhibits</b>	2.52	An application for export of samples or exhibits, which are restricted for export, may be made to DGFT.
<b>Free of Cost Exports</b>	2.52.1	Status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rs.10 lakh or 2% of average annual export realisation during preceding three licensing years whichever is higher.
<b>Gifts / Spares / Replacement Goods</b>	2.53	For export of gifts, indigenous / imported warranty spares and replacement goods in excess of ceiling / period prescribed in paragraphs 2.32, 2.33 and 2.37 respectively of FTP, an application may be made to DGFT.
<b>Furnishing of Returns in respect of Exports in non Physical form</b>	2.54	All exports made in non physical form by using communication links including high speed data communication links, internet, telephone line or any other channel which do not involve Customs authorities has to be compulsorily reported on quarterly basis to concerned EPC (Para 3.6 of FTP) as given in Appendix 19C.  These provisions shall be applicable to all exporting units located anywhere in country including those located in STP, SEZ, EHTP and under 100% EOU scheme.
<b>Duty Free Import of R&amp;D Equipment for Pharmaceuticals and Bio-technology Sector</b>	2.55	Duty free import of goods (as specified in list 28 of Customs notification No.21/2002 dated 1.3.2002, as amended from time to time) upto 25% of FOB value of exports during preceding licensing year, shall be allowed.  The eligible unit may furnish an application given in Appendix 15A to RA concerned duly countersigned by Chartered Accountant.

	2.55.1	Duty free imports of goods as specified in list 28A of Customs notification No. 21/2002 dated 1.3.2002, upto 1% of FOB value of exports made during preceding licensing year, shall be allowed to agro chemicals sector unit having export turnover of Rs. 20 crore or above during preceding licensing year.
		The eligible unit shall apply in form given in Appendix 15B to RA concerned duly countersigned by Chartered Accountant.
<b>Conversion of E.P. copy of shipping bill from one scheme to Another</b>	2.56	If Customs Authorities, after recording reasons in writing, permit conversion of an E.P. copy of any scheme-shipping bill on which benefit of that scheme has not been availed, exporter would be entitled to benefit under scheme in which shipment is subsequently converted.
<b>Relocation of Industries</b>	2.57	Deleted.
<b>Offsetting of Export Proceeds</b>	2.58	Subject to specific approval of RBI, any payables, or equity investment made by an Autorisation holder under any export promotion scheme, can be used to offset receipts of his export proceeds. In such cases, offsetting would be equal to realisation of export proceeds and exporter would have to submit following additional documents: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Appendix 22D in lieu of Bank Realisation Certificate.</li> <li>b) Specific permission of RBI.</li> </ul>
<b>Quality Certification</b>	2.59	It has been a constant endeavor to promote quality standards in export product / units manufacturing export product.
	2.59.1	One of salient features incorporated in FTP as per paragraph 3.5.2 Note.1 for promotion of quality standards is grant of Export / Trading House status on achievement of a lower threshold limit for units having ISO-9000 (series), ISO-14000 (Series) or HACCP certification or WHO GMP or SEI CMM level-2 & above status / certification.
	2.59.2	List of such agencies authorised to grant quality certification is given in Appendix 6.  Any agency desirous of enlistment in Appendix -6 may submit their application as per Annexure I to Appendix 6 to concerned RA.
	2.59.3	Deleted.
	2.60	Deleted.
<b>Procedure for import Under the Tariff Rate</b>	2.61	Attention is invited to Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. 21/2002-Customs

**Quota Scheme**

dated 01.03 2002. As per it, import of four items viz., (1) Skimmed and whole milk powder, milk food for babies etc. (0402.10 or 0402.21) (2) Maize (corn): other (1005.90) (3) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (1512.11) and (4) Refined rape, colza or mustard oil, other (1514.19 or 1514.99) is allowed in a financial year, up to quantities as well as such concessional rates of customs duty as indicated below:

S. No.	ITC Code No. & Item	Quantity of Quota	Concessional duty
1.	Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21 Skimmed and whole Milk Powder. Milk Food for babies etc.	10,000 MTs	15%
2.	Tariff Code No. 1005.90 Maize (Corn): other	5,00,000 MTs	15%
3.	Tariff Code No. 1512.11 Crude Sunflower seed or safflower oil or fractions thereof	150,000 MTs	50%
4.	Tariff Code No. 1514.19 & 1514.99 Rape, Colza or Mustard Oil, Other (Refined)	150,000 MTs	45%

**Eligible entities for allocation of quota:**

- 2.61.1 (a) Milk Powder (Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21): National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), National Cooperative Dairy Federation (NCDF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), Projects & Equipment Corporation of India Limited (PEC) and Spices Trading Corporation Limited (STCL)
- (b) Maize (corn)(Tariff Code No. 1005.90): National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED), State Trading Corporation (STC), Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), Projects & Equipment Corporation of India Limited(PEC), Spices Trading Corporation Limited (STCL) and State Cooperative Marketing Federations
- (c) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (Tariff Code No. 1512.11) and Refined rape, colza or mustard oil, other (Tariff Code No. 1514.19 or 1514.99): National Dairy Development Board (NDDB), State

Trading Corporation (STC), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED) Spices Trading Corporation Limited (STCL) and Central Warehousing Corporation (CWC) State Cooperative Marketing Federation & State Cooperative Civil Supplies Corporation

(d) Deleted.

All eligible entities are eligible to avail quotas as per request of applicants received.

All eligible entities desiring availment of quota as mentioned above, may make application to EFC in ANF to DGFT, Udyog Bhavan, New Delhi – 110 011. Completed application forms along with prescribed documents must reach on or before 1<sup>st</sup> March of each financial year preceding to the year of quota e.g. Applications for TRQ for 2007-2008 must reach DGFT by 01.03. 2007.

Imports have to be completed before 31<sup>st</sup> March of financial year i.e. consignments must be cleared by customs authorities before this date.

Since import of maize (corn) is through STEs, the allottees of quota i.e. designated agencies in para 1 (b) above for this item shall also be granted an import Authorisation for allotted quantities as indicated at Sl. No. 21(b) of Customs Notification No. 21/2002 dated 1.3.2002 in terms of para 2.11 of FTP, 2004-2009, if they do not wish to make imports through FCI.

Application fee for these applications shall be paid according to procedure contained in Appendix 21 B to HBP-v1.

EFC in DGFT will evaluate and allot quota among applicants by 31<sup>st</sup> March of each financial year preceding to year of quota e.g. for 2007-08, EFC will allot quota by 31<sup>st</sup> March 2007.

***Issuance of scrips  
against lost EP copy  
of the Shipping Bills  
and / or original Bank  
Realisation Certificate***

2.62

In case where EP copy of Shipping Bill / original BRC has been lost, claim under VKGUY/ FMS/ FPS can be considered subject to submission of following documents: -

- a) A duplicate /certified copy of concerned document issued by Customs Authority / Bank in lieu of original;
- b) An application fee equivalent to 2% of relevant entitlement. However, no fee shall be charged when such document is lost by Government agencies and a documentary proof to this effect is submitted;

- c) An affidavit by exporter about loss of document and an undertaking to surrender it immediately to concerned RA, if found subsequently.
- d) An indemnity bond by exporter to effect that he would indemnify Government for financial loss if any on account of duty credit issued against lost Shipping Bills / BRC.

Customs Authority, before allowing clearance, shall ensure that benefit / duty credit against such shipping bill has not been availed.

- 2.62.1 Claim against lost Shipping Bill / BRC shall be preferred within a period of six months from date of release of duplicate copy of Shipping Bill / on date of realization of export proceeds. Any application received thereafter shall be rejected.

- 2.63 Deleted

**Export Promotion  
Council (EPC), includes  
Commodity Boards (CB)**

- 2.64 A list and product category of EPCs, including CB is given in Appendix 2. Commodity Boards function as EPCs for products allotted to them. EPC is authority issuing RCMC.

**Non-Profit, Autonomous  
and Professional Bodies**

- 2.65 EPCs are non-profit organizations registered under Companies Act or Societies Registration Act.

- 2.65.1 EPCs shall be autonomous and shall regulate their own affairs. However, if Central Government frames uniform bylaws for constitution and / or for transaction of business for EPCs, they shall adopt the same with such modifications as Central Government may approve having regard to special nature or functioning of such EPC.

Concerned Administrative Ministry would interact with Managing Committee of EPC concerned at least twice a year.

- 2.65.2 Deleted

- 2.66 Deleted

**Registering Authorities  
issuing RCMC**

- 2.67 A status holder has option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters Organization (FIEO).

Exporters of minor forest produce and their value added products shall obtain RCMC from SHEFEXIL, EPC.

Software exporters shall register themselves with Electronic and Software EPC. Exporters of 13 specific services as listed in Sl. No. 34 of Appendix 2 of HBP v1, are required to register themselves with Services EPC. Other service exporters shall

register themselves with FIEO.

In respect of exporters having their head office / registered office in State of Orissa, RCMC may be obtained from FIEO office in Bhubaneswar irrespective of product being exported by them.

	2.67.1	In addition, an exporter has option to obtain RCMC from FIEO or any other relevant EPC if products exported by him relate to those EPC's.
	2.67.2	If export product is such that it is not covered by any EPC, RCMC in respect thereof may be issued by FIEO.
<b>Registration cum-Membership Certificate (RCMC)</b>	2.68	An exporter may, on application given in Appendix 19A, register and become a member of EPC. On being admitted to membership, applicant shall be granted forthwith Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) of EPC concerned, in format given in Appendix 19B. In case an exporter desires to get registration as a manufacturer exporter, he shall furnish evidence to that effect.
		Prospective / potential exporters may also, on application, register and become an associate member of an EPC .
<b>Validity Period of RCMC</b>	2.68.1	RCMC shall be deemed to be valid from 1 <sup>st</sup> April of licensing year in which it was issued and shall be valid for five years ending 31 <sup>st</sup> March of licensing year, unless otherwise specified.
<b>Intimation Regarding Change In Constitution</b>	2.69	In case of change in ownership, constitution, name or address of an exporter, it shall be obligatory on part of RCMC holder to intimate such change to registering authority within a period of one month from date of such change. Registering authority, however, may condone delays on merits.
<b>Furnishing Of Returns</b>	2.70	Exporter shall furnish quarterly returns / details of his exports of different commodities to concerned registering authority. However, status holders shall also send quarterly returns to FIEO in format specified by FIEO.
<b>De-Registration</b>	2.71	Registering authority may de-register an RCMC holder for a specified period for violation of conditions of registration. Before such de-registration, RCMC holder shall be given a show cause notice by registering authority, and an adequate and reasonable opportunity to make a representation against the proposed de-registration. Upon de-registration, concerned EPC shall intimate the same to all RAs.
<b>Appeal Against De-registration</b>	2.72	A person aggrieved by a decision of registering authority in respect of any matter connected with issue of RCMC may



prefer an appeal to DGFT or an officer designated in this behalf within 45 days against said decision and decision of appellate authority shall be final.

### **Directives of DGFT**

2.73

DGFT may direct any registering authority to register or de-register an exporter or otherwise issue such other directions to them consistent with and in order to implement provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made there under, FTP or this Handbook.

2.74

### **Electronic Data Interchange**

2.74.1

Role and functions of EDI are defined in Para 2.45 of FTP. Basic purpose of EDI Initiatives is to improve services for DGFT user community thereby achieving greater transparency of operations and reducing transaction costs by decreasing processing time for obtaining Authorisation from DGFT. These EDI initiatives have made our exports competitive in international markets.

### **Eligibility**

2.74.2

Facility of electronic filing of applications shall be available to all exporters.

### **Procedure**

2.74.3

An exporter would be able to file his application on DGFT website at <http://dgft.gov.in/>. Application will then be processed in accordance with prevalent rules and regulations.

Applicant will have to visit concerned office to hand-over hard copy of application along with requisite documents including application fee. Authorisation shall be issued on receipt of hard copies of documents as mentioned above after due scrutiny as prescribed in HBP v1.

### **Fiscal Incentives for EDI**

2.74.4

Following deductions in Application Fee would be admissible for applications signed digitally and / or where application fee is paid electronically through EFT (electronic fund transfer) :

Sr. No.	Mode of Application	Fee Deduction (as a % of normal application fee)
1	Digitally signed .	25%
2	Application fee payment vide EFT	25%
3	Both digitally signed as well as use of EFT for payment of application fee	50%

**Benefits**

- 2.74.5 Facility will reduce unnecessary physical interface with DGFT. It will enable faster processing, speedier communication of deficiencies, if any, and on-line availability of application processing status.
- 2.74.6 Authorisation issued using DGFT Electronic Application System shall be transmitted electronically to Customs through EDI Mode. This shall also obviate need for verification of Authorisations before allowing clearance.

**New EDI Initiatives**

- 2.74.7 To further improve quality of services some new EDI Initiatives are being taken by DGFT.

In order to simplify 'Aayaat Niryaat Form' (ANF), Scheme specific ANF has been introduced this year. This is downloadable from DGFT website.

## CHAPTER-3

### PROMOTIONAL MEASURES

#### *Status Certificates*

3.1 Policy for status holder is given in Chapter 3 of FTP.

#### *Application for Grant of Status Certificate*

3.2 Application for grant of status shall be filed by 31<sup>st</sup> March, in ANF 3A.

An existing status holder shall be automatically treated to be an equivalent status holder as given hereinunder:

Status as per FTP (2004-09) (RE 2006)	Converted Status as per FTP (2004-09) (RE 2007)
One Star Export House	Export House
Two Star Export House	Star Export House
Three Star Export House	Trading House
Four Star Export House	Star Trading House
Five Star Export House	Premier Trading House

3.2.1 Application shall be filed with jurisdictional RA / Development Commissioner (DC). However, in cases where export performance of EOUs / SEZs is clubbed together with company or firm / Group Company in DTA, the same will be considered by jurisdictional RA only.

3.2.2 All newly issued Status certificates shall be valid from 1<sup>st</sup> April of the year during which application for recognition was filed. For renewals, application filed before expiry of current validity, renewals shall have a validity commencing from 1<sup>st</sup> April of next licensing year, otherwise validity period shall be 1<sup>st</sup> April of year during which application was filed. However all Status Certificates shall lapse on 31.03.2009.

3.2.3 Deleted  
to 3.2.5

#### *Maintenance of Accounts*

3.3 Status holder shall maintain true and proper accounts of its exports and imports based on which such recognition has been granted. Record shall also be maintained during validity period and for a minimum period of three years thereafter. These accounts shall be made available for inspection to RA concerned or any authority nominated by DGFT.

**Refusal / Suspension /  
Cancellation of Certificate**

3.4 Status certificate may be refused or suspended or cancelled by RA concerned, if status holder or any agent or employee or authorized representative acting on his behalf:

- (a) Fails to discharge export obligation imposed;
- (b) Tampers with Authorisations;
- (c) Misrepresents or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any Authorisation;
- (d) Commits a breach of FT (D& R) Act, or Rules, Orders made there under and FTP; or
- (e) Fails to furnish information required by this Directorate.

3.4.1 A reasonable opportunity shall be given to status holder before taking any action under above paragraph.

**Appeal**

3.5 An applicant, who is not satisfied with decision taken to suspend or cancel status certificate, may file an appeal to DGFT within 45 days. Decision of DGFT shall be final thereon.

3.6 to  
3.12 Deleted

3.12.1 Deleted

3.12.1.1 Deleted

3.12.2 to Deleted  
3.12.4

3.13 to Deleted  
3.17

3.17.1 to Deleted  
3.17.7

3.18 **SERVED FROM INDIA SCHEME (SFIS)**

- (a) Policy for SFIS is given in Chapter 3 of FTP.
- (b) A single consolidated application for Duty Credit scrip shall be filed with jurisdictional RA in ANF 3B along with documents prescribed therein.
- (c) to Deleted
- (f)

- (g) Service provider shall within one month of completion of imports made or expiry of validity of Duty Credit scrip whichever is earlier, submit a statement of imports made under it to jurisdictional RA with a copy to jurisdictional Excise authorities (service tax cell) wherever applicable.

(h) & (i) Deleted

**Ineligible Remittances  
and Services**

- 3.18.1 Foreign exchange remittances other than those that are earned for rendering of services would not be counted for entitlement. Thus, other sources of foreign exchange earnings such as equity or debt participation, donations, receipts of repayment of loans etc. and any other inflow of foreign exchange, unrelated to rendering of service, would be ineligible.

For calculation of entitlement, following shall not be taken into account.

- (a) Foreign Exchange remittances:

I. ~~related~~ to Financial Services Sector

1. Raising of all types of foreign currency Loans;
2. Export proceeds realization of clients;
3. Issuance of Foreign Equity through ADRs / GDRs or other similar instruments;
4. Issuance of foreign currency Bonds;
5. Sale of securities and other financial instruments;
6. Other receivables not connected with services rendered by financial institutions; and

II. earned through contract / regular employment abroad (e.g. labour remittances);

- (b) Payments for services received from EEFC Account;
- (c) Foreign exchange turnover by Healthcare Institutions like equity participation, donations etc. (However, remittances received on account of medical treatment, surgery, testing, consultancy and health care provided by the institution shall be eligible);
- (d) Foreign exchange turnover by Educational Institutions like equity participation, donations etc. (However remittances

received on account of the course fees and consultancy provided by the institution shall be eligible);

- (e) Export turnover relating to services of units operating under SEZ / EOU / EHTP / STPI / BTP Schemes or supplies of services made to such units;
- (f) Clubbing of turnover of services rendered by SEZ / EOU / EHTP / STPI / BTP units with turnover of DTA Service Providers; and
- (g) Export of Goods.

3.18.2 Deleted.

### 3.19 **VISHESH KRISHI AND GRAM UDYOG YOJANA (VKGUY)**

3.19.1 Policy pertaining to VKGUY is given in Chapter 3 of FTP. Appendix 37A contains the list of VKGUY items.

Application for grant of Duty Credit scrip under VKGUY for export made from 1.4.2007 onwards shall be made to RA concerned in ANF 3C along with documents prescribed therein.

Applicant may file one or more applications subject to condition that each application shall contain not more than 50 shipping bills. All shipping bills in any one application must relate to exports made from one Customs House only, which shall be the port of registration for Duty Credit Scrip.

Application for obtaining Duty Credit scrip shall be filed within a period of twelve months from date of exports or within six months from date of realization or within three months from date of printing / release of shipping bill, whichever is later, in respect of shipments for which claim is being filed.

3.19.2 Deleted.

3.19.3 For direct as well as third party exports, the Export documents viz Export Order, Invoice, GR form, Bank Realization Certificate should be in the name of applicant only.

3.19.4 to Deleted.

3.19.9

**FOCUS MARKET SCHEME (FMS)**

3.20 Policy pertaining to FMS is given in Chapter 3 of FTP. Notified Markets are listed in Appendix 37C.

3.20.1 A single consolidated application for all exports through EDI enabled ports shall be filed with RA concerned in ANF 3D along with documents prescribed therein. Application shall be filed on a six monthly basis, i.e. April– September Period and October – March Period where realization has been made during period of application. In case of Advance Payment (and in cases where Para 3.23.3 of HBP v1 applies), date of exports shall be taken into account for inclusion in period of application.

Application for claiming Duty Credit scrip shall be submitted within a period of six months from last date of period of application (i.e. for April–September 2007 Period, last date shall be March 2008 and for October–March 2008 Period, last date shall be Sept. 2008).

As FMS has been launched for exports w.e.f 1.4.2006, applications for grant of benefits for exports w.e.f 1.4.2006 shall be considered as under:

- (a) In respect of application for April–September 2006 period, last date for filing application shall be 31<sup>st</sup> March 2008. This shall include only those shipments exported on or after 1.4.2006 but for which realization has been received till 30.09.2006.
- (b) In respect of application for October–March 2007 period, last date for filing application shall be 31<sup>st</sup> March 2008. This shall include all shipments exported on or after 1.4.2006, but for which realization has been received till 31.3.2007.

Exporters can file only one supplementary claim each, in case some shipments have not been included in original claim for April–September and October–March periods. This shall attract supplementary cut on claim amount, after ensuring that shipment has not been included in earlier claim. In case supplementary claim is filed late, late cut shall also be imposed. This shall apply even to exports made w.e.f 1.4.2006.

3.20.2 For direct as well as third party exports, the Export documents viz. Export Order, Invoice, GR form, Bank Realization Certificate should be in the name of applicant only.

3.20.3 Applicant shall be required to submit proof of landing of export consignment in specified market.

Duty Credit scrip shall be granted on FOB value realized as per BRC / FIRC.

3.20.4 to Deleted

3.20.8

### **FOCUS PRODUCT SCHEME (FPS)**

3.21 Policy pertaining to FPS is given in Chapter 3 of FTP. Notified Products are listed in Appendix 37D.

3.21.1 A single consolidated application for all exports through EDI enabled ports shall be filed with RA concerned in ANF 3E along with documents prescribed therein. Application shall be filed on a six monthly basis, i.e. April– September Period and October – March Period where realization has been made during period of application. In case of Advance Payment (and in cases where Para 3.23.3 of HBP v1 applies), date of exports shall be taken into account for inclusion in period of application.

Application for claiming Duty Credit scrip shall be submitted within a period of six months from last date of period of application (i.e. for April-September 2007 Period, last date shall be March 2008 and for October-March 2008 Period, last date shall be Sept. 2008).

As FPS has been launched for exports w.e.f 1.4.2006, applications for grant of benefits for exports w.e.f 1.4.2006 and for supplementary claims shall be the same as under FMS:

3.21.2 For direct as well as third party exports, the Export documents viz Export Order, Invoice, GR form, Bank Realization Certificate should be in the name of applicant only.

3.21.3 Duty Credit scrip shall be granted on FOB value realized as per BRC / FIRC.

3.21.4 to Deleted

3.21.8

### **3.22 HIGH-TECH PRODUCTS EXPORT PROMOTION SCHEME (HTPEPS)**

3.22.1 Policy pertaining to HTPEPS is given in Chapter 3 of FTP. Notified High Tech Products are listed in Appendix 37E.

3.22.2 Application for grant of Duty Credit scrip under HTPEPS shall be made to RA concerned in ANF 3F along with documents prescribed therein.



Application for obtaining Duty Credit scrip for incremental growth in exports during current licensing year 2007-08 shall be filed within a period of twelve months after expiry of current licensing year.

### 3.23 COMMON PROCEDURAL FEATURES FOR PROMOTIONAL SCHEMES, APPLICABLE TO ALL SCHEMES IN THIS CHAPTER, UNLESS SPECIFICALLY PROVIDED FOR:

#### *Jurisdictional RA / RA Concerned*

3.23.1 Applicant shall have option to choose Jurisdictional RA on the basis of Corporate Office, Registered Office, Branch Office address endorsed on IEC. However, once opted, no change would be allowed.

3.23.2 Provisions contained in Chapter 2, 9 of HBP v1 shall apply to all Promotional Schemes.

#### *Port of Registration*

3.23.3 Duty Credit scrip (including splits) shall be issued with a single port of registration as per choice of applicant. Before registration, authorities shall verify genuineness of Duty Credit scrip, from RA concerned, until EDI system of message exchange is put in place.

However, applicant may use Duty Credit scrip for imports from any other port (that includes ICD / LCS) after obtaining TRA from authorities at port of registration.

#### *Facility for Split Scrips*

3.23.4 Split certificates of Duty Credit scrip subject to a minimum of Rs 5 lakh each and multiples thereof may also be issued, on request at the time of application with different port of registration. A fee of Rs 1000/- each shall be paid for each split certificate.

After issue, request of splits shall be permitted with same port of registration as appearing on the original scrip.

#### *Import from private / public bonded warehouses*

3.23.5 Entitlement can be used for import from private / public bonded warehouses subject to fulfillment of paragraph 2.28 of FTP and terms and conditions of DoR notification.

#### *Re-export of defective / unfit goods*

3.23.6 Goods imported and are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per DoR guidelines. Where Duty Credit scrip has been used for imports, Customs shall issue a certificate containing particulars of scrip used, date of import of re-exported goods and amount debited while importing such goods. Based on this certificate, upon application, a fresh Scrip shall be issued by concerned RA to the extent of 98% of debited amount, with

same port of registration and valid for a period equivalent to balance period available on date of import of the defective / unfit goods.

***Validity Period &  
Revalidation***

3.23.7

Duty Credit scrip shall be valid for a period of 24 months.  
Revalidation of Duty Credit scrip shall not be allowed.

**CHAPTER-4****DUTY EXEMPTION / REMISSION SCHEME**

- Policy** 4.1 Policy relating to Duty Exemption / Remission Scheme is prescribed in Chapter 4 of FTP.
- General Provision** 4.2 An application for grant of an Advance Authorisation / Advance Authorisation for Annual Requirement / DEPB / DFIA may be made by Registered office or Head office or a branch office or manufacturing unit of eligible exporter, to RA concerned.
- 4.3 Where applicant is branch office or manufacturing unit(s) of an exporter, it shall furnish self certified copy of valid RCMC where name of branch office or manufacturing unit is given.
- Advance Authorisation** 4.4 Where SION have been published, an application in ANF 4A, along with documents prescribed therein, shall be submitted to RA concerned.
- 4.4.1 In case of export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof, quantity, wastage and value addition norms shall be as prescribed in paragraph 4A of FTP and HBP v1.
- 4.4.2 In case where norms have not been published, an application in ANF 4B, along with prescribed documents, shall be furnished to concerned Norms Committee (NC) at DGFT Headquarter for fixation of Norms.
- In such cases, original copy of application along with prescribed fee shall be filed with RA concerned and a self attested copy of same shall be filed with NC. Authorisation in such cases shall be issued by RA as NC recommends.
- NC shall also function as a recommendatory authority for SION. DGFT may notify such norms.
- 4.4.3 Applications, where Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudoephedrine is required as an input for import, shall be filed with RA concerned.
- Copies of such applications shall also be simultaneously endorsed to the Drug Controller of India, Nirman Bhawan, New Delhi, Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics, Gwalior and respective Zonal Director of Narcotics Control Bureau, alongwith a declaration that applicant will maintain prescribed records and also submit prescribed returns.

4.4.4 RA, while issuing Advance Authorisation for import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo-ephedrine, shall endorse a condition that before effecting imports, NOC shall be obtained from Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Gwalior and shall also endorse a copy of Authorisation to Drug Controller, Nirman Bhawan, New Delhi and concerned Zonal Director of Narcotics Control Bureau.

4.4.5 Deleted

***Advance Authorisation  
for applicants with  
multiple units***

4.5 Transfer of any duty free material imported or procured against Advance Authorisation from one unit of company to another for manufacturing purpose shall be done with prior intimation to jurisdictional Excise Authorities with a clear understanding that no benefit of CENVAT shall be claimed on such transferred inputs. In case of non-excisable company / products, units should maintain a proper record. However to avail facility, all such units should be available in IEC certificate and follow rules and regulation of Central Excise for job work. Large Taxpayer Units (LTUs) having multiple units, may not follow above job work procedure, after fulfillment of EO.

***Advance Authorisation  
for Free of Cost and  
Paid Material***

4.6 For policy in paragraph 4.1.8, a specific endorsement shall be made on exchange control copy of Advance Authorisation disallowing remittances for material being supplied free of cost. All inputs imported shall be utilised in manufacturing of product except wastage.

***Self Declared  
Authorisations where  
SION does not exist***

4.7 RA may also issue Advance Authorisations, where SIONs are not fixed, based on self declaration and an undertaking by applicant for a final adjustment as per Adhoc / SION fixed by NC.

However, no Advance Authorisation shall be issued under this paragraph for import of following products:-

- i. All vegetable / edible oils classified under Chapter - 15 and all types of oilseeds classified under Chapter - 12 of ITC (HS) book;
- ii. All types of cereals classified under Chapter - 10 of ITC (HS) book;
- iii. All spices other than light black pepper (light berries) having a duty of more than 30%, classified under Chapter- 9 and 12 of ITC (HS) book;
- iv. All types of fruits/vegetables having a duty of more than 30%, classified under Chapter 7 and 8 of ITC (HS) book; and

## v. Horn, hoof and any other organ of animal.

For export of perfumes, perfumery compounds and various feed ingredients containing vitamins, no Authorisation shall be issued by RA and applicants may apply under Para 4.4.2 above. Where export and / or import of biotechnology items are involved, Authorisation under this paragraph shall be issued by RA only on submission of a "No Objection Certificate" from Department of Biotechnology.

**Entitlement**

- 4.7.1 CIF value of one or more such authorisations shall be maximum 500% of FOB and / or FOR value of preceding year exports and / or supplies in case of status holders and Rs. 5 crore or 500% of the FOB and / or FOR value of preceding year exports and / or supply, whichever is more, for others.

However, in cases where NC has already ratified norms for same export and import products in respect of an Authorisation obtained under paragraph 4.7, such norms shall be valid for a period of six months reckoned from date of ratification.

In such cases Authorisations shall be issued by RA concerned under "Adhoc Norms Fixed" category and application copies need not be forwarded to NC for fixation / ratification of norms.

Authorisation holder in such cases shall be entitled for further authorisation(s) as per norms ratified by NC without need for subsequent ratification by NC. In such cases applicant would file application under "Adhoc Norms Fixed" category. However, NC should ensure that such adhoc norm(s), if not notified already, are notified within a period of one month after six months of ratification of such adhoc norm(s).

- 4.7.2 Once norms are fixed by NC, value limits mentioned in above paragraph would not be applicable to advance authorisations issued under this paragraph. Such authorisations, subsequent to fixation of norms by NC, may be enhanced.

It is mandatory for industry to provide production data etc. as may be required by DGFT / EPC for fixation of SION. Otherwise, applicant shall not be allowed to take benefit of Advance Authorization scheme for taking repeat advance authorizations on self-declared basis.

**Authorisation in Excess of Entitlement**

- 4.7.3 An applicant shall be entitled for authorisation in excess of entitlement mentioned in paragraph 4.7.1 subject to furnishing of 100% Bank Guarantee to Customs authority to cover exemption from customs duties. A specific endorsement to this effect shall be made on authorisation.

**Application** 4.7.4 Original application with prescribed documents shall be submitted to concerned RA. RA shall forward a copy of application within 7 days from Authorisation issue date to NC for fixation of norms within prescribed time.

**Undertaking** 4.7.5 Applicant shall give an undertaking that he shall abide by norms fixed by NC and accordingly pay duty, together with interest, on unutilised inputs as per norms fixed by NC. However Authorisation holder has option to undertake additional EO in proportion to excess unutilized inputs. In case application is rejected by NC, authorization holder shall pay customs duty saved along with interest on imported inputs, as notified.

In addition, an amount as per Para 4.28(i)(b) below has to be deposited.

4.7.6 In such cases, where norms are not finalised by NC within four months from Authorisation issue date, norms as applied for shall be treated as final and no adjustment will be made. However, where application for fixation of adhoc / SION is rejected on account of non-furnishing of required documents / information, Authorisation holder shall be liable for penalty as stated in above paragraph. In case SION for the said product is notified, SION would be made applicable for deciding wastage norm and EO.

In such cases, where export obligation is completed pending fixation of norms by NC, entitlement for authorisation as given in paragraph 4.7.1 may be re-credited upon production of documentary evidence (copies of Shipping bill / bill of export / Central Excise certified copies of invoices) showing fulfillment of export obligation in respect of previous authorisations. However, bond waiver / redemption shall not be allowed pending fixation of norms in such cases.

**Financial Powers** 4.8 Financial powers of RA and NC are given in table below:

Category of Application	On published norms and under paragraph 4.7 of <i>HBP v I</i>			
	RA		RA on recommendation of DGFT Hqr (SION cases) / NC (adhoc Norms cases).	
	Petroleum / Petrochemical products & Advance Authorisation for Annual Requirements	Others	Petroleum / Petrochemical products & Advance Authorisation for Annual Requirements	Others
CIF value of Authorisation	Upto Rs. 500 crore	Upto Rs. 100 crore	Rs. 500 crore or above	Rs. 100 crore or above

**Standardisation of  
Adhoc Norms**

4.9

For standardization of norms, an application may be made by manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer, duly filled in with complete data. Such applications shall be made to NC in ANF 4B.

Import of fuel may also be allowed under SION by NC subject to following :-

- (a) Facility of import of fuel shall be allowed only to manufacturer having captive power plant.
- (b) In cases where SION specifically allows fuel, same shall be permitted under advance Authorisation. However, If fuel is not covered specifically under SION, it may be allowed as per general fuel Policy for products covered under SION or under paragraph 4.7 above.
- (c) Fuel should be allowed only against an actual user Authorisation. However in case of DFIA, fuel can only be transferred to agencies granted marketing rights by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
- (d) Deleted
- (e) Applications of fixation for fuel entitlement for new sectors and modification of the existing entitlement as per General Note for Fuel in HBP v2 would be made to NC along with requisite data in ANF 4C pertaining to "Data Sheet for Fuel Rate".

**Modification of SION**

4.10

An application for modification of existing SION may be filed before the NC by manufacturer exporter or merchant-exporter, tied to supporting manufacturer, in form given in ANF 4B.

**Amendment of Export  
item and inputs**

4.10.1

An application for amendment of an export item or inputs under SION or under Adhoc Norms may be filed by any manufacturer or merchant exporter as per ANF 4B.

Applicant would give justification for seeking amendment and same would be considered by Regional Office with specific approval of Head of Office. In case of any major change in input or request for more wastage to that allowed under SION or adhoc norm, same should be referred to NC for ratification.

**Revision of SION by NC**

4.10.2

NC may identify SIONs which in its opinion are required to be reviewed. Exporters are required to submit revised data in ANF 4B for such revision. It is mandatory for industry / exporter(s) to provide production and consumption data etc. as may be required by DGFT / EPC for revision of SION.

Otherwise, applicant shall not be allowed to take benefit of Advance Authorization scheme.

**Description of an  
Advance Authorisation**

4.11 An Advance Authorisation shall specify:

- (a) names and description of items to be imported and exported / supplied;
- (b) quantity of each item to be imported or wherever quantity cannot be indicated, value of item shall be indicated. However, if in SION, quantity and value of individual inputs is a limiting factor, same shall be applicable.
- (c) aggregate CIF value of imports; and
- (d) FOB / FOR value and quantity of exports / supplies.

**Exports in Anticipation  
of Authorisation**

4.12 Exports / supplies made from date of EDI generated file number for an Advance Authorisation, may be accepted towards discharge of EO. Shipping / Supply document(s) should be endorsed with File Number or Authorisation Number to establish co-relation of exports / supplies with Authorisation issued. If application is approved, authorisation shall be issued based on input / output norms in force on the date of receipt of application by RA in proportion to provisional exports / supplies already made till any amendment in norms is notified. For remaining exports, Policy / Procedures in force on authorisation issue date shall be applicable.

4.12.1 Exports / supplies made in anticipation of grant of an Advance Authorisation shall be entirely on risk and responsibility of exporter.

4.12.2 Conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills may also be permitted by customs authorities in case application for an Advance Authorisation is rejected or modified by RA.

**Advance Authorisation  
or DFIA for Intermediate  
Supplies**

4.13 Application for grant of Advance Authorisation or DFIA for Intermediate supply may be made on the basis of a tie-up agreement with exporter (physical / deemed) holding an Advance Authorisation or DFIA. RA concerned shall consider such requests.

Advance Authorisation or DFIA for Intermediate supply shall be issued after making Authorisation invalid for direct import of items to be supplied by intermediate manufacturer. In such cases, a copy of the invalidation letter will be given to Authorisation holder and copy thereof will be sent to intermediate supplier as



well as RA of intermediate supplier. Authorisation holder in such case has an option either to supply intermediate product to holder of Advance Authorisation DFIA or to export (physical / deemed) directly. However, once Electronic message transfer facility among the RAs becomes fully operational, sending copy of invalidation letter / ARO to jurisdictional RA shall not be required.

Facility of Advance Authorisation shall be available even in cases where intermediate supplier has supplied or intend to supply material subsequent to fulfilment of EO by exporter holding Advance Authorisation / DFIA from where invalidation letter was issued.

***Advance Release Order***

4.14 An application may be made to RA concerned for grant of ARO to procure inputs from indigenous sources / STEs.

4.14.1 Application shall specify:

- (i) name, description and quantity of items; and
- (ii) individual value of items to be procured. An ARO may be issued along with Advance Authorisation / DFIA or subsequently, and its validity shall be co-terminus with validity of Advance Authorisation / DFIA.

An ARO issued for procurement of an individual item shall be automatically valid for procurement from one or more indigenous sources.

***Back to Back Inland Letter of Credit (L/C)***

4.15 Exporter may alternatively avail facility of a back to back inland letter of credit from banks. An Advance Authorisation / DFIA holder may approach a bank for opening an inland letter of credit (L/C) in favour of an indigenous supplier.

4.15.1 Before opening the L/C, bank will ensure that necessary BG / LUT has been executed by Advance Authorisation / Non Transferable DFIA holder and an endorsement to that effect has been made on the Authorisation.

However, execution of BG / LUT shall not be required against transferable DFIA. After opening inland L/C, bank shall make following endorsement on Exchange Control and Customs copy of Advance Authorisation/ DFIA;

Value of this Advance Authorisation / DFIA stands reduced by a sum of Rs. \_\_\_\_\_, being value of inland L/C No. \_\_\_\_\_ opened today by authorisation holder in favour of M/s \_\_\_\_\_ (name and address of indigenous supplier).

- 4.15.2 Authorisation shall be invalidated by bank for direct import only in respect of full quantity and value of item being sourced indigenously.
- 4.15.3 Original Letter of credit (L/C) may be retained by bank for negotiation and only non-negotiable copy of L/C may be given to indigenous supplier.
- 4.15.4 Responsibility of bank shall be confined to making endorsement. Bank shall not be liable for any misrepresentation or false statement made by authorisation holder while requesting bank to make endorsement. Inland L/C opened by bank in favour of indigenous supplier shall not be cancelled for any reason whatsoever.
- 4.15.5 Non negotiable copy of inland L/C together with photocopy of Advance Authorisation / DFIA duly carrying endorsements made by bank shall be sufficient for indigenous supplier to claim deemed export benefits. L/C issued shall be entitled to benefits given in paragraph 8.3 (b) and (c) of FTP.
- 4.15.6 Where import is permitted as an input under this scheme, gold / silver can be sourced through nominated agencies as given in FTP (Chapter 4) for supply against the Advance Authorisations/ DFIA issued. Before supply of material, nominated agencies should follow same procedure as given in paragraph 4.15.1 above.

**Facility of Supporting  
Manufacturers /  
Jobber / co-licensee**

- 4.16 Imported material may be used in any unit of holder of Advance Authorisation or Non Transferable DFIA or jobber / supporting manufacturer provided same is endorsed on authorisation by RA. If applicant desires to have name of any manufacturer or jobber added to authorisation, he may apply. Such endorsement shall be mandatory where prior import before export is a condition for availing Advance Authorisation / DFIA scheme and authorisation holder desires to have material processed through any other manufacturer or jobber.

Upon such endorsement made by RA, authorisation holder and co- authorisation holder shall jointly and severally be liable for completion of EO. Any one of co-authorisation holders may import goods in his name or in joint names. BG/LUT shall also be furnished in their joint names.

However if authorisation holder is registered with Central Excise, he has an option of getting names of jobber endorsed by Central Excise as per Central Excise Rules in lieu of RA's endorsement. In case manufacturer exporter holding authorisation is not registered / not required to be registered with Central Excise

authority, job work may be allowed as per Central Excise Rules and regulations without insisting for endorsement of supporting manufacturer's name. However, authorisation holder shall be solely responsible for imported items and fulfillment of EO.

In case BG / LUT has been redeemed, advance authorization holder can get duty free inputs processed from any manufacturer under Actual User condition as per job work regulations prescribed under Central Excise Rules. However such restriction shall not be applicable in case of transferable DFIA holder.

**Facility Of Co-Licensee** 4.17

Deleted.

**Acceptance of BG / LUT** 4.18

At the time of issue of authorisation, acceptance of undertaking given by applicant to RA concerned in relevant ANF will be endorsed on the reverse of Advance Authorisation. Authorisation holder shall execute Bank Guarantee / Legal Undertaking, as the case may be, in terms of para 2.20 of HBP v1.

**Port of Registration** 4.19

Advance Authorisation shall be issued for purpose of import and export through one of sea ports or airports or ICDs or LCS specified below. Authorisation holder shall register authorisation at the port specified in authorisation and thereafter all imports against said authorisation shall be made only through that port, unless the authorisation holder obtains permission from customs authority concerned to import through any other specified port. However, exports may be made through any of the specified ports.

**Sea Ports :** Mumbai, Kolkata, Cochin, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagao, Chennai, Nhavasheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Vishakhapatnam, Dahej, Nagapattinam, Okha, Mundhra, Surat (Magdalla), Jamnagar, Nhava Sheva, Bedi (including Rozi-Jamnagar), Muldwarka, Porbander, Dharamtar and Vadinar.

**Air-ports :** Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Air Cargo Complex, Cochin, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur, Chennai, Raja Sansi (Amritsar) and Lucknow (Amausi).

**ICDs :** Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati (Amingaon), Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad, (Wanjarwadi and

Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthi, Salem Mallanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry, Garhi Harsaru Bhatinda, Dappar, Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj, Rewari, Bhusawal, Jamshedpur, Surajpur and Dadri, Tuticorin, Bhadoi, Raipur, Mandideep (Distt. Raisen), Durgapur (Export Promotion Industrial Park) and Babarpur.

LCS : Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Mahadipur, Hilly, Chengrabanda, Dawki, Atari, Nepalganj Road, Agartala, Sutrakhandi, Amritsar Rail Cargo and Atari Road.

SEZ : As notified by Central Government any SEZ can be a specified port for import and export.

4.19.1 Commissioner of Customs may permit imports and exports from any other seaport / airport / ICD or LCS .

4.19.2 In such cases, where authorisation has not been registered at specified port (in Authorisation) and no import has taken place, request for change in Port of Registration may be considered by RA provided the Authorisation has not been redeemed.

4.19.3 For imports from Airport / Seaport / ICD / LCS other than port of registration, a TRA shall also be issued by the customs authority at the port of registration to customs authority at port of import.

#### ***Facility of Clubbing***

4.20 Facility of clubbing shall be available only for redemption / regularisation of cases and no further import or export shall be allowed. For this facility, authorisations are required to have been issued under similar Customs notification even pertaining to different financial years. However in case of Authorisations issued in 2004-09 period, Advance Authorisations with different customs notification can be clubbed.

4.20.1 RA, under whose jurisdiction authorisation is issued or NC in other cases, shall consider a request in ANF 4D for clubbing all imports and exports of more than one Advance Authorisation provided imported inputs are properly accounted for as per norms. Value addition of the authorisations so clubbed shall be average of minimum value addition prescribed in FTP and Procedure laid thereunder, imposed on individual authorisations. Upon clubbing, authorisations shall, for all purposes, be deemed to be one Authorisation and thereafter shortfall, if any, shall be regularized in terms of para 4.28 of HBP v1.

- 4.20.2 Accountability of imports and exports shall be restricted in relation to individual categories of Advance Authorisations including Advance Authorisation for annual requirements.
- 4.20.3 Facility is available only for Advance Authorisation(s) where there is shortfall in fulfillment of EO, and which is sought to be clubbed with an advance Authorisation(s) which is valid for imports. For expired Authorisation(s) with EO shortfall and which is sought to be clubbed with an advance Authorisation(s) which is valid for imports, applicant shall pay composition fee for EO period extension as per paragraph 4.22 below.
- 4.20.4 Wherever exports are effected beyond EO extension period (allowed vide paragraph 4.22 below) of earlier authorisation, no clubbing shall be permitted.
- 4.20.5 Notwithstanding provisions of para 4.20.3 and 4.20.4 above, Clubbing of all expired Authorisations may also be permitted provided all expired Authorisations have been issued during Exim Policy period 1992-1997 & 1997-2002 i.e., 1<sup>st</sup> April 1992 to 31<sup>st</sup> March, 2002. However clubbing of erstwhile Value Based Advance licences shall not be allowed.

***Enhancement / Reduction  
in the Value of  
Authorisation*** 4.21

In respect of an Advance Authorisation, RA concerned (as per their financial powers) may consider a request for:

- (a) enhancement / reduction in CIF value of advance authorisation;
- (b) enhancement / reduction in CIF value, quantity of inputs, FOB value and quantity of exports of an advance authorisation;

provided VA after such enhancement does not fall below minimum VA stipulated in FTP and HBP v1 laid thereunder and there is no change in input-output norms and FTP under which advance authorisation was issued.

- 4.21.1 Deleted.
- 4.21.2 Request for prorata enhancement in value and quantity may be made either before or after exports. In such cases where there is a change in SION prior to export of said product, pro-rata enhancement shall be given after calculating entitlement on revised SION.
- 4.21.3 The application for the enhancement / reduction in the value of Authorisation shall be made in ANF 4E.

***Application fee for enhancement***

- 4.21.4 Application fee leviable for enhancement would be on the difference in CIF values of original and final Authorisation. However, no application fee would be charged if value of Authorisation is being reduced or applicant has paid maximum fee of Rs 150,000 (for manual applications) and Rs 75,000 (for digitally signed applications) respectively in original application for Advance Authorisation.

***Export Obligation (EO) Period and its Extension***

- 4.22 Fulfillment Period of EO under an Advance Authorisation shall commence from Authorisation issue date. EO shall be fulfilled within 24 months except in case of supplies to projects / turnkey projects in India / abroad under deemed exports category where EO must be fulfilled during contracted duration. In case of Spices {(covered by chapter 9 of ITC (HS))}, EO shall be fulfilled within 90 days from the date on which first import consignment is cleared by Customs Authorities.

However, in case of import of spices for VA purpose like crushing / grounding / sterilisation or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading, re-packing etc., EO shall be fulfilled within 120 days.

EO Period for import of drugs (with a specific export order and pre-import condition) and for import of tea shall be 6 months.

- 4.22.1 Request for extension in EOP may be made in ANF 4E. RA shall grant one extension for six months from expiry date with payment of composition fee of 2% of duty saved on all unutilized imported items as per Authorisation.

Request for a further extension of six months may be considered by RA with payment of composition fee of 5% of duty based on all unutilized imported items as per Authorisation.

Facility of extension of EOP shall not be allowed in case of advance authorisation wherein import of penicillin and its salts (ITC (HS) Code No. 29411010) and 6 – APA (ITC (HS) Code No. 29411 050) have been allowed as an input and also for import of spices and tea. RA shall make an endorsement in advance authorisation to this effect.

Such extensions would not be permitted in erstwhile Value Based Advance Authorisations (VABALs). Additionally, no extension in EO would be allowed in respect of Authorisations where misrepresentation / fraud has come to notice of RA. Further, in respect of Authorisations where adjudication orders have already been passed, no extension in EOP shall be admissible.

- 4.22.2 Customs may allow provisional clearance of export consignment as and when Authorisation holder produces documentary evidence of having applied for EO extension to concerned RA.
- Revalidation of Authorisation** 4.23 RA may consider a request of original Authorisation holder and grant one revalidation for six months from expiry date. Request(s) for revalidation of Authorisation shall be made in ANF 4I.
- Monitoring of Obligation** 4.24 RA, with whom undertaking is executed by Advance Authorisation holder, shall maintain a proper record in a master register indicating starting and closing dates of obligation period and other particulars to monitor EO.
- Within two months from date of expiry of period of obligation, Authorisation holder shall submit requisite evidence in discharge of export obligation in accordance with paragraph 4.25 below.
- However, in respect of shipments where six months period (one year in case of status certificate holder) for realisation of foreign exchange has not become due, RA shall not take action for non submission of bank certificate of exports and realisation provided other document substantiating fulfillment of EO have been furnished.
- 4.24.1 In case Authorisation holder fails to complete EO or fails to submit relevant information / documents, RA shall take action by refusing further Authorisations, enforce condition of Authorisation and Undertaking and also initiate penal action as per law.
- Advance Authorisation for Annual Requirement** 4.24A (a) Exporters eligible for such Authorisations shall file an application in ANF 4A to RA concerned. All provisions as to Advance Authorisation given above would apply except the following:
- (i) RA while issuing Authorisation shall mention technical characteristics quality and specifications in respect of such inputs:-  
Alloy steel including stainless steel, copper alloy, synthetic rubber, bearings, solvents, perfumes/ essential oils / aromatics chemicals, surfactants, relevant fabrics and marble.
  - (ii) Authorisation holder shall have flexibility to export any product falling under export product group using duty exempted material.

(iii) Within eligible entitlement, an exporter may apply for one or more than one authorisations in a licensing year, subject to condition that against one port of registration only one authorisation can be issued for same product group. One time enhancement / reduction of the authorisation shall be available in terms of paragraph 4.21 above.

(iv) On completion of EO against one or more authorisations, all issued in same licensing year, entitlement of an exporter for that licensing year shall be deemed to be revived by an amount equivalent to EO completed against authorisation(s).

(b) to (g) Deleted:

4.24B Deleted.

***Fulfillment Of Export Obligation***

4.25 Authorisation holder shall furnish prescribed documents in ANF 4F in support of fulfillment of EO.

A (i) to Deleted.  
(iv)

B (i) to Deleted.  
(iv)

***Redemption / No Bond Certificate***

4.26 In case EO has been fulfilled, RA shall redeem the case. After redemption, RA shall forward a copy of redemption letter indicating shipping bill number(s), date(s), FOB value in Indian rupees as per shipping bill(s) and description of export product in respect of shipment which were taken into account for the purpose of fulfillment of EO to Customs authority at port of registration. Such details shall also be placed by the Zonal Offices in their website immediately after issuance of export obligation discharge/redemption letter / No Bond Certificate (in case of "No BG / LUT" facility) and by DGFT Hqr in DGFT website on monthly basis for customs authority to access it from website.

Cancellation / redemption of BG / LUT would be undertaken by Customs within 30 days of issue of Export Obligation Discharge Certificate (EODC) / bond waiver by RA.

Ordinarily, redemption of BG / LUT shall not preclude customs authority from conducting random checks and from taking action against Authorisation holder for any misrepresentation, mis-declaration and default detected subsequently.

Further RA shall also take action against authorisation holder in case of non-submission of Appendix 23, duly filled in, as



stipulated in Paragraph 4.30 below or for any misrepresentation, misdeclaration and default detected subsequently in details declared and furnished in Appendix 23. An endorsement to this effect shall be made by RA in the redemption certificate.

***Transitional Arrangement  
for Authorisations issued  
upto 31.8.2004***

4.27

Advance Licences including Advance Licences for Annual Requirement issued upto 31.8.2004 shall be governed by provisions contained in Chapter-7 of HBP v1 (RE-2001) and Chapter 4 of HBP v1 (2002-2007) as Notified on 31.3.2002 respectively as amended from time to time, excepting provisions relating to clubbing and extension in E.O. period which shall be governed by provisions of paragraphs 4.20 and 4.22.1 respectively above and any other provision, as notified by DGFT.

However, wherever Customs duty is to be paid on unutilised material, same shall be paid alongwith interest thereon as notified.

***Regularisation of  
Bonafide Default.***

4.28

Cases of bonafide default in fulfillment of EO may be regularised by RA as under:

- (i) If EO is fulfilled in terms of value, but there is a shortfall in terms of quantity, the Authorisation holder shall, for regularisation, pay:-
  - a) to customs authority, customs duty on unutilised value of imported material alongwith interest as notified; and
  - b) an amount equivalent to 3% of the CIF value of unutilised imported material through a TR in authorised branch of Central Bank of India indicating the "Head Account: 1453, Foreign Trade and Export Promotion and Minor Head 102". Authorisation holder shall also be required to obtain a separate authorisation for regularisation of excess imported input. However, provisions of this sub paragraph shall not be applicable if unutilised imported material was freely importable on date of import.
- (ii) If the EO is fulfilled in quantity but there is shortfall in value, no penalty shall be imposed if Authorisation holder has achieved minimum value addition prescribed. However, if value addition falls below the minimum value addition prescribed Authorisation holder shall be required to deposit an amount equal to 1% of shortfall in FOB value in Indian Rupee through TR in authorised branch of Central Bank of India as above or through EFT mode.

Value wise shortfall shall be calculated with reference to actual quantity of exports and FOB value of realisation with reference to prorata quantity of imports and CIF value. For example, if export performance is only 50% quantitywise but import has been for complete CIF value permitted, then value addition would be calculated on a prorata basis, i.e with reference to 50% of CIF value of imports. This would accordingly imply that where Authorisation holder is unable to export, no penalty on valuwewise shortfall shall be imposed.

- (iii) If EO is not fulfilled both in terms of quantity and value, the Authorisation holder shall, for the regularisation, pay as per (i) and (ii) above.
- (iv) In case an exporter is unable to complete EO undertaken in full and he has not made any import under Authorisation, Authorisation holder will also have an option to get the Authorisation canceled and apply for drawback after obtaining permission from Customs authorities for conversion of shipping bills to Drawback Shipping Bills.
- (v) RA shall compare relevant portion of Appendix 23 duly verified and certified by Chartered Accountant with that of norms allowed in Authorisation(s) and actual quantity imported against Authorisation(s) in the beginning of licensing year for all such Authorisations redeemed in preceding licensing year. In this verification process, in case it is found that Authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than imported, authorisation holder shall be liable to pay customs duty on unutilized value of imported material alongwith interest thereon as notified or effect additional export within the EO period.

***Time Period For  
Depositing Fines,  
Customs Duty, etc.***

4.29

Customs duty with interest to be recovered from Authorisation holder on account of regularisation or enforcement of BG / LUT, shall be deposited by Authorisation holder in relevant Head of Account of Customs Revenue i.e., "Major Head 0037 - Customs and minor head 001- Import Duties" in prescribed T.R. Challan within 30 days of demand raised by regional / customs authority and documentary evidence shall be produced to this effect to RA / customs authority immediately.

On receipt of such documentary evidence from Authorisation holder, RA shall intimate details of recovery / deposits made to Customs Authority at port of registration under intimation to Joint Secretary (Drawback), Department of Revenue, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, New Delhi.

Payment of amount of duty, interest and any dues for regularisation shall, however, be without prejudice to any other action that may be taken by Customs Authorities at any stage under Customs Act, 1962.

**Maintenance of  
Proper Accounts.**

4.30

Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 23. These records are required to be sent to the concerned RA at the beginning of each licensing year for all those authorisations, which have been redeemed in previous licencing year. However, these records in said format are required to be submitted for authorisations issued on or after 13-05-2005. Such records should be preserved for a period of at least three years from date of redemption.

**Duty Free  
Replenishment  
Certificate(DFRC)**

4.31

Deleted.

4.31A

Deleted.

4.32 to

Deleted.

4.34

4.34.1 to Deleted.

4.34.3

4.35

Deleted

4.35.1

Deleted

4.36

Deleted

4.36A

Deleted.

**DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK (DEPB) SCHEME**

**Duty Entitlement  
Passbook (DEPB)  
Scheme**

4.37

Policy relating to Duty Entitlement Passbook (DEPB) Scheme is given in Chapter-4 of FTP. Duty credit under the scheme shall be calculated by taking into account deemed import content of said export product as per SION. Value addition achieved by export of such product shall also be taken into account while determining the rate of duty credit under the scheme.

**Fixation of DEPB Rate**

4.38

ANF 4C prescribes form regarding fixation of DEPB rates. All applications for fixation of DEPB rates shall be routed through concerned EPCs which shall verify the FOB value of exports as well as international price of inputs covered under SION.

**Provisional DEPB Rate**

4.38A

To encourage diversification and to promote export of new products, DEPB Committee would be empowered to notify provisional DEPB rates. However, such DEPB rates would be

		valid for a limited period of time during which exporter would furnish data on export and import for regular fixation of rates.
<b>Exports in anticipation of DEPB Rate</b>	4.39	No exports shall be allowed under DEPB scheme unless DEPB rate of concerned export product is notified.
<b>Port of Registration</b>	4.40	Exports / imports made from specified Sea Ports, Airports, ICD & LCSs given in paragraph 4.19 above and made to any Special Economic Zone (SEZ), notified by Central Government, are entitled to DEPB.
	4.40.1	DEPB shall be issued with single port of registration, which will be port from where exports have been effected.
<b>Maintenance of Record</b>	4.40.2	Each Custom House at ports shall maintain a separate record of details of exports made under DEPB.
<b>Credit under DEPB and Present Market Value</b>	4.41	In respect of products where rate of credit entitlement under DEPB Scheme comes to 10% or more, amount of credit against each such export product shall not exceed 50% of Present Market Value (PMV) of export product. During export, exporter shall declare on shipping bill that benefit under DEPB Scheme would not exceed 50% of PMV of export product.
		However PMV declaration shall not be applicable for products for which value cap exists irrespective of DEPB rate of product.
<b>Utilisation of DEPB credit</b>	4.42	Credit under DEPB shall be utilised for payment of customs duty on any item including capital goods, which is freely importable.
<b>Application for DEPB</b>	4.43	An application for grant of credit under DEPB may be made to RA concerned in ANF 4G alongwith prescribed documents. Agency commission shall be allowed for DEPB entitlement upto 12.5% of FOB value only. FOB value in free foreign exchange shall be converted into Indian rupees as per - exchange rate for exports, notified by Ministry of Finance, as applicable on the date of order of "Let Export" by Customs.
	4.43A	In respect of consignment exports wherein exporter has declared FOB value on a provisional basis, exporter shall be eligible for final assessment of such shipping bill based on actual FOB realised upon sale of such goods in freely convertible currency.
	4.43B	An application for grant of credit for supplies from DTA to SEZ can be made by DTA unit or SEZ unit. DTA unit may claim benefits either from RA or Development Commissioner concerned. In case claim have been filed with RA, RA while allowing benefits to the DTA unit will simultaneously endorse a

copy of communication to concerned Development Commissioner alongwith details of export documents. In case DTA supplier prefers claim with Development Commissioner, the Development Commissioner will verify Denied Entity List (DEL) status of supplier from DGFT website before allowing DEPB benefits. SEZ unit will file application with Development Commissioner concerned in ANF 4G along with prescribed documents.

- 4.44 DEPB shall be issued with transferable endorsement after payment confirmation. In other cases, DEPB shall be initially issued with non-transferable endorsement and upon realization, can be endorsed as transferable.

**Monitoring of Realisation** 4.45

RA shall monitor earlier cases where DEPB has been granted prior to realisation of export proceeds so as to ensure that realisation takes place within prescribed time. Failing this, RA shall initiate action for recovery of an amount equivalent to DEPB credit with interest as notified. Recovered amount in such cases shall be deposited in head of account of Customs as stated in paragraph 4.29 above.

- 4.45.1 If export proceeds are not realised within the stipulated time period DEPB holder shall pay in cash an amount equivalent to duty free credit utilised on imports, against such exports with interest as notified from date of import till date of deposit. If amount realised in foreign exchange is less, then payable amount would be reduced proportionately.

**Time Period**

- 4.46 Application for obtaining credit shall be filed within a period of twelve months from date of exports or within six months from date of realization or within three months from date of printing / release of shipping bill, whichever is later, in respect of shipments for which claim have been filed.

- 4.47 Wherever provisional shipment has been allowed by customs authorities, DEPB against such exports shall be issued only after release of shipping bill by Customs. In such cases, application for DEPB shall be filed within six months from date of release of such shipping bill or six months from date of realisation, whichever is later.

**Frequency of Application** 4.48

All shipping bills in any one application must relate to exports made from one Custom House only. There is no limit on number of shipping bills which can be filed through EDI mode in a single application.

**Verification by Customs** 4.49

In case of EDI shipping bills before 1.10.2005 and non-EDI shipping bills, RA shall ensure that while issuing DEPB, Shipping

Bill No(s) and date(s), FOB value in Indian Rupees as per Shipping Bill(s) and description of export product are endorsed on DEPB. Before allowing imports against such DEPB, Customs shall verify that details of exports, as given on DEPB, are as per their records. However, in case of EDI shipping bills issued on or after 1-10-2005 from EDI ports which are being transmitted electronically by Customs to DGFT, DEPBs issued shall be sent to Customs at port of registration through an electronic message exchange system and DEPB shall be registered at port of registration electronically. No verification of shipping bills against which such DEPBs have been issued, will be required before allowing imports against these DEPBs.

- |   |      |   |
|---|------|---|
| <b>Revalidation</b>   | 4.50 | No revalidation shall be granted beyond original period of validity of DEPB unless it expires in custody of Regional / Customs Authorities as per paragraph 2.13 of HBP v1.   |
| <b>Re-export of goods imported under DEPB Scheme</b>  | 4.51 | Goods imported under DEPB scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per guidelines given in paragraph 3.23.6 of HBP v1.  |
| <b>Issuance of DEPB and other duty credit certificates against lost EP copy of the Shipping Bills</b> | 4.52 | <p>In case where EP copy of Shipping Bill has been lost, DEPB and other duty credit certificates, claim can be considered subject to submission of following documents:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) A duplicate / certified copy of Shipping Bill issued by Customs authority in lieu original;</li> <li>b) An application fee equivalent to 2% of the DEPB or other duty credit entitlement in respect of lost Shipping Bills. However, no fee shall be charged when Shipping Bill is lost by Government agencies and a documentary proof to this effect is submitted;</li> <li>c) An affidavit by exporter about loss of Shipping Bills and an undertaking to surrender it immediately to concerned RA, if found subsequently; and</li> <li>d) An indemnity bond by exporter to the effect that he would indemnify Government for financial loss if any on account of DEPB or other duty credit certificate issued against lost Shipping Bills.</li> </ol> |

Customs authority, before allowing clearance, shall ensure that no DEPB benefit has been availed against same shipping bill.

- |        |   |
|--------|---|
| 4.52.1 | Claim against lost Shipping Bill shall be preferred within a period of six months from date of release of duplicate copy of shipping bill and any application received thereafter will be rejected. |
|--------|---|

However, if a provisionally assessed DEPB shipping bill is lost, time period for filing an application for DEPB would be six months from the date of release of the finally assessed shipping bill.

***Loss of Original  
Bank Certificate***

4.53

In such cases where original Bank Realisation Certificate (BRC) has been lost, the DEPB claim can be considered subject to submission of following documents:

- a) A duplicate copy of BRC issued by bank authority in lieu of original loss;
- b) An application fee equivalent to 2% of the DEPB entitlement in respect of lost BRC;
- c) An affidavit by exporter about loss of BRC and an undertaking to surrender it immediately to RA, if found subsequently;
- d) An indemnity bond by exporter to the effect that he would indemnify Government for financial loss, if any, on account of DEPB issued against lost BRC.

Claim against lost BRC shall be preferred within a period of six months from date of realisation and application received thereafter will be rejected.

In such cases, where both documents have been lost, exporter shall follow procedure laid down in paragraph 4.52 and 4.53. Time period for such application shall be as per paragraph 4.52 and 4.53, whichever is later.

## **DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION (DFIA) SCHEME**

***Duty Free Import  
Authorisation (DFIA)  
Scheme***

4.54

Policy relating to the Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme is prescribed in Chapter 4 of FTP.

***Application***

4.55

An application in ANF 4H along with documents therein, shall be submitted to RA concerned.

4.55.1

Guidelines as in paragraph 4.4.1 and 4.4.3 above would be adhered to.

4.55.2

Deleted

4.55.3

However in respect of following items, exporter shall be required to give declaration with regard to technical characteristics, quality and specification in shipping bill. RA while issuing DFIA shall mention technical characteristics, quality and specification in

respect of such inputs:

Alloy steel including Stainless Steel, Copper Alloy, Synthetic Rubber, Bearings, Solvent, Perfumes/ Essential Oil/ Aromatic Chemicals, Surfactants, Relevant Fabrics, Marble, Articles made of polypropylene, Articles made of Paper and Paper Board, Insecticides, Lead Ingots, Zinc Ingots, Citric Acid, Relevant Glass fibre reinforcement (Glass fibre, Chopped / Stranded Mat, Roving Woven Surfacing Mat), Relevant Synthetic Resin (unsaturated polyester resin, Epoxy Resin, Vinyl Ester Resin, Hydroxy Ethyl Cellulose), Lining Material.

	4.55.4	Deleted
<b><i>DFIA for applicants with multiple units</i></b>	4.56	Transfer of any duty free material imported or procured against actual user DFIA shall be governed by provisions of paragraph 4.5 above.
<b><i>DFIA for Free of Cost and Paid Material</i></b>	4.57	Procedure would be as per paragraph 4.6 above and 4.2.7 in FTP.
<b><i>Financial Powers</i></b>	4.58	Financial powers shall be as per paragraph 4.8 above.
<b><i>Description of a DFIA</i></b>	4.59	A DFIA shall specify details as per paragraph 4.11 above.
<b><i>Exports in Anticipation of DFIA</i></b>	4.60	Exports / supplies made from date of EDI generated file number for a DFIA, may be accepted on similar lines as in paragraph 4.12, 4.12.1 & 4.12.2 above.
	4.60.1	Deleted
	4.60.2	Deleted
<b><i>Port of Registration</i></b>	4.61	Provision of paragraph 4.19 above shall be applicable in case of DFIA.
<b><i>Acceptance of BG / LUT</i></b>	4.62	Provision of paragraph 4.18 above shall be applicable.
<b><i>Enhancement / Reduction in the Value of DFIA</i></b>	4.63	Provision of paragraph 4.21 above shall be applicable.
<b><i>Export Obligation period (EOP) and its extension</i></b>	4.64	Export obligation fulfillment period and its extension shall be governed as per paragraph 4.22 above. However, any extension beyond 36 months from the authorisation issue date shall not be allowed.
<b><i>Revalidation of DFIA</i></b>	4.65	Facility of revalidation shall be available to DFIA holder as per paragraph 4.23 above.



<b>Re-export of goods imported under DFIA Scheme</b>	4.66	<p>Goods imported against transferable DFIA, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per DoR guidelines. In such cases 95% of CIF value debited against DFIA for export of such goods, shall be generated by concerned Commissioner of Customs as an Authorisation, containing amount generated and the details of original DFIA.</p> <p>Based on the certificate, a fresh DFIA shall be issued by concerned RA.</p> <p>Fresh DFIA, so issued, shall have same port of registration and shall be valid for a period equivalent to balance period available on date of import of such defective / unfit goods.</p>
<b>Monitoring of Export Obligation</b>	4.67	Provision of paragraph 4.24 above shall apply.
<b>Fulfillment of Export Obligation and maintenance of proper accounts of imports</b>	4.68	<p>Provision of paragraph 4.24 above shall apply.</p> <p>Original DFIA holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported /domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 23. These records are required to be sent to concerned RA along with request for bond waiver / redemption / discharge of export obligation/ transferability. Such records should be preserved for a period of at least three years from date of redemption.</p>
	4.69	Deleted.
<b>Redemption</b>	4.70	Provision of paragraph 4.26 above shall apply.
<b>Regularisation of Bonafide default</b>	4.71	Cases of bonafide default in fulfillment of export obligation may be regularised by as prescribed in paragraph 4.28 above.
<b>Transferability of DFIA</b>	4.72	Once export obligation is fulfilled and required documents as stipulated in paragraph 4.68 above have been furnished, RA shall make authorisation transferable subject to conditions stipulated for this scheme. However, restricted item endorsed in authorisation shall be allowed to be transferred only against a separate authorisation / permission issued as per FTP and the procedure laid thereunder.

**GEMS AND JEWELLERY****Replenishment  
Authorisation**

- 4A Policy relating to Gem Replenishment Authorisation, and scheme for gold / silver / platinum jewellery is given in paragraph 4A of FTP.
- 4A.1 An application for REP Authorisation may be made in *ANF 4I* alongwith documents prescribed therein to *RA* concerned as in Appendix 1A.
- 4A.1.1 Application shall be filed within six months following the month during which the export proceeds are realised. For export proceeds realised during month, a consolidated application for entire month shall be filed.
- 4A.1.2 Deleted
- 4A.1.3 In case where payment is received in advance and exports take place subsequently, application for REP Authorisation shall be filed within six months following the month during which exports are made.
- 4A.1.4 For purpose of clarity, it is again reiterated that the month in which the export has been made in case of advance payment and the month in which export proceeds have been realised in part or full after making of exports, shall be excluded while calculating period of six months for filing of application for REP Authorisation.

**Wastage Norms**

- 4A.2 Wastage or manufacturing loss on gold / silver / platinum jewellery and articles thereof is as follows:

Item of exports		Percentage of wastage by weight with reference to Gold / Platinum / Silver content in export item	
		Gold/ Platinum	Silver
a)	Plain jewellery and articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads / imitation stones, cubic zirconia, diamonds, precious, semi-precious stones.	3.5%	4.5%
b)	Studded jewellery and articles thereof	9.0%	10%
c)	Mountings and findings manufactured (by non-mechanised process) indigenously	3.5%	4.5%

d)	Any jewellery / articles manufactured by a fully mechanised process and unstudded.	1.25%	1.25%
e)	Mountings, whether imported or indigenously procured / manufactured, used in studded jewellery	2.5%	2.5%
f)	Gold / silver / platinum medallions and coins (excluding coins of nature of legal tender)	0.25%	0.25%
g)	Findings and mountings manufactured by mechanized process	1.25%	1.25%

**Value Addition**

4A.2.1 Under scheme for export of jewellery, value addition shall be calculated as per paragraph 4A.6 of FTP. Minimum value addition shall be:

S.No.	Item of Export	Minimum Value Addition
a)	Plain gold / platinum / silver jewellery and Articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads / imitation stones, except in studded form of jewellery.	4%
b)	All types of Studded gold / platinum / silver Jewellery and articles thereof.	6.5%
c)	Any jewellery / articles manufactured by fully mechanised process	2%
d)	Gold / silver / platinum medallions & coins (excluding coins of nature of legal tender)	2%
e)	Gold / silver / platinum findings / mountings manufactured by mechanised process	3%

4A.2.2 Entitlement of quantity of gold / silver / platinum against the export shall be quantity of gold / silver / platinum in item of export plus admissible wastage / manufacturing loss.

**Loss of Gem and Jewellery 4A.3**

Consignments of gem and jewellery items exported out of country and lost in transit after exports, where foreign exchange against such exports has been realised or insurance claims settled, will also be eligible for REP Authorisation.

***Gem & Jewellery  
Replenishment  
Authorisations***

4A.4 Gem REP Authorisations shall be valid for import of precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls. In addition, Authorisation shall also be valid for import of empty jewellery boxes upto 5% of value of Authorisation within its overall CIF value. Gem REP Authorisations issued against export of studded gold / silver / platinum jewellery articles, shall also be valid for import of cut and polished precious / semi-precious stones other than emerald upto 10% of CIF value of Authorisation within its overall CIF value.

4A.4.1 Gem REP Authorisation are available as per scale given in Appendix 12B.

***Filing of Application***

- 4A.4.2
- (i) An application for Gem Rep Authorisation may be given to RA concerned as given in Appendix 1A in the form given in Appendix 22-F alongwith prescribed documents.
  - (ii) In case E.P Copy of Shipping Bill and Customs attested invoice is submitted to nominated agencies, exporter shall furnish a self certified photo copy of same along with a certificate from nominated agencies certifying carat / value of studdings in case of studded jewellery and excess value addition achieved in case of plain jewellery and articles.
  - (iii) Provision of paragraph 4A.1.1 to 4A.1.4 will also be applicable for Gem Rep Authorisations.

***Agency Commission***

4A.5 Exporter availing scheme of gold / silver / platinum jewellery are allowed to pay agency commission. Value addition shall be calculated after deducting agency commission. Wherever such agency commission is paid, value addition shall be correspondingly increased by percentage of agency commission.

***Endorsement on shipping  
Bill and Invoice***

4A.6 During export of jewellery, shipping bill and invoice presented to customs authorities shall contain description of item, its purity, weight of gold / silver / platinum content, wastage claimed thereon, total weight of gold / silver / platinum content plus wastage claimed and its equivalent quantity in terms of 0.995/0.999 fineness for gold/ silver and in terms of 0.9999 fineness for platinum and its value, fob value of exports and value addition achieved. If purity of gold / silver / platinum used is same in respect of all or some of items made out from each of these metals for export, exporter may give total weight of gold/silver/ platinum and other details of such similar items which are of same purity. In case of studded items, shipping bill shall also contain description, weight and value of precious / semi-precious stones / diamonds / pearls used in manufacture, and weight / value of any other precious metal used for alloying gold / silver.

**Conditions of Exports**

4A.7

Exports shall be allowed by customs authorities provided endorsement made on shipping bill and invoice are correct and value addition achieved is not below minimum prescribed in FTP.

**Proof of Exports**

4A.8

Exporter has to furnish the proof of exports, wherever required for export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof, by furnishing following documents:

- (a) E.P copy of the shipping bill;
- (b) Customs attested invoice;
- (c) Bank certificate of export as in Appendix 22A showing that documents have been sent for negotiation / collection; and
- (d) A declaration on following lines:

“ I / We declare that outstanding realisation of export proceeds beyond 180 days does not exceed 10% of average exports of preceding three licensing years. I/We further declare that no export proceeds are outstanding beyond one year or such extended period for which RBI permission has been obtained.”

In case of Personal carriage of jewellery by foreign buyer, following documents should be submitted by the exporter/seller as proof of exports for claiming export entitlements:

- (a) Copy of shipping bill filed by Indian Seller;
- (b) A copy of Currency Declaration Form filed by Foreign Buyer with Customs at the time of his arrival; and
- (c) Foreign Exchange Encashment Certificate from Bank.

In addition to this, Personal Carriage on Documents Against Acceptance (DA) / Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. Exporter will have to furnish following documents as proof of exports for claiming export entitlements:

- (i) Copy of Shipping Bill filed by Indian Seller; and
- (ii) Bank Certificate of Export and Realisation

Instructions issued by Customs Department in this regard should be followed mutatis mutandis.

<b>Conversion of Purity / Fineness</b>	4A.9	<p>For conversion of quantity of gold / silver / platinum in terms of equivalent quantity in terms of fineness, following formula shall be used:</p> <p>(i) Where items of gold has been exported in terms of carats, quantity of gold shall be multiplied by number of carat of gold exported, divided by 24 and thereafter again divided by 0.995 / 0.999 / 0.900 to arrive at equivalent quantity of gold in terms of fineness of 0.995 / 0.999 / 0.900 respectively; and</p> <p>(ii) Wherever purity of item of export is expressed in terms of fineness, the quantity of gold/silver/platinum shall be multiplied by fineness of gold/silver/platinum exported and thereafter divided by 0.995 / 0.999 / 0.900 to arrive at equivalent quantity of gold / silver / platinum in terms of 0.995 / 0.999 / 0.900 fineness respectively'.</p>
<b>Release of Gold / Silver / Platinum by Nominated Agencies</b>	4A.10	<p>Gold / silver / platinum shall be released to exporter of jewellery by nominated agencies/RBI authorised banks in multiples of 10 gms or in Ten Tola Bars in respect of golds. However, silver shall be released to exporters in multiples of 1 Kg only. Any balance of gold / silver / platinum shall be available to exporter along with his future entitlement. Gold / silver shall be released by the nominated agencies in terms of 0.995 fineness or more and platinum in terms of 0.900 fineness or more.</p>
<b>Terms of payment</b>	4A.11	<p>Export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof shall be against irrevocable letter of credit, payment of cash on delivery basis, Documents Against Acceptance (DA) basis or advance payment in foreign exchange.</p>
<b>Port of Export</b>	4A.12	<p>Exports under schemes of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Customs House at Mumbai, Calcutta, Chennai, Cochin, Delhi, Jaipur, Bangalore, Kochi, Coimbatore, Ahmedabad, Dabolin Airport, Goa and Hyderabad. Export by courier shall also be allowed through Custom Houses at Mumbai, Calcutta, Chennai, Cochin, Coimbatore, Delhi, Jaipur, Bangalore, Ahmedabad and Hyderabad upto FOB value of Rs.20 lakhs per consignment.</p>
<b>Export by Post</b>	4A.13	<p>Policy for export of gems and jewellery parcel by post is in paragraph 4A.17 of FTP. At the time of exports, exporter shall submit following documents:</p> <p>(i) Shipping bills or invoice presented at foreign Post Office;</p>

(ii) Certificate from nominated agencies indicating price at which gold / silver / platinum was booked or given on outright sale basis or loan basis;

(iii) Three copies of invoice.

4A.14 Deleted

**Export Against Supply  
By Foreign Buyer**

4A.15 Before clearance of each consignment of import supplied by foreign buyer, nominated agency shall execute a bond with Customs, undertaking to export within stipulated *period* in contract, gold / silver / platinum jewellery or articles equivalent to entire import quantity of gold / silver / platinum, mountings and findings etc excluding admissible wastage.

In case of direct supply of gold / silver / platinum, alloys, findings and mountings of gold / silver / platinum and plain semi-finished gold / silver / platinum jewellery to status holder / exporter, Status Holder / exporter shall furnish a Bank Guarantee / LUT, as per Customs Rules and regulations to Customs equivalent to Customs Duty leviable on imported gold / silver / platinum, alloys, findings and mountings of gold / silver / platinum and plain semi-finished gold / silver / platinum jewellery etc.

BG / LUT, executed with Customs shall be valid for one year. In case of direct supply to Status Holder / exporter, exports shall be completed within 90 days. In case of non-fulfillment of EO / non-achievement of stipulated value addition, Customs Department shall proceed to recover custom duty alongwith interest which may include enforcement of BG / LUT. Besides importer will be liable to penal action under Customs Act

4A.15.1 Nominated agency / Status Holder / exporter shall be liable to pay customs duty leviable on that quantity which is proved to have been not exported.

4A.15.2 Goods shall be cleared through Customs by nominated agency Status Holder / exporter. Even where export order is received by an Associate, goods shall be cleared through Customs by nominated agency only and not Associate. Associate shall, in such cases, authorise nominated agency to act as its agent to file Bill of Entry and shipping bill.

4A.15.3 At time of export, shipping bill presented to Customs shall also contain the following:

(i) Name and address of associate / Status Holder / exporter;

- (ii) An endorsement by nominated agency that export is made against an order received by concerned associate, its date of registration with nominated agency. In case of exports by Status Holder / exporter, a Self Declaration shall be provided to this effect;
  - (iii) Name of Customs House through which gold / silver / platinum / plain semi-finished gold / silver / platinum jewellery was imported and corresponding Bill of Entry No. and date and date of import.
- 4A.15.4 Each shipping bill shall be valid for exports only through Customs House located at the place where office of nominated agency / Status Holder / exporter concerned is situated. It shall be valid for shipment for a period of seven days including the date on which endorsement was made by nominated agency in case of exports through nominated agency. If exports cannot be made within this period, exporter shall file a fresh shipping bill.
- 4A.15.5 At the time of export, exporter shall submit following documents:
- (i) Shipping bill with two extra copies where exports are made from a Customs House other than Customs House through which corresponding import of gold / silver / platinum / plain semi-finished gold / silver / platinum jewellery was effected. In other cases, shipping bill with an extra copy;
  - (ii) Three copies of invoice;
  - (iii) Certificate from nominated agency indicating quantity and value of items supplied by foreign buyer.
- 4A.15.6 Customs authorities shall return two copies of shipping bill and connected invoice duly attested. One copy shall be sent to person who presented documents and the other copy shall be sent by Customs to office of nominated agency / Status holder / exporter.
- 4A.15.7 In case of exports through nominated agency, exporter shall submit proof of exports to nominated agency within 15 days of exports, who shall, after verifying documents, release admissible quantity of the gold / silver / platinum etc. to exporter.
- 4A.15.8 Exporter may also obtain, in advance, gold / silver / platinum etc. supplied by foreign buyer by furnishing a BG / LUT for an amount equal to international price of such items plus customs duty payable thereon. BG / LUT shall be redeemed only when the exporter has furnished proof of exports to nominated agency



and accounted for the use of items supplied in advance in export product.

- 4A.15.9 For redemption of bond / BG / LUT executed with Customs, nominated agency / Status Holder / exporter shall furnish a statement indicating items, its quantity and value supplied by foreign buyer, corresponding Bill of Entry number and date, number of each of shipping bills against which corresponding exports was made.

**Maintenance of Accounts**

- 4A.16 Nominated agency shall maintain complete account, consignment-wise, of the gold, silver, platinum, mountings, findings / plain semi-finished gold / silver / platinum jewellery etc. imported for execution of each export order, exports effected and quantity of gold, silver, platinum mountings, findings etc. released against such exports. For direct exports, similar accounts shall also be maintained by Status Holder. Such accounts shall be maintained for a minimum period of three years from date of exports.

**Export Through Exhibitions / Export Promotion Tours / Export of Branded Jewellery**

- 4A.17 Nominated agencies shall produce to Customs Authorities letter in original or its certified copy, containing Government's approval for holding exhibition / export of branded jewellery. Any other person shall produce to Asst. Commissioner, customs letter in original or its certified copy containing GJEPC's approval for holding exhibitions / export promotion tour / export of branded jewellery.

In case of re-import, such items, on arrival, shall be verified alongwith export documents before clearance.

- 4A.18 (a) Exports under this scheme shall be subject to following conditions for following modes of export:

- (i) Export of Gems and Jewellery for holding / participating in overseas exhibition.

Exports under this scheme shall be subject to the following conditions:

Items not sold abroad shall be re-imported within 60 days of close of exhibition. However in case exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of first exhibition, then 60 days shall be counted from date of close of last exhibition. In case of personal carriage of gems and jewellery for holding / participating in overseas exhibitions, value of such gems and jewellery shall not exceed US \$ 2 million. Gold / silver / platinum content on items sold in such exhibitions may be imported as replenishment.

Exporter shall take replenishment from nominated agency within 120 days from the close of the exhibition gold / silver / platinum for replenishment content against items sold abroad in exhibition.

- (ii) Personal Carriage of gems & jewellery or export through airfreight / post parcel route for Export Promotion Tours /photo shoots / fashion shows overseas.

Personal carriage / export through airfreight / post parcel route of gold / silver / platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US\$ 100,000 for export promotion tours / photo shoots / fashion shows and temporary display / sale abroad is also permitted with approval of Gem & Jewellery & Jewellery EPC subject to the condition that promoter would bring back jewellery / goods or repatriate sale proceeds within 45 days from date of departure through normal banking channel. In case of personal carriage for export promotion tours, exporter shall declare personal carriage of such samples to Customs while leaving country and obtain necessary endorsement on Export Certificate issued by Jewellery Appraiser of Customs. In such cases exporter shall book with nominated agency, within 120 days after export promotion tour or expiry of stipulated period of 45 days, whichever is earlier, gold / silver / platinum for replenishment content against items sold abroad.

- (iii) Export of branded jewellery.

Export of branded jewellery is also permitted with approval of Gem & Jewellery and Jewellery EPC for display / sale in permitted shops set up abroad or in showroom of their distributors / agents. Items not sold abroad within 180 days shall be re-imported within 45 days. Exporter shall book with nominated agency within 120 days after the end of stipulated period of 180 days, gold / silver / platinum for replenishment content against items sold abroad.

- (b) Following documents shall be submitted for claiming such replenishment:

- (i) Customs attested invoice;

(ii) Copy of the approval letter issued by Government / GJEPC;

(iii) Certificate from nominated agency / GJEPC as in Appendix 22F.

(c) In case of exhibitions organised by nominated agencies, gold / silver / platinum shall be imported as replenishment by nominated agencies within 60 days from close of exhibition.

4A.19 Nominated agencies shall maintain a complete account of exports made, goods sold abroad, goods re-imported, and metals purchased abroad and imported into India. Such account shall be maintained for a minimum period of three years from date of close of exhibition.

***Export Against Supply  
By Nominated Agencies***

4A.20 Exporter may obtain gold / silver / platinum on following basis:-

(i) Replenishment basis after completion of exports;

(ii) Outright purchase basis in advance;

(iii) Loan basis.

***Replenishment Basis***

4A.21 Exporter may apply to nominated agency for booking of precious metal gold / silver / platinum. Quantity of precious metal booked with nominated agency shall be equivalent to precious metal content in the export product and admissible wastage.

4A.21.1 Applicant shall at the time of booking deposit an earnest money for a minimum amount of 20% of notional price of precious metal, which shall be adjusted at actual sale.

4A.21.2 Exporter may also export jewellery on a notional rate based on certificate provided by Bank. Exporter must fix price within credit terms allowed to buyer and realise proceeds within the due date of the credit terms or 180 days, whichever is earlier. Exporter exporting on a notional basis under Replenishment Scheme must book the same quantity of gold with Nominated Agency on same rate that he may have booked with buyer. Nominated agencies shall purchase precious metal on behalf of exporter at the rate so fixed and thereafter issue a purchase certificate bearing a serial number to exporter indicating quantity of gold / silver / platinum and CIF value, in dollars including the Rupee equivalent. Price shall be actual price at which gold / silver / platinum is purchased by nominated agencies plus permitted service charges levied by nominated agencies shall be included with the price of gold / silver / platinum for value addition. Duplicate and triplicate

copies of exporter's application together with copies of purchase certificate for exporter shall be sent by nominated agencies to concerned Custom House as well as to the negotiating bank who will confirm realization at which gold has been purchased. Exporter exporting under notional rate will get replenishment only after proceeds are realised.

- 4A.21.3 Exports shall be effected within a period of 120 days from date of booking and drawal of precious metal shall be completed within a period of 150 days from date of booking or within 30 days from date of export whichever is later.

***Outright Purchase Basis  
in Advance***

- 4A.22 Exporter may obtain required quantity of precious metal in advance on outright purchase basis subject to furnishing of BG / LUT to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agency. On failure to effect exports within period prescribed, the nominated agencies shall enforce BG / LUT, as the case may be.

- 4A.22.1 Exports shall be effected within a maximum period of 90 days from date of outright purchase of precious metal.

***Loan Basis***

- 4A.23 Exporter may obtain required quantity of precious metal on loan basis subject to furnishing of BG / LUT, for customs duty to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agencies. On failure to effect exports within period prescribed, the nominated agencies shall enforce the BG / LUT.

- 4A.23.1 Exporter has to pay interest on gold taken on loan basis at the rate as may be specified.

- 4A.23.2 Export has to be completed within a maximum period of 90 days from date of release of gold on loan basis. No extension for fulfillment of EO shall be allowed.

- 4A.23.3 Exporter shall be permitted to export jewellery on the basis of a notional rate certificate to be issued by nominated agency / GJEPC. This rate will be based on prevailing Gold / USD rate and the USD / INR rate in notional rate certificate. Certificate issued by nominated agency / GJEPC should not be older than 7 working days of date of shipment.

Value addition will have to be achieved on rate as may be got fixed with buyer and Nominated Agency.

Exporter shall have flexibility to fix the price and repay Gold Loan within 180 days from date of export. This price shall be communicated to nominated agencies who will issue a certificate

showing final confirmation of the rate to the bank negotiating documents, to ensure export proceeds are realized at this rate.

4A.24 Nominated agencies may accept payment in dollars towards cost of import of precious metal from EEFC account of exporter.

**Exports against Advance Authorisation**

4A.25 Procedure applicable to Advance Authorisations under Chapter-4 of HBP v1 shall generally apply to this scheme except norms for value addition, EO period and regularization of default.

4A.25.1 EO will be required to be fulfilled within 120 days from date of import of each consignment against Authorisation. However EO period shall be 180 days from date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and export of jewellery. No further extension in EO period will be allowed. Advance Authorisation holder may also import gold as replenishment after completion of exports.

4A.25.2 Advance Authorisation holder may obtain gold / silver / platinum from nominated agencies in lieu of direct imports. In such a case, nominated agency shall make, both exchange control copy and customs purpose copy of Authorisation invalid for direct imports.

**Diamond Imprest Authorisation**

4A.26 Policy for Diamond Imprest Authorisation is prescribed in paragraph 4A.14 of FTP.

**Application**

4A.26.1 For the scheme, an application in ANF 4J, alongwith prescribed documents therein shall be submitted to RA concerned.

**Export Obligation**

4A.26.2 EO against each consignment shall be fulfilled within a period of five months from date of clearance of such consignment through Customs. However, at no point of time, importer shall be required to maintain records of individual import consignments nor will they be required to co-relate export consignments with corresponding import consignments towards fulfilment of EO.

**Regularisation of Bonafide Default**

4A.27 Cases of bonafide default in fulfillment of EO by an exporter who has obtained precious metals from nominated agencies may be regularised provided exporter has paid customs duty alongwith interest thereon as notified to Customs. However, in case of Advance Authorisation, the provisions as given in paragraph 4.28 above shall apply. This shall be without prejudice to any action that may be taken against exporter under FT(D&R) Act, Order or Rules issued thereunder.

**Replenishment Authorisation for Import of Consumables etc.**

4A.28 A Replenishment Authorisation for duty free import of consumables, tools, machinery and equipments for metals other than Gold, Platinum equal to 2% and for Gold and Platinum

equal to 1% of FOB value of exports of the preceding year may be issued on production of Chartered Accountant's Certificate indicating export performance. However, in case of rhodium-finish silver jewellery, entitlement will be 3% of such jewellery. This Authorisation shall be non-transferable and subject to actual user condition. This Replenishment Authorisation shall be valid for duty free import of consumables, tools, machinery & equipments as notified by Customs.

Application for import of consumables as given above may be made to the concerned RA in ANF 41.

***Personal Carriage of  
Gems & Jewellery  
Export Parcels***

- 4A.29 Personal Carriage of gems & jewellery parcels by Foreign Bound Passengers from all EOU / SEZ units and all firms in DTA through Airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Cochin, Coimbatore, Bangalore, Hyderabad, Jaipur is permitted. Procedure for Personal Carriage of exports shall be as prescribed by Customs. Export proceeds shall, however, be realised through normal banking channel. For claiming Replenishment in case of Personal Carriage of Exports by Foreign Bound passenger, documents shall be same as mentioned under paragraph 4A.21.2 above. Authorised Courier Companies are also permitted to operate on the above lines.

***Personal Carriage of  
Gems & Jewellery  
Import Parcels***

- 4A.30 Personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian importer / Foreign National may be permitted into all EOUs / SEZ units and all firms in DTA through airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad Jaipur. Procedure will be same as for import of goods by air-freight except that parcels shall be brought to Customs by Importer / Foreign National for examination and release. Clearance of imports under this scheme shall be as per normal customs clearance procedure.

***Duty free import  
of samples***

- 4A.31 Duty free import of gems and jewellery samples upto Rs 3 lakhs or 0.25% of the average of last three years export turnover of gems and jewellery items, whichever is lower, shall be allowed in a financial year as per Customs notification.

***Re-import of rejected  
jewellery***

- 4A.32 An exporter of plain / studded precious metal jewellery shall be allowed to re-import duty free jewellery rejected and returned by buyer upto 2% of FOB value of exports in preceding licencing year with refund of any duty exemption / refund / replenishment benefit availed on inputs used as per customs rules and regulations.

- 4A.32.1 However, an exporter desirous of re-importing plain/ studded precious metal jewellery for re-export shall submit a CA certified copy of export of his preceding year to jurisdictional Customs

Authorities and also execute a bond with them to re-export equivalent quantity of plain / studded jewellery of same quantity (equivalent weight of gold & value of studdings that were re-imported) within 60 days of re-import.

***Diamond & Jewellery  
Dollar Accounts***

4A.33

Policy for Diamond and Jewellery Dollar Accounts is given in paragraph 4A.19 of FTP. Detailed procedure for its operation will be notified separately.

***Import of precious metal  
scrap / used jewellery for  
melting and re-export  
of jewellery.***

4A.34

Policy for Import of precious metal scrap/used jewellery for melting and re-export of jewellery is given in paragraph 4A.21 of FTP. Procedure is laid as under:

Imported precious metal scrap / used jewellery shall be allowed to be cleared by Customs subject to the condition:

- a) that importer files a bond along with Bank Guarantee for a sum equivalent to one and half times customs duty leviable on said used jewellery / precious metal scrap;
- b) importer fulfils the export obligation and value addition as notified by Central Government;
- c) such import will not be allowed through Hand Baggage.

Detailed procedure including value addition requirement and export obligation etc. for operationalisation of the facility under this paragraph shall be notified separately by DGFT.

***Export of Diamond &  
Jewellery on  
consignment basis***

4A.35

Policy for export of diamond and jewellery on consignment basis is given in paragraph 4A.23 of FTP.

Detailed procedure in this regard shall be governed as per the relevant Customs Rules & Regulations. Re-import of these items (either in complete or partial lot) exported on consignment basis shall be subject to condition that exporter follows prescribed provisions of relevant customs notification to establish that goods are the same which were exported.

**CHAPTER-5****EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS ( EPCG) SCHEME**

- |                                      |       |   |
|--------------------------------------|-------|---|
| <b>Policy</b>                        | 5.1   | Policy relating to EPCG Scheme is given in Chapter 5 of FTP.  |
| <b>Application Form</b>              | 5.2   | An application for grant of an authorization, upto Rs.50 Crore of duty saved amount may be made to RA concerned in ANF 5A along with documents prescribed therein.  |
| <b>Consideration of Applications</b> | 5.3   | For cases wherein duty saved amount is above Rs. 50 crores, applicant may apply to DGFT Headquarters directly with a copy endorsed to concerned RA. In such cases, concerned RAs will issue EPCG authorisation according to directions from DGFT.   |
|                                      | 5.3.1 | RA concerned shall, on the basis of nexus certificate from an Independent Chartered Engineer (CEC) submitted by applicant in Appendix 32A, issue EPCG authorization.  |
|                                      | 5.3.2 | Authorisation holder shall produce to concerned RA a certificate from jurisdictional Central Excise authority or an independent Chartered Engineer (CEC) confirming installation of Capital goods at factory premises of authorization holder or his supporting manufacturer(s) vendor(s) within six months from date of completion of imports. |
|                                      | 5.3.3 | EPCG authorization shall be issued with a single port of registration mentioned in paragraph 4.19 of HBP v1 for imports. However, exports can be made from any port specified in paragraph 4.19.  |
|                                      | 5.3.4 | (i) An applicant may also apply for import of spares, tools, spare refractories and catalyst as are required for installation and maintenance of capital Goods.   |
- Application shall contain list of plant / machinery installed in factory / premises of applicant for which spares, tools, spare refractories and catalyst are required, duly certified by Chartered Engineer or Jurisdictional Central Excise authorities.
- In such cases EPCG authorization shall not specify list of spares but shall indicate:-
- (a) Name of plant / machinery for which spares are required.
  - (b) Value of duty saved allowed under authorization.



- (c) Description of product to be exported with value of export obligation as per FTP.
- (ii) Deleted
- (iii) Further at the time of final redemption of export obligation, authorization holder shall submit certificate from Independent Chartered Engineer confirming use of spares tools, spare refractories and catalyst so imported in the installed capital goods on the basis of stock & consumption register maintained by authorization holder.
- Conversion of EOU / Relocated SEZ Units to EPCG Scheme** 5.4 An EOU / a relocated SEZ unit may apply for an EPCG authorization in ANF alongwith documents prescribed therein. "No Objection Certificate" should be produced from concerned DC.
- Indigenous Sourcing of Capital Goods** 5.5 EPCG authorization holder intending to source capital goods indigenously, either alongwith application or after issuance of EPCG authorisation, shall request to RA for invalidation of EPCG authorization for direct import / issue of ARO, alongwith name and address of source person of the capital goods.
- 5.5.1 RA concerned will issue such invalidation letter / ARO, in duplicate.
- 5.5.2 Indigenous manufacturer intending to supply capital goods to EPCG authorization holder may apply to RA in ANF for issuance of Advance authorization for import of inputs including components required for manufacture of capital goods to be supplied to EPCG authorization holder.
- 5.5.3 Deleted
- Leasing of Capital Goods** 5.6 An EPCG authorization holder may, source capital goods from a domestic leasing company. In such cases, the Bill of Entry of imported capital goods or commercial invoice of indigenous capital goods, shall be signed jointly by EPCG authorization holder and leasing company. However, EPCG authorization holder shall alone be fully responsible for fulfillment of export obligation.
- Condition for Fulfilment of Export Obligation** 5.7 In addition to conditions mentioned in paragraph 5.4 of FTP following conditions shall also be applicable for fulfillment of export obligation.
- 5.7.1 EPCG authorisation holder shall export either directly or through third party(s). If a merchant exporter is EPCG authorisation holder, name of supporting manufacturer shall also be indicated

on shipping bills. At the time of export, EPCG authorisation No. and date shall be endorsed on shipping bills which are proposed to be presented towards discharge of export obligation.

5.7.2 Export proceeds shall be realised in freely convertible currency except for deemed exports.

5.7.3 Deleted.

5.7.3.1 Supplies made to Oil and Gas sector also may be counted towards discharge of export obligation against an EPCG Authorisation provided it has been issued on or before 31.3.2000 and no benefit under paragraph 8.3 of FTP has been claimed on such supplies.

5.7.4 Exports made to former USSR or to such countries as notified by DGFT shall not be counted for fixing average level of exports.

5.7.5 Exports under EPCG scheme shall also be entitled for benefits under Chapter 4 of FTP.

5.7.6 In case of export of goods relating to handicraft, handlooms, cottage, tiny sector, agriculture, aqua-culture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture shall not be required to maintain average level of exports.

Goods excepting tools imported under EPCG scheme by such sectors shall not be allowed to be transferred for a period of five years from date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled. However, transfer of capital goods would be permitted within the group companies or managed hotels under intimation to RA and jurisdictional Central Excise Authority in case of manufacturer/merchant exporters and to RA only in case of Service providers.

5.7.7 Deleted.

5.7.8 Wherever more than one EPCG authorisations are issued simultaneously or concurrently, fresh EPCG authorisation would build upon last average export obligation only, notwithstanding actual achievements.

5.8 Deleted.

5.8.1 Deleted.

to 5.8.3

5.8.4 EPCG Authorisations issued upto 31.3.2000 shall be governed

by provisions laid down in paragraph 6.11 in HBP v1 (RE-99). Notwithstanding the same in HBP v1 (RE-99), authorisation holder shall not have to surrender Special Import licence in case of value wise shortfall.

Authorisations issued from 1<sup>st</sup> April, 2000 upto 31<sup>st</sup> March, 2002 shall be governed by provisions of Chapter 6 of HBP v1 (RE-01) as amended from time to time.

Authorisations issued from 1<sup>st</sup> April, 2002 upto 31<sup>st</sup> August, 2004 shall be governed by provisions of para 5.8 of HBP v1 (RE-02) as amended from time to time. However, provision of clubbing even in case of old licences would be as per current provision of para 5.18 of this Handbook.

5.8.5 Deleted.

5.8.6 In case of an existing export obligation under EPCG scheme a fresh EPCG authorisation can only be issued provided average of last obligation (including increased amount due to duty saved in last EPCG) has been maintained.

**Monitoring of Export Obligation**

5.9.1 Authorization holder shall submit to RA concerned by 30<sup>th</sup> April of every year, report on fulfillment of export obligation. Such report shall also be submitted electronically on DGFT website. RA concerned may issue partial EO fulfillment certificate, provided export performance is proportionately adequate to fulfillment of export obligation.

**Automatic Reduction / Enhancement upto 10% of CIF value and Prorata Reduction / Enhancement in Export Obligation**

5.10 If authorization issued has actually been utilized for import of a value in excess upto 10% of CIF value / duty saved amount of authorization, authorization shall be deemed to have been enhanced by that proportion. Customs shall automatically allow clearance of goods in excess upto 10% of authorization value / duty saved amount without endorsement by concerned RA.

In such cases, authorization holder shall furnish additional fee to cover excess imports effected in terms of CIF value / duty saved amount to RA concerned within one month of excess imports taking place. Export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.

5.10.1 Similarly, if EPCG authorization holder has utilised authorization less than the value earmarked in authorization, his export obligation shall stand reduced on prorata basis with reference to actual utilisation of authorization.

**Extension of Export Obligation Period**

5.11 Concerned RA, may consider one or more request for grant of extension in export obligation period, on payment of

composition fee of 2% of total duty saved under authorization or an enhancement in export obligation imposed to the extent of 10% of total export obligation imposed under authorization, as the case may be, at the choice of exporter, for each year of extension sought. Such extension can be for a maximum period of 2 years.

Extension in EO period beyond two years' period available above, may be considered, for a further extension upto 2 years with a condition that 50% of duty payable in proportion to the unfulfilled export obligation is paid by authorization holder to Custom authorities before an endorsement of extension is made on EPCG authorization by RA concerned. In such cases, no composition fee is to be paid or additional EO is to be imposed as prescribed in the Para above. In case the firm is still not able to complete the export obligation duty already deposited will be deducted from total duty plus interest to be paid for EO default.

Extension in export obligation period shall also be subject to such terms and conditions as may be prescribed by competent authority.

- 5.11.1 The firm / company, which is applying for registration with BIFR / Rehabilitation Department of State Government shall also intimate DGFT with regard to relief sought for EPCG authorization, if any, within 30 days of receipt of application by agency concerned.

DGFT, thereafter shall take up the matter with agency concerned to safeguard government interest on account of default in fulfillment of export obligation imposed on EPCG authorization obtained by such firm / companies.

DGFT may consider such application for grant of period of extension upto 12 years or as per rehabilitation package prepared by operating agency and approved by BIFR board / state authority.

- 5.11.2 Waiver of EO may be considered where, because of force majeure or other unforeseen circumstances / reasons, exporter is unable to fulfill export obligation. Such requests shall be considered by a committee comprising representative(s) of DoC and DoR under DGFT. Decision of this committee shall be notified by DoR for implementation.

**Export Obligation  
Shortfall**

- 5.12 RA concerned may condone shortfall upto 5% in export obligation arising out of duty saved amount.

**Redemption**

- 5.13 As evidence of fulfillment of export obligation, authorization

holder shall furnish application in ANF 5B with documents prescribed therein.

(a) to (c) Deleted.

On being satisfied, RA concerned shall issue a certificate of discharge of export obligation to the EPCG authorization holder and send a copy to customs authorities with whom BG / LUT has been executed.

RA shall ensure disposal of such applications within 30 days. Shortcomings, if any, shall be pointed out in one go. All correspondence, thereafter, shall relate to these deficiencies only. Fresh correspondence, if necessary, shall be within 15 days. Once documents are complete EO will be discharged within 30 days of receipt of complete documents / information.

Process of issue of final discharge certificate / rejection shall be completed within a period of 90 days from date of receipt of initial request. Applications that remain outstanding beyond a period of 90 days shall be reported to DGFT alongwith reasons thereof, immediately thereafter.

**Regularisation of  
Bonafide Default**

5.14

In case EPCG authorization holder fails to fulfill prescribed export obligation, he shall pay duties of Customs plus interest as prescribed by Customs authority. Such facilities can be availed by EPCG authorisation holder to exit at his option.

**Maintenance of Records**

5.15

Every EPCG authorization holder shall maintain, for a period of 3 years from date of redemption, a true and proper account of exports / supplies made and services rendered towards fulfillment of export obligation.

**Re-Export of Capital  
Goods Imported Under  
EPCG Scheme**

5.16

Capital Goods imported under EPCG scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported back to foreign supplier within three years from the date of payment of duty on importation thereof with permission of RA / Customs Authority. Consequently, EO would be refixed.

**Replacement of  
Capital Goods**

5.16.1

Capital Goods imported and found defective or otherwise unfit for use may be exported and Capital Goods in replacement thereof be imported under EPCG scheme. In such cases, while allowing export, Customs shall credit duty benefit availed which can be debited again at the time of import of such replaced Capital Goods.

**Penal Action**

5.17

In case of failure to fulfill export obligation or any other condition of authorization, authorization holder shall be liable for action under FT(D&R) Act, Orders and Rules made there under, provisions of FTP and Customs Act, 1962.

***Clubbing of EPCG authorizations***

- 5.18 Clubbing of two or more EPCG authorizations of same authorization holder would be permitted.
- 5.18.1 Deleted.
- 5.18.2 An application for clubbing can be made only to RA concerned in ANF 5D. Clubbing shall not be permitted in case authorisations issued by different RAs.
- (a) to (c) Deleted.
- 5.18.3 Total export obligation would be refixed taking into account total of duty saved or total of CIF value of imports.
- 5.18.4 On clubbing, authorizations for all purposes shall be deemed to be a single EPCG authorization. Export obligation period for clubbed authorization shall be reckoned from first authorization issue-date. However, in cases where clubbed CIF / duty saved value exceeds Rs 100 crore, no corresponding benefit of increase in export obligation period shall be admissible.
- 5.18.5 Average export obligation for clubbed authorizations would be highest of average export obligations endorsed on individual authorizations so clubbed.
- 5.18.6 No clubbing would be permitted after expiry of EOP.

***Refixation of Export Obligation upon conversion from CIF based to duty based EO***

- 5.19 (a) EPCG authorization holder can apply for refixation of export obligation as given in para 5.4 (i) of FTP in ANF 5C.
- (b) Deleted.
- (c) For all EPCG authorizations, authorization holder should have fulfilled mandated (original or amended) block wise export obligation, till previous block to application date. In all such cases, refixed export obligation would be computed as under:
- (% export obligation unfulfilled) x (8) x (duty saved on authorization issue-date )
- (d) Deleted.
- (e) There would be no change in average export obligation fixed or export obligation period of original authorization.
- (f) Deleted.

**Technological Upgradation of Capital Goods** 5.20

Application for technological upgradation of the capital goods would be made in ANF 5A.

**Import of Refurbished / Reconditioned Spares and Tools** 5.21

Import of refurbished spares shall be permitted under EPCG Scheme.

However such refurbished / reconditioned spares must have a residual life not less than 80% of life of original spare which would be certified by EPCG authorization holder.

The tools imported under EPCG Scheme may be transferred to any of units or group companies of applicant.

5.22

Revalidation of authorizations issued under EPCG scheme shall not be allowed.

## CHAPTER-6

### EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) SCHEME AND BIO-TECHNOLOGY PARKS(BTPS).

<i>Scheme</i>	6.1	Policy relating to EOUs, EHTPs, STPs and BTPs Schemes is given in Chapter 6 of FTP.
	6.2	Deleted
<i>Approval / Application and renewal of Application</i>	6.3.1	For setting up an EOU, three copies of application as in Appendix 14-I-A may be submitted to Development Commissioner (DC).
	6.3.2	Applications for setting up units under EOU scheme other than proposals for setting up of unit in service sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by BoA), shall be approved or rejected by Units Approval Committee within 15 days as per criteria indicated in Appendix 14-I-B and sector specific conditions relating to approval as in Appendix 14-I-C. In other cases, approval may be granted by DC after clearance by Board of Approval (BoA).
	6.3.3	Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by DC after clearance of proposal by BoA (as per Appendix 14-I-D) and Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) within 45 days on merits.
	6.3.4.1	STP / EHTP complexes can be set up by Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof, duly approved by Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) in Ministry of Communication and Information Technology (Department of Information Technology). Application for setting up EHTP / STP unit shall be in format prescribed by Ministry of Communication and Information Technology (Department of Information Technology - DoIT) and shall be submitted to officer designated by DoIT.
	6.3.4.2	BTP can be set up by Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof. Application for setting up of BTP shall be submitted to Department of Bio-Technology (DoBT) and such applications which meet guidelines prescribed by DoBT will be approved and recommended to DGFT for notification. Application for setting up of BTP unit shall be submitted to Officer designated by DoBT.



- 6.3.6 LOP/LOI shall specify item(s) of manufacture / service activity, annual capacity, projected annual export for first five years in dollar terms, Net Foreign Exchange (NFE) earnings, limitations, if any, regarding sale of finished goods, by-products and rejects in DTA and such other matter as may be necessary and also impose such conditions as may be required.
- 6.3.7 LoP/LoI issued to EOU / EHTP / STP / BTP units by concerned authority would be construed as an authorization for all purposes. Standard format for LoP for EOU units is given in Appendix 14-I-E.
- 6.3.8 EOUs shall have separate earmarked premises for separate LoP. Similarly, EOUs may be approved on leased premises provided lease has been obtained from Government Department / Undertaking / Agency. However, in case lease is obtained from private parties, it shall have a validity period of five years from date of LUT and DC shall satisfy himself of genuine nature of lease.
- 6.3.9 On completion of approval period as provided for in paragraph 6.6 of FTP, it shall be open to unit to continue under scheme or opt out of scheme. If no intimation in this regard is received from unit within a period of six months of expiry of approval period, DC will take action, suo moto, to cancel approval under EOU scheme and take further action in this regard. Where unit opts to continue, DC concerned will extend approval period.
- Legal Undertaking (LUT)** 6.4.1 Approved EOU / EHTP / STP / BTP unit shall execute a LUT with DC / Designated Officer concerned as in Appendix 14- I-F.
- 6.4.2 All EOU / EHTP / STP / BTP units should have permanent e-mail address. No LUT for new units shall be executed unless unit has its permanent e-mail address and digital signature on said e-mail ID. In event of an EOU not having permanent e-mail address and digital signature, further imports and DTA sale shall not be permitted by DC.
- Export of goods and services** 6.5.1 Software units may undertake exports using data communication links or in form of physical exports (which may be through courier service also), including export of professional services.
- 6.5.2 EOUs shall be permitted to export jewellery on basis of a notional rate certificate issued by nominated agency. This rate will be based on prevailing Gold / US\$ rate and US\$ / INR rate in notional rate certificate. Certificate issued by nominated agency should not be older than 3 working days of date of shipment.

6.5.3 Exporter shall have flexibility to fix price and repay gold loan within 180 days from date of export. Price shall be communicated to nominated agencies who will issue a certificate showing final confirmation of rate to bank negotiating document, to ensure export proceeds are realized at this rate.

6.5.4 Gem & Jewellery and Jewellery EOUs may re-export imported goods and export domestically procured goods, including goods generated out of partial processing / manufacture. Besides, supply of unsuitable / broken cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones upto 5% of value of imported or indigenously procured goods to DTA against valid Gem & Jewellery REP as applicable on payment of appropriate duty is also permitted.

***Import / Domestic  
Procurement of Goods***

6.6.1 Goods permitted to be imported / procured from DTA shall include:

- (a) Raw materials, components, consumables, intermediates, spares and packing materials;
- (b) Capital goods, whether new or second-hand, including inter-alia following and their spares:
  - (i) DG sets, captive power plants, transformers and accessories for all above.
  - (ii) Pollution control equipment.
  - (iii) Quality assurance equipment.
  - (iv) Material handling equipment, like fork lifts and overhead cranes, mobile cranes, crawler cranes, hoists and stackers.
  - (v) Un-interrupted Power Supply System (UPS), Special racks for storage, storage systems, modular furniture, computer furniture, anti-static carpet, teleconference equipment, Servo Control System, Air-conditioners / Airconditioning system, panel for electricals and special data transmission cable.
  - (vi) Security Systems.
  - (vii) Tools, jigs, fixtures, gauges, moulds, dyes, instruments and accessories.
- (c) Raw material for making capital goods for use within unit.
- (d) Others including:

- (i) Prototypes and technical samples for existing product(s) and product diversification development or evaluation.
- (ii) Drawings, blue prints, charts, microfilms and technical data.
- (iii) Office equipment, including PABX, Fax machines, projection system, Computers, Laptop, Server.

(e) Spares and consumables for above items.

(f) Any other items not mentioned above with approval of BOA.

6.6.2 EOUs may import plain / studded gold / platinum or silver jewellery for export after repairs / remaking.

### **Conditions of Import**

6.7 Import of goods by EOU / EHTP / STP / BTP units shall be subject to following conditions:

- (a) Goods shall be imported into EOU / EHTP / STP / BTP premises. However, agriculture and allied sectors and granite sector units in EOU may supply / transfer capital goods and inputs in farm / fields / quarries with prior intimation to jurisdictional Customs / Central Excise authorities, provided ownership of goods rests with EOU units. Granite sector would also be allowed to take spares upto 5% of value of Capital Goods to quarry site.
- (b) Procedure as prescribed under Customs / Excise rules for EOUs and units in EHTP / STP / BTP will be followed and appropriate bond executed with Customs / Excise authorities.
- (c) Goods, except capital goods and spares, shall be utilised by EOU / EHTP / STP / BTP units within a period of three years or as may be extended by Customs authorities. However, imported tea shall be utilized within a period of 6 months from date of import. Similarly, export obligation against import of items [covered by chapter 9 of ITC (HS)] shall be fulfilled within a period of 90 days from date on which first import consignment is cleared by Customs authorities.

However in case of import of spices for VA purpose like crushing / grounding / sterilisation or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading, re-packing etc., EO shall be fulfilled within 120 days.

- (d) Goods already imported / shipped / arrived before issue of LoP / LoI are also eligible for duty free clearance under EOU / EHTP / STP / BTP scheme provided customs duty has not been paid and goods have not been cleared from Customs.

***Fax machines / laptop computers outside approved premises***

- 6.8.1 EOU / EHTP / STP / BTP units may install one fax machine at a place of its choice, outside premises of unit, subject to intimation of its location to concerned Customs / Central Excise authorities.
- 6.8.2 EOU / EHTP / STP / BTP units may, temporarily take out of premises of unit duty free laptop computers and video projection systems for working upon by authorized employees.
- 6.8.3 EOU / EHTP / STP / BTP units may install personal computers not exceeding two in number, imported / procured duty free in their registered / administrative office subject to DoR guidelines.
- 6.8.4 For IT and IT enabled services, persons authorized by software units may access facility installed in EOU / EHTP / STP / BTP unit through communication links.

***Leasing of Capital Goods***

- 6.9 Value of imported capital goods financed through leasing companies or obtained free of cost and / or on loan / lease basis shall also be taken into account for purpose of calculation of NFE as defined in FTP.

***Net Foreign Exchange (NFE) Earnings***

- 6.10.1 EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. Net Foreign Exchange (NFE) Earnings shall be calculated cumulatively for a block of five years from commencement of production according to formula given below. Items of manufacture for export specified in Letter of Permission (LoP) / Letter of Intent (LoI) alone shall be taken into account for calculation of NFE.

$$\text{Positive NFE} = A - B > 0$$

Where

'NFE' is Net Foreign Exchange;

'A' is FOB value of exports by EOU / EHTP / STP / BTP unit;

'B' is sum total of CIF value of all imported inputs and CIF value of all imported capital goods, and value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees, dividends, interest on external borrowings / high sea sales during first five year period or any other charges. "Inputs" mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

- 6.10.2 If any goods are obtained from another EOU / EHTP / STP / SEZ / BTP unit, or procured from an international exhibition held in India, or bonded warehouses or precious metals procured from nominated agencies value of such goods shall be included under 'B'.
- 6.10.3 If any capital goods imported duty free or leased from a leasing company, received free of cost and / or on loan basis or transfer, CIF value of capital goods shall be included pro-rata, under 'B' for period it remains with units.
- 6.10.4 For annual calculation of NFE value of imported capital goods and lumpsum payment of foreign technical know-how fee s hall be amortized as under:
- 1st – 10th year 10%.

**Maintenance of accounts**

- 6.11.1 EOU/EHTP/STP/BTP unit shall maintain proper account, and shall file digitally signed quarterly and annual report as prescribed in Annexure to Appendix 14-I-F to DC / Designated Officer in DOIT / DOBT and Customs and Central Excise authorities.
- 6.11.2 Unit shall be able to account for entire quantity of each category of homogenous goods imported / procured duty free, by way of exports, sales / supplies in DTA or transfer to other SEZ / EOU/EHTP/STP/BTP units and balance in stock. However, at no point of time units shall be required to correlate every import consignment with its exports, transfer to other SEZ / EOU/EHTP / STP / BTP units, sales in DTA and balance in stock. Any matter for clarification as to whether goods are homogenous or not shall be decided by Units Approval Committee.

**Monitoring of NFE**

- 6.12.1 Performance of EOUs shall be monitored by Units Approval Committee as per guidelines given in Appendix –14-I-G. Performance of EHTP / STP / BTP shall be monitored by DoIT / DoBT jointly with jurisdictional Central Excise / Customs authority.
- 6.12.2 Failure to ensure positive NFE or to abide by any of terms and conditions of LoP / LoI / IL / LUT shall render unit liable to penal action under provisions of FT (D&R) Act, 1992 and Rules and Orders made there under without prejudice to action under any other law / rules and cancellation or revocation of LoP / LoI / IL.

**Conversion of Scrap / dust / sweeping of Gold / silver / platinum into standard Bars**

- 6.13 Scrap / dust / sweeping of gold / silver / platinum may be sent to Government of India Mint / Private Mint from EOU / EHTP / STP units and returned to them in standard bars in accordance with procedure prescribed by Customs authorities or may be permitted to be sold in DTA on payment of applicable customs

duty, on basis of gold / silver / platinum content, as may be notified by Customs authorities.

<b><i>DTA supplies</i></b>	6.14	Notwithstanding provision of DTA sales in Para 6.8 of FTP, such DTA sales shall not affect application to any goods of any other prohibition or regulation affecting import thereof in force at time when such goods are imported. This also does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from any commitment or compliance with any requirements to which importer may be subject to under other laws or regulations.
<b><i>Supplies to other EOU / EHTP / STP / SEZ / BTP units</i></b>	6.15	Supplies to other EOU / SEZ / EHTP / STP / BTP units shall be counted towards NFE provided that such goods are permissible for procurement by these units.
<b><i>Transfer of Power from one unit to another</i></b>	6.16	Transfer of power from Captive Power plants (DG Sets) from one unit of EOU / EHTP / STP / BTP to another is permitted as prescribed in sector specific condition in Appendix 14-I-C.
<b><i>Supply of precious / semiprecious / Synthetic stones from DTA</i></b>	6.17	Supplier of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOUs shall be eligible for grant of Replenishment Authorisation at rates and for items mentioned in HBP v1. Procedure for submission of application for grant of Replenishment Authorisation as contained in relevant Chapter of HBP v1 shall be applicable. However, application shall be made to DC concerned. Such supplies to EOUs are not treated as deemed exports for purpose of any of deemed export benefits.
<b><i>Application for grant of entitlements</i></b>	6.18	Application for grant of all entitlements may be made to DC concerned.
<b><i>Export through other exporters</i></b>	6.19	<p>An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export goods manufactured/ software developed by it through other exporter or any other EOU / EHTP / STP / SEZ / BTP unit subject to condition that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Goods shall be produced in EOU / EHTP / STP / BTP unit concerned.</li> <li>Level of NFE or any other conditions relating to imports and exports as prescribed shall continue to be discharged by EOU / EHTP / STP unit concerned.</li> <li>Export orders so procured shall be executed within parameters of EOU / EHTP / STP / BTP schemes and goods shall be directly transferred from unit to port of shipment.</li> <li>Fulfillment of NFE by EOU / EHTP / STP / BTP units in</li> </ol>

regard to such exports shall be reckoned on basis of price at which goods are supplied by EOUs to other Exporter or other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit.

- (e) All export entitlements, including recognition as Status Holder would accrue to exporter in whose name foreign exchange earnings are realized. However, such export shall be counted towards fulfillment of obligation under EOU / EHTP / STP / BTP scheme only.

### **Other Entitlements**

- 6.20.1 FOB value of export of an EOU / EHTP / STP / BTP unit can be clubbed with FOB value of exports of its parent company in DTA or vice versa for purpose of according Export House and Trading House status.
- 6.20.2 Sectoral norms as notified by Government shall apply to FDI in service activities.
- 6.20.3 Software units may also use computer system for training purpose (including commercial training) subject to condition that no computer terminal shall be installed outside bonded premises for this purpose.
- 6.20.4 Export of iron ore shall be subject to decision of Government. Requirements of other conditions of exports like minimum export price / export in consumer pack etc. as per ITC(HS) shall apply in case raw materials are sourced from DTA and exported without further processing / manufacturing by EOU. Export of textile items shall be covered by bilateral agreements. Wood based units shall comply with direction of Supreme Court contained in its order dated 12.12.1996 in Writ (civil) No 202 of 1995- T.N.Godavarman Thirumulpad v/s Union of India and others with WP(Civil) No 171 of 1996 in regard to use of timber / other wood.

### **Sub-Contracting**

- 6.21.1 Sub-contracting by EOU gems and jewellery units through other EOUs or SEZ Units or units in DTA shall be subject to following conditions:-
- (a) Goods, finished or semi finished, including studded jewellery, taken out for sub- contracting shall be brought back to unit within 90 days.
- (b) No cut and polished diamonds, precious and semiprecious stones (except precious, semi-precious and synthetic stones having zero duty) shall be allowed to be taken out for sub-contracting.
- (c) Receive plain gold / silver / platinum jewellery from

DTA/EOU/SEZ units in exchange of equivalent quantity of gold / silver / platinum, as case may be, contained in said jewellery.

- (d) EOUs shall be eligible for wastage as applicable as per para 4A.2 of HBP v1 for sub-contracting and against exchange.
- (e) DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold / silver / platinum shall not be entitled to deemed export benefits.

6.21.2 Facility of getting job work done from DTA unit will be available even when job worker is not registered with Central Excise authority subject to condition that goods are brought back to premises of Unit on completion of job work.

6.21.3 Export of finished goods from job worker's premises may be permitted provided such premises are registered with Central Excise authorities. Where job worker is SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP unit, no such excise registration is required and export may be effected either from job worker's premises or from premises of unit. Export of such products from job worker's premises shall not be allowed through third parties as provided in FTP.

6.21.4 EOUs may be permitted to remove moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers and patterns and drawings to premises of sub-contractors subject to conditions that these shall be brought back to premises of units on completion of job work within a stipulated period. Raw materials may or may not be sent along with these goods.

6.21.5 In case of sub-contracting of production process abroad, goods may be exported from sub-contractor premises subject to conditions that job work charges shall be declared in export declaration forms, invoices etc. and full repatriation of foreign exchange.

#### ***Contract Farming***

6.22 EOUs engaged in production / processing of agriculture / horticulture / aquaculture products, may, on basis of annual permission from Customs authorities, take out inputs and equipments (specified at Appendix 14-I-J) to DTA farm subject to following conditions:-

- (a) Supply of inputs by EOUs to contract farm(s) shall be subject to input-output norms approved by DGFT / BoA.
- (b) There shall be contract farming agreement between EOU and DTA farmer(s).



- (c) Unit has been in existence for at least two years and engaged in export of agriculture / horticulture / aquaculture products; otherwise it shall furnish bank guarantee equivalent to duty foregone on capital goods / inputs proposed to be taken out to Deputy / Assistant Commissioner of Customs / Central Excise till unit completes two years
- Export through Exhibitions / Export Promotion tour** 6.23 EOU / EHTP / STP / BTP units may export goods for holding / participating in exhibitions abroad with permission of DC subject to following conditions:-
- (a) Unit shall produce to Customs authorities letter in original or its certified copy containing approval of DC. For gems and jewellery items, a self certified photograph of products shall also be submitted.
- (b) In case of re-import, such items, on arrival shall be verified along with export documents before clearance.
- (c) Items not sold abroad shall be re-imported within 60 days of close of exhibition. However, in case exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of first exhibition, then 60 days shall be counted from date of close of last exhibition.
- (d) In case of personal carriage of goods and for holding / participating in overseas exhibitions, value of such gems and jewellery shall not exceed US \$ 2 million.
- Personal Carriage of gems and jewellery for Export promotion tours** 6.24 Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US \$ 100,000 for export promotion tours and temporary display / sale abroad by EOUs is also permitted with approval of DC subject to following conditions:-
- (a) EOU shall bring back goods or repatriate sale proceeds within 45 days from date of departure through normal banking channel.
- (b) Unit shall declare personal carriage of such samples to Customs while leaving country and obtain necessary endorsement.
- Export through show-rooms abroad / duty free shops** 6.25 Export of goods is also permitted for display / sale in permitted shops set up abroad or in showrooms of their distributors / agents. Items not sold abroad within 180 days shall be re-imported within 45 days.

***Sale through  
showrooms / retail  
outlets at International  
Airports***

- 6.26 EOUs may set up showrooms /retail outlets at International Airports for sale of goods in accordance with procedure laid down by Customs authorities. Items remaining unsold after a period of 60 days shall be exported or returned to respective EOUs.

***Personal carriage of  
Import / export Parcels  
including through  
foreign bound passengers***

- 6.27.1 Import / export through personal carriage of gem and jewellery items may be undertaken as per procedure prescribed by Customs. Export proceeds shall be realized through normal banking channel. Import / export through personal carriage, other than gem and jewellery units, shall be allowed provided goods are not in commercial quantity.
- 6.27.2 For Personal carriage of jewellery by foreign bound passenger, following documents shall be submitted by EOU units as proof of exports:
- (a) Copy of shipping bill filed by EOUs ;
  - (b) A copy of Currency Declaration Form filed by Foreign buyer with Customs at time of his arrival; and
  - (c) Foreign Exchange Realisation / Encashment Certificate from Bank.
- 6.27.3 In addition to this, Personal Carriage by foreign bound passenger on Document Against Acceptance (DA) / Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. EOUs will have to furnish following documents as proof of exports:-
- (a) Copy of Shipping Bill;
  - (b) Bank Certificate of Export and Realisation.
- 6.27.4 Procedure for personal carriage of import parcels will be same as for import of goods by airfreight except that parcels shall be brought to Customs by EOUs / foreign national for examination and release. Instructions issued by Customs authorities in this regard should be followed mutatis mutandis.
- 6.27.5 Personal carriage of parts by foreign bound passengers shall be allowed in case same are required for repairs of exported goods at customer site. Following documents should be submitted as proof of exports:-
- (a) Permission letter from Customs for exports.
  - (b) Invoice with value (for payment or free of charge)

**Replacement / Repair  
of imported / indigenous  
goods**

- 6.28.1 Units may send capital goods abroad for repair with permission of Customs authorities. Any foreign exchange payment for this purpose will also be allowed. However, no permission will be required for sending capital goods for repair within country.
- 6.28.2 EOU/EHTP/STP/BTP units may, on basis of records maintained by them and prior intimation to Customs authorities:-
- (a) Transfer goods to DTA/ abroad for repair / replacement, testing or calibration and return.
  - (b) Transfer goods for quality testing / R&D purpose to any recognised laboratory / institution upto Rs.5 lakhs per annum without payment of duty, on giving suitable undertaking to Customs for return of goods. However, if goods have been consumed / destroyed in process of testing etc. a certificate from laboratory / institution to this effect be furnished to Customs.

**Samples**

- 6.29.1 EOU/EHTP/STP/BTP units may on basis of records maintained by them, and on prior intimation to Customs authority supply or sell samples in DTA for display / market promotion on payment of applicable duties.
- 6.29.2 Remove samples without payment of duty, on furnishing a suitable undertaking to Customs authorities for bringing back samples within a stipulated period.
- 6.29.3 An EOU may export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds, silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through courier agencies / post.
- 6.29.4 An EOU on basis of records maintained by them and on prior intimation to customs authorities may send samples to other EOUs for display on returnable basis within a period of 30 days.

**Donation of Computer  
and Computer peripherals**

- 6.30 EOU / EHTP / STP / BTP unit may be allowed by Customs authorities concerned to donate imported / indigenously procured (bought or taken on loan) computer and computer peripherals, including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage units without payment of duty, two years after their import / procurement and use by units, to a school run by Central Government, or Government of a State or, a Union Territory or, a local body, an Educational Institution run on non-commercial basis by any organization, a Registered Charitable Hospital, a Public Library, a Public Funded Research and Development Establishment, a Community Information Center run by Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or

- local body, an Adult Education Center run by Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or a local body, or an organization of Central Government or, a Government of a State or, a Union Territory as per Customs / Central Excise notification.
- Destruction of goods*** 6.31 No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap / waste / remnants / rejects are destroyed within Unit after intimation to Custom authorities or destroyed outside Unit with permission of Customs authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.
- Distinct Identity*** 6.32 If an industrial enterprise is operating both as a domestic unit as well as an EOU / EHTP / STP / BTP unit, it shall have two distinct identities with separate accounts, including separate bank accounts. It is, however, not necessary for it to be a separate legal entity, but it should be possible to distinguish imports and exports or supplies affected by EOU / EHTP / STP / BTP units from those made by other units of enterprise.
- Unit Approval Committee for EOUs*** 6.33.1 Powers and functions of Unit Approval Committee of EOUs shall be as under:-
- (a) To consider applications for setting up EOUs other than proposals for setting up of unit in services sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by BoA). Items of manufacture requiring industrial licence under industrial (Development & Regulation) Act, 1951 shall be considered by BoA.
  - (b) to consider and permit conversion of units in SEZ to EOU;
  - (c) to monitor performance of Units;
  - (d) to supervise and monitor permission, clearances, licences granted to units and take appropriate action in accordance with law;
  - (e) to call for information required to monitor performance of unit under permission, clearances, licenses granted to it;
  - (f) to perform any other function delegated by Central Government or its agencies;

- (g) to perform any other function as may be delegated by State Governments or its agencies; and
- (h) to grant all approvals and clearances for establishment and operation of EOUs.

**Approval of EHTP /  
STP / BTP units**

6.33.2 In case of units under EHTP / STP scheme, necessary approval / permission shall be granted by officer designated by DOIT / Director (STPI). Designated officer shall also exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of FT (D&R) Act, 1992 in respect of STP / EHTP as mentioned in Gazette Notification No. S.O. 106 (E) dated 30-1-2006. Similarly in case of units under BTP, necessary approval / permission shall be granted by officer designated by DoBT. However, designated officers shall adopt criteria for automatic approval of new units as laid down in Appendix 14-I-B.

**Administration of EOUs /  
Power of DC /  
Designated Officer**

6.34 DC / Designated Officer shall have following powers in respect to units. Jurisdiction of DC is given in Appendix 14-I-K.

- (1) Conversion of sick / closed DTA unit into EOU;
- (2) Conversion of EOU to STP / EHTP / BTP and vice-versa as per prescribed procedure;
- (3) To allow increase in value of capital goods in terms of Indian Rupees, on account of foreign exchange rate fluctuations;
- (4) To permit capacity enhancement without any limit in case of de-licensed industries only;
- (5) Permit broad-banding for similar goods and activities mentioned in LoP or to provide for backward or forward linkages to existing line of manufacture;
- (6) Authorize change in name of company or implementing agency and change from a company to another provided new implementing agency / company undertakes to take over assets and liabilities of existing unit;
- (7) Permit change of location from place mentioned in LoP to another and/or include additional location provided that no change in other terms and conditions of approval is envisaged and that new location is within territorial jurisdiction of DC / Designated Officer;
- (8) Extend validity period of LoP by three years beyond initial validity period of LoP (except in case where there is

a restriction on initial period of approval, like setting up of oil refinery projects);

- (9) Cancel LoP wherever warranted;
- (10) Permit merger of two or more units into one unit provided units fall within jurisdiction of same DC/Designated Officer subject to conditions that activities are covered under provision of broad banding;
- (11) Exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of FT (D&R) Act, in respect of EOUs as mentioned in Gazette Notification No. SO. 194(E) dated 6.3.2000;
- (12) Do valuation of exports declared on SOFTTEX form by EOUs as per RBI A.D. (M.A Series) Circular AP (DIR series Circular No.9 dated 25.10.2001);
- (13) Issue eligibility certificates for grant of employment visa to low level foreign technicians to be engaged by EOUs as per Ministry of Home Affairs' letter No. 25022 / 7 / 99- F.1 dated 20.9.1999;
- (14) Function as a Registering authority for EOU / EHTP / STP/ BTP. A separate Registration cum- Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in paragraph 2.44 of FTP except in case of spices. In case of spices, it would be mandatory for units to get themselves registered with Spices Board also.
- (15) Allot Importer-Exporter Code number for EOUs, if same has already not been allotted to entity;
- (16) Issue of Green Card automatically after execution of LUT;
- (17) Grant / renewal of Status Certificate in respect of EOUs provided it does not involve clubbing of FOB value of exports of its parent company in DTA;
- (18) Publicity of EOU / EHTP / STP / BTP Scheme under their jurisdiction.

**Registration-cum-Membership Certificate**

**Importer Exporter Code No.**

**Green Card**

**Clearance of Capital Goods in DTA**

6.35

Clearance of Capital Goods including second hand in DTA shall be allowed as per FTP under EPCG Scheme. In other cases, clearance in DTA may be allowed on payment of applicable duty and Import Policy in force on date of such clearance.

**Depreciation norms**

6.36.1

Depreciation up to 100% is permissible for Computers and Computer peripherals in 5 years and 10 years in case of other items.

- Depreciation norms for Computers and Computer peripherals** 6.36.2 Depreciation for computers and computer peripherals shall be as follows:-
- 10% for every quarter in first year;
  - 8% for every quarter in second year;
  - 5% for every quarter in third year;
  - 1% for every quarter in fourth and fifth year.
- Depreciation norms for other Capital goods** 6.36.3 For capital goods, other than above, depreciation rate would be as follows:-
- 4% for every quarter in first year;
  - 3% for every quarter in second and third year; and
  - 2.5% for every quarter in fourth and fifth year.
  - 2% for every quarter thereafter.
- Conversion** 6.37.1 Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU / EHTP / STP / BTP unit, but no concession in duties and taxes would be available under scheme for plant, machinery and equipment already installed. On conversion, they would get Income Tax concessions but limited to period of 10 year from original commencement of manufacture or that prescribed under Section 10 of Income Tax Act whichever is earlier. For this purpose, DTA unit may apply to DC / Designated Officer concerned in same manner as applicable to new units. In case there is an outstanding export commitment under EPCG scheme / Advance Authorization Scheme, it will follow the procedure laid down in Appendix.14-I-O of HBP v1.
- 6.37.2 Existing EHTP / STP / BTP units may also apply for conversion / merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, units will continue to avail permissible exemption in duties and taxes as applicable under relevant scheme. EHTP / STP / BTP units desiring conversion as an EOU may apply to DC concerned through Officer designated by DoIT / DoBT in same manner as applicable to new units. Likewise EOU desiring conversion into EHTP / STP / BTP may apply to officer designated by DoIT / DoBT through DC concerned.
- 6.37.3 An EOU may be shifted to SEZ with approval of DC provided EOU unit has achieved pro-rata obligation under EOU scheme.
- Revival of Sick units** 6.38 Subject to a unit being declared sick by appropriate authority, proposals for revival of unit or its take over may be considered by BOA . Guidelines on revival of sick units are given in Appendix 14-I-M.

6.39 **FAST TRACK CLEARANCE PROCEDURE**

<b>Eligibility</b>	6.39.1	EOUs having a status holder certificate under FTP shall be eligible for Fast Track Clearance Procedure.
<b>Examination of Import Cargo</b>	6.39.2	Status holder units shall be exempted from examination of import cargo at Port of import. Jurisdictional Commissioner of Customs / Central Excise may, however, examine consignments at unit's place on random basis.
<b>Domestic procurement and import of goods</b>	6.39.3	Units having physical export turnover of Rs. 15 crores and above in preceding financial year shall be allowed to import goods without payment of duty on basis of pre-authenticated procurement certificate issued by jurisdictional Customs / Central Excise Authority.
<b>Installation of Fax Machine/ Computers</b>	6.39.4	Eligible EOUs may install one fax machine and two computers in their administrative / registered office outside bonded premises under prior intimation to jurisdictional Asst / Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.
<b>Procurement of DG sets</b>	6.39.5	Procurement of DG set of capacity commensurate with actual requirement of unit shall be permitted under intimation to DC and jurisdictional Central Excise authority.
<b>Temporary removal of Capital Goods</b>	6.39.6	Eligible EOU units may remove their capital goods or parts thereof for repairs under prior intimation to jurisdictional Asstt. / Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.
<b>Clearance of rejects in DTA</b>	6.39.7	Request for permission for DTA clearance of rejects shall be considered by jurisdictional Excise Authority on priority basis.
<b>Personal carriage of samples</b>	6.39.8	Personal carriage of samples of Gems & Jewellery by status holder EOUs are allowed subject to limit fixed in Para 6.24 without a need for prior permission from DC / Customs / Central Excise.
<b>Activities which do not require permission</b>	6.39.9	In respect of following activities of a status holder, permission will not be required from DC or jurisdictional Central Excise authority:  DTA sale of finished products in terms of para 6.8(a) of FTP, Participation in exhibition and Personal carriage of Gems & Jewellery for export promotion tours subject to fulfillment of conditions of para 6.24 of HBP v1. However, prior intimation thereof needs to be given.
<b>Time bound disposal of applications</b>	6.40	DC shall dispose off applications expeditiously. Following time schedule shall normally be followed to dispose of applications provided application is complete in all respects and is accompanied by prescribed documents.



S. No	Category of Application	Time limit for disposal (days)
1	Issue of LoP / LoI	15
2	Conversion of LoP / LoI	15
3	Acceptance of LUT	3
4	Renewal of LUT	3
5	Permission for broad banding / diversification	3
6	Permission for change in locations	7
7	Permission for Advance DTA sale	2
8	Permission for merger of units	7
9	Permission for enhancement of production capacity	3
10	Cancellation of LoP	3
11	Permission for debonding / exit	7
12	Permission for DTA sale	2
13	Eligibility certificate for employment visa for lower level technicians	2
14	Issue of Green Card	2
15	Renewal of Green Card	Same day
16	Permission to lease CG	1
17	Permission for disposal of scrap/waste	2
18	Permission for change in name	2
19	Inter Unit Transfer	2
20	Wastage Norms, ad-hoc	2
21	Permission for re-import	Same day
22	Permission for re-export	Same day
23	Permission for replacement/repair of goods	Same day
24	Allotment of I.E. Code	1
25	Authorization of softex form	1
26	Reimbursement of CST claims	7
27	Issue of GSP Certificate	Same day
28	Permission for conversion of EOU to STPI, EPCG	5
29	Permission of final exit of EOU	5
30	Permission of extension of EOU	2
31	Permission to allow increase in value of CG	2
32	Permission for export through exhibition / tour	2
33	Reimbursement of Duty Drawback / TED	7

## CHAPTER – 7

### SPECIAL ECONOMIC ZONES

Policy relating to Special Economic Zones is contained in Special Economic Zone Rules, 2006, notified in the Gazette of India, Extraordinary No. GSR 54(E) dated 10.2.2006.

## CHAPTER-8

### DEEMED EXPORTS

<i>Policy</i>	8.1	Policy relating to Deemed Exports is in Chapter-8 of FTP.
<i>Criteria for claiming Deemed Exports Benefits</i>	8.2.1	In respect of supplies under Paragraph 8.2(a) of FTP procedure for issue of ARO and Back-to-Back Inland Letter of Credit is given in paragraphs 4.14 and 4.15 of HBP v1.
	8.2.2	In respect of supplies under paragraph 8.2(b) of FTP and DFIA, deemed export benefits may be claimed from Development Commissioner or RA concerned. Advance Authorisation and DFIA shall be claimed from the concerned RA. Such supplies shall be certified by receiving agencies.
	8.2.3	In respect of supply of capital goods under paragraph 8.2 (c) of FTP, supplier shall produce a certificate from EPCG Authorisation holder evidencing supplies / receipt of manufactured capital goods.
	8.2.4	In respect of supplies under categories mentioned in paragraphs 8.2(d), (e), (f), (g), (i) and (j) of FTP application for advance authorisation shall be accompanied with a Project Authority Certificate in Appendix 27. Payment against such supplies shall be certified by Project Authority concerned as in Appendix 22C.

***Procedure for claiming  
Deemed Exports  
Drawback & Terminal  
Excise Duty Refund /  
Exemption from payment  
of Terminal Excise Duty***

8.3.1 Procedure for claiming benefits under paragraph 8.3 (b) and (c) of FTP shall be as under:-

- (i) An application in ANF 8 along with prescribed documents, shall be made by supplier to RA concerned. Recipient may also claim benefits on production of a suitable disclaimer from supplier along with a self declaration in Appendix 22C of HBP v1 regarding non-availment of CENVAT credit in addition to prescribed documents.
- (ii) In case of supplies under paragraph 8.2(a), (b) & (c), claim shall be filed against receipt of payment through normal banking channel as in Appendix 22B. Such claims shall be filed within a period of 6 months from end of monthly / quarterly / half yearly period reckoned from the date of payment as per the option of applicant. In cases where payment is received in advance, last date for submission of application may be correlated with date of supply instead of date of receipt of payment.
- (iii) In respect of supplies under paragraph 8.2(b) of FTP where supplier wants to claim benefits from RA, RA shall allow deemed export benefits to DTA supplier, on receipt of certified copies of Central Excise attested invoice as proof of supplies made and / or Excise attested CT3 form and proof of validity of LOP.
- (iv) In respect of supplies under categories mentioned in paragraphs 8.2(d), (e), (f), (g), (h), (i) and (j) of FTP claim may be filed for payment received / supplies effected during a particular month / quarter / half year at option of applicant either on the basis of proof of supplies effected or payment received. Claim may be filed either against a particular project or all the projects. Such claims shall be filed within a period of 6 months from end of monthly / quarterly / half yearly period reckoned from date of receipt of supplies by project authority or from date of receipt of the payment as per the option of applicant. Such claims may also be filed where part payments have been received.

8.3.2 For claiming exemption from payment of terminal excise duty, procedure prescribed by Central Excise authority shall be followed.

- 8.3.3 Where All Industry Rate of Drawback is not available or same is less than 4/5th of duties actually paid on materials or components used in production or manufacture of the said goods, exporter / supplier may apply for fixation of brand rate in application form as given in ANF 8 to RA or DC.
- 8.3.4 Claim application shall be filed along with application for fixation of brand rate of duty drawback in case brand rate is required to be fixed. Provision of late cut under paragraph 9.3 and supplementary claim under paragraph 9.4 shall also be applicable under this sub-paragraph.
- 8.3.5 RA may consider provisional payment up to 75% of drawback claim in case of private companies and 90% in case of PSUs, pending fixation of Brand Rate.
- 8.3.6 Subject to procedure laid down in this Handbook, Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1995 shall apply mutatis mutandis to deemed exports.
- 8.4 In respect of supplies made by sub-contractor to main contractor under paragraph 8.2(d), (e), (f), (g), (i) and (j), main contractor may make payment to sub-contractor and issue payment certificate as in Appendix 22-C as Form 1-C. However, for supplies under paragraph 8.2(d), (e), (f), (g) and (j), payment certificate from main contractor shall not be insisted for refund of Terminal Excise duty. Deemed exports benefits to sub-contractor would be available to the extent of goods that are manufactured and supplied by him or outsourced from other manufacturers, for value as indicated in Appendix 22-C of HBP v1.

***Procedure for claiming  
deemed export benefit  
by Sub- contractor***

**CHAPTER - 9****MISCELLANEOUS MATTERS**

<b><i>Change In Name and Constitution</i></b>	9.1	An IEC holder must get the change in name / address / constitution incorporated within 90 days of such change. Provided, however, RA issuing IE Code may, condone delay on payment of penalty of Rs. 1000/-.
		Change in constitution, aforesaid, does not include change in directors of Public Limited Company.
<b><i>Denomination of Import Authorisation / Licence / Certificate / Permissions</i></b>	9.2	CIF value of Authorisation / FOB value of export obligation shall be indicated both in Rupees and in freely convertible currency(s) at the exchange rate(s) prevailing on Authorisation issue date.
	9.2.1	Remittance of foreign exchange and discharge of export obligation against Authorisation shall be regulated in freely convertible currency.
	9.2.1.1	No enhancement in Rupee value shall be necessary if remittance of foreign exchange is covered by CIF value of Authorisation shown in freely convertible currency.
	9.2.2	However, on Advance Authorisation(s), issued for exports to ACU countries, export obligation shall be denominated and discharged in ACU dollars.
	9.2.3	Export obligation in Advance Authorisation for intermediate supply and for deemed export, where supplies are to be made within the country, shall be denominated and discharged in Indian rupees.
<b><i>Applications Received After Expiry of Prescribed Date of Receipt</i></b>	9.3	Wherever any application is received after expiry of last date for submission of such application but within six months from last date, such application may be considered after imposing a late cut @ 10% on entitlement.
<b><i>Supplementary Claims</i></b>	9.4	Wherever any application for supplementary claim is received, within specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @ 10% on the entitlement.
<b><i>Furnishing of Information</i></b>	9.5	Every importer / exporter shall furnish such information as may be called for by DGFT or any officer duly authorised.
<b><i>Clarifications On Policy / Procedures</i></b>	9.6	A request seeking clarifications on any provision of FTP or HBP, importability or exportability of items under ITC (HS),

- may be made to DGFT in the form in Appendix 28. Clarification may also be sought on E-mail.
- Consumption Register** 9.7 Importer shall maintain a register as in Appendix 23 (for 3 years period) of items imported under an Authorisation and separately for items imported with actual user condition and its consumption.
- In respect of particular schemes such register shall be maintained for specified period.
- Export Facilitation** 9.8 In order to resolve exporters' problems in a co-ordinated manner, field offices of DGFT shall act as Export Facilitation Centres and nodal agencies.
- In addition, Nodal Officers have also been nominated in other Ministries / Departments and a list of such officers nominated to assist exporters is given in Appendix 17.
- Standing Grievance Committee** 9.9 Detail of the Grievance Redressal Mechanism is given in para 2.49 of FTP.
- For speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to FTP and Procedure, Grievance Committees have been constituted chaired by (i) DGFT at Headquarters and (ii) head(s) of RA(s) in regional offices.
- Grievance Committee will include representatives of Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Export Promotion Councils / Commodity Boards, Development Authorities, and Government Departments / technical authorities as their members.
- 9.9.1 Chairman of the respective Grievance Committee(s) may also co-opt any other member. Meetings of such Committees shall be held on a monthly basis.
- 9.9.2 Every exporter / importer shall have a right to seek and have an opportunity to make a representation (in writing) to and be personally heard, if he so desires, by Grievance Committee.
- 9.9.3 A representation to Grievance Committee may be made in as in Appendix 26.
- Counter Assistance** 9.10 For speedy disposal of applications, "Counter Assistance" will function in all offices of DGFT.
- An FTDO shall be in charge of counter in each office. On submission of application at the counter, applicant will be handed over a token and would be advised on same day whether

his application is complete and admitted for further processing by the office or whether there is any deficiency that needs to be rectified.

- 9.10.1 Counter Assistant will send application to concerned section on day of receipt for necessary scrutiny. If there are any deficiencies, these will be noted by concerned section and returned to counter on the same day. In case of complete applications, applicant will be given a formal receipt indicating file number for further reference.

Deficient applications will be returned to applicant for complying with all deficiencies. Complete applications shall be processed by concerned section within the time frame as given under paragraph 9.11.

Communication of any deficiency noted subsequently should be undertaken only with approval of head of office who shall be responsible for effective functioning of Counter Assistance.

- 9.10.2 Counter Assistance may also be availed of for amendments of minor nature / enquiries. Applications, in such cases, will be received in regional offices at counter against a proper receipt. Authorisation / licence / list / enquiry, shall be returned after carrying out necessary amendments / giving necessary reply as far as possible on the same day, across the Counter.

***Time Bound disposal  
of applications***

- 9.11 RA shall dispose off applications expeditiously. Following time schedule shall normally be followed to dispose of applications provided it is complete in all respects and is accompanied by prescribed documents.

S.No.	Category of Application	Time Limit For Disposal (in working days)
a)	IEC Number	2
b)	Advance Authorisation where Input-Output norms are notified or under paragraph 4.7, Advance Authorisation for Annual Requirement and DFIA.	3
	Advance Authorisation where Input-Output norms are notified but where cases are to be approved by Commerce & Industry Minister	15

	Advance Authorisations where Input-Output Norms are not notified,	45
	Fixation of input output norms	90
c)	DEPB	3
d)	(i) EPCG Authorisations on self declaration basis	3
	(ii) EPCG Authorisations for fixation of nexus { other than those covered in (i) above }	45
e)	All Authorisations under Gem & Jewellery scheme.	3
f)	Revalidation of Authorisation and extension of export obligation period by R.A.	3
g)	Acceptance of BG / LUT	3
	Redemption of BG / LUT for Advance Authorisations and DFIA.	15
	Redemption of BG / LUT for EPCG Authorisations.	30
h)	Issuance/renewal of status certificate.	3
i)	Amendment of any category of Authorisation	3
j)	Fixation of deemed exports Drawback rate	45
k)	Miscellaneous	10
l)	All applications filed through EDI mode	1

Cases of undue delay in disposal of applications may be brought to notice of head of regional offices by way of a written representation, which shall be promptly enquired into and responded to.

***Date of Shipment /  
Dispatch In respect  
of Imports***

9.11 A Date of shipment / dispatch for imports will be reckoned as under:-

<b>Mode of Transportation</b>	<b>Date of Shipment / Dispatch</b>
(i) By Sea	The date affixed on the Bill of Lading
(ii) By Air	Date of relevant Airway Bill provided this



represents date on which goods left last airport in the country from which the import is effected.

- (iii) From land-locked countries Date of dispatch of goods by rail, road or other recognised mode of transport to consignee in India through consignment basis.
- (iv) By Post Parcel Date stamp of office of dispatch on the packet or dispatch note
- (v) By Registered Courier Service Date affixed on Courier Receipt / Waybill
- (vi) Multimodal transport Date of handing over goods to first carrier in a combined transport Bill of Lading.

***Date of Shipment / Dispatch in respect of Exports***

9.12

Date of shipment /despatch for exports will be reckoned as under:-

**Mode of Transportation**

**Date of Shipment / Dispatch**

**(i) By Sea**

For bulk cargo, date of Bill of Lading or date of mate receipt, whichever is later.

a) For containerised cargo, date of "Onboard Bill of Lading", or "Received for Shipment Bill of Lading", where the L/C provides for such Bill of Lading. For exports by containers from Inland Container Depot (ICD), date of Bill of Lading issued by shipping agents at the time of loading of export goods in ICD after customs clearance.

b) For Lash barges, date of Bill of Lading evidencing loading of export goods on board.

**(ii) By Air**

Date mentioned by appropriate officer of Customs on Shipping Bill, evidencing loading or handing over of goods to air cargo complex, which are not international airports, or by way of rotation of flight number and date.

**(iii) By Post Parcel** Date stamped on postal receipt.

**(iv) By Rail** Date of RR (Railway Receipt).

(v) By Registered Date affixed on Courier Receipt/ Waybill.  
Courier  
Service

(vi) By Road Date on which goods crossed Indian border  
as certified by Land Customs Authorities.

However, wherever Procedural / Policy provisions have been modified to disadvantage of exporters, same shall not be applicable to consignments already handed over to Customs for examination and subsequent exports upto Public Notice / Notification date.

Similarly, in such cases where goods are handed over to the customs authorities before expiry of export obligation period but actual Exports take place after expiry of the export obligation period, such exports shall be considered within export obligation period and taken towards fulfilment of export obligation.

**General Power of review** 9.13

DGFT may, on his own or otherwise, call for records of any case pending with or decided by an officer subordinate to him or an officer of any EPC / FIEO including a Group / Committee of officers nominated, appointed or authorised by him and pass such orders as he may deem fit.

## APPENDICES

APPENDICES ARE AN INTEGRAL PART OF THE HANDBOOK OF PROCEDURES – VOLUME 1 (2004-2009) INCORPORATING THE ANNUAL SUPPLEMENT AS NOTIFIED BY THE PUBLIC NOTICE NO.1 (RE-2007) / 2004-2009 DATED 19<sup>TH</sup> APRIL 2007.

APPENDICES ARE AVAILABLE ON THE DGFT WEBSITE AND CAN BE ACCESSED AT <http://dgft.gov.in>